



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 1993/पौष 4, 1915

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25, 1993/PAUSA 4, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministry of the Government of India (other than  
Ministry of Defence)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1993

(पुरातत्व)

का.आ. 2783.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्त्व के हैं।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के निकाले जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारकों में हितवद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगा आक्षेप, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली 110011 के पते पर भेजे जा सकते हैं।

## अनुसूची

क्रम सं०	राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लॉट संख्यांक	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हिमाचल प्रदेश	लाहौल और स्पीति	शाशुर ग्राम	ताशी शुलिंग मठ (शाशुर)	सम्पूर्ण खसरा संख्यांक 718	0.0180 हेक्टर	उत्तर : खसरा नं. 717 और पहाड़ी, पूर्व : पहाड़ी दक्षिण : पहाड़ी पश्चिम : खसरा नं. 719	प्राइवेट	
2.	हिमाचल प्रदेश	लाहौल और स्पीति	तुप चिलिंग	घांडेला मठ (गुरु घंटाल)	संपूर्ण खसरा सं 16	0.0412 हेक्टर	उत्तर : पहाड़ी पूर्व : पहाड़ी दक्षिण : पहाड़ी पश्चिम : पहाड़ी	प्राबादी डीह	

[सं. 2/35/87-एम]  
अचला मौलिक, महानिदेशक—

## ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 7th December, 1993

S.O. 2783.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monuments specified in the schedule annexed hereto are of national importance ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and

Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months notice of its intention to declare the said ancient monuments to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of said notification in the official Gazette from any person interested in the said ancient monuments will be taken into consideration by the Central Government. The objections may be addressed to the Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011.

## SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Locality	Name of Monument
1	2	3	4	5
1.	Himachal Pradesh	Lahaul and Spiti	Shashur Village	Tashishuling monastery (Sha shur)
2.	Himachal Pradesh	Lahaul and Spiti	Tup chilling	Ghandhola Monastery (Guru Ghantal)

Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9	10
Whole of Khasra no. 718	0.0180 Hectares	North—Khasra No. 717 and hill East Hill South Hill West Khasra No. 719	Private	
Whole of Khasra No. 16.	0.0412 Hectares	North Hill East Hill South Hill West Hill	Abadi deh	

[No. 2/35/87-M]

ACHALA MOULIK, Dir. General

## शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1993

का.घा. 2784.—यसः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोवर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 10-10-92 के नोटिस संख्या एफ 3(57)90-एस.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यसः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं अतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली बृहद् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त बृहद् योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :  
“उप-जोन एफ-14 (किशनगढ़ क्षेत्र) में पड़ने वाले तथा उत्तर दक्षिण एवं पूर्व में क्षेत्रीय पार्कों से और पश्चिम में मौजूदा सब्जक तथा क्षेत्रीय पार्क के घिरे लगभग 1.500 हेक्टेयर (2.5 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को “मनोरंजनात्मक” से “सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं” (रमशांन भूमि) में परिवर्तित किया गया है।”

[स. के 13011/19/91-डी डी आई डी]

एस.सी. सागर, भवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(Delhi Division)

New Delhi, the 4th November, 1993

S.O. 2784.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F.3(57)90-MP, dated 10-10-92, in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice;

And whereas no objection/suggestions were received from the public with regard to the said proposed modifications and whereas the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

## MODIFICATION :

“The land use of an area measuring 1.00 ha. (2.5 acres) falling in sub-zone F-14 (Kishan Garh Area) bounded by regional parks in the North, South and East and existing road and regional park in the West, is changed from ‘recreational’ to ‘public and semi-public facilities’ (Cremation Ground)”

[No. K-13011/19/91-DDPB]  
S. G. SAGAR, Under Secy.

## पेट्रोलियम और रसायनिक संभालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2785.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि-दोम्नेर पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के अण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के.जी.बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलि-दोम्नेर

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	बून्डजवरम	ताडिपुड	112-4 भाग	0-05-50	
			112-5 भाग	0-01-00	
			112-6 भाग	0-04-00	
			112-7 भाग	0-10-50	
			113-1 भाग	0-07-00	
			113-7 भाग	0-14-50	
			113-6 भाग	0-00-50	
			123-2 भाग	0-05-50	
			123-3 भाग	0-02-00	
			123-4ए भाग	0-01-50	
			123-5 भाग	0-04-00	
			123-6 भाग	0-06-00	
			123-7 भाग	0-06-00	
			123-8 भाग	0-01-00	
			123-9 भाग	0-05-50	
			123-10 भाग	0-08-50	
			126-1ए भाग	0-08-00	
			126-1 बी भाग	0-09-00	
			126-2 भाग	0-11-50	
			126-3बी भाग	0-12-50	
			126-3सी भाग	0-00-50	
			127-4 भाग	0-10-00	
			135-2 भाग	0-14-00	
			134-1 भाग	0-30-00	
			134-2 भाग	0-01-00	



अन्य	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
			134-3 भाग	0-05-00	
			134-4 भाग	0-05-00	
			134-5 भाग	0-07-00	
			133-1ए भाग	0-04-50	
			139-1बी भाग	0-05-50	
			139-2 भाग	0-06-50	
			139-3 भाग	0-06-50	
			139-4 भाग	0-04-00	
			139-5 भाग	0-19-50	
			41-7 भाग	0 01-00	
			41-8 भाग	0-13-00	
			41-10 भाग	0-06-00	
			40-1 भाग	0-05-50	
			40-13ए भाग	0-21-50	
			40-13 बी भाग	0-16-00	
			39-1 भाग	0-12-00	
			36-2 भाग	0-05-50	
			36-4ए भाग	0-06-50	
			36-4बी भाग	0-11-00	
			36-6ए भाग	0-03-00	
			36-6बी भाग	0-02-00	
			36-6सी भाग	0-00-25	
			37-1ए भाग	0-08-75	
			37-1बी भाग	0-00-25	
			37-2 भाग	0-03-00	जि. वि.
			37-4 भाग	0-08-25	
			18- भाग	0-03-00	जि. वि.
			19-1 भाग	0-01-00	
			19-2 भाग	0-01-00	
			19-3 भाग	0-06-50	
			19-7 भाग	0-23-50	
			19-9 भाग	0-05-00	
			19-10 भाग	0-07-50	
			16-2ए भाग	0. 07-50	
			16-2बी भाग	0-06-00	
			16-2सी भाग	0-10-00	
			16-3ए भाग	0-07-50	

1	2	3	4	5
			16-3वीं भाग	0-07-00
			15-2 भाग	0-05-50
			14-4 भाग	0-12-00
			14-3 भाग	0-17-00
			14-5 भाग	0-05-50
			14-6 भाग	0-03-50
			14-7 भाग	0-01-00
			13-7ए भाग	0-21-50
			13-7बी भाग	0-03-00
			13-8 भाग	0-04-00
			13-9 भाग	0-04-00
			13-10 भाग	0-07-00
			12-2 बी भाग	0-00-50
			12-2 सी भाग	0-02-00
			12-2 डी भाग	0-01-50
			125-8 ए भाग	0-02-50
			125-8 बी भाग	0-05-50
			141-भाग	0-08-50 जी.पी.
			11-भाग	0-03-00 जी.पी.
			योग	5-60-50 या 13.85 एकड़

[सं० एल-14016/14/93-जी.पी.]

प्रचण्डु सेन, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2785.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object, the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Peravali—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (in Hect/- Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	undrajavaram	Tadipatru	112-4 Parts	0-05-50	
			.. 5 ..	0-01-00	
			.. 6 ..	0-04-00	
			.. 7 ..	0-10-50	
			113-1 Part	0-07-00	
			.. 7 ..	0-14-50	
			.. 6 ..	0-00-50	
			123-2 Part	0-05-50	
			.. 3 ..	0-02-00	

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Undrajavaram	Tadiparru	.. 4A ..	0-01-50	
			.. 5 ..	0-04-00	
			.. 6 ..	0-06-00	
			.. 7 ..	0-06-00	
			.. 8 ..	0-01-00	
			.. 9 ..	0-05-50	
			.. 10 ..	0-08-50	
			126-1A Part	0-08-00	
			.. 1B ..	0-09-00	
			.. 2 ..	0-11-50	
			.. 3B ..	0-12-50	
			.. 3C ..	0-00-50	
			127-4 Part	0-10-00	
			135-2Part	0-14-00	
			134-1 Part	0-30-00	
			.. 2 ..	0-01-00	
			.. 3 ..	0-05-00	
			.. 4 ..	0-05-50	
			.. 5 ..	0-07-00	
			133-1A Part	0-04-50	
			.. 1B ..	0-01-00	
			139-1B Part	0-05-50	
			.. 2 ..	0-05-50	
			.. 3 ..	0-06-50	
			.. 4 ..	0-04-00	
			.. 5 ..	0-19-50	
			41-7 Part	0-01-00	
			.. 8 ..	0-13-00	
			.. 10 ..	0-06-00	
			40-1 Part	0-05-50	
			.. 13A ..	0-21-50	
			.. 13B ..	0-16-00	
			39-1 Part	0-12-00	
			36-2 Part	0-05-50	
			.. 4A ..	0-06-50	
			.. 4B ..	0-11-00	
			.. 6A ..	0-03-00	
			.. 6B ..	0-02-00	
			.. 6C ..	0-00-25	
			27-1A Part	0-08-75	
			.. 1B ..	0-00-25	
			.. 2 ..	0-03-00	G.P.
			.. 4 ..	0-00-25	
			18-Part	0-03-00	G.P.
			19-1 Part	0-01-00	
			.. 2 ..	0-01-00	
			.. 3 ..	0-06-50	
			.. 7 ..	0-23-50	
			.. 9 ..	0-05-00	
			.. 10 ..	0-07-50	

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Undrajavaram	Tadiparru	16-2A Part	0-07-50	
			„ 2B „	0-06-00	
			„ 2C „	0-10-00	
			„ 3A „	0-07-50	
			„ 3B „	0-07-00	
			15-2 Part	0-05-50	
			14-4 Part	0-12-00	
			„ 3 „	0-17-00	
			„ 5 „	0-05-50	
			„ 6 „	0-03-50	
			„ 7 „	0-01-00	
			13-7A Part	0-21-50	
			7B „	0-03-00	
			8 „	0-04-00	
			„ 9 „	0-04-00	
			„ 10 „	0-07-00	
			12-2B Part	0-00-50	
			„ 2C „	0-02-00	
			„ 2D „	0-01-50	
			125-8A Part	0-02-50	
			„ 8B „	0-05-50	
			141-Part	0-08-50	G.P.
			11-Part	0-03-50	G.P.
			Total	5-60-50 R.A.C. 13.85 Cents.	

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2786.--जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेखलि दोम्मेरु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न बिबरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की आज्ञा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सहाम प्राधिकारी गैस (अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के. जी. बसोन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड़ी-533104, पान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष सच से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से सरकार विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची  
गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट  
पेरवल-दोम्मेरू

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आं. प्रदेश)	पेरवल्लि	नडुपल्लि	142- भाग	0-05-50	जी.पी.
			141-6 भाग	00-05-00	
			141-7 भाग	0-19-50	
			135-1 भाग	0-05-50	
			135-2 भाग	0-05-50	
			135-3 भाग	0-05-50	
			135-5 भाग	0-00-50	
			135-4 भाग	0-14-00	
			136-1बी भाग	0-14-50	
			136-1डी भाग	0-18-50	
			136-2 भाग	0-01-00	
			136-5 भाग	0-00-50	
			136-6बी भाग	0-05-50	
			136-6सी भाग	0-01-00	
			131-5 भाग	0-01-00	
			130-1 भाग	0-06-00	
			130-2 भाग	0-18-50	
			130-3 भाग	0-07-00	
			130-8 भाग	0-12-50	
			128-3 भाग	0-13-00	
			128-4 भाग	0-11-50	
			118-7 भाग	0-07-50	
			118-8 भाग	0-10-00	
			118-9 भाग	0-18-00	
			102-0 भाग	0-03-00	जी.पी.
			101-7 भाग	0-06-00	
			101-6ए भाग	0-03-50	जी.पी.
			159-5 भाग	0-03-50	
			159-6 भाग	0-30-50	जी.पी.
			159-7 भाग	0-23-00	
			156 भाग	0-30-50	जी.पी.
			85-2 भाग	0-16-50	
			85-5 भाग	0-00-50	जी.पी.
			85-4 भाग	0-05-50	
			96. 1 भाग	0-11-50	जी.पी.
			96-3 भाग	0-15-00	
			149-6 भाग	0-23-00	जी.पी.
			149-7 भाग	0-03-50	
			150-2 भाग	0-01-00	जी.पी.
			150-7 भाग	0-10-00	
			150-6 भाग	0-16-50	जी.पी.
			88 भाग	0-04-00	
			जोड़	4-14-00 और 10.23 एकड़	

[सं. एल-14016/14/93-जी.पी. 7]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2786.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the Right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of the notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Peravali.—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Peravali	Nadu Palli	142-Part	0-50-50	G.P.
			141-6 Part	0-05-00	
			141-7 Part	0-19-50	
			135-1 Part	0-05-50	
			135-2 Part	0-05-50	
			135-3 Part	0-05-50	
			135-5 Part	0-00-50	
			135-4 Part	0-14-00	
			136-1B Part	0-14-50	
			136-1D Part	0-18-50	
			136-2 Part	0-01-00	
			136-5 Part	0-00-50	
			136-6B Part	0-05-50	
			136-6C Part	0-01-00	
			131-5 Part	0-01-00	
			130-1 Part	0-06-00	
			130-2 Part	0-18-50	
			130-3 Part	0-07-00	
			130-8 Part	0-12-50	
			128-3 Part	0-13-00	
			128-4 Part	0-11-50	
			118-7 Part	0-07-50	
			118-8 Part	0-10-00	
			118-9 Part	0-18-00	
			102-Part	0-03-00	G.P.
			101-7 Part	0-06-00	
			101-6A Part	0-03-50	
			159-5Part	0-03-50	
			159-6 Part	0-30-50	
			159-7 Part	0-23-00	
			156-Part	0-30-50	
			85-2 Part	0-16-50	
			85-5 Part	0-00-50	
			85-4 Part	0-05-50	
			96-1 Part	0-11-50	
			96-3 Part	0-15-00	

## Paravali— Domnderu

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (AP)	Paravali	Nadupalli	149-6 Part	0-23-00	
			149-7 Part	0-03-50	
			150-2 Part	0-01-00	
			150-7 Part	0-10-00	
			150-6 Part	0-16-50	
			88-Part	0-04-00	G.P.
			G. Total	4-14-00	or 10.23 Acres

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN. Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2787.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि डोम्मेरु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति मक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के.जी. बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

## पेरवलि-डोम्मेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
वेस्ट गोदावरी (आ.प्र.)	पेरवलि	कानूडू	300-2 भाग	0-19-00	
			300-5 भाग	0-11-00	
			300-6 भाग	0-07-00	
			300-7 भाग	0-03-00	

1	2	3	4	5	6
वेस्ट गोदावरी	पेरबलि	कानूडू	298-3 भाग	0-00-50	
			298-4 भाग	0-05-00	
			298-5 भाग	0-08-00	
			298-6ए भाग	0-05-00	
			297-1 भाग	0-32-00	
			280-5 भाग	0-04-00	
			283 भाग	0-05-00	जीपी
			284-2 भाग	0-18-50	
			284-3 भाग	0-11-00	
			286-1 भाग	0-00-50	
			286-2 भाग	0-21-50	
			285-1ए भाग	0-00-50	
			285-1बी भाग	0-07-00	
			285-5 भाग	0-19-00	
			29 भाग	0-06-50	जी पी
			33-भाग	0-01-00	
			28-6 भाग	0-15-00	
			28-8 भाग	0-08-50	
			28-10 भाग	0-11-00	
			28-11 भाग	0-09-50	
			28-12 भाग	0-00-50	
			27-7 भाग	0-02-00	
			22-8बी भाग	0-05-50	
			22-8ए भाग	0-02-00	
			22-9 भाग	0-04-50	
			22-10 भाग	0-10-00	
			22-11 भाग	0-03-00	
			22-12 भाग	0-05-50	
			22-13 भाग	0-07-50	
			22-4 भाग	0-01-00	
			21-2 भाग	0-04-50	
			21-3 भाग	0-03-00	
			21-4 भाग	0-11-50	
			21-5 भाग	0-09-50	
			15-1 भाग	0-01-00	
			15-3ए भाग	0-00-50	
			15-3बी भाग	0-15-00	
			15-2 भाग	0-16-00	
			16-6 भाग	0-02-00	
			16-7 भाग	0-29-50	
			4-1-भाग	0-18-50	
			4-4 भाग	0-17-50	



1	2	3	4	5	6
वैष्ट गोदावरी (आ.प्रा.) जारी	पेरवली	कानूरु	4-5 भाग	0-01-50	
			4-9 भाग	0-10-50	
			2-भाग	0-03-00	जी.पी.
			जोड़	1-43-50	
			पहला पेज योग	2-71-00	
			महा योग	4-14-50	
			या		
			एकड़ 10, 24 सेन्ट्स		

[सं. एल-14016/14/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2787. -Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object, the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104 Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Pervavali--Dommeru**

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Peravali	Kanuru	300-2 Part	0-19-00	
			5 „	0-11-00	
			6 „	0-07-00	
			7 „	0-03-00	
			298-3 Part	0-00-50	
			4 „	0-05-50	
			5 „	0-08-50	
			6A „	0-05-00	
			297-1 Part	0-35-00	
			080-5 Part	0-04-00	
			283 Part	0-05-00	G.P.
			284-2 Part	0-18-50	
			3 „	0-11-00	
			286-1 A Part	0-00-50	
			2 Part	0-21-50	
			285-1 A Part	0-00-50	
			1B „	0-07-00	
			5 „	0-19-00	
			29-Part	0-06-00	G.P.
			33-1 Part	0-01-00	
			28-6 Part	0-15-00	

1	2	3	4	5	6
West Godavari	Peravali	Kanuru	8 Part	0-08-50	
A.P.—Contd.			10	0-11-00	
			11	0-09-50	
			12	0-00-50	
			22-7 Part	0-02-00	
			8B	0-05-05	
			8A	0-02-00	
			9 „	0-04-50	
			10 „	0-10-00	
			11 „	0-03-00	
			12 „	0-05-50	
			13 „	0-07-50	
			4 „	0-01-00	
			21-2 Part	0-04-50	
			3 „	0-03-00	
			4 „	0-11-50	
			5 „	0-09-50	
			15-1 Part	0-01-00	
			3A Part	0-00-50	
			3B „	0 15-00	
			2 „	0-16-00	
			16-6 Part	0-02-00	
			7 „	0-29-50	
			4-1 Part	0-18-50	
			4 „	0-17-50	
			5 „	0-01-50	
			9 „	0-10-50	
			2-Part	0-03-00	G.P.
			Grand Total	4-14-50	
				OR	
				A.C. 100-4 Cens.	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.मा. 2788.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि डोमेश पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती कि उस कार्य के लिए इसके साथ सलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की आज्ञा की घोषणा करती है।

वशत कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है।

**अनुसूची**  
**गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट**

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
बेस्ट गोदावरी	पेरवल्लि	अजारम	99-2 भाग	0-11-50	जी.पी.
			99-5 भाग	0-07-50	
			99-6 भाग	0-09-50	
			98-2 भाग	0-02-00	
			98-3 भाग	0-01-50	
			98-4 भाग	0-26-50	
			96-3 भाग	0-17-50	
			96-4 भाग	0-03-00	
			95-1 भाग	0-02-00	
			32-5 भाग	0-10-50	
			32-6 भाग	0-09-50	
			81-3 भाग	0-05-50	
			81-4 भाग	0-05-50	
			81-7 भाग	0-04-00	
			31-11 भाग	0-04-00	
			81-6 भाग	0-00-50	
			79-2वीं भाग	0-03-50	जी पी
			79-4 भाग	0-07-50	
			79-5 भाग	0-04-00	
			79-7 भाग	0-04-50	
			43 भाग	0-04-00	
			44-5 भाग	0-08-50	
			44-6 भाग	0-13-00	
			45 भाग	0-26-50	
			46-1 भाग	0-08-00	
			46-3 भाग	0-01-00	
			46-4 भाग	0-17-50	
			8 भाग	0-03-00	
			9-8वीं भाग	0-04-00	
			9-7 भाग	0-18-00	
			10-1 भाग	0-01-00	
			10-4 भाग	0-10-50	

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	विवरण
वेस्ट गोदावरी (अ०प्र०)—जारी	पेरवली	अजारास	10-5 भाग	0-02-00	
			11-1 भाग	0-07-00	
			11-2 भाग	0-06-00	
			11-3 भाग	0-01-00	
			11-5 भाग	0-05-50	
			15-1डी भाग	0-12-00	
			15-1ई भाग	0-05-50	
			15-1जी भाग	0-00-25	
			15-14 भाग	0-05-50	
			15-4 भाग	0-04-00	
			15-6 भाग	0-16-50	
			15-16 भाग	0-02-00	
			15-19 भाग	0-01-00	

महायोग 3-23-25 या 7-98-1/2

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

अर्घेन्द सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2788.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

### SCHEDULE GAS PIPE LINE PROJECT

Peravali—Dommeru.

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Peravali	Ajaram	99-2 Part	0-11-50	
			99-5 Part	0-07-50	
			99-6 Part	0-09-50	
			98-2 Part	0-02-00	
			98-3 Part	0-01-50	
			98-4 Part	0-26-50	
			96-3 Part	0-17-50	
			96-4 Part	0-03-00	
			95/Part	0-02-00 G.P.	
			2-5 Part	0-10-50	
			„ 6 Part	6-09-50	
			81-3 Part	0-05-50	

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Peravali	Ajjaram	„ 4 Part	0-05-50	
			„ 7 Part	0-04-00	
			„ 11 Part	0-04-00	
			„ 6 Part	0-00-50	
			79-2B Part	0-03-50	
			„ 4 Part	0-07-50	
			„ 5 Part	0-04-00	
			„ 7 Part	0-04-50	
			43 Part	0-04-00	
			44-5 Part	0-08-50	
			„ 6 Part	0-13-00	
			45 Part	0-26-50	
			46-1 Part	0-08-00	
			„ 3 Part	0-01-00	
			„ 4 Part	0-17-50	
			„ 8 Part	0-03-00	
			9-8B Part	0-04-00	
			„ 7 Part	0-10-00	
			10-1 Part	0-01-00	
			„ 4 Part	0-10-50	
			„ 5 Part	0-02-00	
			11-1 Part	0-07-00	
			„ 2 Part	0-06-00	
			„ 3 Part	0-01-00	
			„ 5 Part	0-05-50	
			15-1 DPart	0-12-00	
			„ 1 E Part	0-05-50	
			„ 1 G Part	0-00-25	
			„ 14 Part	0-05-50	
			„ 4 Part	0-04-00	
			„ 64 Part	0-16-50	
			16 Part	0-02-00	
			19 Part	0-01-00	
			Total	3-23-25	Or AC7-98-1/2

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993.

का.ओ. 2789—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि-दोम्मेरु पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस प्रशॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

2816 GI/93-3

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए हमके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बराते कि उक्त भूमि में अपनी हवि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अप्यारिटी आफ इंडिया लि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज कर सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

**अनुसूची**  
**गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट**  
**पेराली-डोममेरु**

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	बुन्डजवरम	वेलगडुरे	96-4बी भाग	0-05-00	
			96-5बी भाग	0-09-50	
			96-6बी भाग	0-10-50	
			96-7बी भाग	0-00-50	
			97 भाग	0-03-00	
			98 भाग	0-03-50	
			100-1 बी भाग	0-03-00	
			100-6बी भाग	0-00-50	
			100-7 बी भाग	0-02-50	
			100-2 बी भाग	0-12-00	
			100-3बी भाग	0-15-00	
			101-4बी भाग	0-09-50	
			101-4सी भाग	0-04-00	
			101-5बी भाग	0-05-50	
			100-5सी भाग	0-00-50	
			103 भाग	0-15-50	
			104-3ए भाग	0-03-50	
			104-4 बी भाग	0-07-50	
			104-1ए भाग	0-00-50	
			महा योग		

[सं. एल-14016/14/93-जी पी  
ग्रहेंदु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2789—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**

Peravali—Dommeru.

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari	Undrajavaram	Velagadurru	96-4B Part	0-05-00	
			„ 5B Part	0-09-50	
			„ 6B „	0-10-50	
			„ 7B „	0-00-50	
			97—Parts	0-03-00	
			98-Part	0-03-50	
			100-1B Part	0-03-00	
			„ 6B Part	0-00-50	
			„ 7B „	0-02-50	
			„ 2B „	0-12-00	
			„ 3B „	0-15-00	
			101-4BPart	0-09-00	
			„ 4C „	0-04-00	
			„ 5B „	0-05-00	
			„ 5C „	0-00-50	
			103-Part	0-15-50	
			104-3APart	0-03-50	
			„ 4B „	0-07-50	
			„ 1A „	0-00-50	
			Grand Total	1-11-50	Or AC 2.76 Cents.

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.ओ. 2790.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस साने के लिए पेखलि से तनुक पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की आज्ञा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी सचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इन्डिया लि. के जी बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंडी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

**अनुसूची**  
**गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट**  
**पेरवलि से तमुकु**

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	पेरवल्लि	पेरवल्लि	131-3 भाग	0-09-00	
			131-1ए भाग	0-08-50	
			132-1बी 3 भाग	0-05-25	
			132-1बी 2 भाग	0-05-25	
			132-1बी 1 भाग	0-16-00	
			136-2 भाग	0-14-00	
			137-5 भाग	0-05-50	
			137-2बी 2 भाग	0-02-50	
			137-2बी 1 भाग	0-02-50	
			137-1बी 1 भाग	0-07-00	
			76-5बी 1 भाग	0-05-50	
			76-4बी भाग	0-06-00	
			76-3बी भाग	0-14-00	
			76-2बी भाग	0-09-00	
			76-1बी भाग	0-09-50	
			77-1बी भाग	0-13-50	
			77-2 भाग	0-04-00	
			55-2सी भाग	0-08-00	
			55-2ए भाग	0-05-00	
			86-2 भाग	0-18-00	
			86-1बी भाग	0-08-50	
			87-4 भाग	0-02-00	
			87-5 भाग	0-23-50	
			87-6ए भाग	0-01-00	
			जोड़	2-03-00 या	
				एकड़ 5-02 सेंट्स	

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

प्रचोम्बु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2790.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali o Tamuku pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.



**SCHEDULE**  
**GAS PIPELINE PROJECT**  
**Pervavali To Tanuku**

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Peravali	Peravali	131-3 Part	0-09-00	
			„ 1A2 „	0-08-50-	
			132-1B3Part	0-05-25	
			„ 1B2 „	0-05-25	
			„ 1B1 „	0-16-00	
			136-2Part	0-14-00	
			137-5Part	0-05-50	
			„ 2B2 „	0-02-50	
			„ 2B1 „	0-02-50	
			„ 1B2 „	0-07-50	
			76-5B1 Part	0-05-50	
			„ 4B „	0-06-00	
			„ 3B „	0-14-00	
			„ 2B „	0-09-00	
			„ 1B „	0-09-50	
			77-1B Part	0-13-50	
			„ 2 „	0-04-00	
			55-2C Part	0-08-00	
			„ 2A „	0-05-00	
			86-2Part	0-18-00	
			„ 1B „	0-08-50	
			87-4Part	0-02-00	
			„ 5 4 „	0-23-50	
			„ 6A „	0-01-00	
			Total	2-03-00	Or AC 5.02 Cents.

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का० आ० 2791.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए धोम्मोह से चागल्लु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बनते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. के. जी. बसोन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विरोध रूप से निरिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि-व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

## दोम्मेरे से चागल्ल

अनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	
पश्चिम गोदावरी	चागल्लु	चागल्लु	621-3-भाग	0-02-25	
आन्ध्र प्रदेश			621-4-भाग	0-00-25	
			621-5 भाग	0-03-00	
			621-6 भाग	0-09-50	
			620-1 भाग	0-08-00	
			620-2 भाग	0-09-00	
			620-3 भाग	0-10-00	
			620-5 भाग	0-02-00	
			620-8 भाग	0-19-50	
			383-भाग	0-02-50	
			378- भाग	0-02-00	
			379-1 भाग	0-18-50	
			379-2 भाग	0-01-00	जी.पी.
			380-1 भाग	0-21-00	
			380-2 भाग	0-21-50	
			400-20 भाग	0-17-50	
			400-23 भाग	0-16-00	
			400-6 भाग	0-18-00	
			400-5 भाग	0-08-00	
			402- भाग	0-04-50	जी.पी.
			397-1 भाग	0-08-50	
			397-2 भाग	0-08-50	
			397-3 भाग	0-02-00	
			421-भाग	0-40-50	
			417-भाग	0-64-50	
			416-भाग	0-21-50	
			437-भाग	0-03-00	जी.पी.
			जोड़	3-42-50	Or Ac. 8.47 cent

[सं. एल.-14016/14/93 जी. पी.]

मधेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2791.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through through Dammen to Chagallu pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104 Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Dommeru —Chagalul**

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Chagallu	Chagallu	621-3 Part	0-02-25	G.P.
			„ 4 „	0-00-25	
			„ 5 „	0-03-00	
			„ 6 „	0-09-50	
			620-1 Part	0-08-00	
			„ 2 „	0-09-00	
			„ 3 „	0-10-00	
			„ 5 „	0-02-00	
			„ 8 „	0-19-50	
			383-Part	0-02-50	
			278-Part	0-02-00	
			379-1Part	0-18-50	
			„ 2 „	0-01-00	
			380-1 „	0-21-00	
			„ 2 „	0-21-50	
			400-20 Part	0-17-50	
			„ 23 „	0-16-00	
			„ 6 „	0-18-00	
			„ 5 „	0-08-00	
			402-Part	0-04-50	G.P.
			397-1 Part	0-08-50	
			„ 2 „	0-08-50	
			„ 3 „	0-02-00	G.P.
			421-Part	0-04-50	
			417-Part	0-64-50	
			416-Part	0-21-50	
			437-Part	0-03-00	
			Total	3-42-50	Or Ac. 8.48 Cents

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का० आ० 2792.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पम्पिड से कोडपुर्बेम पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

बतलाने कि उक्त भूमि में अपनी हस्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. क. जो. बसोन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

पंगिडि से कोनडेगुडेम

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ० प०)	कोव्वूर	पंगिडि	11-1 भाग	0-05-50	
			13-2 भाग	0-11-00	
			14-1बी भाग	0-13-00	
			14-1ए भाग	0-05-00	
			17-1ए भाग	0-09-00	
			17-1बी भाग	0-15-00	
			18-1 भाग	0-38-50	
			जोड़	0.97-00 या एस 2.40 सेन्टी	

[एल संख्या-14016/14/93 एल-जी पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2792.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Pangidi to Kondakudem pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., K.G. Basin (Project) 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104 Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

#### SCHEDULE

#### GAS PIPE LINE PROJECT

Pangidi To Kondakudem

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari A.P.	Kavuru.	Pangidi	11-1 Part	0-05-50	
			13-2 Part	0-11-00	
			14-1B Part	0-13-00	
			24-1A Part	0-05-00	
			17-1A Part	0-09-00	
			17-1B Part	0-15-00	
			18-1 Part	0-38-50	
			Total	0.97-00	Or AC 2.40 Cents.

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2793.—जबकि केन्द्र सरकार का यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पन्गिडि से देवरापल्लि पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि पर अपनी हवि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विषय रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूचि  
गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
पन्गि ते से कोन्डूडम

जनप	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकर में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी आन्ध्र प्रदेश	देवरापल्लि	कोन्डूडम	63-2 भाग	0011-00	
			64-भाग	0-16-50	
			65-1-भाग	0-04-50	
			65-2 भाग	0-08-00	
			65-3 भाग	0-04-50	
			65-4 भाग	0-03-00	
			72-1 A भाग	0-01-000	
			73-2 C- भाग	0-06-50	
			73-2- B भाग	0-20-00	
			73-3 A- भाग	0-08-00	
			73-3 B- भाग	0-07-00	
			75-5- B भाग	0-32-50	
जोड़				1-18-00 या AC	2.92 Cents

[सं एल-14016/14/93-जी-पी ]  
अर्वेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2793.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Pangidi to Devarapalli pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Aquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT**

Pangidi to Kandagudem

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari A.P.	Devarapalli.	Kodagudem	63-2 Part	0-11-00	
			64-Part	0-16-50	
			65-1 Part	0-04-00	
			.. 2 ..	0-08-00	
			.. 3 ..	0-04-50	
			.. 4 ..	0-03-00	
			72-1A Part	0-01-00	
			73-2C Part	0-01-00	
			.. 2B ..	0-20-00	
			.. 3A ..	0-08-00	
			.. 3B ..	0-07-50	
			75-58	0-32-50	
			Total	1-18-00	ORAC 2.92 Cents.

[L. No. 14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director,

दई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2794 .—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पन्निडि-गौरिकण्टम पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है—

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अखिली रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिमूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. के. जी. बलीन प्रोवैस्ट, 29-7-1/3/1 राजमुंड्री-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज कर सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पन्निडि-गौरि पण्टम.

जनपद	तहसील	ग्राम	खर्चे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	डेवरापल्लि	कोन्डगूडेम	9-7 भाग	0-07-50	
			8-4 भाग	0-09-00	
			8-5 भाग	0-03-00	

7-2 भाग	0-24-50	जि-पि.
6-2 भाग	0-07-00	
5-1 भाग	0-09-00	
5-2 सी भाग	0-07-50	
4-6 भाग	0-09-50	
4-5 भाग	0-15-50	
3-4 भाग	0-24-50	
2- भाग	0-34-50	
86- भाग	0-00-50	
84- भाग	0-48-00	
83- भाग	0-73-00	
Total	2-73-00	ORAC 6.74 Acres

[सं. एल-14016/14/93 जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2794.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Pangidi to Gowripatnam pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Aquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

#### SCHEDULE GAS PIPE LINE PROJECT

Pangidi—Gowripatnam.

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
West Godavari	A.P. Devarapalliz	Kondagudem	9-7 Part	0-07-50	
			8-4 Part	0-09-00	
			„ 5 Part	0-03-00	
			7-2 Part	0-24-50	
			6-2 Part	0-07-00	
			5,1 Part	0-09-00	
			„ 2C „	0-07-50	
			4-6 Part	0-09-50	
			„ 5 „	0-15-50	
			3-4 Part	0-24-50	
			2-Part	0-34-50	
			86-Part	0-00-50	
			84-Part	0-48-00	
			83-Part	0-73-00	
			Total	2-73-00	ORAC 6.74 Cents.

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director,

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

सं. का. आ. 2795 .—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पन्गिडि से गौरीपन्थम पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बनते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि., के. जी. बसीन प्रोजेक्ट 19-7-1/3/1 राजमंड़ी-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज हकराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूचि

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
पन्निडि से गीरीपट्टम

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आं.प्र.)	कोठ्यूर	पन्निडि	185-2 भाग	0-37-50	
			185-1 भाग	0-08-50	
			184-1 भाग	0-12-00	
			179- भाग	0-07-50	
			180-1 भाग	0-03-00	
			178-2 भाग	0-07-75	
			178-1 भाग	0-07-75	
			41- भाग	0-03-00	
			40-4 भाग	0-07-50	
			40-3 भाग	0-06-00	
			40-2 भाग	0-05-00	
			40-1 भाग	0-01-50	
			40-5 भाग	0-06-00	
			33-8 भाग	0-00-50	
			34-4 भाग	0-20-50	
			34-3 भाग	0-07-50	
			34-1बी भाग	0-14-00	
			30-9 भाग	0-01-00 जि० पि०	
			30-7 भाग	0-07-00	
			30-8 भाग	0-03-00	
			34-6 भाग	0-01-00	
			34-5 भाग	0-05-50	
			34-4 भाग	0-01-00	
			34-1ए भाग	0-16-00	
			34-1बी भाग	0-03-00	
			28- भाग	0-75-50	
			24-2 भाग	0-01-00	
			24-1 भाग	0-03-00	
			जोड़	2-72-50	



जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)—जारी	कोव्वूरु	पन्गिडि	25- भाग	0-02-00	जि.पि.
			26- भाग	0-03-00	जि.पि.
			11-2 भाग	0-15-50	
			11-1 भाग	0-08-00	
			11-3ए भाग	0-05-50	
			12-2 भाग	0-20-00	
			8-4 भाग	0-01-50	जि.पि.
			8-3 भाग	0-12-50	
			8-2 भाग	0-11-50	
			8-1 भाग	0-03-00	
			7-2सी भाग	0-03-00	
			7-2बी भाग	0-03-00	
			7-2ए भाग	0-03-00	
			7-1 भाग	0-09-50	
			7-1 भाग	0-64-00	
			कुल जोड़	4-38-00	
				या	
				एकर 10.82 सेन्ट्स	

[सं. एल 14016/14/93-जी.पी.]

अर्थेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2795.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Pangidi to Gowripatnam pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land, to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Pangidi-To-Gowripatnam**

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Kovvuru	Pangidi	182-2 Part	0-37-50	
			„ 1,,	0-08-50	
			184-1 Part	0-12-00	
			179-Part	0-07-50	
			180-1 Part	0-03-00	
			178-2 Part	0-07-75	
			„ 1 „	0-07-75	

1	2	3	4	5	6
			41-Part	0-03-00	G.P.
			4-04-Part	0-07-50	
			„ 3 „	0-06-00	
			„ 2 „	0-05-00	
			„ 1 „	0-01-50	
			„ 5 „	0-06-00	
			33-8 Part	0-01-00	
			34-4 Part	0-20-50	
			3 „	0-07-50	
			„ 1B „	0-14-00	
			30-9 Part	0-01-00	G.P.
			„ 7 „	0-07-00	
			„ 8 „	0-03-00	
			„ 3 „	0-01-00	
			„ 5 „	0-05-50	
			„ 4 „	0-01-00	
			„ 1A „	0-16-00	
			„ 1B „	0-03-00	
			28-Part	0-75-50	
			24-2 Part	0-01-00	
			„ 1 „	0-03-00	
			25-Part	0-02-00	G.P.
			26-Part	0-03-00	
			11-2 Part	0-15-50	
			„ 1 „	0-08-0J	
			„ 3 A „	0-05-50	
			12-2 Part	0-20-00	
			8-4 Part	0-01-50	G.P.
			„ 3 „	0-12-50	
			„ 2 „	0-11-50	
			„ 1 „	0-03-00	
			7-2C Part	0-03-00	
			„ 2B „	0-03-00	
			„ 2 A „	0-03-00	
			„ 1 „	0-09-50	
			1-3 Part	0-64-00	
			Grand Total	4-38-00	
				or AC 10-82--Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2796 .—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि से दोम्पेरपाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्ररत शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एवं द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बतर्त कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि. के जी. ब्रमीन प्रोजेक्ट, 29-7-13-1 राजमस्की-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पैरवलि से दोम्मेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरि(आ.प्र.)	कोव्वूरु	दोम्मेरु	625-भाग	0-03-00	जि.पि.
			624-2 भाग	0-20-00	
			632-1-भाग	0-07-00	
			623-2-भाग	0-11-50	
			617-1-भाग	0-00-50	
			618-2-भाग	0-27-00	
			622-2 भाग	0-01-50	
			615-1 भाग	0-41-00	
			515-2 बी भाग	0-14-00	
			615-2 ए भाग	0-21-00	
			584-2 भाग	0-18-00	
			584-3 भाग	0-34-00	
			583-2-ए भाग	0-16-50	
			583-2 बी भाग	0-18-00	
			583-5 भाग	0-16-00	
			582 भाग	0-27-50	
			471-2 भाग	0-03-00	
			471-3ए भाग	0-09-50	
			471-3 बी भाग	0-16-50	
			471-3 सी भाग	0-12-50	
			469-1-बी भाग	0-01-00	
			469-1-ए-भाग	0-04-50	
			461-4 भाग	0-03-50	
			462-भाग	0-41-50	
			452-4 भाग	0-03-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आं प्र.)	कोल्लूरु	वोम्मेरु	452-3 भाग	0-02-50	
			452-2 भाग	0-03-00	
			452-1ए भाग	0-04-00	
			452-1बी भाग	0-02-00	
			453 भाग	0-20-50	
			458 भाग	0-11-50	
			458-3 सी भाग	0-08-50	
			458-3 ए भाग	0-08-50	
			458-2 भाग		
			456 भाग	0-47-00	
			442-1 भाग	0-03-50	
			442-2 भाग	0-36-50	
			441 भाग	0-11-50	
			434 भाग	0-78-00	
			436 भाग	0-09-50	
			388-1 भाग	0-06-00	
			388-2 भाग	0-10-50	
			387-1 भाग	0-06-50	
			387-2 भाग	0-25-00	
			386 भाग	0-06-00	
			381 भाग	0-04-00 जि.नि.	
			379-1 भाग	0-01-00	
			379-2 भाग	0-15-50	
			378 भाग	0-00-50	
			377 भाग	0-30-00	
			370-1 भाग	0-21-50	
			370-2 भाग	0-22-00	
			369 भाग	0-43-50	
			368-3 भाग	0-00-50	
			368-1 भाग	0-27-50	
			364-1 भाग	0-01-00	
			364-2 भाग	0-20-00	
			364-3 भाग	0-04-00	
			364-4 भाग	0-01-00	
			363 भाग	0-26-00 जि.नि.	
			362-4 भाग	0-20-00	
			362-7 भाग	0-07-50	
			362-6 भाग	0-14-50	
			362-7 भाग	0-01-00	
			362-8 भाग	0-04-00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पश्चिम गोदावरि (आन्ध्र प्रदेश)	कोव्वूर	दोम्मेरु	357-भाग 356 भाग 346-1 ई भाग -1 एक भाग -1 जी भाग -2 सी भाग -3 डी भाग -5 ए भाग -5 बी भाग -5 सी भाग -5 डी भाग 345 भाग 342-8 भाग -6 भाग -5 भाग 581 भाग 460 भाग	0-14-00 0-45-50 0-05-50 0-05-00 0-01-00 0-04-50 0-06-50 0-09-50 0-11-50 0-06-50 0-13-00 0-26-50 006-50 003-00 0-00-50 004-50 जी पी 002-50 जी पी	जीपी
कुल योग				10-99-50	

[सं. एल-14016/14/93-जी. पी.)

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2796.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

## GAS PIPE LINE PROJECT

Peravali to Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Kovvuru	Dommeru	625-Part	0-03-00	G.P.
			624-2 Part	0-20-00	
			623-1Part	0-07-00	
			-2 Part	0-11-50	
			617-1 Part	0-00-50	
			618-2Part	0-27-00	
			622-2Par	0-01-50	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A. P.)	Kowur	Dommeru.	615-1 Part	0-41-00	
			—2B Part	0-14-00	
			—2A Part	0-21-00	
			58421 Part	0-18-00	
			—3 Part	0-34-00	
			583 2A Part	0-16-50	
			—2B Part	0-18-00	
			—5 Part	0-16-00	
			582-Part	0-27-50	
			471-2 Part	0-03-00	
			—3A Part	0-09-50	
			—3B Part	0-16-50	
			—3C Part	0-12-50	
			469-1B Part	0-01-00	
			—1A Part	0-04-50	
			461-4 Part	0-00-50	
			462-4 Part	0-4-150	
			452-4 Part	0-03-00	
			—3 Part	0-02-50	
			—2 Part	0-03-00	
			—1A Part	0-04-00	
			—1B Part	0-02-00	
			453-Part	0-20-50	
			458-3C Part	0-11-50	
			—3A Part	0-08-50	
			—2 Part	0-08-50	
			456-Part	0-47-00	
			442-1 Part	0-03-50	
			—2 Part	0-36-50	
			441-Part	0-11-50	
			434-Part	0-78-00	
			436-Part	0-09-50	
			388-1 Part	0-06-00	
			—2C Part	0-10-50	
			387-1 Part	0-06-50	
			—2 Part	0-25-00	
			386-Part	0-06-00	
			381-Part	0-04-00	G. P.
			379-1 Part	0-01-00	
			—2 Part	1-15-50	
			378-Part	0-00-50	
			377-Part	0-30-00	
			370-1 Part	0-21-50	
			—3 Part	0-22-00	
			369-Part	0-43-50	
			368-3 Part	0-00-50	
			—1 Part	0-27-50	
			364-1 Part	0-01-00	
			—2 Part	0-20-00	
			—3 Part	0-04-00	

1	2	3	4	5	6
West Godavaru (A.P.)	Kovvur	Dommeru	-4 Part 363-Part 362-4Part -7Part -6Part -7 Part -8Part 357-Part 356-Part 346-1EPart -1FPart -1G Part -2CPart -3DPart -5APart -5B Part -5C Part -5D Part 345-Part 342-8Part -6Part -5Part 581-Part 460-Part G. Total	0-01-00 0-26-00 0-20-00 0-07-50 0-14-50 0-01-00 0-05-00 0-14-00G.P. 0-45-50 0-05-50 0-05-00 0-01-50 0-04-50 0-06-50 0-09-50 0-11-50 0-06-50 0-13-00 0-26-50 0-06-50 0-03-00 0-00-50 0-04-50G.P. 0-02-00G.P. 10-99-50	Dr-AC 27-17

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2797....-जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवल से दोम्मर पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरुद्ध में अपनी आपत्ति सश्रम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी.-बशोत प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजामुन्नी-533 104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशय रूप से निर्विष्ट करमा होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायाक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

**अनुसूची**  
**गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट**

पेरवलि से दोमेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट/ एकड़ में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	चागल्लू	चागल्लू	437 भाग	0-27-50	जी पी
			435 भाग	0-19-00	
			434 भाग	0-05-50	
			जोड़	0-52-00	1.29

[सं एल-14016/14/93—जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2797.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104. Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**

Peravali—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Codavari A.P.	Chagallu	Chagallu	437-Part	0-27-50	G.P.
			435-Part	0-19-00	
			434-Part	0-05-50	
			Total	0-52-00	Or AC 1.29

[No. L-14016/14/93-G: P]  
ARDHENDU SEN, Director,

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2798.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि से दोमेरु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ सलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।



अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा को घोषणा करती है।

बसते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. के .जी. बसोस प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंत्री—533104, ग्रान्ध प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्विण्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### पेरबलि—डोमोहर

जमपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पश्चिम गोदावरी (ग्रान्ध प्रदेश)	कोव्वूर	कोव्वूर	525--भाग	0-11-50	
			526-भाग	0-09-00	
			527-1-भाग	0-08-00	
			527-2-भाग	0-06-00	
			528-1ए-भाग	0-05-50	
			528-1बी-भाग	0-37-50	
			528-2बी-भाग	0-14-50	
			519-2-भाग	0-11-50	जि.पि.
			519-3ए-भाग	0-04-00	जि.पि.
			518-भाग	0-43-50	
			516-1-भाग	0-03-50	
			518-2ए-भाग	0-09-00	
			516-2बी-भाग	0-15-50	
			515-भाग	0-06-50	जि.पि.
			514-1बी-भाग	0-00-50	
			514-1सी-भाग	0-15-50	
			568-2ए-भाग	0-18-00	
			568-3ए 2-भाग	0-00-50	
			568-3ए 3-भाग	0-01-50	
			569-3-भाग	0-05-00	
			569-4ए-भाग	0-16-00	
			572--1ए-भाग	0-28-50	
			573-1ए/1-भाग	0-00-25	
			573-1ए 2-भाग	0-30-50	
			574-4ए 1-भाग	0-41-50	
			574-3बी-भाग	0-00-25	
			588-2-भाग	0-01-00	

(1)	2	3	(4)	(5)	(6)	(7)
पश्चिम गोदावरी (अ. प्र.)	कोमूरु	कोमूरु	588-1-भाग	0-10-50	जि.पि.	
			592-1-भाग	0-16-50		
			592-2-भाग	0-00-50		
			592-3-भाग	0-05-00		
			591-1-भाग	0-08-00		
			591-3-भाग	0-14-00		
			590-1ए 3-भाग	0-00-50		
			590-1बी-भाग	0-01-50		
			590-1ई 3-भाग	0-03-50		
			590-2सी-भाग	0-00-25		
			601-1-भाग	0-00-50		
			601-2-भाग	0-13-00		
			601-3-भाग	0-07-00		
			602-भाग	0-22-50		
			603-1-भाग	0-02-50		
			603-2-भाग	0-22-50		
			328-भाग	0-00-25	जि.पि.	
			381-1-भाग	0-10-00		
			381-2-भाग	0-05-00		
			618-2-भाग	0-01-50		
			380-1-भाग	0-14-50		
			380-2-भाग	0-14-50		
			380-4-भाग	0-09-50		
			379-2-भाग	0-07-50		
			379-3-भाग	0-03-00		
			379-5-भाग	0-13-00		
			377-1-भाग	0-00-25		
			377-2-भाग	0-11-00		
			378-1-भाग	0-01-00		
			378-2-भाग	0-02-00		
			378-3-भाग	0-39-50		
			372-1-भाग	0-14-50		

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी कोठवूरु	कोठवूरु	372-3-भाग	0-22-50	जी.पी.	
		373-भाग	0-02-50		
		370-भाग	0-52-00		
		310-1-भाग	0-13-00		
		310-2-भाग	0-13-00		
		309-1-भाग	0-11-00		
		309-4-भाग	0-09-50		
		309-5-भाग	0-21-50		
		302-भाग	0-63-00		
		301-भाग	0-30-50		
		293-2-भाग	0-02-50		
		293-3-भाग	0-15-00		
		294-1-भाग	0-12-50		
		294-2-भाग	0-01-00		
जोड़—			8-89-75 या एकड़ 21.99½ सैदी.		

[स एल-14016/14/93 जी पी]

अश्वेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2798.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

### SCHEDULE GAS PIPE LINE PROJECT

Peravali—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Kovvuru	Kovvuru	525-Part	0-11-50	
			526-Part	0-09-00	
			527-1 Part	0-08-00	
			527-2 Part	0-06-00	
			528-1A Part	0-05-50	
			528-1B Part	0-37-00	
			528-2B Part	0-14-50	
			519-2Part	0-11-50	G.P.
			519-3A Part	0-04-00	G.P.
			518-Part	0-43-50	
			516-1Part	0-03-50	
			516-2A Part	0-09-00	

1	2	3	4	5	6
West Godavari	Kovvuru	Kovvuru	516 2B Part	0-15-50	
			515Part	0-60-50	G.P,
			514-1B Part	0-00-50	
			„ 1C „	0-15-50	
			568-2APart	0-18-00	
			„ 3A2 „	0-00-50	
			„ 3A3 „	0-01-50	
			569-3Part	0-05-00	
			„ 4A „	0-16-00	
			572-1APart	0-28-50	
			573-1A Part	0-00-25	
			„ 1A2 „	0-30-50	
			574-4A1Part	0-41-50	
			3B „	0-00-25	
			588-2Part	0-01-00	
			„ 1 „	0-10-50	
			592-1 Part	0-16-50	
			„ 2 „	0-00-50	
			„ 3 „	0-05-00	
			591-1 Part	0-08-00	
			„ 3 „	0-14-00	
			590-1A3Part	0-00-50	
			„ 1B „	0-01-50	
			„ 1E3 „	0-03-50	
			„ 2C „	0-00-25	
			601-1Part	0-00-50	
			„ 2 „	0-13-00	
			„ 3 „	0-07-00	
			602-Part	0-22-50	
			603-1Part	0-02-50	
			602-Part	0-22-50	
			328-Part	0-00-25	
			381-1Part	0-10-00	
			„ 2 Part	0-05-00	
			618-2 Part	0-01-50	
			380-1-Part	0-14-50	
			„ 2 „	0-14-50	
			„ 4 „	0-09-50	
			379-2 Part	0-07-50	
			„ 3 „	0-03-00	
			„-5 Part	10-13-00	
			377-1 Part	0-00-25	
			„ 2 „	0-11-00	
			378-1 Part	0-01-00	
			378-2 Part	0-02-00	
			378-3 Part	0-39-50	
			372-1Part	0-14-50	
			372-3 Part	0-22-50	
			373-Part	0-02-50	G.P.
			370-Part	0-52-00	

1	2	3	4	5	6
West Godavari	Kovvuru	Kevvuru	310-1 Part	0-13-00	
			310-2 Part	0-13-00	
			309-1 Part	0-11-00	
			309-4 Part	0-09-50	
			309-5 Part	0-21-50	
			302-Part	0-63-00	
			301-Part	0-30-50	
			293-2 Part	0-02-50	
			293-3 Part	0-15-00	
			294-1 Part	0-12-50	
			294-2 Part	0-01-00	
Grand Total				8-89-75 or AC 21.99 ½ Cents	

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. ग्रा. 2799.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि से दोम्मेरु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ सम्बन्ध विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा का घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के. जो. बसीन प्रजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी 533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज करने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### पेरवलि से दोम्मेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	कोव्वूरु	वेनुलूरु	145-भाग	0-24-50	
			144-9-भाग	0-14-50	
			144-8सी-भाग	0-07-50	
			144-8ए-भाग	0-05-00	
			144-8बी-भाग	0-03-00	
			144-7-भाग	0-03-50	
			144-6-भाग	0-02-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (अ.प्र.)	कोंवरु	वेमलूरु	144-4-भाग	0-03-00	
			144-5-भाग	0-02-50	
			144-3-भाग	0-05-50	
			144-1-भाग	0-32-00	
			106-1बी-भाग	0-19-50	
			160-1 ए-भाग	0-18-50	
			120-भाग	0-02-00	जी.पी.
			121-भाग	0-06-50	
			122-भाग	0-06-50	
			123-भाग	0-05-00	
			124-भाग	0-06-00	
			117-3सी-भाग	0-13-00	
			117-3बी-भाग	0-01-50	
			117-3ए-भाग	0-13-00	
			114-2सी-भाग	0-11-50	
			114-2डी-भाग	0-10-50	
			114-1सी-भाग	0-03-00	
			114-1ए-भाग	0-07-50	
			113-3-भाग	0-27-50	
			113-1-भाग	0-11-00	
			81-भाग	0-15-00	
			82-4ए-भाग	0-12-50	
			82-3-भाग	0-09-50	
			82-2बी-भाग	0-01-50	
			82-2ए-भाग	0-08-00	
			82-1ए-भाग	0-09-50	
			77-भाग	0-03-50	जी.पी.
			44-7-भाग	0-00-25	
			44-6-भाग	0-07-25	
			44-5-भाग	0-13-00	
			44-1-भाग	0-02-50	
			43-2-भाग	0-09-00	
			43-1-भाग	0-15-00	
			51-2बी-भाग	0-04-50	
			51-2ए-भाग	0-07-00	
			54-7ई-भाग	0-09-00	
			54-7डी-भाग	0-03-00	
			54-7सी-भाग	0-00-25	
			54-7बी-भाग	0-13-50	
			64-भाग	0-03-50	जी.पी.
			63-भाग	0-16-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	कोव्वूरु	वेल्लूरु	62-भाग 61-भाग 60-4-भाग 60-3-भाग 59-भाग	0-05-00 0-14-00 0-02-00 0-24-00 0-05-00	
			जोड़	4-79-25 या AC11:84½ Cent s	

[सं. एल—14016/14/93 जी पी]

मधोन्तु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2799.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin (Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Peravali to Dommeru**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Kovvuru	Vemuluru	145-Part	0-24-50	G.P.
			144-9 Part	0-14-50	
			144-8C Part	0-7-50	
			144-8A Part	0-05-00	
			144-8B Part	0-03-00	
			144-7 Part	0-03-50	
			144-6 Part	0-02-50	
			144-4 Part	0-03-00	
			144-5 Part	0-02-50	
			144-3 Part	0-05-50	
			144-1 Part	0-32-00	
			160-1B Part	0-19-50	
			160-1A Part	0-18-50	
			120-Part	0-02-00	
			121-Part	0-06-50	
			122-Part	0-06-50	
			123-Part	0-05-00	
			124-Part	0-06-00	
			117-3C Part	0-13-00	
			117-3B Part	0-01-50	

1	2	3	4	5	6
			117-3A Part	0-13-00	
			114-2C Part	0-11-50	
			114-2D Part	0-10-50	
			114-1C Part	0-03-00	
			114-1A Part	0-07-50	
			113-3 Part	0-27-50	
			113-1 Part	0-11-00	
			81-Part	0-15-00	
			82-4A Part	0-12-50	
			82-3 Part	0-09-50	
			82-2B Part	0-01-50	
			82-2A Part	0-08-00	
			82-1A Part	0-09-50	
			77-Part	0-03-50	G.P.
			44-7 Part	0-00-25	
			44-6 Part	0-07-25	
			44-5 Part	0-13-500	
			44-1 Part	0-02-50	
			43-2 Part	0-09-00	
			43-1 Part	0-15-00	
			51-2B Part	0-04-50	
			51-2A Part	0-07-00	
			54-7E Part	0-09-00	
			54-7D Part	0-03-00	
			54-7C Part	0-00-25	
			54-7B Part	0-13-50	
			64-Part	0-03-50	G.P.
			63-Part	0-16-00	
			62-Part	0-05-00	
			61-Part	0-4-00	
			60-4 Part	0-02-00	
			60-3 Part	0-24-00	
			59-Part	0-05-00	G.P.
			Total	4-77-25	
				or	AC 11-841/2 Cents

[No. L-14016/14/73-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2800 — जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यहाँ आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवल से दोम्मेरू पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।



अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस प्राथरिटी ग्राफ इंडिया लिमि. के.जो. बसोन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमुट्टी-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विषय रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट पंखलि से दोम्मोर

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	कोय्वूर	तोगुम्मि	41-2 भाग	0-11-50	
			- 3 भाग	0-12-50	
			-4 भाग	0-08-00	
			42-1 भाग	0-11-50	
			-2 भाग	0-11-00	
			-4 भाग	0-21-00	
			62-1 भाग	0-03-50	
			-3 भाग	0-14-50	
			-4 भाग	0-06-00	
			-5 भाग	0-05-50	
			43- भाग	0-12-00	
			44-2 भाग	00-8-00	
			-4 भाग	0-01-50	
			-5 भाग	0-04-50	
			-6 भाग	0-07-00	
			45-5 भाग	0-08-00	
			-3 भाग	0-00-50	
			-6 भाग	0-05-50	
			46-4 भाग	0-13-50	
			-5 भाग	0-12-00	
			47-1 भाग	0-09-00	
			-3 भाग	0-16-00	
			49-1 भाग	0-01-50 जि०पि०	
			-3 भाग	0-31-50	
			-7 भाग	0-11-50	
			-8 भाग	0-12-00	
			जोड़	2-59-00 अथवा ए०सी 6.40	

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2800.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Peravali to Dommeru**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Kovvur	Thogummi	41-2 Part	0-11-50	G.P.
			41-3 Part	0-12-50	
			41-4 Part	0-08-00	
			42-1 Part	0-11-50	
			42-2 Part	0-11-00	
			42-4 Part	0-21-00	
			62-1 Part	0-03-50	
			62-3 Part	0-14-50	
			62-4 Part	0-06-00	
			62-5 Part	0-05-50	
			43- Part	0-12-00	
			44-2 Part	0-08-00	
			44-4 Part	0-01-50	
			44-5 Part	0-01-50	
			44-6 Part	0-07-00	
			45-5 Part	0-08-00	
			45-3 Part	0-00-50	
			45-6 Part	0-05-50	
			46-4 Part	0-13-50	
			46-5 Part	0-12-00	
			47-1 Part	0-09-00	
			47-3 Part	0-16-00	
			49-1 Part	0-01-50	
			47-3 Part	0-31-50	
			47-7 Part	0-11-50	
			47-8 Part	0-12-00	
			Total	2-59-00	Or AC 6.40

[No.L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

क्रा. आ. 2801— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरबनिसा दोम्मोर, पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बनते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस आथॉरिटी आफ इंडिया लिमि! के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533 014, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह ब्याक्तिगत रूप से प्रथम विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

### अनसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### पेरवल्लि से दोम्मेरू

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विषय
पश्चिम गोदावरि (आ. प्र.)	कोय्यूरू	वाडपल्लि	417-2 भाग	0-22-00	जि. पि.
			417-1 भाग	0-06-00	
			421-2 भाग	0-00-50	
			421-1 भाग	0-19-50	
			419-1 भाग	0-09-50	
			419-1 भाग	0-09-00	
			420-2ए भाग	0-08-00	
			420-1 बी भाग	0-10-50	
			403- भाग	0-04-00	
			400-1बी- भाग	0-12-00	
			400-2सी भाग	0-01-00	
			399-1डी भाग	0-05-00	
			399-1सी भाग	0-09-50	
			399-1ए भाग	0-05-50	
			399-1बी भाग	0-08-00	
			257-1 भाग	0-16-50	
			259-1बी भाग	0-12-00	
			259-1ए भाग	0-16-00	
			260-1डी भाग	0-11-00	
			260-2बी भाग	0-00-50	
			260-1सी भाग	0-05-00	
			260-1ए भाग	0-00-50	
			260-2ए भाग	0-11-50	
			262 भाग	0-16-00	
			263 भाग	0-26-00	
			264 भाग	0-03-00	

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण		
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	कावूरु	वाडपल्लि	262-भाग	0-07-00	जिपि		
			271-3 भाग	0-07-00			
			271-4 भाग	0-02-00			
			271-2 भाग	0-04-50			
			271-5 भाग	0-05-50			
			271-1 भाग	0-20-00			
			99-3ए भाग	0-06-50			
			99-3बी भाग	0-04-00			
			99-2 भाग	0-05-50			
			99-1 भाग	0-05-00			
			96-2 भाग	0-12-50			
			96-1 भाग	0-11-50			
			88 भाग	0-65-50			
			87 भाग	0-12-50			
			84-2 भाग	0-00-50			
			84-3 भाग	0-11-00			
			84-1 भाग	0-14-50			
			83 भाग	0-05-00		जिपि	
			कुल जोड़			4-48-00	
			अथवा एसी 11-07-सेन्ट्स				

[सं०एल-14016/14/93 जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2801.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification objects to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Peravali to Dommeru**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Kovvuru	Vadapalli	417-2 Part	0.22-00	
			417-1 Part	0-06-00	
			421-2 Part	0-00-50	
			421-1 Part	0-19-50	
			419-2 Part	0-09-50	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.) Kovvuru	Vadapalli	419-1 Part	0-09-00		
		420-2A Part	0-08-00		
		420-1B Part	0-10-50		
		403-Part	0-04-00		G.P.
		400-1B Part	0-12-00		
		400-2C Part	0-01-00		
		399-1D Part	0-05-00		
		399-1C Part	0-09-50		
		399-1A Part	0-05-50		
		399-1B Part	0-08-00		
		257-1 Part	0-16-50		
		259-1B Part	0-12-00		
		259-1A Part	0-16-00		
		260-1D Part	0-11-00		
		260-2B Part	0-00-50		
		260-1C Part	0-05-00		
		260-1A Part	0-00-50		
		260-2A Part	0-11-50		
		262-Part	0-16-00		
		263-Part	0-26-00		
		264-Part	0-03-00		
		269-Part	0-07-00		G.P.
		271-3 Part	0-07-00		
		271-4 Part	0-02-00		
		271-2 Part	0-04-50		
		271-5 Part	0-05-50		
		271-1 Part	0-20-00		
		99-3A Part	0-06-50		
		99-3B Part	0-04-00		
		99-2 Part	0-05-50		
		99-1 Part	0-05-00		
		96-2 Part	0-12-50		
		96-1 Part	0-11-50		
		88-Part	0-65-50		
		87-Part	0-12-50		
		84-2 Part	0-00-50		
		84-3 Part	0-11-00		
		84-1 Part	0-14-50		
		83-Part	0-05-00		G.P.
		Grand Total	4-48-00		
			Or AC 11-07 CENTS		

[No. L-14016/14/93 GP]  
ARDHENDU SEN, Di

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2802—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम से पेवल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमुंड्री-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्विण्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

**अनुसूची**  
**गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट**  
**नरसपुरम से पेवल**

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	पालकेल्लू	पालकेल्लू-भाग-I	349-3 भाग	0-16-00	
			358-2बी भाग	0-24-50	
			347-भाग	0-18-50	
			346-1 भाग	0-02-50	जीपी
			346-2 भाग	0-02-50	जीपी
			328-3बी भाग	0-00-50	
			328-4 भाग	0-03-00	
			328-5ए भाग	0-03-50	
			323-5बी भाग	0-02-50	
			328-2ए भाग	0-01-00	
			328-2बी भाग	0-00-50	
			328-6 भाग	0-00-50	
			328-7 भाग	0-05-50	
			328-9 भाग	0-03-50	
			328-10ए भाग	0-07-50	
			328-10बी भाग	0-07-50	
			328-11 भाग	0-11-00	
			329-1 भाग	0-01-50	
			330 भाग	0-24-50	
			335 भाग	0-13-50	
			337 भाग	0-16-00	
			336-1 भाग	0-07-50	
			336-2 भाग	0-23-50	
			301-2 भाग	0-05-50	
			300-1 भाग	0-15-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	पालकेल्लू	पालकेल्लू -भाग-I	303-1 भाग	0-07-00	
			303-2 भाग	0-06-00	
			305 भाग	0-27-00	
			306 भाग	0-09-50	
			308 भाग	0-01-50	
			309 भाग	0-02-00	
			278 भाग	0-04-00	जी.पी.
			253 भाग	0-00-50	जी.पी.
			254-1ए भाग	0-01-00	जी.पी.
			254-5ए भाग	0-04-00	जी.पी.
			254-6ए भाग	0-00-50	जी.पी.
			254-2बी भाग	0-05-00	जी.पी.
			254-3बी भाग	0-01-50	
			254-4 भाग	0-03-00	
			255-1ए भाग	0-07-50	
			255-2ए भाग	0-10-00	
			255-3 भाग	0-14-50	
			255-4 भाग	0-11-50	
			255-5 भाग	0-11-00	
			250-7 भाग	0-16-00	
			249-1 भाग	0-01-00	
			249 -2 भाग	0-11-50	
			248- भाग	0-12-50	
			247-2 भाग	0-00-50	
			11-3 भाग	0-09-50	
			246- भाग	0-24-50	
			210 भाग	0-00-50	जी. पी.
			974 भाग	0-05-50	जी. पि.
			973-1 भाग	0-06-50	
			973-2 भाग	0-02-00	
			973-4 भाग	0-04-50	
			973-5 भाग	0-12-00	
			973 -6 भाग	0-00-50	
			972-6 भाग	0-02-50	
			200-1 भाग	0-01-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	पालकोलू	पालकोलू भाग II	200-2 भाग	0-01-50	
			196-8 भाग	0-15-50	
			197-1 बी भाग	0-00-50	
			197 1सी भाग	0-05-50	
			,,-2 भाग	0-15-50	
			198-2 भाग	0-00-50	
			198-3 भाग	0-06-00	
			198-4 भाग	0-05-50	
			198-5 ए भाग	0-07-50	
			198-5 बी भाग	0-06-50	
			198-6 भाग	0-04-00	
			189- भाग	0-02-50	
			189-भाग	0-02-50	
			190-10 भाग	0-00-50	जी पी
			188-1 भाग	0-01-00	
			188-2 भाग	0-01-00	
			188-4 भाग	0-02-00	
			220- भाग	0-05-00	
			163.2/ ए भाग	0-25-50	
			163-2 भाग	0-00-50	
			164-1 भाग	0-07-00	
			164-2 भाग	0-19-00	
			165- भाग	0-10-00	
			166 भाग	0-14-0	
			158-1 बी /1 भाग	0-10-00	
			158-1 बी 2 भाग	0-04-50	
			154 भाग	0-11-50	
			153 भाग	0-09-00	
			152-भाग	0-03-50	जी पी
			148-1 सी ,,	0-09-50	
			,, -1 डी ,,	0-11-50	
			,, -5 ,,	0-11-00	
			डी ,,	0-11-00	
			145-1 डी-भाग	0-23-00	
			143- ,,	0-03-00	जी पी
			140-2 ,,	0-24-50	
			138- ,,	0-02-50	
			136-2/सी	0-18-50	



1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पालकोलू	पालकोलू भण्डा-II	11-4/डी भाग	0-00-50	
			124-1/डी ,,	0-28-50	
			11-1 बी ,,	0-26-50	
			11-1 सी	0-21-50	
			11-1 डी ,,	0-15-50	
			11-1 ई ,,	0-11-50	
			11-1 एच ,,	0-03-00	
			122-3 ,,	0-04-50	
			123-1 ,,	0-11-00	
			11-2 ,,	0-05-50	
			11-3 ,,	0-13-50	
			113-1 ,,	0-03-00	
			11-2 ,,	0-06-00	
			100 ,,	0-06-50	
			109 ,,	0-17-00	
			108-1 बी ,,	00-9-50	
			102- ,,	0-04-50	जी पी
			103-1 ए ,,	0-01-00	
			11-1 बी 1 ,,	0-11-50	
			11-1 बी 2	0-06-50	
			11-1 ए 3 ,,	0-13-50	
			104- ,,	0-39-00	
			93 ,,	0-002-50	
				3-69-00 या एकड़ 9-12	

[सं. एल-14016/14/93-जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2802.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapura to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification objects to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Narasapura Aol-Peruvali**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Palakol	Palakol Bit No. I	349-3 Part	0-16-0	
			358-2 B Part	0-24-50	
			347-Part	0-18-50	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.) Palakol	Palakol--Bit-1	346-1 Part	0-01-50		G.P.
		346-2 Part	0-02-50		G.P.
		328-3B Part	0-00-50		
		328-4A Part	0-03-00		
		328-5A Part	0-03-50		
		328-5B Part	0-02-50		
		328-2A Part	0-01-00		
		328-2B Part	0-00-50		
		328-6 Part	0-00-50		
		328-7 Part	0-05-50		
		328-9 Part	0-03-50		
		328-10 Part	0-07-50		
		A			
		328-10B Part	0-07-50		
		328-11 Part	0-11-00		
		329-1 Part	0-01-50		
		330-Part	0-24-50		
		335-Part	0-13-50		
		337-Part	0-16-00		
		336-1 Part	0-07-50		
		336-2 Part	0-23-50		
		301-2 Part	0-05-50		
		300-1 Part	0-15-50		
		303-1 Part	0-07-00		
		303-2 Part	0-06-00		
		305-Part	0-27-00		
		306-Part	0-09-50		
		308-Part	0-01-50		G.P.
		309-Part	0-02-00		G.P.
		278-Part	0-04-00		G.P.
		253-Part	0-00-50		G.P.
		254-1A Part	0-01-00		G.P.
		254-5A Part	0-04-00		
		254-6A Part	0-00-50		
		254-2B Part	0-05-00		
		254-3B Part	0-01-00		
		254-4 Part	0-03-00		
		255-1A Part	0-07-50		
		255-2A Part	0-10-00		
		255-3 Part	0-14-50		
		255-4 Part	0-11-50		
		255-5 Part	0-11-00		
West Godavari (A.P.) Palakol	Palakol-Bit-No. II	250-7 Part	0-16-00		
		249-1 Part	0-01-00		G.P.
		249-2 Part	0-11-50		
		248-Part	0-12-50		

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Palakol	Palakol-Bit No. 247-2 Part	0-00-50		
		II 247-3 Part	0-09-50		
		246-Part	0-24-50		
		210-Part	0-00-50		G.P.
		974-Part	0-05-50		G.P.
		973-1 Part	0-06-50		
		973-2 Part	0-02-00		G.P.
		973-4 Part	0-04-50		
		973-5 Part	0-12-00		
		973-6 Part	0-00-50		
		972-Part	0-02-50		G.P.
		200-1 Part	0-01-00		
		200-2 Part	0-01-50		
		196- Part	0-15-50		
		197-1B Part	0-00-50		
		197-1C Part	0-05-50		
		197-2 Part	0-15-50		
		198- Part	0-00-50		
		198-3 Part	0-06-00		
		198-4 Part	0-03-50		
		198-5A Part	0-07-50		
		198-5B Part	0-06-50		
		198-6 Part	0-04-00		
		198-7 Part	0-01-00		
		189-Part	0-02-50		G.P.
		190-1 Part	0-00-50		
		188-1 Part	0-01-00		
		188-2 Part	0-01-00		
		188-4 Part	0-02-00		
		220-Part	0-09-00		
		163-2A Part	0-20-50		
		163-2B Part	0-00-50		
		164-1 Part	0-07-00		
		164-2 Part	0-19-00		
		165-Part	0-10-00		
		166-Part	0-14-00		
		158-1B Part	0-10-00		
		158-1B2 Part	0-04-50		
		154-Part	0-11-50		
		153-Part	0-09-00		
West Godavari (A.P.)	Palakol	Palakol-Bit No. 152-Part	0-03-50		G.P.
		III 148-1C Part	0-09-50		
		148-1D Part	0-11-50		
		148-5 Part	0-11-00		
		145-1D Part	0-23-00		

West Godavari (A.P.)	Palakol	Palakol-Bit No. 143-Part	0-03-00	G.P.
		III 140-2 Part	0-24-50	
		138-Part	0-02-50	
		136-2 C Part	0-18-50	
		136-4D Part	0-00-50	
		124-1A Part	0-28-50	
		124-1B Part	0-26-50	
		124-1C Part	0-21-50	
		124-1D Part	0-15-50	
		142-1E Part	0-11-50	
		124-1H Part	0-03-00	
		122-3 Part	0-04-50	
		123-1 Part	0-11-00	
		123-2 Part	0-05-50	
		123-3 Part	0-13-50	
		113-1 Part	0-03-00	
		113-2 Part	0-06-00	
		110 Part	0-06-50	
		109-Part	0-17-00	
		1081B Part	0-09-50	
		102-Part	0-04-50	G.P.
		103-1A Part	0-01-00	
		103-1B Part	0-11-50	
		103-1B2 Part	0-06-50	
		103-1A3 Part	{ 0-13-50	
		104-Part	0-39-00	
		93-Part	0-02-50	G.P.
Total			3-69-00 Or Ac 9-12	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2803—जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम पेखलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अपारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पार्श्व लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवर्तमान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की घोषणा करती है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में आपत्ती अथवा सक्षम प्राधिकारी गैस अपारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसोत प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंडी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्विष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

नरसापुरम से पेरावलि.

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरि (आं. प्र.)	पेनुमंद्र	नेगि पुडि	95- भाग	0. 03. 75	जि. पि.
			96- 4 भाग	0. 06. 50	
			145-2 भाग	0. 14. 25	
			145-3 भाग	0. 11. 00	
			144-1 भाग	0. 09. 50	
			144-4 भाग	0. 09. 50	
			144-5 भाग	0. 17. 50	
			142- भाग	0. 03. 50	
			123-1 भाग	0. 04. 50	
			123-4 भाग	0. 13. 00	
			122-6 भाग	0. 06. 00	जि. पि.
			122-2 भाग	0. 05. 00	
			122-3 भाग	0. 04. 50	
			122-4 भाग	0. 08. 50	
			120-1 भाग	0. 23. 00	
			119-5 भाग	0. 02. 50	
			119-4 भाग	0. 00. 50	
			119-6 भाग	0. 05. 00	
			119-3 भाग	0. 03. 00	
			119-7 भाग	0. 03. 00	
योग			1-57-00 या ए.सी. 3.88 केन्ट्स		

[सं. एल.-14016/14/93-जीपी]

अर्बन्धु सेन, निर्देशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2803.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram—Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Narasapuram to Peravali

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Penumantra	Neggipudi	95-Part	0-03-75	G.P.
			96-4 Part	0-06-50	

1	2	3	4	5	6
			145-2 Part	0-14-25	
			145-3 Part	0-14-00	
			144-1 Part	0-09-50	
			144-4 Part	0-09-50	
			144-5 Part	0-17-50	
			142 Part	0-03-50	G.P.
			123-1 Part	0-04-50	
			123-4 Part	0-13-00	
			122-6 Part	0-06-00	
			122-2 Part	0-05-00	
			122-3 Part	0-04-50	
			122-4 Part	0-08-50	
			120-1 Part	0-23-00	
			119-5 Part	0-02-50	
			119-4 Part	0-00-50	
			119-6 Part	0-05-00	
			119-3 Part	0-03-00	
			119-7 Part	0-03-00	
			Total	1-57-00 Or Ac 3.88 Cents.	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2904.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम-पेरवल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

नरसापुरम-पेरवल

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी आ.प्र.	पेनुमन्त	मार्टेड	72—भाग	0.04.00	जी.पी.
			71-1 भाग	0.10.75	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	पेनुमन्त	मोटेंस	70-4 भाग	0.09.00	
			65- भाग	0.28.00	
			68-6 भाग	0.03.00	
			64-5 भाग	0.09.00	
			64-3 भाग	0.08.50	
			77-1 भाग	0.10.50	
			82-6 भाग	0.09.50	
			82-3 भाग	0.10.25	
			82-2 भाग	0.09.50	
			83-1 भाग	0.09.50	
			83-2 भाग	0.01.50	
			85- भाग	0.05.00	जी.पी.
			86-10 भाग	0.01.00	
			86-11 भाग	0.04.00	
			86-12 भाग	0.02.00	
			86-14 भाग	0.04.00	
			86-15 भाग	0.07.00	
			102-भाग	0.00.50	जी.पी.
			88-भाग	0.02.50	जी.पी.
			89-5 भाग	0.05.50	
			89-2 भाग	0.07.75	
			89-3 भाग	0.05.50	
			89-4 भाग	0.03.00	
			91-8 भाग	0.05.50	
			91-4 भाग	0.04.50	
			91-5 भाग	0.00.25	
			91-6 भाग	0.11.00	
			92-2 भाग	0.06.00	
			92-3 भाग	0.14.00	
			95-1 भाग	0.00.50	
			94-2 भाग	0.01.50	
			94-7 भाग	0.03.00	
			94-1 भाग	0.03.00	
			कुल योग	2.20.00	या एकड़ 5.44 सेग्ट्स

[सं. एल- 14016 /14/93-जी. पी.]

अधैन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2804.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd. ;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthamj Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

### GAS PIPE LINE PROJECT

Narasapuram—Peravali

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Penumantra	Marteru	72-Part	0-04-00	G.P.
			71-1 Part	0-10-75	
			70-4 Part	0-09-00	
			65-Part	0-28-00	
			68-6 Part	0-03-00	
			64-5 Part	0-09-00	
			64-3 Part	0-08-50	
			77-1 Part	0-10-50	
			82-6 Part	0-09-50	
			82-3 Part	0-10-75	
			82-2 Part	0-09-50	
			83-1 Part	0-09-50	
			83-2 Part	0-01-50	
			85-Part	0-05-00	G.P.
			86-10 Part	0-01-00	
			86-11 Part	0-04-00	
			86-12 Part	0-02-00	
			86-14 Part	0-04-00	
			86-15 Part	0-07-00	G.P.
			102-Part	0-00-50	
			88-Part	0-02-50	
			89-5 Part	0-05-50	
			89-2 Part	0-07-75	
			89-3 Part	0-05-50	G.P.
			89-4 Part	0-03-00	
			91-8 Part	0-05-50	
			91-4 Part	0-04-50	
			91-5 Part	0-00-25	
			91-6 Part	0-11-00	
			92-2 Part	0-06-00	
			92-3 Part	0-14-00	
			95-1 Part	0-00-50	
			94-2 Part	0-01-50	



1	2	3	4	5	6
West Gopavan(A.P.)	Penumantra	Marteri	94-7 Part	0-03-00	
			94-1 Part	0-03-00	G.P.
Grand Total				2-20-00 Or Ac 5-44 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 1993

का. आ. 2805—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि., के. जी. वसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1 /3 /1 राजमंजूरी 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करणा चाहता है।

## अनुसूची

गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

नरसपुरम से पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (.आ प्र.)	पोडूरु	वेंडुगि	297-भाग	0.02.50	
			297-2भाग	0.03.00	
			297-3भाग	0.03.50	
			297-4भाग	0.06.00	
			297-5भाग	0.06.50	
			299-भाग	0.16.00	
			301.2भाग	0.15.00	
			302-भाग	00.7.00	

1	2	3	4	5	5	6
पश्चिम गौदावरि अ. प्र.	पोडूरु	वेडंगि	303. 1भाग	0. 01. 25		
			303. 2भाग	0. 17. 25		
			320. 2भाग	0. 33. 50		
			335. 1 भाग	0. 19. 00		
			319 भाग	0. 20. 00		
				1. 50. 50 या एसी 3. 72		

[सं. एल-14016/14/93 जी. पी.]

अर्धेन्दु सेंन, निदेशक,

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2805.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd. ;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification objects to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

## GAS PIPE LINE PROJECT

Narasapuram to Peravali

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Poduru	Vedangi	297-1 Part	0-02-50	
			297-2 Part	0-03-00	
			297-3 Part	0-03-50	
			297-4Part	0-06-00	
			297-5 Part	0-06-50	
			299	0-16-00	
			301-2 Part	0-15-00	
			302 Part	0-07-00	
			303-1 Part	0-01-25	
			303-2 Part	0-17-25	
			320-2 Part	0-33-50	
			325-1 Part	0-19-00	
			319-Part	0-20-00	
				1-50-50 Or AC 3-72	

[No. L-14016/14/93-G.P

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 1993

का. आ. 2806.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम पेरवलि पाईप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ राजपत्र विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर भूमिगत पाईप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि., के. जी. खनिज प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंजूरी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यक्तायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

नरसापुरम से पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़में)	विवरण
पश्चिम गोदावरि (अ. प्र.)	पोडूर	महुपूर	129-15 भाग	0.09.50	जीपि
			126भाग	0.01.50	
			125 भाग	0.10.00	
			124 1A/2भाग	0.07.50	
			-1बी 2 भाग	0.09.50	
			-1सी पार्ट भाग	0.09.00	
			-3 पार्ट भाग	0.00.50	
			137--भाग	0.10.50	
			138. 3भाग	0.10.50	
			-4-भाग	0.06.00	
			146. 2भाग	0.16.00	
			151. 2भाग	0.15.50	
			3. भाग	0.05.00	
			-4भाग	0.10.50	
			152. 2भाग	0.03.00	
			-3भाग	0.08.00	
			-4-भाग	0.07.00	
			163. भाग	0.31.75	
			164. 1भाग	0.09.00	
			172--भाग	0.25.00	
			171. भाग	0.01.75	
			139-भाग	0.02.50	
			136-भाग	0.06.00	
योग			2.15.50 या एकड़ 5.33		

[ सं. एल-14016/14/93जीपी ]

अर्धेन्द्र सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2806.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasampuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962

(50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification objects to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3-1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Narasapuram to Peravali

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Podur	Mattaparru	129-15 Part	0-09-50	G.P.
			126-Part	0-01-50	
			125-Part	0-10-00	
			124-1A2 Part	0-07-50	
			124-1B2 Part	0-09-50	
			124-1C Part	0-09-00	
			124-3 Part	0-00-50	
			137-Part	0-10-50	
			138-3 Part	0-10-50	
			138-4 Part	0-06-00	
			146-2 Part	0-16-00	
			151-2 Part	0-15-50	
			151-3 Part	0-05-00	
			151-4 Part	0-10-50	
			152-2 Part	0-03-00	
			152-3 Part	0-08-00	
			152-4 Part	0-07-00	
			163-Part	0-31-75	
			164/1 Part	0-09-00	
			172-Part	0-25-00	
			171-Part	0-01-75	
			139-Part	0-02-50	
			136-Part	0-06-00	
			Total	2-15-50 Or AC 5-33	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2807.—जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम-पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाईन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिमूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाईप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी -533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह बिशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूची

#### गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

#### नरसपुरम पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे. नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरि (आ.प्र.)	पालकोल्लू	दिगमर्ह	99.-भाग	0.01.00	जि.पि.
			98-भाग	0.80.00	
			96-1भाग	0.08.50	जि.पि.
			96-2 भाग	0.08.50	
			96-5 भाग	0.00.50	जि.पि.
			96-4भाग	0.05.50	
			83-2भाग	0.21.00	
			85.भाग	0.02.50	जि.लि.
			79-भाग	0.19.00	
			116-1भाग	0.03.00	
			116-2 भाग	0.45.50	
			117.-भाग	0.02.00	जि.पि.
			129.-7भाग	0.11.50	
			129-5 भाग	0.09.00	
			129-4 भाग	0.09.00	
			129-1भाग	0.10.00	
			131-भाग	0.49.00	
			132-भाग	0.02.50	जि.पि.
			127-भाग	0.01.00	जि.पि.
			135-भाग	0.52.50	
			150-2-ए भाग	0.00.25	
			150-2बी भाग	0.24.50	
			150-2सी भाग	0.18.00	
			149-ए भाग	0.00.50	
			153.-भाग	0.03.00	जि.पि.
			155-भाग	0.12.50	
			156.-भाग	0.38.00	
			158-भाग	0.01.50	जि.पि.
योग			4.33.75 या एसी 10.71½सेण्ट्स		

[सं. एल. -14016/14/93/जी-पी]

अर्धेन्द्र सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2807.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali Pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowdhami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Narasapuram to Peravali

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area	Remarks		
				(In Hect/Acres)			
West Godavari (A.P.)	Palakollu	Digamarru	99-Part	0-01-00	G.P.		
			98-Part	0-80-00			
			96-2 Part	0-03-50			
			96-1 Part	0-02-50	G.P.		
			96-5 Part	0-00-50	G.P.		
			96-4 Part	0-05-50			
			83-2 Part	0-21-00			
			85-Part	0-02-50	G.P.		
			79-Part	0-19-00			
			116-1 Part	0-03-00			
			2 Part	0-45-50			
			117-Part	0-02-00	G.P.		
			129-7 Part	0-11-50			
			129-5 Part	0-09-00			
			129-4 Part	0-09-00			
			129-1 Part	0-10-00			
			131-Part	0-49-00			
			132-Part	0-02-50	G.P.		
			127-Part	0-01-00	G.P.		
			135-Part	0-52-50			
			150-2A Part	0-00-25			
			150-2B Part	0-24-50			
			150-2C Part	0-18-00			
			149-A Part	0-00-50			
			153-Part	0-03-00	G.P.		
			155-Part	0-12-50			
			156-Part	0-38-00			
			158-Part	0-01-50	G.P.		
			Total			4-33-75	
						Or	
						AC 10-71½ CENTS	

[No. L-14016/14/92-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2808.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरमापुरम पेरवलि पार्श्व लाईन परियोजना के अन्तर्गत पार्श्व लाइन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न खिबरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पार्श्व लाईन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पार्श्व लाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंजूरी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज कर सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यावसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पार्श्व लाईन प्रोजेक्ट

नरमापुरम पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे. न.	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	खिबरण
पश्चिम गोदावरी	आं. प्र. पोडुरु	पोडुरु	186--भाग	0.02.50	जि. पि.
			187-1भाग	0.25.00	
			187-2भाग	0.08.00	
			187-3भाग	0.00.50	
			188-5भाग	0.08.50	
			188-6भाग	0.04.00	
			183-भाग	0.04.75	
			184- 1 एभाग	0.07.75	
			184 1वीं भाग	0.03.50	
			184-2ए भाग	0.09.00	
			184 2वीं भाग	0.02.50	
			184-2बी भाग	0.02.50	
			180-भाग	0.16.50	
			178-भाग	0.22.00	
			181-2भाग	0.14.25	
			156-2भाग	0.13.50	
			156-4भाग	0.11.00	
			157-1भाग	0.13.50	
			157-2भाग	0.08.00	
			157-3भाग	0.06.75	
			157-4भाग	0.06.25	
			157-5भाग	0.05.75	
			152-1ए भाग	0.00.50	

1	2	3	4	5	6
			152-5भाग	0.04.50	जि.पि.
			159-3भाग	0.16.50	
			151-भाग	0.03.00	
			162-भाग	0.34.50	
			147.भाग	0.21.50	
			163. 3भाग	0.01.00	
			163-4भाग	0.24.00	
			164-भाग	0.05.00	
			योग	3.06.50 या ए सी 7.58 सेन्ट्स	

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2808.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram Parawali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the section 3 of the petroleum & Mine-

ral's pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by Legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Narasapuram to Peravali**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Poduru	Poduru	186-Part	0-02-50	G.P.
			187-1 Part	0-25-00	
			187-2 Part	0-08-00	
			187-3 Part	0-00-50	
			188-5 Part	0-08-50	
			188-6 Part	0-04-00	
			183-Part	0-04-75	
			184-1A Part	0-07-75	
			184-1B Part	0-03-50	
			184-2A Part	0-09-00	
			184-2B Part	0-02-50	
			184-2D Part	0-02-50	
			180-Part	0-16-50	
			178-Part	0-22-00	
			181-2 Part	0-14-25	
			156-2 Part	0-13-50	
			156-4 Part	0-11-00	
			157-1 Part	0-13-50	
			157-2 Part	0-08-00	



1	2	3	4	5	6
			157-3 Part	0-06-75	
			157-4 Part	0-06-25	
			157-5 Part	0-05-75	
			152-1A Part	0-00-50	
			152-5A Part	0-04-50	
			159-3 Part	0-16-50	
			151-Part	0-03-00	
			162-Part	0-34-50	
			147-Part	0-21-50	
			163-3 Part	0-01-00	
			163-4 Part	0-24-00	
			164-Part	0-05-00	G.P.
		Total		3-06-50	OR Ac 7.58 Cents

[No. L-14016/14/93-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2809 :- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम से पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

नरसापुरम से पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	खर्च.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेर एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (सा.प्र.)	पोडुच	कविटाम	487-भाग	0.02.50	जि.नि.
			488-4भाग	0.10.00	
			488-5भाग	0.12.00	
			488-6भाग	0.30-00	
			489-1भाग	0.00.25	
			2-भाग	0.03.00	
			3-भाग	0.03-50	
			4-भाग	0-07-00	
			5-भाग	0-06-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पोंडुरु	काविट्टाम	491-1भाग	0.14.50	
			491-2भाग	0.00.50	
			492-5भाग	0.16.00	
			514-भाग	0.24.50	
			513-1 भाग	0.10.50	
			513-2 भाग	0.13.00	
			500-1 भाग	0.09.00	
			500-2 भाग	0.09.00	
			501-1 भाग	0.00.25	
			501-2भाग	0.13.50	
			501-3भाग	0.05.00	
			502-3 भाग	0.09.50	
			503-1 भाग	0.21.00	
			504-भाग	0.09.00	
			403-2भाग	0.14.00	
			403-3भाग	0.19.00	
			401-भाग	0.02.00	जिपि
			400-3 भाग	0.05.50	
			399-भाग	0.02.50	जिपि
			397-भाग	0.03.50	
			398-भाग	0.31.00	
			392-भाग	0.16.50	
			391-भाग	0.21.50	
			390-1भाग	0.16.50	
			390-3भाग	0.04.00	
			389-भाग	0.04.00	
			388-भाग	0.01.50	जिपि
			493-भाग	0.02.50	
			कुल योग	3.47.00	
			या		
			ए सी	8.58 सैन्टस	

[सं. एल.—14016/14/93 जी पी]

सधेन्द्र सेन निदेशक

अनुसूची  
अल्लम्पुर से वेन्ड गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	वीरवसरम	वीरवसरम	29-2-बी भाग]	0-08-00	
			29-3 "	0-09-00	
			1-डो "	0-08-75	
			2-ए "	0-02-00	
			1-ए "	0-05-00	
			1-बी "	0-05-00	
			33- "	0-15-75	
			27-2-बी "	0-09-25	
			2-सी "	0-06-00	
			34-1 "	0-09-75	
			34-3 "	0-04-50	
			36-2 "	0-19-00	
			48- "	0-03-50	
			47- "	0-18-00	
			45-1 "	0-04-25	
			2 "	0-07-00	
			43-6-बी "	0-06-00	
			43-7 "	0-16-00	
			131-2-ए "	0-07-50	
			-2-बी "	0-02-50	
			130-1-ए "	0-03-00	
			1-बी "	0-07-50	
			1-सी "	0-13-50	
			2-ए "	0-15-00	
			135- भाग	0-03-00	
			139- "	0-33-00	
			138- "	0-19-25	
			170- "	0-03-00	
			172- "	0-22-75	
			178-1 "	0-06-00	
			2ए "	0-05-75	
			175-1 "	0-07-50	
			2 "	0-07-75	
			4ए "	0-14-50	
			4बी "	0-15-00	
			5 "	0-01-00	
			6 "	0-03-00	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Porudru	Kavitam	398-Part	0-31-00	
			392-Part	0-16-50	
			391-Part	0-21-50	
			390-1 Part	0-16-50	
			390-3 Part	0-04-00	
			389-Part	0-04-00	
			388-Part	0-01-50	G.P.
			493-Part	0-02-50	
			Grand Total	3-47-00	
				Or	
			AC	8-58 Cents	

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2810—जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाइने के लिए नरसपुरम-पेरवलि पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाईन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाईन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि., के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, राजमुंड्री - 533-104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसा आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

नरसापुरम—पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	पोडूरु	पेतुमादम	1035-भाग	0.05.50	जि.पि.
			1034-2 भाग	0.16.00	
			1033-भाग	0.05.00	
			1042-2 भाग	0.00.50	
			1032-1 भाग	0.14.00	
			1032-2 भाग	0.09.50	
			1031-1 भाग	0.30.00	
			1031-2 भाग	0.04.00	
			1029-1 भाग	0.19.00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पोडर	पेनुमादम	1015-भाग	0.14.00	
			1018-2भाग	0.34.75	
			1019-1भाग	0.01.00	
			1019-2भाग	0.21.50	
			1007-2भाग	0.03.00	
			1007-7भाग	0.13.50	
			997-2भाग	0.22.00	
			998-भाग	0.44.50	
			999-1 भाग	0.04.00	
			1000-भाग	0.36.00	
			1001-भाग	0.00.25	
			994-ए भाग	0.01.00	
			994-बी भाग	0.00.25	
			995-ए भाग	0.02.00 जी.पी	
			995-बी भाग	0.01.00	
			योग	3.02.25 या	
				ए सी 7.46 1/2 सेंट	

[स. एल.-14016 / 14 / 93-जी पी]

अर्धेन्दु सैन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2810.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram Parawali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the section 3 of the petroleum & Mine-

ral's pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in if the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person by Legal Practitioner.

### SCHEDULE GAS PIPE LINE PROJECT

Narasapuram to Perayali.

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari	Paduni	Penumadavri	1035-Part	0-05-50	G.P.
			1034-2-Part	0-16-00	
			1033-Part	0-05-00	G.P.
			1042-2-Part	0-00-50	
			1032-1-Part	0-14-00	
			„ -2-Part	0-09-50	
			1031-1-Part	0-30-00	
			„ 2-Part	0-04-00	
			1029-Part	0-19-00	

1	2	3	4	5	6
			1015-Part	0-14-00	
			1018-2-Part	0-34-75	
			1019-1-Part	0-01-00	
			„ 2-Part	0-21-50	
			1007-2-Part	0-03-00	
			„ -7-Part	0-13-50	
			997-2-Part	0-22-00	
			998-Part	0-44-50	
			999-1-Part	0-04-00	
			1000-Part	0-36-00	
			1001-Part	0-00-25	
			994-A-Part	00-01-00	
			„ -B-Part	0-00-25	
			995-A-Part	0-02-00	G.P.
			B-Part	0-01-00	
			Total	3-02-25	or AC 7.46 1/2 Cents.

[No. L-14016/14/93—G.P.]

Sd/-

ARDHENDU SEN., Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2811.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ सज्जन धिरनणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भी भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि., के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, राजमुट्टी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति का यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

नरसापुरम से पेरवलि गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल (हेक्ट. एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	पोडूरु	जिन्नूरु	332-6भाग	0.18.00	
			333-1भाग	0.02.25	
			333-2भाग	0.05.50	
			333-6-भाग	0.07.00	
			336-1भाग	0.08.00	

1	2	3	4	5	6
			336-3भाग	0-06-50	
			336-4भाग	0-06-75	
			336-7भाग	0-12-75	
			337-1भाग	0-21-50	
			338-भाग	0-19-00	
			315-1भाग	0-02-00	
			318-4भाग	00-1-00	
			316-1भाग	0-33-00	
			316-3भाग	0-02-50	
			317-4भाग	0-02-25	
			304-भाग	0-26-50	
			299-2भाग	0-17-00	
			300-भाग	0-17-50	
			298-1भाग	0-04-50	
			292-5भाग	0-01-50	
			292-6भाग	0-08-50	
			293-2भाग	0-23-00	
			293-1भाग	0-10-00	
			294-1भाग	0-19-50	
			331-भाग	0-03-00	जी. पी.
			339-भाग	0-03-00	जि. पी.
			295-भाग	0-01-50	जि. पी.
			315-2भाग	0-00-25	जि. पी.
			315-3भाग	0-00-25	जि. पी.
2.84.00					

सं. एल. 140/36/14/93-जी पी)

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2811.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Narasapuram-Peravali pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the section 3 of the Petroleum & Mine-

erals Pipelines (Acquisition of right of users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE NARASAPURAM TO PARAVALI GAS PIPE LINE PROJECT

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari	Poduru	Jennuru	332-3-Part	0-18-00	
			333-1-Part	0-02-25	
			„ -2-Part	0-05-50	
			„ -6-Part	0-07-00	

1	2	3	4	5	6
			336-1-Part	0-08-00	
			-3-Part	0-06-60	
			-4-Part	0-06-75	
			7-Part	0-12-75	
			337-1-Part	0-21-50	
			338-Part	0-19-00	
			315-1-Part	0-02-00	
			318-4-Part	0-01-00	
			316-1-Part	0-33-00	
			-3-Part	0-02-50	
			317-4-Part	0-02-25	
			304-Part	0-26-50	
			299-2-Part	0-17-00	
			300-Part	0-17-50	
			298-1-Part	0-04-50	
			292-5-Part	0-01-50	
			-6-Part	0-08-50	
			293-2-Part	0-23-00	
			-1-Part	0-10-00	
			294-1-Part	0-19-50	
			331-1-Part	0-03-00	G.P.
			339-Part	0-03-00	G.P.
			295-Part	0-01-50	G.P.
			315-2-Part	0-00-25	G.P.
			-3-Part	0-00-25	G.P.
			Total	0-84-00	G.P.

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2812:—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम-येराबलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न बिबरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, प्रकाश नगर, राजमंडी-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।



**अनुसूची**  
**नरसापुरम पेरवली गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट**

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्जें नं	क्षेत्रफल (हेक्ट. / एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (अ. प्र.)	नरसापुरम	बिड्डवरम	49-1 भाग	0-00-5	जमादा या कम
			49-1 "	0-12-5	"
			49-1 "	0-02-0	"
			51 "	0-20-0	"
			50 "	0-37-0	"
			47-2 "	0-04-5	"
			55-3 "	0-08-0	"
			4 "	0-06-5	"
			56-6 "	0-09-5	"
			7 "	0-12-0	"
			57-4 "	0-04-0	"
			2 "	0-03-5	"
			58-1 "	0-50-0	"
			59 "	0-15-0	"
			41 "	0-02-5	"
			36-1 "	0-34-0	"
			36-1 "	0-08-5	"
			2 "	0-04-0	"
			35 "	0-01-5	"
			37-1 "	0-07-5	"
			2 "	0-09-5	"
			38 "	0-00-5	"
			20-1 "	0-39-5	"
			2 "	0-39-5	"
			3 "	0-39-5	"
			4 "	0-03-0	"
हेक्ट.				3-35-0	साकर 8.28 सेंट्स

[सं. एल-14016/14/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O.2812.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline is to be laid by the Gas Authority of India,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User) in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowtham Library, Rajamundry-533104, Andhra Pradesh,

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE  
NARASAPURAM PERAVALI GAS PIPE LINE PROJECT

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	
West Godavari (A.P.)	Narasapuram	Chittawaram	49-1-Part	0-00-5	More or less	
			49-1-Part	0-12-5	"	
			49-1-Part	0-02-0	"	
			51-Part	0-20-0	"	
			50-Part	0-37-00	"	
			47-2-Part	0-04-5	"	
			55-3-Part	0-08-0	"	
			55-4-Part	0-06-5	"	
			56-6-Part	0-09-5	"	
			56-7-Part	0-12-0	"	
			57-4-Part	0-04-0	"	
			57-2-Part	0-03-5	"	
			58-1-Part	0-50-0	"	
			59-Part	0-15-0	"	
			41-Part	0-02-5	"	
			36-1-Part	0-34-0	"	
			36-1-Part	0-08-5	"	
			36-2-Part	0-04-0	"	
			35-Part	0-01-5	"	
			37-1-Part	0-07-5	"	
			2-Part	0-09-5	"	
			38-Part	0-00-5	"	
			20-1-Part	0-39-5	}	"
			2-Part			"
			3-Part			"
			4-Part			"
			Hec.	3-35-00	OR AC 8-28 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

क्रा. आ. 2813.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये रसए नरसापुरम-पेरावलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न बिबरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोगता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सभ्य प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के जी. बंसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1, राजमुन्नी-833 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी प्राप्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## नरसापुरम से पेरवल्लि गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जम्मा	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट. एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	नरसापुरम	चिन्तामिडिपल्लि	69 भाग	0-01-50	ज्यादा या कम्ती
			83 भाग	0-00-50	"
			71-2 "	0-04-50	"
			72-1 "	0-35-50	"
			73-1 "	0-11-50	"
			2 "	0-13-50	"
			74-1 "	0-01-00	"
			74-2 "	0-00-50	"
			66-4 "	0-14-00	"
			67-2 "	0-00-50	"
			67-3 "	0-01-50	"
			65-2 "	0-14-50	"
			63-3 "	0-13-50	"
			62- "	0-11-00	"
			57 "	0-26-50	"
			58 "	0-22-50	"
			51 "	0-03-00	"
			49-1 "	0-03-00	"
			49-2 "	0-14-00	"
			49-3 "	0-01-00	"
			70-1 "	0-05-00	"
			2 "	0-00-50	"
				1-99- या 4.92 एकड़	

[सं. एल-14016/14/93-जीपी]

अर्थेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2813.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Narasapuram to Peravalli pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajamundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

**SCHEDULE**  
**NARASAPURAM-PERAVALI GAS PIPE LINE PROJECT**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	
West Godavari (A.P.)	Narasapuram	Chinamahidipalli	69-Part	0-01-50	More or Less	
			83-Part	0-00-50		
			71-2-Part	0-04-50		
			72-1-Part	0-35-50		
			73-1-Part	0-11-50		
			73-2-Part	0-13-50		
			74-1-Part	0-01-00		
			74-2-Part	0-00-50		
			66-4-Part	0-14-00		"
			67-2-Part	0-00-50		"
			67-3-Part	0-01-50		"
			65-2-Part	0-14-50		"
			63-3-Part	0-13-50		"
			62-Part	0-11-00		"
			57-Part	0-26-50		"
			58-Part	0-22-50		"
			51-Part	0-03-00		"
			49-1-Part	0-03-00		"
			49-2-Part	0-14-00		"
			49-3-Part	0-01-00		"
			70-1-Part	0-05-00		"
			2-Part	0-00-50		
				1-99-00	Or 4-92-Cents.	

[No. L—14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2814 :— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए अरलम्पक से वेण्ड पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा एक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी सधि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के दिरेक्ष में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. असीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## अल्लम्पुर से वेन्डु गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. ' एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	वीरवसरम	वीरवसरम	29-2-बी भाग]	0-08-00	
			29-3 "	0-09-00	
			1-डी "	0-08-75	
			2-ए "	0-02-00	
			1-ए "	0-05-00	
			1-बी "	0-05-00	
			33- "	0-15-75	
			27-2-बी "	0-09-25	
			2-सी "	0-06-00	
			34-1 "	0-09-75	
			34-3 "	0-04-50	
			36-2 "	0-19-00	
			48- "	0-03-50	
			47- "	0-18-00	
			45-1 "	0-04-25	
			2 "	0-07-00	
			43-6-सी "	0-06-00	
			43-7 "	0-16-00	
			131-2-ए "	0-07-50	
			-2-बी "	0-02-50	
			130-1-ए "	0-03-00	
			1-बी "	0-07-50	
			1-सी "	0-13-50	
			2-ए "	0-15-00	
			135- भाग	0-03-00	
			139- "	0-33-00	
			138- "	0-19-25	
			170- "	0-03-00	
			172- "	0-22-75	
			178-1 "	0-06-00	
			2ए "	0-05-75	
			175-1 "	0-07-50	
			2 "	0-07-75	
			4ए "	0-14-50	
			4बी "	0-15-00	
			5 "	0-01-00	
			6 "	0-03-00	

1	2	3	4	5	9
पश्चिम गोदावरी	वीरवसरम	वीरवसरम	304- भाग	0-04-00	
(आ० प्र०)			303-1 "	0-27-75	
			3 "	0-03-25	
			306-3 "	0-01-00	
			307- "	0-01-05	
			301- "		
			298-2 "	0-00-25	
			4 "	0-00-25	
			300- "	0-03-00	
			264-1 "	0-20-75	
			6 "	0-18-00	
			8 "	0-07-75	
			265- "	0-03-00	
			267-1 "	0-03-25	
			3 "	0-16-00	
			4 "	0-22-00	
			290-2 भाग	0-11-50	
			290-3 भाग	0-14-00	
			290-5 भाग	0-12-50	
			291- "	0-00-75	
			289-1 "	0-09-50	
			289-2 "	0-16-75	
			393- "	0-32-50	
			392-1 "	0-06-75	
			392-2 "	0-08-25	
			391- "	0-18-00	
			391-1-ए-3 "		
			391-1-डी	0-11-50	
			391-2 "	0-00-50	
			381-1 "	0-01-00	
			381-2 "	0-03-00	
			409- "	0-06-50	
			410- "	0-18-00	
			411	0-11-00	
					6-62-50 पा ए सी 16-37-1/2

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

अर्थन्तु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O.2814.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajamundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**FROM ULLAMPARRU TO VENDRA**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Areas)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Veeravasaram	Veeravasaram	29-2-B Part	0-08-00	
			29-3-Part	0-09-00	
			1D-Part	0-08-75	
			2A-Part	0-02-00	
			1A-Part	0-05-00	
			1B-Part	0-05-00	
			33-Part	0-15-75	
			27-2-B-Part	0-09-25	
			2C-Part	0-06-00	
			34-1-Part	0-09-75	
			34-3-Part	0-04-50	
			36-2-Part	0-19-00	
			48-Part	0-03-50	
			47-Part	0-18-00	
			45-1-Part	0-04-25	
			2-Part	0-07-00	
			43-6B-Part	0-06-00	
			43-7-Part	0-16-00	
			131-2A-Part	0-07-50	
			2B-Part	0-02-50	
			130-1A-Part	0-03-00	
			1B-Part	0-07-50	
			1C-Part	0-13-50	
			2A-Part	0-15-00	
			135-Part	0-03-00	
			139-Part	0-33-00	
			138-Part	0-19-25	
			170-Part	0-03-00	
			172-Part	0-22-75	
			178-Part	0-06-00	
			2A	0-05-75	
			175-1-Part	0-07-50	
			2-Part	0-07-75	

1	2	3	3	5	6
West Godavari	Veeravasaram	Veeravasaram	4A-Part	0-14-50	
			4B-Part	0-15-00	
			5-Part	0-01-00	
			6-Part	0-03-00	
			304-Part	0-04-00	
			303-1-Part	0-27-75	
			303-3-Part	0-03-25	
			306-3 Part	0-01-03	
			307-Part	0-01-50	
			301-Part	0-01-50	
			298-2 Part	0-00-25	
			4 Part	0-00-25	
			300-Part	0-03-00	
			264-1-Part	0-20-75	
			264-6-Part	0-18-00	
			264-8-Part	0-07-75	
			265-Part	0-03-00	
			267-1-Part	0-03-25	
			267-3-Part	0-16-00	
			267-4-Part	0-22-00	
				2-74-75	
			290-2-Part	0-11-50	
			290-3-Part	0-14-00	
			290-5-Part	0-12-50	
			291-Part	0-00-75	
			289-1-Part	0-09-50	
			289-2-Part	0-16-75	
			393-Part	0-32-50	
			392-1-Part	0-06-75	
			392-2-Part	0-08-25	
			391-1A3-Part	0-18-00	
			391-1D-Part	0-11-50	
			391-2-Part	0-0050	
			381-1-Part	0-01-00	
			381-2-Part	0-03-00	
			409-Part	0-06-50	
			410-Part	0-18-00	
			411-Part	0-11-00	
				6	
			PT	1-82-00	—4-50
			Page - 2	2-74-75	6-78
			Page-1	2-05-75	5-09"
			Total	6-62-50 or AC 16-37 Cents	



नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

क्रा. आ 2815.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए ऊल्लम्पडु से वेन्डा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाईन गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमि. के. जी. बेसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

ऊल्लम्पडु से वेन्डा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरि (आ. प्र.)	पाल्लकोल्लू	ऊल्लम्पडु	216-1 भाग	0-05-50	
			„ 2वीं „	0-04-50	
			„ 3वीं „	0-07-00	
			215-1 „	0-06-00	
			2 „	0-26-00	
			214-1 „	0-03-00	
			2 „	0-18-00	
			3 „	0-05-75	
			175-3 „	0-19-00	
			4 „	0-06-00	
			174- „	0-04-50	
			156-1 „	0-21-50	
			159- „	0-02-75	
			158-1सी „	0-01-50	
			„ 3सी „	0-01-75	
			„ 4सी	0-01-50	
			„ 4खी „	0-12-00	
			144- „	0-09-50	
			127- „	0-02-00	
			131-1वीं „	0-14-50	
			2वीं „	0-08-00	
			132- „	0-02-50	
			118-1वीं „	0-23-50	
			2वीं „	0-17-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरी (आं.प्र.)	पाल्लकोल्लू	उल्लम्पट्टु	113-1	0-08-50	
			114-1	0-03-00	
			2	0-03-00	
			3	0-11-00	
			4	0-07-00	
			93-1	0-06-00	
			2	0-07-00	
			3	0-07-00	
			4	0-06-25	
				2-83-00	
			92-5 भाग	0-17-50	
			69-	0-02-50	
			91-2	0-05-50	
			3	0-05-75	
			4	0-05-00	
			70-	0-02-00	
			72-1	0-09-00	
			2	0-16-50	
			3	0-27-50	
			73-2	0-10-75	
			3	0-09-50	
			53-	0-00-50	
			32-2	0-09-50	
			3	0-08-00	
			31-1	0-12-50	
			3	0-22-00	
			52-2	0-01-00	
			3	0-17-00	
			33-	0-04-00	
				4-69-00 या ए सी	11-59 सैंट्स

[सं. एल-14016/14/93-जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन; निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2815.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullampattu to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

als Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., K.G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library Rajanbundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Ullamparru To Vendra

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Palakollu	Ullamparru	216-1-Part	0-05-50	
			216-2-B-Part	0-04-50	
			216-3B-Part	0-07-00	
			215-1-Part	0-06-00	
			215-2-Part	0-26-50	
			214-1-Part	0-03-00	
			214-2-Part	0-18-00	
			214-3-Part	0-05-75	
			175-3-Part	0-19-00	
			175-4-Part	0-06-00	
			174-Part	0-04-50	
			156-1-Part	0-21-50	
			159-Part	0-02-75	
			158-1C-Part	0-01-50	
			158-3C-Part	0-01-75	
			158-4C-Part	0-01-50	
			158-4D-Part	0-12-00	
			144-Part	0-09-50	
			127-Part	0-02-00	
			131-1B-Part	0-14-50	
			131-2B-Part	0-08-00	
			132-Part	0-02-50	
			118-1B-Part	0-23-50	
			118-2B-Part	0-17-00	
			113-1-Part	0-08-50	
			114-1-Part	0-03-00	
			141-2-Part	0-03-00	
			141-3-Part	0-11-00	
			141-4-Part	0-07-00	
			93-1-Part	0-06-00	
			93-2-Part	0-07-00	
			93-3-Part	0-07-50	
			93-4-Part	0-06-25	
			92-5-Part	0-17-50	
			69-Part	0-02-50	
			91-2-Part	0-05-50	
			91-3-Part	0-05-75	
			91-4-Part	0-05-00	
			70-Part	0-02-00	
			72-1-Part	0-09-00	
			72-2-Part	0-16-50	
			72-3-Part	0-27-50	
			73-2-Part	0-10-75	

1	2	3	4	5	6
			73-3-Part	0-09-50	
			53-Part	0-00-50	
			52-2-Part	0-01-00	
			52-3-Part	0-17-00	
			33-2-Part	0-09-50	
			33-3-Part	0-08-00	
			31-1-Part	0-12-50	
			31-3-Part	0-22-00	
				4-69-00 or AC 11-59-cents	

[No. L—14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2816.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए ऊल्लम्परू से वेन्ड्रा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. के. जी. बेसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंडी-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### ऊल्लम्परू से वेन्ड्रा

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	3	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरि (आ.प्र.)	पाल्लकोल्लू	बल्लिपाडु	119-1 भाग	0-07-50	
			„ 2 „	0-06-75	
			120-1 भाग	0-19-50	
			36-2 भाग	0-15-00	

1	2	3	4	5	6
			36 3 भाग	0-03-75	
			36 1 „	0-06-50	
			35-1 भाग	0-35-75	
			35 3 „	0-03-75	
			34- भाग	0-03-00	जिपि
			33- भाग	0-22-00	जिपि
			32-1 भाग	0-04-00	जिपि
			32 2 „	0-02-50	
			53- भाग	0-11-00	जिपि
			54-भाग	0-01-75	जिपि
			52-1 भाग	0-13-25	
			52-2 „	0-05-50	
			125- भाग	0-18-50	
			126- भाग	0-02-00	
				1-82-00	
				या 4.50 सेंट	

[सं. एल-14016/14/93—जी. पी.]

प्रमोदु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2816.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

als pipelines (Acquisition of Right of Users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library Rajanhmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
ULLAMPARRU TO VENDRA

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Palakollu	Ballipadu	119-1-Part	0-07-50	
			119-2-Part	0-06-75	
			120-1-Part	0-19-50	
			36-2-Part	0-15-00	
			36-3-Part	0-03-75	
			36-1-Part	0-06-50	
			35-1-Part	0-35-75	
			35-3-Part	0-03-75	
			34-Part	0-03-00	G.P.
			33-Part	0-22-00	G.P.

1	2	3	4	5	6
			32-1-Part	0-04-00	G.P.
			32-2-Part	0-02-50	
			53-Part	0-11-00	G.P.
			54-Part	0-01-75	G.P.
			52-1-Part	0-13-25	
			52-2-Part	0-05-50	
			125-Part	0-18-50	
			126-Part	0-02-00	
			Total	1-82-00	
				or AC 4-50 Cents	

[ No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2817.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए अल्लम्परु से बेंड्रा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमि. के. जी. बेसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अपना विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

अल्लम्परु से बेंड्रा

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हे० एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	पाल्लकोलू	चित्तपारु	91-ए-भाग	0-01-50	जीपी
			„ बी „	0-06-00	
			„ सी „	0-01-00	जीपी
			188-भाग	0-14-50	
			187-भाग	0-04-00	जीपी
			186-1 भाग	0-10-00	
			„ 2 „	0-05-50	
			185-1-भाग	0-00-25	
			„ 2 „	0-15-25	
			87-भाग	0-15-75	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आं. प्र.)	पाल्लिकोलू	चित्तपारु	84-भाग	0-15-50	
			83-2सी भाग	0-09-50	
			" 3 "	0-09-50	
			82-1-भाग	0-14-50	
			" 2 "	0-09-25	
			81-2-भाग	0-06-00	
			" 3 "	0-04-75	
			" 4 "	0-07-00	
			" 5 "	0-05-00	
			179-2-भाग	0-06-50	
			" 3 "	0-02-00	
			178-1 भाग	0-03-00	
			" 2 "	0-04-50	
			79-भाग	0-00-75	जी.पी.
			107-भाग	0-16-50	जी.पी.
			176-भाग	0-15-25	
			74-भाग	0-01-00	
			योग	2-04-75	
			73-भाग	0-16-25	
			175-1-भाग	0-05-50	
			" 3 "	0-03-00	
			" 5 "	0-06-50	
			" 6 "	0-06-50	
			" 7 "	0-03-00	
			66-भाग	0-45-00	
			60-भाग	0-06-75	जी.पी.
			6-7 भाग	0-23-50	
			13-2 भाग	0-08-00	
			" 3 "	0-04-00	
			172-भाग	0-02-75	जी.पी.
			16-1 भाग	0-13-75	
			" 2 "	0-10-00	
			" 3 "	0-25-25	
			171-2 भाग	0-07-00	
			" 1 "	0-23-75	
				2-10-50	
				2-04-75	
				4-15-25	
			या ए.सी	10.26 1/2	

[सं. एल०-14016/14/93-जी. पी.]

मधेनु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2817.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

erals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library Rajanmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**ULLAMPARRU TO VENDRA**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari	Palakollu	Chintaparru	91-A-Part	0-01-50	G.P.
			91-B-Part	006-00	
			91-C-Part	0-01-00	G.P.
			188-Part	0-14-50	
			187-Part	0-04-00	G.P.
			186-1-Part	0-10-00	
			186-2-Part	0-05-50	
			185-1-Part	0-00-25	
			185-2-Part	0-15-25	
			87-Part	0-15-75	
			84-Part	0-15-50	
			83-2C-Part	0-09-50	
			83-3-Part	0-09-50	
			82-1-Part	0-14-50	
			82-2-Part	0-09-25	
			81-2-Part	0-06-00	
			81-3-Part	0-04-75	
			81-4-Part	0-07-00	
			81-5-Part	0-05-50	
			179-2-Part	0-06-50	
			179-3-Part	0-02-00	
			178-1-Part	0-03-00	
			178-2-Part	0-04-50	
			79-Part	0-00-75	G.P.
			107-Part	0-16-50	G.P.
			176-Part	0-15-25	
			74-Part	0-01-00	
			73-Part	0-16-25	
			175-1-Part	0-05-50	
			175-3-Part	0-03-00	
			175-5-Part	0-06-50	
			175-6-Part	0-06-50	
			175-7-Part	0-03-00	



1	2	3	4	5	6
West Godabari (A.P.)	Pollakollu	Chentaparru	66-Part 60-Part 6-7-Part 13-2-Part 13-3-Part 172-Part 16-1-Part 16-2-Part 16-3-Part 171-2-Part 171-1-Part	0-45-00 0-06-75 0-23-50 0-08-00 0-04-00 0-02-75 0-13-75 0-10-00 0-25-25 0-07-00 0-23-75	G.P.     G.P.
Grand Total				4-15-25 Or AC	10.26- $\frac{1}{4}$ Cents

[No. L-14016/14/93-G.P.]

Sd/

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का०मा० 2818.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए ऊल्लमपारु-वेंडु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वशात् कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि०, के०जी० बसीन प्रोजेक्ट, 29-7/1/3/1 राजमंड़ी 533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## ऊल्लमपारु-वेंडु गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जमपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न०	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गौदवरी	पल्लकोल्लू	कापारूरु	371-2 भाग 373-1 भाग 373-2 भाग 374-1 भाग 374-2 भाग	0-01-50 0-15-00 0-01-00 0-07-50 0-07-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी गोदावरी	पल्लकोलु	कायवरम	374-8 भाग	0-06-50	
			374-9 भाग	0-01-00	
			369-2 भाग	0-09-75	
			375-1 भाग	0-08-00	
			368-भाग	0-20-25	
				0-78-00 or AC.1.93 cents	

[स० एल-14016/14/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2818.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

ral Piplines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

## SCHEDULE

## GAS PIPE LINE PROJECT

## ULLADIPARRU - VENDRA

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari	Palacollu	Kapavarami	371-Part	0-01-50	
			373-1-Part	0-15-00	
			373-2-Part	0-01-00	
			374-1-Part	0-07-50	
			374-2-Part	0-07-50	
			374-8-Part	0-06-50	
			374-9-Part	0-01-00	
			369-2-Part	0-09-75	
			375-1-Part	0-08-00	
			368-Part	0-20-25	
			Total	0-78-00 Or 1.93 AC	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का० आ० 2819.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए ऊल्लूपरू से बीन्डू पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्शते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि०, के०जी बसीन प्रोजेक्ट, 29 7 1/3/1 राजमंड़ी 533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

ऊल्लूपरू से वेन्डू गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरी (आ०प्र०)	पल्लकोल्लू	इंटगवक्षम	39-भाग	0-03-50	
			38-2 भाग	0-06-00	
			38-4 भाग	0-14-00	
			37-1 भाग	0-07-50	
			37-2 भाग	0-06-50	
			35-1 भाग	0-07-00	
			35-2 भाग	0-07-00	
			35-3 भाग	0-05-00	
			35-5 भाग	0-00-50	
			36-6 भाग	0-05-50	
			34-1 भाग	0-11-50	
			34-2 भाग	0-10-00	
			30-1 भाग	0-03-00	
			30-3 भाग	0-25-50	
			28-1 भाग	0-18-00	
			28-2 भाग	0-01-00	
			28-3 भाग	0-01-00	
			28-4 भाग	0-20-00	
			28-5 भाग	0-01-50	
			22-1 भाग	0-18-00	
			22-2 भाग	0-08-00	
			21-भाग	0-15-50	
			20-1 भाग	0-05-50	
			20-2 भाग	0-05-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पल्लिकोल्सू	अंगवक्षम	20-3 भाग	0-09-00	
			59-भाग	0-06-00	जीपी
			60-भाग	0-00-50	
			94-1 भाग	0-30-00	
			94-2 भाग	0-02-50	जीपी
			112-भाग	0-38-00	
			90-2 भाग	0-21-00	
			90-1 भाग	0-02-50	
			88-1 भाग	0-30-00	
			115-2 भाग	0-18-00	
			116- भाग	0-31-00	
			117-2 भाग	0-16-50	
			84-1 भाग	0-19-50	
			139-1 भाग	0-01-50	
			139-2 भाग	0-11-50	
			139-3 भाग	0-14-00	
			140-2 भाग	0-11-00	
			140-3 भाग	0-02-50	जीपी
			141-2 भाग	0-09-50	
			142-2 भाग	0-20-50	
			142-3 भाग	0-10-00	
			182-भाग	0-13-00	
			181-2 भाग	0-10-00	
			189-1 भाग	0-27-00	
			189-2 भाग	0-09-00	
			188-1 भाग	0-23-00	
			191-भाग	0-02-50	
			190-भाग	0-03-00	जीपी

योग 5-99-00

Or Ac 14.80 CENTS

[सं० एल-14016/14/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2819.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

erals pipelines (Acquisition of Right of Users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**ULLAMPARRU TO VENDRA**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Palakollu	Srungavruksham	39 Part	0-03-50	G.P.
			38-2-Part	0-06-00	
			38-4-Part	0 14-00	
			37-1 Part	0 07-50	
			37-2 Part	0 06-50	
			35-1 Part	0 07-00	
			35-2-Part	0 07-00	
			35-3 Part	0 05-00	
			35-5 Part	0 00-50	
			35-6 Part	0 05-50	
			34-1 Part	0 11-50	
			34-2 Part	0 10-00	
			30-1 Part	0 03-00	
			30-2 Part	0 25-50	
			28-1 Part	0 18-00	
			28-2 Part	0 01-00	
			28-3 Part	0 01-00	
			28-4 Part	0 20-00	
			28-5 Part	0 01-50	
			22-1 Part	0 18-00	
			22-2 Part	0 08-00	
			21-Part	0 15-50	
			20-1 Part	0 05-50	
			20-2 Part	0 05-50	
			20-3 Part	0 09-00	
			59-Part	0 06-00	G.P.
			60-Part	0 00-50	
			94-1 Part	0 30-00	G.P.
			94-2 Part	0 02-50	
			Total	2-54-50	
			112 Part	0 38-00	
			90-2-Part	0 21-00	
			90-1-Part	0 02-50	
			88-1-Part	0 30-00	
			115-2 Part	0 18-00	
			116-Part	0 31-00	
			117-2 Part	0 16-50	
			84-1 Part	0 19-50	
			139-1 Part	0 01-50	
			139-2 Part	0 11-50	
			139-3 Part	0 14-00	
			140-2 Part	0 11-00	
			140-3-Part	0 02-50	G.P.
			141-2-Part	0 09-50	
			142-2-Part	0 20-50	
			142-3-Part	0 10-00	
			182-Part	0 13-00	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Palakollu	Srongavruksham	181-2-Part 189-1-Part 189-2-Part 188-1-Part 191-Part 190-Part	0-10-00 0-27-00 0-09-00 0-23-00 0-02-50 0-03-00	G.P
Grand Total				5-99-00	
OR AC 14-80-Cents					

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का०आ० 2820.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए उल्लम्पई-वेंडू पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि०, के०जी० बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंडी-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

## उल्लम्पई-वेंडू

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न०	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदवरी	पल्लकोल्लू	वेंडू	52-भाग	0-08-00	जीपी
			74-1 भाग	0-01-00	
			74-3 भाग	0-10-00	
			74-4 भाग	0-09-50	
			75-भाग	0-17-50	
			73-भाग	0-05-00	जीपी
			69-1B भाग	0-00-50	
			72-भाग	0-01-50	जीपी

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी गोदावरी	पल्लिकोल्तू	वेन्ड्रा	70-1 भाग	0-14-00	
			70-2A भाग	0-20-00	
			71-1 भाग	0-25-00	
			91-भाग	0-18-00	
			90-भाग	0-18-00	
			89-A-भाग	0-16-00	
			94-1 भाग	0-09-00	
			94-2 भाग	0-04-50	
			94-3 भाग	0-04-00	
			94-4 भाग	0-03-50	
			95-12 भाग	0-01-50	
			88-2 भाग	0-01-00	
			88-3 भाग	0-07-50	
			88-4 भाग	0-09-50	
			88-5 भाग	0-08-00	
			88-6 भाग	0-07-00	
			87-1A भाग	0-13-50	
			87-2A भाग	0-11-50	
			86-2A भाग	0-07-50	
			86-3A भाग	0-03-00	
			86-4A भाग	0-09-00	
			190-2 भाग	0-01-50	
			192-1A भाग	0-16-00	
			192-2 भाग	0-09-00	
			192-3 भाग	0-09-50	
			195-5 भाग	0-05-00	
			195-6 भाग	0-05-00	
			196-7 भाग	0-03-50	
			196-2 भाग	0-01-00	
			Total		

[सं० एल-14016/14/93-जीपी]

अर्घेदु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2820.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

ral pipelines (Acquisition of Right of Users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-522104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT

Ullamparru-to-Vendra

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Palakollu	Vendra	52-Part	0-08-00	G. P.
			74-1 Part	0-01-00	
			„ 3 Part	0-10-00	
			„ 4 Part	0-09-50	
			75-Part	0-17-50	G. P.
			73-Part	0-05-00	
			69-1B Part	0-00-50	
			72-Part	0-01-50	
			70-1Part	0-14-00	G. P.
			„ 2A „	0-20-00	
			71-1 Part	0-25-00	
			91-Part	0-18-00	
			90-Part	0-18-00	
			89-A Part	0-16-00	
			94-1Part	0-09-00	
			„ 2 „	0-40-50	
			„ 3 „	0-40-00	
			„ 4 „	0-03-50	
			95-12 Part	0-01-50	
			88-2 Part	0-01-00	
			„ 3 „	0-07-50	
			„ 4 „	0-09-50	
			„ 5 „	0-08-00	
			„ 6 „	0-07-00	
			87-1A Part	0-13-50	
			2A „	0-11-50	
			86-2A Part	0-07-50	
			3A „	0-03-00	
			„ 4A „	0-09-00	
			190-2 Part	0-01-50	
			192-1A Part	0-16-00	
			„ 2 „	0-09-50	
			„ 3 „	0-09-50	
			195-5 Part	0-05-00	
			„ 6 „	0-05-00	
			„ 7 „	0-03-50	
			„ 2 „	0-01-00	
			Total	3-15-00 or AC	7-78 Cents

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का० आ० 2821.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए उल्लम्पारु-वेन्ड्र पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विद्यमान सन्तान है।

और यह भी अनुभव करती है कि कार्य के लिए इसके साथ संलग्न धिवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।



अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि० के०जी० ब्रसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1, राजमंडी-533 104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

उत्पत्ति-क्षेत्र

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	पालकोल्लु	लन्कलकोडेरु	251-1 भाग	0-11-50	
			251-3 भाग	0-06-00	
			251-4 भाग	0-01-50	
			252-2 ए भाग	0-16-50	
			252-2 बी भाग	अ-00-50	
			280-भाग	0-02-75	जीपी
			279-भाग	0-22-75	
			283-2 भाग	0-02-50	जीपी
			290-15 भाग	0-05-50	
			290-14 भाग	0-04-50	
			290-16 भाग	0-09-50	
			289-भाग	0-02-50	जीपी
			286-1 भाग	0-22-00	
			286-5 भाग	0-03-50	
			287-6 भाग	0-00-50	
			287-7 भाग	0-03-50	
			287-11 भाग	0-17-00	
			321-भाग	0-03-00	जीपी
			322-1 भाग	0-16-50	
			322-7 भाग	0-07-00	
			322-8 भाग	0-09-50	
			323-2 भाग	0-24-50	
			325-भाग	0-02-50	जीपी
			326-2 भाग	0-21-75	
			327-2 भाग	0-17-00	
			327-6 भाग	0-15-00	
			332-1 भाग	0-11-00	
			332-2 भाग	0-00-50	

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी	पालकोल्लु	लन्कालकोडे रु	679-1 भाग	0-10-00	
			679-2 भाग	0-01-00	
			680-भाग	0-11-50	
				2-83-25या 6.99½ एकड़	

[सं एल-14016/14/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2821.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajamundry-533104, Andhra Pradesh;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Ullamparru-to-Vendra

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Palakollu	Lankalkoderu	251-1Part	0-11-50	
			— 3Part	0-6-00	
			— 4 Part	0-01-50	
			252-2A Part	0-16-50	
			— 2B Part	0-00-50	
			280-Part	0-02-75	G. P.
			279-Part	0-22-75	
			283-2Part	0-02-50	G. P.
			290-15Part	0-05-50	
			—14Part	0-04-50	
			—16Part	0-09-50	
			289-Part	0-02-50	G. P.
			286-1Part	0-22-00	
			—5Part	0-03-50	
			287-6Part	0-00-50	
			—7Part	0-03-50	
			—11Part	0-17-00	
			321-Part	0-03-00	G. P.
			322-1Part	0-16-50	
			—7Part	0-07-00	
			—8Part	0-09-50	
			323-2Part	0-24-50	
			325-Part	0-02-50	G. P.
			326-2Part	0-21-75	

1	2	3	4	5	6
West Godavari	Palakollu	Lankalakoderu	327-2Part ---6Part 332-1Part ---2Part 679-1Part ---2Part 680-Part	0-17-00 0-15-00 0-11-00 0-00-50 0-10-00 0-01-00 0-11-30	
Total			2-83-25	or AC 6-99½	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का०ग्रा०2822. —जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए उल्लम्पल्लु-वेन्डू पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उभ पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि० के०जी० बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूची

गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

उल्लम्पल्लु-वेन्डू

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पालकोल्लू	शिवदेवुनि चिक्काल	365-1 भाग	0-03-50	जीपी
			365-2 भाग	0-23-50	
			365-3 भाग	0-02-50	
			364-1 भाग	0-07-75	
			364-2 भाग	0-13-25	
			363-भाग	0-33-25	जीपी
			362-भाग	0-11-50	
			361-भाग	0-02-50	
			360-2 भाग	0-10-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पल्लकल्लु	सिवदेरुनि चिक्काल	360-3 भाग	0-18-00	
			359-भाग	0-04-00	
			358-भाग	0-27-50	
			12-भाग	0-02-00	जीपी
			9-2 भाग	0-23-75	
			10-1 भाग	0-00-50	
			4 भाग	0-11-50	
योग				1-86-00 या एकड़ 4.59 सेंट	
[(सं० एल-14016/14/93-जीपी)]					
अर्धेन्दु सेन, निदेशक					

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2822.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Orp. Gowthami Library, Rajamundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

#### SCHEDULE

#### GAS PIPE LINE PROJECT Ullamparru—Vendra

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Pallakallu	Sivaderuni chikkala	365-1Part	0-03 50	G.P.
			365-2Part	0-23-50	
			365-3Part	0-02 50	
			364-1Part	0-07-75	
			364-2Part	0-13-25	G.P.
			363-Part	0-33-25	
			362-Part	0-11-50	
			361-Part	0-02-50	
			360-2Part	0-01-00	G.P.
			360-3Part	0-18-00	G.P.
			359-Part	0-04-00	
			358-Part	0-27-50	
			12-Part	0-02-00	
			9-2Part	0-23-75	
			10-Part	0-00-50	
			4-Part	0-11-50	
Total			1-86-00 or	OR AC 4.59 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

क्रा० आ० 2823.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए उल्लम्पर्ड-वेस्ट्र पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विद्यमान है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है :

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है.

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिगुचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन विछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि०, के०जी० बर्सीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, राजमंड्री-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

उल्लम्पर्ड-वेस्ट्र

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण			
पश्चिम गोदावरि	पालनेरु	दमगुलूरु	57-भाग	0-04-50	जीपी			
			55-3 भाग	0-12-00				
			53-भाग	0-07-50				
			54-1 भाग	0-15-50				
			54-2 भाग	0-11-50				
			51-भाग	0-01-00				
			67-1 भाग	0-08-50				
			224-भाग	0-26-50				
			91-2 भाग	0-05-50				
			91-3 भाग	0-35-00				
			92-भाग	0-02-50	जीपी			
			223-1 भाग	0-46-50				
			19-2 भाग	0-03-50				
			19-1 भाग	0-09-50				
			18-2 भाग	0-05-50	जीपी			
			18-3 भाग	0-25-00				
			221- भाग	0-02-50				
			15-2 भाग	0-17-00				
			14-2 भाग	0-08-00				
			12-2 भाग	0-08-50				
			12-1 भाग	0-11-50				
			11-2 भाग	0-31-00				
						योग	2-98-50	
						या		
							AC	7.37 CENTS

[मं० एल-14016/14/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक,

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2823.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

als Pipelines (Acquisition) of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Ullamparru to Vendra**

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Paalkoilu	Dagguluru	57-Part	0-04-50	G.P.
			55-3Part	0-12-00	
			53-Part	0-07-50	
			54-1 Part	0-15-50	
			„ 2 „	0-11-50	
			51-Part	0-01-00	
			67-1 Part	0-08-50	
			224-Part	0-26-50	
			91-2Part	0-05-50	
			„ 3 „	0-35-00	
			92-Part	0-02-50	G.P.
			223-1 Part	0-46-50	
			19-2 Part	0-03-50	
			„ 1 „	0-09-50	
			18-2 Part	0-05-50	
			„ 3	0-25-00	G.P.
			221-Part	0-02-50	
			15-2 Part	0-17-00	
			14-Part	0-08-00	
			12-2 Part	0-08-50	
			„ 1 „	0-11-50	
			11-Part	0-31-00	
			Total	2-98-50	
				OR	
				AC 7-37 Cents.	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का०आ० 2824.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए उल्लम्पार्लू-वेन्द्र पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है :

वशत कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर पाइप लाइन विछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस आथरिटी आफ इण्डिया लिमि०, के०जी० बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, राजमंड्री-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है :

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### ऊलम्पूर-बैन्डू

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे / एकड़ में)	विवरण				
पश्चिम गोदावरी	वीरवरम	रायकुडुरु	499-2 भाग	0-09-50	जीपी				
			498-4 भाग	0-11-50					
			498-3 भाग	0-26-00					
			498-1 भाग	0-21-50					
			496-भाग	0-11-50					
			495-9 भाग	0-15-00					
			495-14 भाग	0-02-00					
			495-7 भाग	0-03-00					
			495-6 भाग	0-01-25					
			495-1 भाग	0-00-25					
			490-2 भाग	0-05-50					
			490-1 भाग	0-16-25					
			491-1 भाग	0-12-00					
			491-2 भाग	0-00-25					
			491-3 भाग	0-03-50					
			484-4 भाग	0-07-25					
			484-3 भाग	0-08-00					
			484-2 भाग	0-08-00					
			477- भाग	0-05-50	जीपी				
			478-4 भाग	0-00-25					
			478-3 भाग	0-13-50					
			478-2 भाग	0-08-00					
			480-2 भाग	0-02-00					
			480-1 भाग	0-07-00					
			479-1 भाग	0-20-00					
						योग	2-18-50		
						या			
						OR AC	5.40	CENTS	

[सं० एल-14016/14/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2824.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Ullamparru to Vendra pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine-

als Pipelines (Acquisition) of Right of Users in the Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1. Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by Legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Ullamparru to Vendra**

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Veeravasaram	Rayakuduru	499-2B Part	0-09 50	G.P.
			498-4 Part	0-11-50	
			„ 3 „	0-26-00	
			„ 1Part	0-21-50	
			496-Part	0-11-50	
			496-9Part	0-15-00	
			„ 14 „	0-02-00	
			„ 7 „	0-03-00	
			„ 6 „	0-01-25	
			„ 1 „	0-00-25	
			490-2 Part	0-05-50	G.P.
			„ 1 „	0-16-25	
			491-1 Part	0-12-00	
			„ 2 „	0-00-25	
			„ 3 „	0-03-50	
			484-4 Part	0-07-25	
			„ 3 „	0-08-00	
			„ 2 „	0-08-00	
			477-Part	0-05-50	
			478-4 Part	0-00-25	
			„ 3 „	0-13-50	
			„ 2 „	0-08-00	
			480-2 Part	0-02-00	
			„ 1 „	0-07-00	
			479-1 Part	0-20-00	
			Total	2-18-50	OR AC5.40 Cents

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

क्र० आ० 2325.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोपिप म पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए तनुक से गौतमि सव्ल्नहस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस पवारिणो आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ सलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;



अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एाद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बगलें कि जवत भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिमूर्चना की तारीख में 21 दिनों के भीतर भविष्य पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस आथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, के.जी.सी. गौथमी प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमन्ट्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### तनुकु से गौथमी सान्त्वन्टम

जनपद .	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे / एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	तनुकु	तेतलि	327-भाग	0-01-50	
			325-7 भाग	0-07-50	
			377-1 भाग	0-04-00	
			377-2 भाग	0-02-00	
			377-3 भाग	0-01-00	
			374-भाग	0-04-00	जीपी
			326-4 बी भाग	0-02-00	जीपी
			326-6 ए भाग	0-02-00	
			326-122 ए भाग	0-01-25	
			326-133 ए भाग	0-01-00	
				0-29-25	073

[सं० एल-14016/14/93-जीपी]

अर्थन्तु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2825.-Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Tanuku to Gowthami Solvents pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner

## SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT  
Tanuku to Gowthani Solvent

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	A.P. Tapuku	Tetali	327-Part	0-01-50	G.P.
			325-7 Part	0-07-50	
			377-1 Part	0-04-00	
			„ 2 „	0-02-00	
			„ 3 „	0-01-00	
			374-Part	0-04-00	G.P.
			326-4B Part	0-02-00	
			„ 6A „	0-02-00	
			„ 12A „	0-01-25	
			„ 13A „	0-04-00	
				0-29-25 OR 0 73 Cents.	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director,

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का० आ० 2826.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए तनुकु से गौतमि सालन्वस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है :

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति मक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि० के०जी० बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, राजमंड़ी-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह बिगेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

तनुकु से गौतमि सालवान्टस

जन्पद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	तनुकु	सज्जापुरम	2-5 भाग	0-03-50	
(आन्ध्र प्रदेश)			2-6 भाग	0-11-50	

4	5
2-8 भाग	0-02-00
1-2 भाग	0-02-00
1-3 भाग	0-02-00
1-5 भाग	0-03-00
1-7 भाग	0-02-50
1-6 भाग	0-03-25
1-8 भाग	0-04-75
1-9 भाग	0-02-50
1-10 भाग	0-00-50
1-11 भाग	0-03-25
1-12 भाग	0-01-00
1-13 भाग	0-01-00
12-1 भाग	0-02-75
12-2 भाग	0-01-00
3-भाग	0-04-00 जीपी
0-50-50 और एमी 3.25 (सेट्स)	

[सं० एल-14016/14/93-जी०पी०]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2826.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Tanuku to Gowthami Solvents pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

## GAS PIPE LINE PROJECT

## Tanuku to Gowthami Solvents

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Tanuku	Sajjapuram	2-5 Part	0-03-50	
			2-6 ..	0-11-50	
			2-8 ..	0-02-00	
			1-2 ..	0-02-00	
			3 ..	0-02-00	
			5 ..	0-03-00	
			7 ..	0-02-50	
			6 ..	0-03-25	
			8 ..	0-04-75	

	4	5	6
1 9 Part	0-02-50		
„ 10 „	0-00-50		
„ 11 „	0-03-25		
„ 12 „	0-00-00		
„ 13 „	0-01-00		
12-1 Part	0-02-75		
2	0-01-00	G.P.	
3-Part	0-04-00		
Total	0-50-50	OR AC 1.25 Cetns.	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2827 :—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रो-लियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए तनुकु से गौतमि साब्लन्ट्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस-अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के .जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजसंज्ञी 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
तनुकु से गौतमि साब्लन्ट्स

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	चित्रण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	उन्मज्जरम	चिक्कटाम	111-भाग	0-02-00	जि. पि
			112 2सी भाग	0-04-00	
			„ 2 बी „	0-01-00	
			„ 3 „	0-07-50	
			„ 4	0-03-50	
			„ 5 „	0-02-00	
			109-7 भाग	0-01-50	
			109-8-भाग	0-03-50	
			113-4-भाग	0-03-00	
			113-3-भाग	0-03-00	
			113-7-भाग	0-06-00	
			108-भाग	0-11-50	

4	5
107-5 भाग	0-03-75
„ 4 „	0-00-25
„ 6 „	0-04-50
„ 3 „	0-00-50
106-2 बी भाग	0-05-50
„ 4 बी „	0-04-00
„ 7 „	0-03-00
122-1 भाग	0-06-75
„ 2 „	0-05-50
„ 3 ए „	0-01-00
„ 3 बी „	0-00-25
योग	0-83-50
	or A.C 2-00 Cents

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

अर्थेन्दु रेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2827 --Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Tanuku to Gowthami Solvents pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.,

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT  
Tanuku To Gowthami Solvents

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Undrajavaram	Chivaram	111-Part	0-02-00	G.P.
			112-2C Part	0-04-00	
			2B „	0-01-00	
			„ 3 „	0-07-50	
			„ 4 „	0-03-50	
			„ 5 „	0-02-00	
			109-7 Part	0-01-50	
			„ 8 „	0-03-50	
			113-4 Part	0-03-00	
			„ 3 „	0-03-00	
			„ 7 „	0-06-00	
			108-Part	0-11-50	
			107-5 Part	0-03-75	

4	5
107-4 Part	0-00-25
„ 6 „	0-04-50
„ 3 „	0-00-50
106-2B-Part	0-05-50
„ 4B „	0-04-00
„ 7 „	0-03-00
122-1 Part	0-06-25
„ 2 „	0-05-50
„ 3A „	0-01-00
„ 3B „	0-00-25
Total	0-83-50 OR AC 2-06 Cents.

[No. L-14016/14/93-G.P]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2828 :—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए तनुकु से गौतमि सालवन्दस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है,

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है,

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है,

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7/1-3/1 राजमंजूरी 533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है,

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

तनुकु से गौतमि सालवन्दस

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	उन्नुजवरम	के. सवरम	32-5 भाग	0-00-50	जि.पी.
			„ 8 „	0-01-00	
			31-8 भाग	0-16-75	
			„ 9 „	0-01-00	
			29-7 सी भाग	0-06-25	
			„ 7 बी „	0-03-25	
			„ 7 ए „	0-03-25	

	4	5	6
29-6 भाग	0-01-25	जि.पी.	
„ 1 „	0-01-50		
21-4 भाग	0-07-00		
„ 3 „	0-03-00		
„ 2 „	0-06-00		
„ 1 „	0-01-25		
20-1 भाग	0-07-50		
„ 2 „	0-12-50		
19-1 भाग	0-12-00		
„ 4th „	0-08-50		
10-1 भाग	0-05-00		
„ 2 „	0-05-50		
„ 3 „	0-11-75		
4-भाग	0-01-50	जि.पी.	
3-भाग	0-17-50		
2-2 भाग	0-06-00		
„ 3 „	0-13-50		
योग	1-53-25		
या AC 3.77 Cents			

[सं. एल-14016/14/93-जी पी

मधुसेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2828.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Tanuku to Gowthami Solvents pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1|3|1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

GAS PIPE LINE PROJECT  
Tanuku to Gowthami Solvents

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari A.P.	Undrajavaram	K. Savraram	32-5 Part	0-00-50	
			„ 8 „	0-01-00	G.P.
			31-8 Part	0-16-75	
			„ 9 „	0-01-00	
			29-7C Part	0-06-25	
			„ 7B „	0-03-25	
			„ 7A „	0-03-25	

	4	5	6
29-6 Part		0-01-25	G.P.
„ 1 „		0-01-50	
21-4 Part		0-07-00	
„ 3 „		0-03-00	
„ 2 „		0-06-00	
„ 1 „		0-01-25	
20-1 Part		0-07-50	
„ 2 „		0-12-50	
19-1 Part		0-12-00	
„ 4 „		0-08-50	
10-1 Part		0-05-00	
„ 2 „		0-05-50	
„ 3 „		0-11-75	
4-Part		0-01-50	G.P.
3-Part		0-17-50	
2-2 Part		0-06-00	
„ 3 „		0-13-50	
Total		1-53-25	Gr Ac. 3.77 1/2 Cents.

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2829 :— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस खाने के लिए तनुकु से गौतमि साब्लन्ट्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है,

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है,

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है,

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7/1-3/1 राजमुंड़ी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज तथा सकता है,

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

तनुकु से गौतमि साब्लन्ट्स

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोवावारि	तनुकु	तनुकु वेमवरम	75-1 ए भाग	0-50-50	
आन्ध्र प्रदेश			„ 1 बी „	0-03-50	
			74-2 भाग	0-06-00	



			4	5
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	तनुकु	तनुकु वेमवरम	71-2 "	0-01-00
			" 3 "	0-04-00
			" 4 "	0-04-00
			69-3 "	0-07-50
			72- "	0-04-50
			68- "	0-02-50 जी.पी.
			61- "	0-01-50 जी.पी.
			60- "	0-07-50
			59-1 "	0-06-00
			53-2 "	0-14-00
			" 3 "	0-05-50
			52-6 "	0-10-50
			35- "	0-01-00 जी.पी.
			27-1 ए "	0-00-50
			" 1 बी "	0-13-00
			" 2 "	0-06-00
			" 3 "	0-05-00
			" 4 "	0-04-00
			18- "	0-02-00
			15-4 भाग	0-14-25
			16-1 "	0-13-00
			7 "	0-00-25
			4 "	0-01-50
			8 "	0-05-00
			9-3 "	0-01-00
			" 4 "	0-05-50
			" 5 "	0-05-00
			4-1 "	0-08-00
			" 2 "	0-03-50
			" 3 "	0-00-50
			" 4 "	0-04-50
			" 5 "	0-05-50
			2-3 "	0-00-50
			कुल योग	1-83-00 या एसी 4.02 1/2सेंट

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2829.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Tanuku to Gowthami Solvent pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Tanuku to Gowthami Solvent**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect /Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Tanuku	Tanuku Vemavaram	75-1A Part	0-05-50	
			75-1B	0-03-50	
			74-2	0-06-00	
			71-2	0-01-00	
			71-3	0-04-00	
			71-4	0-04-00	
			69-3	0-07-50	
			72-Part	0-04-50	
			68 Part	0-02-50	
			61 Part	0-01-50	
			60 Part	0-07-50	
			59-1 Part	0-06-00	
			53-2 Part	0-14-00	
			53-3 Part	0-05-50	
			52-6 Part	0-10-50	
			35-Part	0-01-00	
			27-1A Part	0-00-50	
			1B Part	0-13-00	
			2 Part	0-06-00	
			3 Part	0-05-00	
			4 Part	0-04-00	
			18-Part	0-02-00	
			15-4 Part	0-14-25	
			16-1 Part	0-13-00	
			7 Part	0-00-25	
			4 Part	0-01-50	
			8 Part	0-05-00	
			9-3 Part	0-01-00	
			4 Part	0-05-50	
			5 Part	0-05-00	
			4-1 Part	0-08-00	
			4-2 Part	0-03-50	

1	2	3	4	5	6
			4-3 Part	0-00-50	
			4-4 Part	0-04-50	
			4-5 Part	0-05-50	
			2-3 Part	0-00-50	
			Total	1-83-00 Or Ac 4-52 1/2 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2830:- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए तनुकु से गौतमि सल्वेन्ट्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथा- रिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है,

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है,

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्त कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस यथा रिटी आफ इण्डिया लिमि., के.जी. बगीच प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंजूरी 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विश्व व्यावसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

तनुकु से गौतमि सल्वेन्ट्स

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	तनुकु	तनुकु	376-भाग	0-04-00	
			380-5 बी भाग	0-05-50	
			„ 3 बी „	0-10-50	
			„ 1 ए „	0-01-00	जी.पी.
			379-2 भाग	0-02-50	जी.पी.
			„ 1 बी 2 „	0-01-00	जी.पी.
			„ 1 ए „	0-00-75	
			543-5-भाग	0-30-00	
			„ 4 „	0-03-00	
			„ 2 „	0-04-00	

4	5
„ 1 डी भाग	0-04-50
545-2 भाग	0-07-50
„ 7 „	0-01-00
„ 6 „	0-05-50
„ 5 „	0-05-50
„ 3 „	0-03-50
„ 1 „	0-05-00
547-5 भाग	0-01-00
टोटल	0-75-75 या एसी 1-87½ सेंट

[सं. एन-14016/14/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2830.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Tanuku to Gowthami Solvents pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd., K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**GAS PIPE LINE PROJECT**  
Tanuku-To-Gowthami Solvents

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (Andhra Pradesh)	Tanuku	Tanuku	376-Part	0-04-00	
			380-3B Part	0-05-50	
			380-3B Part	0-10-50	
			380-1A Part	0-01-00	G.P.
			379-2 Part	0-02-50	G.P.
			379-1B2 Part	0-01-00	G.P.
			379-1A Part	0-00-75	
			543-5 Part	0-10-00	
			543-4 Part	0-03-00	
			543-2 Part	0-04-00	
			543-1D Part	0-04-50	
			545-2 Part	0-07-50	
			545-7 Part	0-01-00	
			545-6 Part	0-05-50	
			545-5 Part	0-05-50	
			545-3 Part	0-03-50	
			545-1 Part	0-05-00	
			547-5 Part	0-01-20	
			Total	0-75-75	
				Or AC 1-87 1/2 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. अ. 2831 :- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रो-लियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए दोम्मेरु-एन सी एल इंडस्ट्रीज दोम्मेरु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार करना आवश्यक है,

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है,

बताते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है,

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्विष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

## अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
दोम्मेरु-एन सी एल इंडस्ट्रीज, दोम्मेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे) (एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	कोव्वूरु	दोम्मेरु	520 भाग	0-18-50	जी.पो.
			519 „	0-19-50	
			753 „	0-10-00	
			619 „	0-06-50	
			618 „	0-27-00	
			615 „	0-20-00	
			जोड़	1-01-50 या एकड़ 2.51 सेंट	

[सं. एल-14016/14/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2831.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Dommeru to NCL Industry in Dommeru (Village) pipeline to be laid by the Gas Authority of India;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of uses in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**

Dommeru to NCL Industry [in Dommeru (V)]

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (Andhra Pradesh)	Kovvuru	Dommeru	520-Part	0-18-50	G.P.
			519 Part	0-19-50	
			573 Part	0-10-00	
			619 Part	0-06-50	
			618 Part	0-27-00	
			615 Part	0-20-00	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2832:—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए कोव्वूर आरिकेवल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता के अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ;

वर्णित कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति समक्ष प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.सी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/1 राजमुन्नी 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

कोव्वूर-आरिकेवल

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आं. प्र.)	कोव्वूर	कोव्वूर	371-भाग	0-09-50	
			234-1 भाग	0-20-00	
			234-2 भाग	0-12-00	
			235-1 भाग	0-08-00	
			235-2 भाग	0-10-00	
			243-2 भाग	0-02-00	
			244- भाग	0-47-50	
			233- भाग	0-01-00	
			245-2 ए भाग	0-02-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोंदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	कोव्वूरु ज़र्रा	कोव्वूरु ज़र्रा	245-2 बी भाग	0-29-00	
			228-1 ,,	0-10-00	
			187-1 ,,	0-12-00	
			249-1 ,,	0-22-00	
			250-1 ए ,,	0-02-00	जी. पी.
			250-1 सी ,,	0-32-50	
			250-2 ,,	0-30-50	
			83 ,,	0-03-00	जी. पी.
			103-1 ए ,,	0-00-50	जी. पी.
			103-3 बी ,,	0-18-50	
			104-1 ,,	0-24-50	
			140-2 ,,	0-00-50	
			108-2 ,,	0-22-50	
			109-2 ए ,,	0-17-00	
			110	0-34-00	
			111-1 ए ,,	0-02-00	
			111-1 बी ,,	0-45-00	
			115	0-07-50	

जोड़

4-25-50 या एसी 10-52 सेंट्स

[सं. एल-14016/14/93 जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2832.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Kovvuru to Arikarevula pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Kovvuru to Arikarevula

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Kovvuru	Kovvuru	371-Part	0-09-50	
			234-1 Part	0-20-00	
			234-2 Part	0-12-00	
			235-1 Part	0-05-00	
			235-2 Part	0-10-00	
			243-2 Part	0-02-00	
			244-Part	0-47-50	





New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2833.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Kavvuru to Arikalova pipeline is to be laid by the Gas Authority of India;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Kovvuru to Arikarevula**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Kovvuru	Arikolava	149-1B2 Part	0-11-50	
			152-1 Part	0-33-00	
			Total	0-44-50 Or AC 1.10 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2834.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए चिन्तपर्वट्टेपि बगारीस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार) ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिवचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-13/1 राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
चिन्तपर्वट्टे. वि. बगारीस

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी	पालकोल्लु	चित्तपुरु	188 भाग	0.01.25	जी. पी.
			170 भाग	0.09.00	

	4	5	6
90 भाग		0.02.25	
92 भाग		0.20.00	
96-1ए भाग		0.02.50	
96-1बी भाग		0.05.25	
96-1सी भाग		0.05.50	
96-2 ए भाग		0.04.50	
96-3ए भाग		0.03.00	
96-3बी भाग		0.01.50	
97-1 भाग		0.13.75	
97-3 ए भाग		0.04.75	
122-1 भाग		0.13.50	
122-2 ए भाग		0.03.50	
122-2 बी भाग		0.10.00	
125-1ए भाग		0.05.25	
125-2 भाग		0.01.75	जी. पी.
125-3 ए भाग		0.37.00	
125-4 भाग		0.03.75	
157-1ए भाग		0.03.25	
157-1 बी भाग		0.05.75	
157-1 सी भाग		0.10.00	
157-5 ए भाग		0.12.00	
157-5 बी भाग		0.08.00	
157-4 भाग		0.02.50	
157-6 भाग		0.03.50	
155-भाग		0.10.00	
156-1 भाग		0.12.00	
156-2 ए भाग		0.09.50	
कुल		2.24.50 ओ आर ए सी 5.55 सेंट	

[सं. एन-14016/14/93—जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2834.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Chinthaparru—A. P. Baggaries pipeline is to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Chinthaparru—A.P. Baggaries**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari	Palakollu	Chinthaparru	188-Part	0-01-25	G.P.
			170-Part	0-09-00	
			90-Part	0-02-25	
			92-Part	0-20-00	
			96-1A Part	0-02-50	
			96-1B Part	0-05-25	
			96-1C Part	0-05-50	
			96-2A Part	0-04-50	
			96-3A Part	0-03-00	
			96-3B Part	0-01-50	
			97-1 Part	0-13-75	
			97-3A Part	0-04-75	
			122-1 Part	0-13-50	
			122-2A Part	0-03-50	
			122-2B Part	0-10-00	
			125-1A Part	0-05-25	G.P.
			125-2 Part	0-01-75	
			125-3A Part	0-37-00	
			125-4 Part	0-03-75	
			157-1A Part	0-03-25	
			157-1B Part	0-05-75	
			157-1C Part	0-10-00	
			157-5A Part	0-12-00	
			157-5B Part	0-08-00	
			157-4 Part	0-02-50	
			157-6 Part	0-03-50	
			155-Part	0-10-00	
			156-1 Part	0-12-00	
			156-2A Part	0-09-50	
			Total		

[No. L 14016/14/93 G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

भा. आ. 2835.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवनि से तालुकु पाडा लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमि. के जी. वसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3 1 राजमंडी-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विज्ञापन रू से निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### पेरवलि से तनुकु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरि (आ. प्र.)	तनुकु	तनुकु	743-भाग	0.06.50	जी. पी.
			740-1डी भाग	0.27.00	
			740-2 बी भाग	0.19.50	
			737 1 बी भाग	0.09.00	
			737-2 भाग	0.05.00	
			734-2ए भाग	0.09.50	
			733-1 बी भाग	0.14.00	
			733-2 बी भाग	0.14.00	
			730-2 भाग	0.35.00	
			729-भाग	0.02.50	
			724-1 बी भाग	0.14.00	
			724-2 बी भाग	0.13.00	
			723-1 बी भाग	0.15.50	
			723-2बी भाग	0.02.50	
			723-3 भाग	0.15.50	
			459-1ए2 भाग	0.00.50	जी. पी.
			459-1बी2 भाग	0.16.00	
			459-2 बी भाग	0.09.50	
			459-3 बी भाग	0.10.50	
			460-2 बी भाग	0.14.00	
			461-1 भाग	0.01.50	
			461-2 भाग	0.18.00	
			462-2 भाग	0.18.50	
			474-2 भाग	0.21.50	
			473-1 भाग	0.01.50	
			473-3 भाग	0.09.00	
			475-7 भाग	0.07.00	
			444-भाग	0.03.00	
			438-2 भाग	0.17.00	
			439-4 भाग	0.12.50	
			439-5 भाग	0.12.50	
			440-1 भाग	0.10.50	

4	5	6
441-2 भाग	0.04.50	
437-1ए भाग	0.08.00	
437-1बी भाग	0.00.50	
384-2 भाग	0.09.50	
384-3 भाग	0.15.00	
384-5 भाग	0.09.50	
385-1 भाग	0.26.50	
376-भाग	0.44.50	
358-भाग	0.19.00	
359-1 भाग	0.09.50	
359-2 भाग	0.07.50	
356-2 भाग	0.09.00	
356-3 भाग	0.01.00	
357-1 भाग	0.25.50	
351-1 भाग	0.20.00	
351-2 भाग	0.22.00	
348-भाग	0.04.00	जी. पी.
336-1 भाग	0.25.00	
337-3 भाग	0.17.50	
339-भाग	0.22.50	
342-3 भाग	0.19.00	
341-1 भाग	0.18.00	
341-2 भाग	0.06.50	
341-3 भाग	0.00.50	
341-4 भाग	0.14.00	
343-4 भाग	0.26.50	
167-1 भाग	0.07.50	जी. पी.
172-9 भाग	0.30.50	
171-भाग	0.16.00	
174-भाग	0.02.50	जी. पी.
178-भाग	0.22.00	
181-2 भाग	0.22.00	
181-1 भाग	0.11.00	
180-भाग	0.19.00	
183-1 भाग	0.14.00	
185-4 भाग	0.08.00	
185-2 भाग	0.06.50	
184-भाग	0.00.50	
186-1 भाग	0.09.50	
187-भाग	0.17.00	
188-भाग	0.16.00	
246-भाग	0.54.00	
244-भाग	0.01.00	जी. पी.
245-भाग	0.05.50	जी. पी.

4	5	6
192-2 भाग	0.09.00	
216-भाग	0.03.00	जी. पी.
217-1 भाग	0.09.00	
217-2 भाग	0.14.50	
215-भाग	0-03-50	जी. पी.
204-1 भाग	0-23-00	
204-7 „	0-01-50	
205-3 भाग	0-24-50	
205-4 „	0-18-00	
295-5 „	0-10-00	
206-भाग	0-05-00	
	11-54-00	

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

मधुसेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2835.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Tanuku pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

## GAS PIPE LINE PROJECT

## Peravali to Tanuku

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (Andhra Pradesh)	Tanuku	Tanuku	743-Part	0-06-50	G.P.
			740-1D Part	0-27-00	
			740-2B Part	0-19-50	
			737-1B Part	0-09-00	
			737-2 B Part	0-05-00	
			734-2B Part	0-09-50	
			733-1B Part	0-14-00	
			733-2B Part	0-14-00	
			730-2 Part	0-35-00	

1	2	3	4	5	6
			729-Part	0-02-00	
			724-1B Part	0-14-00	
			724-2B Part	0-13-00	
			723-1B Part	0-15-50	
			723-2B Part	0-02-50	
			723-3 Part	0-15-50	
			459-1A2 Part	0-00-50	G.P.
			459-1B2 Part	0-16-00	
			459-2B Part	0-09-50	
			459-3B Part	0-10-50	
			460-2B Part	0-14-00	
			461-1 Part	0-01-50	
			461-2 Part	0-18-00	
			462-2 Part	0-18-50	
			474-2 Part	0-21-50	
			473-1 Part	0-01-50	
			473-3 Part	0-09-00	
			475-7 Part	0-07-00	
			444-Part	0-03-00	G.P.
			438-2 Part	0-17-00	
			439-4 Part	0-12-50	
			439-5 Part	0-12-50	
			440-1 Part	0-10-50	
			441-2 Part	0-04-50	
			437-1A Part	0-08-00	
			437-1B Part	0-00-50	
			384-2 Part	0-09-50	
			384-3 Part	0-15-00	
			384-5 Part	0-09-50	
			385-1 Part	0-26-50	
			376-Part	0-44-50	
			358-Part	0-19-00	
			359-1 Part	0-09-50	
			359-2 Part	0-07-50	
			356-2 Part	0-09-00	
			356-3 Part	0-01-00	
			357-1 Part	0-25-50	
			351-1 Part	0-20-00	
			351-2 Part	0-22-00	
			348-Part	0-04-00	G.P.
			336-1 Part	0-25-00	
			337-3 Part	0-17-50	
			339-Part	0-22-50	
			342-3 Part	0-19-00	
			341-1 Part	0-18-00	
			341-2 Part	0-06-50	
			341-3 Part	0-00-50	
			341-4 Part	0-14-00	
			343-4 Part	0-26-50	
			Total	4-20-50	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (Andhra Pradesh)	Tanuku	Tanuku	167-Part	0-07-50	G.P.
			172-9Part	0-30-50	
			171-Part	0-16-00	
			174-Part	0-02-50	
			178-Part	0-22-00	
			181-2 Part	0-22-00	
			181-1 Part	0-11-00	
			180-Part	0-19-00	
			183-1 Part	0-14-00	
			185-4 Part	0-08-00	
			185-2 Part	0 06-50	
			184-Part	0-00-50	
			186-1 Part	0-09-50	
			187-Part	0-17-00	
			188-Part	0-16-00	
			246-Part	0-54-00	
			244-Part	0-01-00	G.P.
			245-Part	0-05-00	G.P.
			192-2 Part	0-09-00	G.P.
			216- Part	0-03-00	
			217-1 Part	0-09-00	
			217-2 Part	0-14-50	G.P.
			215-Part	0-03-50	
			204-1 Part	0-23-00	
			204-7 Part	0-01-50	
			205-3 Part	0-24-50	
			205-4 Part	0-18-00	
			205-5 Part	0-10-00	
			206-Part	0-05-00	
Grand Total			11-54-00	or 28-53 Cents.	

[No. L-14016/14/93-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. सं. 2836.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेखलि—रोम्मेरू पार्श्व लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है;



बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-13/1 राजमंड्री-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यावसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

## पेखलि—दोम्लेरू

जैनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट./एकर में)	विवरण
पश्चिम गोदावरि (आं.प्र.)	निडदबोलु	मुरिपल्ली	65-11 भाग	0-25-50	
			65--2 भाग	0-11-00	
			59--2 भाग	0-10-00	
			59--3 भाग	0-10-50	
			59--8 भाग	0-12-50	
			61--भाग	0-04-50	जी.पी
			53--1 भाग	0-01-50	
			53--2 भाग	0-11-00	
			53-3 भाग	0-10-00	
			51--4 भाग	0-10-50	
			51--5 भाग	0-00-25	
			52-11 भाग	0-1-000	
			52--12 भाग	0-03-50	
			50--16ए भाग	0-26-00	
			50--16बी भाग	0-16-00	
			50--15 भाग	0-00-25	
			49--भाग	0-03-00	जी.पी.
			69--भाग	0-03-00	जी.पी.
			70--भाग	0-03-00	जी.पी.
			71--2 भाग	0-30-50	
			72--1 भाग	0-01-00	
			144--3 भाग	0-01-00	
			156--1 भाग	0-06-00	जी.पी.
			156--2 भाग	0-03-00	जी.पी.
			155--3 भाग	0-00-25	
			154--भाग	0-02-50	जी.पी.
कुल योग			2 16 25 OR AC-5-34/1/2		

[सं. एल-14016/14/93-जीपी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2836.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Paravali—Dammeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of users

in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-131, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

### SCHEDULE

#### GAS PIPE LINE PROJECT

Peravali—Dammeru

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Nidadavoli	Muripalli	65-1 Part	0-25-50	G.P.
			65-2 Part	0-11-00	
			59-2 Part	0-10-00	
			39-3 Part	0-10-50	
			59-8 Part	0-12-50	
			61-Part	0-04-50	
			53-1 Part	0-01-50	
			53-2 Part	0-11-00	
			53-3 Part	0-10-00	
			51-4 Part	0-10-50	
			51-5 Part	0-00-25	
			52-11 Part	0-10-00	
			52-12 Part	0-03-50	
			50-16A Part	0-26-00	
			50-16B Part	0-16-00	
			50-15 Part	0-00-25	
			49-Part	0-03-00	G.P.
			69-Part	0-03-00	G.P.
			70-Part	0-03-00	G.P.
			71-2 Part	0-30-50	G.P.
			72-1 Part	0-01-00	
			144-3 Part	0-01-00	
			156-1 Part	0-06-00	
			156-2 Part	0-03-00	G.P.
			155-3 Part	0-00-25	G.P.
			155-3 Part	0-00-25	
			154-Part	0-02-50	
Grand Total			2-16-25	Or AC 5-34 1/2 Cents	

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2837 .— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए परवल्लि-दामेरु पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि. द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधि-ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम अधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमि. के.जी. बेसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

परवल्लि-दामेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	कोरूपल्लि	कोरूपल्लि	21-3ए भाग	0-05-50	जी.पी.
			21-2ए भाग	0-17-00	
			21-1ए भाग	0-16-50	
			20-1बी भाग	0-12-00	
			21-1ए भाग	0-09-00	
			19-भाग	0-00-50	
			कुल योग	0-60-50	या ए. सी/49 सेन्ट

[सं. एल-14016/14/93 जी पी]

अर्घेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2837.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Parawali—Dammeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central

Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT

Peravali—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Korupalli	Korupalli	21-3A Part	0-05-50	G.P.
			21-2 Part	0-17-00	
			21-1 Part	0-16-50	
			20-1B Part	0-12-00	
			20-1A Part	0-09-00	
			19-Part	0-00-05	
			Grand Total	0-60-50	Or AC 1-49 Cnts

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2939.— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि-दोम्मोरु पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी, आफ इंडिया लिमि., के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री 533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलि-दोम्मोरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे.नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	उन्नाजावरम	मोर्षा	329-1 भाग	0-08-00	जी.पी.
			329-2 भाग	0-09-00	
			329-3ए भाग	0-20-50	
			328-1 भाग	00-5-50	
			328-3 भाग	0-05-50	

1	2	3	4	5	6
ईष्ट गोदावरी (भांछ प्रवेश)	उम्राजावरम	बोर्मा	328-5 भाग	0-05-00	
			328-7 भाग	0-13-00	
			328-9 भाग	0-10-00	
			328-10ए भाग	0-09-50	
			328-10बी भाग	0-09-00	
			325 ए-1 भाग	0-13-50	
			325-2 भाग	0-15-00	
			325-1-भाग	0-27-50	
			325-2 भाग	00-1-00	
			322-1 भाग	0-05-50	
			322-2 भाग	0-12-50	
			322-3 भाग	0-11-50	
			322-16 भाग	0-01-50	
			322-11-भाग	0-02-00	
			322-12 भाग	0-03-50	
			322-13 भाग	0-03-00	
			322-14 भाग	0-11-50	
			322-15-भाग	0-03-00	
पश्चिम गोदावरी	बुध्दुजवरम	मोर्ता	321-5 भाग	0-07-50	
			321-6 भाग	0-07-50	
			321-7 भाग	0-07-50	
			318-7 भाग	0-24-00	
			318-13 भाग	0-07-00	
			318-12 भाग	0-14-00	
			318-16 भाग	0-00-50	
			318-17 भाग	0-01-50	
			318-18 भाग	0-15-00	
			318-19 भाग	0-18-00	
			253-1 भाग	0-06-00	
			318-2 भाग	0-06-50	
			254-9 भाग	0-10-50	
			252-1 भाग	0-03-00	जी.पी.
			252-5 भाग	0-16-50	
			249-2बी भाग	0-01-00	
			249-3ए भाग	0-03-00	
			249-4 भाग	0-21-50	
			249-1 सी भाग	0-02-50	
			249 1डी भाग	0-09-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	वेन्नाजवरम	मोर्ता	250-2 भाग	0-07-50	
			250-3- भाग	0-07-50	
			250-6वी भाग	0-10-50	
			250-7ए भाग	0-03-00	
			250-7बी भाग	0-02-00	
			242- भाग	0-04-00	
			240-6ए भाग	0-01-50	
			240-6बी भाग	0-17-50	
			240-5ए भाग	0-02-50	
			240-5बी भाग	0-06-00	
			239-2वी भाग	0-04-50	
			239-12 भाग	0-12-50	
			238-1 भाग	0-01-00	
			238-4 भाग	0-01-00	
			237- भाग	0-14-50	जी. पी.
			236-1 भाग	0-05-00	
			236-3 भाग	0-08-00	
			236-4 भाग	0-01-00	
			236-6 भाग	0-04-00	
			322-9 भाग	0-03-50	
			322-14 भाग	0-01-00	
			311-5 भाग	0-05-00	
			311-6 भाग	0-03-50	
			कुल योग	5-15-00	

[स. एल 14016/14/93 जी पी]

मधोमु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2838.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Paravali—Dammeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd. ; .

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE -**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
Peravali—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Undrajavaram	Mortha	329-1 Part	0-08-00	G.P.
			329-2 Part	0-09-00	
			329-3 Part	0-20-50	
			328-1 Part	0-05-50	
			328-3 Part	0-05-50	
			328-5 Part	0-05-00	
			328-7 Part	0-13-00	
			328-9 Part	0-10-00	
			328-10A Part	0-09-50	
			328-10B Part	0-09-00	
			325A	0-13-50	G.P.
			1 Part		
			325-2 Part	0-15-00	
			325-1 Part	0-27-50	
			325-2 Part	0-01-00	
			322-1 Part	0-05-50	
			322-2 Part	0-12-50	
			322-3 Part	0-11-50	
			322-16 Part	0-01-50	
			322-11 Part	0-02-00	
			322-12 Part	0-03-50	
			322-13 Part	0-03-00	
			322-14 Part	0-11-50	
			322-15 Part	0-03-00	
			321-5 Part	0-07-50	
			321-6 Part	0-07-50	
			321-7 Part	0-07-50	
			318-7 Part	0-24-00	
			318-13 Part	0-07-00	
			318-12 Part	0-14-00	
			318-16 Part	0-00-50	
			318-17 Part	0-01-50	
			318-18 Part	0-15-00	
			318-19 Part	0-18-00	
			253-1 Part	0-06-00	
			253-2 Part	0-06-50	
			254-9 Part	0-10-50	
			252-1 Part	0-03-00	
			252-5 Part	0-16-50	
			249-2B Part	0-01-00	
			249-3A Part	0-03-00	
			249-4 Part	0-21-20	
			249-1C Part	0-02-50	
			249-1D Part	0-09-20	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Undrajauram	Mortha	250-2 Part	0-07-50	
			250-3 Part	0-07-50	
			250-6B Part	0-10-50	
			250-7A Part	0-03-00	
			250-7B Part	0-02-00	
			242-Part	0-04-00	
			240-6A Part	0-01-50	
			240-6B Part	0-17-50	
			240-5A Part	0-02-20	
			240-5B Part	0-06-00	
			239-2B Part	0-04-50	
			239-12 Part	0-12-50	
			238-1 Part	0-01-00	
			238-4 Part	0-01-00	
			237-Part	0-14-50	G.P.
			236-1 Part	0-05-00	
			236-3 Part	0-08-00	
			236-4 Part	0-01-00	
			236-6 Part	0-04-00	
			322-9 Part	0-03-50	
			322-14 Part	0-01-00	
			311-5 Part	0-05-00	
			311-6 part	0-03-50	
			G. Total	5-15-00 Or 12-72	

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2839 .—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम-पेरवल पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखनेवाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, के. जी. बेसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राज मंजूरी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा बिना व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।



अनुसूची  
गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट -  
मरमपुरम-पेरबलि

जमपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी आ. प्र.	इरगवरम	ईस्ट विप्पारु	124-1 सी भाग	0-00-50	
			124-1 डी भाग	0-03-50	
			124-3 भाग	0-03-00	
			124-7 भाग	0-03-00	
			124-8 भाग	0-03-00	
			124-9 भाग	0-02-50	
			124-10 भाग	0-02-50	
			124-12 भाग	0-02-00	
			124-13 भाग	0-01-00	
			125-2 भाग	0-10-50	
			125-3 भाग	0-05-00	
			125-5वी भाग	0-02-50	
			125-6 भाग	0-03-00	
			127-1डी भाग	0-00-25	
			127-1ई भाग	0-07-50	
			127-1 एफ भाग	0-04-50	
			127-1जी भाग	0-04-50	
			127-2 भाग	0-22-50	
			128-1 भाग	0-05-00	
			128-2 भाग	0-05-00	
			129-1 भाग	0-04-50	
			129-2 भाग	0-07-50	जी.पी.
			129-3 भाग	0-00-50	
			129-4 भाग	00-01-50	
			132-1 सी भाग	0-14-00	
			132-1डी भाग	00-6-50	
			132-1ई भाग	00-6-50	
			133-भाग	0-03-00	जी.पी.
			124-1 भाग	0-12-00	
			134-2ए भाग	0-07-00	
			138-2बी भाग	0-08-00	
			138-3 भाग	0-23-00	
			139-2 भाग	0-18-50	
			142-1बी भाग	0-05-00	
			142-3 भाग	0-02-00	
			142-4 भाग	0-02-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	इरागवरम	ईस्ट विप्पारु	142-6 भाग 143-8ए भाग 142-8बी भाग 143-8सी भाग 143-8ई भाग 143-2 भाग 150-3सी भाग 188-3 भाग 188-4 भाग 191-2 भाग 191-3 भाग 191-4 ए भाग 191-8-बी भाग	0-01-00 0-03-00 0-03-00 0-01-50 0-08-50 0-05-00 0-04-00 0-01-00 0-09-00 0-14-00 0-01-50 0-09-50 0-11-50	
			कुल योग	2-85-75	

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

मधेन्नु सेन, निवेदक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2839.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram—Peravali Pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users

in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**NARASAPURAM TO PERAVALI**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (in Hect/ Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari-(A.P)	Iragauaram	East Upparru-	124-1C Part „-1 D Part „-3 Part „-7 Part „-8 Part „-9 Part „10 Part	0-0-50 0-03-50 0-03-00 0-03-00 0-03-00 0-02-30 0-02-50	

1	2	3	4	5	6
West Godavari—(A P)	Iragauaram	East Upparru—	124-12 Part	0-02.00	
			„ - 13 Part	0-01.00	
			125-2 Part	0-10.50	
			„ - 3 Part	0-05.00	
			„ - 5 B Part	0-02.50	
			„ - 6 Part	0-03.00	
			127-1 D Part	0-00.25	
			„ - 1 E Part	0-07.50	
			„ - 1 F Part	0-07.50	
			„ - 1 G Part	0-04.50	
			„ - 2 Part	0-22.50	
			128-1 Part	0-05.00	
			„ - 2 Part	0-05.00	
			129-1 Part	0-04.50	B P
			„ - 2 Part	0-00.50	
			„ - 3 Part	0-00.50	
			„ - 4 Part	0-01.50	
			132-1 C Part	0-14.00	
			„ 1 D Part	0-06.50	
			„ 1 E Part	0-06.50	
			133 Part	0-03.00	G P
			134-1 Part	0-12.00	
			„ - 2 A Part	0-07.00	
			138-2B Part	0-08.00	
			„ - 3 Part	0-23.00	
			139-2 Part	0-18.50	
			142-1 B Part	0-05.00	
			„ - 3 Part	0-02.00	
			„ - 4 Part	0-02.50	
			„ - 6 Part	0-01.00	
			143-8 A Part	0-03.00	
			„ - 8 B Part	0-03.00	
			„ - 8 C Part	0-01.50	
			„ - 8 E Part	0-08.50	
			144-2 Part	0-05.00	
			150 3C Part	0-04.00	
			188-3 Part	0-01.00	
			„ - 4 Part	0-09.00	
			191 - 2 Part	0-14.00	
			„ - 3 Part	0-01.50	
			„ - 4 Part	0-09.50	
			„ - 5 B Part	0-11.50	
			G Total	2-85.75	

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2840—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि 'सांख्यिक हित' में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम से पेरबलि पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है,

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए हमके साथ संलग्न बिबरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है,

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 80) के खण्ड 318 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है,

वर्शते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री-533 104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है,

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

नरसापुरम से पेरबलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ. प्र.)	इरगबरम	कापवरम	68-भाग	0-04-00	जी. पी.
			59-2 भाग	0-07-50	
			59-4 भाग	0-00-50	
			66-1 भाग	0-00-50	
			66-2-भाग	0-10-50	
			66-4 भाग	0-16-50	
			66-5-भाग	0-06-00	
			65-1 भाग	0-01-00	
			65-2 भाग	0-25-50	
			64-1 भाग	0-01-00	
			61-4 भाग	0-01-00	
			61-5 भाग	0-07-50	
			62-5 भाग	0-00-50	
			62-18 भाग	0-14-00	
			63-2 भाग	0-18-00	
			86-1 भाग	0-11-50	
			86-7 भाग	0-06-00	
			86-8-भाग	0-04-00	
			86-9ए भाग	0-00-50	
			86-9बी भाग	0-02-00	
			87-1 भाग	0-03-50	
			87-2 भाग	0-03-50	
			259-5ए भाग	0-00-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	इरगवरम्	कापवरम्	259-5वी भाग	0-05-00	
			259-6 भाग	0-05-50	
			259-7 भाग	0-13-50	
			258-4 भाग	0-10-50	
			257-2 भाग	0-00-50	
			257-1 भाग	0-07-00	
			257-3 भाग	0-08-00	
			256-2 भाग	0-26-50	
			255-13 भाग	0-04-00	
			255-10 भाग	0-17-00	
			254-9 भाग	0-00-50	
			263-1 भाग	0-01-00	
			263-2 भाग	0-16-50	
			264-1 भाग	0-04-00	
			264-2 भाग	0-07-50	
			264-5 भाग	0-08-00	
			264-7 भाग	0-12-00	
			270-2ए भाग	0-17-50	
			270-2बी भाग	0-07-50	
			264-5-भाग	0-12-00	
			271-1 भाग	0-27-50	
			250-2 भाग	0-20-00	
			250-3 भाग	0-04-00	जी.पी.
			249-2 भाग	0-08-50	
			248-5 भाग	0-11-50	
			248-7 भाग	0-07-50	
			247-6 भाग	0-01-00	
			247-7 भाग	0-01-50	
			247-8 भाग	0-01-00	
			247-9 भाग	0-01-00	
			247-10 भाग	0-21-50	
			कुल योग	4-43-50 अथवा एकड़ 10.96 सेंट्स	

[सं. एफ-14016/14/93-जी.पी.]

अधोत्तु सेत, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2840.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram—Peravali Pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1|3|1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

### SCHEDULE

#### GAS PIPE LINE PROJECT

Narasapuram to Peravali

District	Mandal	Village	Survey Nos	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West G davari (A.P.)	Iragavaram	Kapavaram	68- Part	0-04-00	G.P.
			59-2 Part	0-07-50	
			59-4 Part	0-00-50	
			66-1 Part	0-00-50	
			66-2 Part	0-10-50	
			66-4 Part	0-16-50	
			66-5 Part	0-06-00	
			65-1 Part	0-01-00	
			65-2 Part	0-25-50	
			64-1 Part	0-01-00	
			61-4 Part	0-10-00	
			61-5 Part	0-07-50	
			62-5 Part	0-00-50	
			62-18 Part	0-14 50	
			63-2 Part	0-18-00	
			86-1 Part	0-11 50	
			86-7 Part	0 06-00	
			86-8 Part	0-04-00	
			86-9A Part	0-00-50	
			86-9B Part	0-02-00	
			87-1 Part	0-03-50	
			87-2 Part	0-03-50	
			259-5A Part	0-00-50	
			259-5B Part	0-05-00	
			259-6 Part	0-05-50	
			259-7 Part	0-13-50	
			258-4 Part	0-10-50	
			257-2 Part	0-00-50	
			257-1 Part	00-7-00	
			257-3 Part	0-08-00	

1	2	3	4	5	6
			256 2 Part	0 26 50	
			255 13 Part	0 04 00	
			255 10 Part	0 17 00	
			254 9 Part	0 00 50	
			263 1 Part	0 01 00	
			263 2 Part	0 16 50	
			264 1 Part	0 04 00	
			264 2 Part	0 07 50	
			264 5 Part	0 08 00	
			264 7 Part	0 12 00	
			270 2A Part	0 17 50	
			270 2B Part	0 07 50	
			270 5 Part	0 12 00	
			271 1 Part	0 27 50	
			250 2 Part	0 20 00	
			250 3 Part	0 04 00 G.P.	
			249 2 Part	0 08 50	
			248 5 Part	0 04 50	
			248 7 Part	0 07 50	
			247 6 Part	0 01 00	
			247 7 Part	0 01 50	
			247 8 Part	0 01 00	
			247 9 Part	0 01 00	
			247 10 Part	0 21 50	
			Grand Total:	4 43 50	Or Ac 10.96 Cents.

[No L-14016/14/93-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2841—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम से पेरबलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिभूजा की तारीख से 21 दिनों के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-41/3/1 राजमंडी - 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची  
गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
नरसपुरम से पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट./एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (भा. प्र.)	इरागवरम	वेलेटियाडू	5.3 भाग	0-03-00	जी.पी.
			54-1 भाग	0-06-50	
			54-2 भाग	0-05-00	
			65-भाग	0-05-50	जीपी
			64-1 भाग	0-03-00	
			64-3 भाग	0-23-00	
			63-4 भाग	0-04-50	
			63-5-भाग	0-08-50	
			62-1 भाग	0-08-00	
			62-2 भाग	0-17-50	
			61-4 भाग	0-05-50	
			61-5 भाग	0-09-50	
			58-6 भाग	0-06-00	
			58-7-भाग	0-10-50	
			59-1 भाग	0-05-00	
			59-2 भाग	0-05-00	
			59-6 भाग	0-14-50	
			कुल योग :	1-40-50 या एसी 3-47	

[सं. एल - 14016/14/93 - जी पी]

अर्धेन्दु सेत, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2841.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali Pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.



**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**NARASAPURA UPTO PERAVALI**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
West Godavari-(AP)	Iragavaram	Yeletipadu	53-Part	0 03-00	G P
			54-1 Part	0 06-50	
			54-2 Part	0 05-50	
			65 Part	0 05-50	G P.
			64-1 Part	0 03-00	
			64-3 Part	0 23-00	
			63-4 Part	0 04-50	
			63-5 Part	0 08-50	
			64-1 Part	0 08-00	
			62-2 Part	0 17-50	
			64-4 Part	0 05-50	
			64-5 Part	0 09-50	
			58-6 Part	0 06-00	
			58-7 Part	0 10-50	
			59-1 Part	0 05-00	
			59-2 Part	0 05-00	
			59-6 Part	0 14-50	
			Grand Total	1 40-50	
					or AC 3-47

[No. L. 14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2842—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम-पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिय लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सूक्ष्म प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंडी - 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

## अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

नरसापुरम से पेरवल्लि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर, एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आं. प्र.)	इरागवरम	राणाक	227-2वीं भाग	0-01-00	जी.पी.
			227-3 भाग	0-05-00	
			226-भाग	0-03-00	
			224-1 भाग	0-06-00	
			224-2वीं भाग	0-10-50	
			224-2सी भाग	0-00-25	
			224-4 भाग	0-00-50	
			223-1 भाग	0-30-50	
			227-7 भाग	0-02-00	
			185-2 भाग	0-12-50	
			185-3 भाग	0-13-50	
			185-4 भाग	0-12-50	
			174-1 भाग	0-07-00	
			174-2 भाग	0-00-25	
			174-3 भाग	0-10-50	
			174-5 भाग	0-03-50	
			173-1 भाग	0-10-00	
			171- भाग	0-13-00	
			170-1 भाग	0-21-50	
			170-2 भाग	0-10-50	
			165- भाग	0-04-00	जी.पी.
			161-1 भाग	0-05-00	
			161-2 भाग	0-05-00	
			161-3वीं भाग	0-11-00	
			161-4 भाग	0-08-50	
			160-2वीं भाग	0-06-50	
			160-3 भाग	0-30-00	
			159-1 भाग	0-00-50	
			159-3 भाग	0-01-50	
			128-1 भाग	0-30-00	
			128-7 भाग	0-10-00	
			133-1 भाग	0-00-25	
			133-2 भाग	0-03-00	
			133-4 भाग	0-14-50	
			127-1 भाग	0-00-50	
			123-3 भाग	0-19-50	

1	2	3	4	5	6
			122-भाग	0-57-50	
			120-6 भाग	0-02-00	
			120-7 भाग	0-04-50	
			119-भाग	0-02-50	
			कुल योग	3-89-75 या एकड़ 9-63-1/2 सैन्ट	
					[सं. एल - 14016/14/93 - जीपी] अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2842.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram—Peravali Pipeline to laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of users

in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Narasapuram to Peravali**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Irogavaram	Rapakal	227-2B Part	0-01-00	G.P.
			227-3 Part	0-05-00	
			226- Part	0-03-00	
			224-1 Part	0-06-00	
			224-2B Part	0-10-50	
			224-2C Part	0-00-25	
			224-4 Part	0-00-50	
			223-1 Part	0-30-50	
			227-7 Part	0-02-00	
			185-2 Part	0-12-50	
			185-3 Part	0-13-50	
			185-4 Part	0-12-50	
			174-1 Part	0-07-00	
			174-2 Part	0-00-25	
			174-3 Part	0-10-50	

1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Iragavarani	Rapaval	174-5 Part	0-03-50	
			173-1 Part	0-10-00	
			171- Part	0-13-00	
			170-1 Part	0-21-50	
			170-2 Part	0-10-50	
			165-Part	0-04-00	G.P.
			161-1 Part	0-05-00	
			161-2 Part	0-05-00	
			161-3 Part	0-11-00	
			161-4 Part	0-08-50	
			160-2B part	0-06-50	
			160-3 Part	0-30-00	
			159-1 Part	0-00-50	
			159-3 Part	0-01-50	
			128-1 Part	0-30-00	
			128-7 Part	0-10-00	
			133-1 Part	0-00-25	
			133-2 Part	0-03-00	
			133-4 Part	0-14-50	
			127-1 Part	0-00-50	
			123-3 Part	0-19-50	
			122- Part	0-57-50	
			120-6 Part	0-02-00	
			120-7 Part	0-04-50	G.P.
			119-Part	0-02-50	G.P.
			Grand Total	3-89-75	RR AC 9.631/2 Cents

[No. L-14016/14/93—GP]

Ardhendu Sen, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2443.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम से पेरवल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं गैस पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

अतः कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के. जी. बलीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड्री - 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विवेक रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

## नरसापुरम से पेरवल

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरि (आ. प्र.)	पेरवल	पेरवल	21- भाग	0-03-00	जि पि
			15-6वी भाग	0-18-50	
			18-1वी भाग	0-23-00	
			18-2 भाग	0-00-50	जि पि
			17-2 भाग	0-07-00	
			17-3 भाग	0-00-50	जि पि
			38- भाग	0-19-50	
			36-1 भाग	0-19-50	
			35-1 भाग	0-19-00	
			35-2 भाग	0-05-50	
			34-1 भाग	0-04-50	
			34-2 भाग	0-05-00	
			34-3 भाग	0-09-50	
			29-1 भाग	0-09-50	
			29-2 भाग	0-00-50	
			33- भाग	0-03-50	
			147-1ए भाग	0-09-00	
			147-1बी भाग	0-18-50	
			145-1ए भाग	0-06-00	
			145-1बी भाग	0-10-00	
			145-3 भाग	0-02-50	
			145-2ए भाग	0-07-50	
			145-2ए2 भाग	0-10-00	
			140- भाग	0-04-00	जि पि
			127-1ए भाग	0-02-00	जि पि
			127-1बी भाग	0-08-50	
			127-2 भाग	0-12-00	
			127-3 भाग	0-05-00	
			127-4 भाग	0-11-00	
			127-5 भाग	0-02-00	
			126-4 भाग	0-00-50	
			126-3ए भाग	0-09-00	
			126-3बी भाग	0-05-50	
			128-भाग	0-07-00	जि पि
			104-3 भाग	0-20-00	
			105-2ए भाग	0-16-50	

1	2	3	4	5	6
			105-2सी भाग	0-00-50	
			120-4 भाग	0-07-00	
			119-भाग	0-01-50	जी पी
			113-2 भाग	0-04-50	
			114-1 भाग	0-03-00	
			114-2 भाग	0-04-50	
			112-1ए भाग	0-07-50	
			112-1बी भाग	0-10-50	
			112-2 भाग	0-08-50	
			338-1 भाग	0-09-00	
			338-2 भाग	0-05-00	
			338-4 भाग	0-13-00	
			338-3बी भाग	0-01-00	
			338-8 भाग	0-01-00	जी पी
			339-भाग	0-18-50	
			343-भाग	0-11-50	जी पी
			349-3 भाग	0-02-50	
			349-4 भाग	0-08-00	
			349-5 भाग	0-02-50	
			349-6 भाग	0-04-50	
			349-7 भाग	0-03-50	
			351-भाग	0-03-00	जी पी
			352-1 भाग	0-07-00	
			352-2 भाग	0-01-00	
			353-भाग	0-07-00	जी पी
			364-1 भाग	0-12-50	
			364-2ए भाग	0-04-50	
			364-2बी भाग	0-01-00	
			कुल योग	4-78-50 या एसी 11.82 सैन्ट्स	

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

अर्वेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2843.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basia Project, 29-7-13/1. Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Narsapuram to Peravali

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Peravali	Peravali	21-Part	0-03-00	G.P.
			15-6B Part	0-18-50	
			18-1B Part	0-23-00	
			18-2 Part	0-00-50	G.P.
			17-2 Part	0-07-00	
			17-3 Part	0-00-50	
			38-Part	0-19-50	G.P.
			36-1 Part	0-19-50	
			35-1 Part	0-19-00	
			35-2 Part	0-05-50	G.P.
			34-1 Part	0-04-50	
			34-2 Part	0-05-00	
			34-3 Part	0-09-00	G.P.
			29-1 Part	0-09-50	
			29-2 Part	0-00-50	
			33- Part	0-03-50	G.P.
			147-1A Part	0-09-50	
			147-1B Part	0-18-50	
			145-1A Part	0-06-00	G.P.
			145-1B Part	0-10-00	
			145-3 Part	0-02-50	
			145-2A1 Part	0-07-50	G.P.
			145-2A2 Part	0-10-00	
			140-Part	0-04-00	
			127-1A Part	0-02-00	G.P.
			127-1B Part	0-08-50	
			127-2 Part	0-12-00	
			127-3 Part	0-05-00	G.P.
			127-4 Part	0-11-00	
			127-5 Part	0-02-00	
			126-4 Part	0-00-50	G.P.
			126-3A Part	0-09-00	
			126-3B Part	0-05-50	
			128-Part	0-07-00	G.P.
			104-3 Part	0-20-00	
			105-2A Part	0-16-50	
			105-2C Part	0-00-50	G.P.
			102-4 Part	0-07-00	
			119-Part	0-01-50	
			113-2 Part	0-04-50	G.P.
			114-1 Part	0-03-00	
			114-2 Part	0-04-50	
			112-1A Part	0-07-50	G.P.
			112-1B Part	0-10-50	

1	2	3	4	5	6
			112-2 Part	0-08-50	
			338-1 Part	0-09-00	
			338-2-Part	0-05-00	
			338-4-Part	0-13-00	
			338-3B Part	0-01-00	
			338-8 Part	0-01-00	G.P.
			339-Part	0-18-50	
			343-Part	0-11-50	G.P.
			349-3 Part	0-02-50	
			349-4 Part	0-08-00	
			349-5 Part	0-02-00	
			349-6 Part	0-04-50	
			349-7 Part	0-03-50	
			351-Part	0-03-00	G.P.
			352-1 Part	0-07-00	
			352-2 Part	0-01-00	
			353-Part	0-07-00	G.P.
			364-1 Part	0-12-50	
			364-2A Part	0-04-50	
			364-2B Part	0-01-00	
			Grand Total	4-78-50	OR AC 11.82 Cents

[No. L-14016/14/93 GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2844.—जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम से पेरवल पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोजना का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि., के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी - 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि आवश्यक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।



अनुसूची  
गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
नरसापुरम से पेरवल्लि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आं. प्र.)	इरागवरम	पेक्केरु	20-7ए भाग	0-12-50	जी. पी.
			20-7बी भाग	0-05-50	
			20-6 भाग	0-01-00	
			20-5वी भाग	0-03-00	
			20-4बी भाग	0-01-00	
			185-1 भाग	0-00-50	जी. पी.
			185-5 भाग	0-01-00	
			185-6 भाग	0-12-50	
			22-2 भाग	0-01-00	
			184-1ए भाग	0-13-25	
			184-1बी भाग	0-13-25	जि. पी.
			184-3 भाग	0-02-50	
			183-1 भाग	0-05-00	
			183-3 भाग	0-14-00	
			183-4 भाग	0-00-25	
			179-1 भाग	0-13-00	जी. पी.
			182-भाग	0-04-50	
			167-8 भाग	0-06-50	
			167-9 भाग	0-04-00	
			167-10 भाग	0-05-50	
			166-7 भाग	0-04-50	जी. पी.
			168-1 भाग	0-07-50	
			168-6 भाग	0-05-00	
			168-5 भाग	0-05-00	
			168-3 भाग	0-03-00	
			168-4 भाग	0-06-50	जी. पी.
			168-7 भाग	0-03-00	
			170-2 भाग	0-04-00	
			152-1 भाग	0-14-00	
			152-2 भाग	0-14-00	
			153 भाग	0-27-00	जी. पी.
			151-2 भाग	0-01-00	
			150-1 भाग	0-05-50	
			150-2 भाग	0-13-50	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आं प्र.)	हरगवरम	पेक्केरु	150-3 भाग	0-07-50	
			150-4 भाग	0-00-25	
			149-4 भाग	0-03-00	
			148-4ए भाग	0-02-50	
			148-4बी भाग	0-10-00	
			148-3 भाग	0-08-00	
			148-8 भाग	0-03-00	
			148-9 भाग	0-03-50	
			147-1ए भाग	0-17-00	
			147-2 भाग	0-00-50	
			210 भाग	0-07-00	जीपी
			211-भाग	0-12-00	जीपी
			219-भाग	0-46-25	
			218 भाग	0-03-00	
			215-भाग	0-05-00	
			217-2 भाग	0-18-00	
			244-4 भाग	0-14-00	
			244-5 भाग	0-07-00	
			244-6 भाग	0-07-00	
			244-7 भाग	0-05-00	
			245-1 भाग	0-07-50	
			245-2 भाग	0-06-50	
			245-3ए भाग	0-01-00	
			242-भाग	0-03-00	जीपी
			239-4सी भाग	0-05-50	
			239-4डी भाग	0-03-00	
			239-3बी भाग	0-26-50	
			256-भाग	0-04-00	
			257-5 भाग	0-01-00	
			276-1 भाग	0-09-50	
			276-5ए भाग	0-05-00	
			276-5बी भाग	0-04-00	
			276-5सी भाग	0-03-50	
			276-5डी भाग	0-04-00	
			276-3 भाग	0-11-50	
			276-7 भाग	0-09-00	
			276-8ए भाग	0-05-50	
			276-8बी भाग	0-03-50	
कुल योग			5-26-75 या एसी 13.01 सैन्ट्स		

[सं. एल-14016/14/93-जीपी]

अर्घेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2844.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Narasapuram To Peravali

District	Mandal	Village	Survey No.	Area	Remarks
(In Hect/Acres)					
1	2	3	4	5	6
West Godavari '(A.P.)	Iragauaram	Pekeru	20-7A Part	0-12-50	
			20-7B-Part	0-05-50	
			20-6 Part	0-01-00	G.P.
			20-5B Part	0-03-00	
			20-4B Part	0-01-00	
			185-1 Part	0-03-50	
			185-5 Part	0-01-00	G.P.
			185-6 Part	0-12-50	
			22-2 Part	0-01-00	
			184-1A Part	0-13-25	
			184-1B Part	0-13-25	
			184-3 Part	0-02-50	
			183-1 Part	0-05-00	
			183- Part	0-14-00	
			183-4 Part	0-00-25	
			179-1 Part	0-13-00	
			182- Part	0-04-50	G.P.
			167-8 Part	0-06-50	
			167-9 Part	0-04-50	
			167-10 Part	0-05-50	
			166-7 Part	0-04-50	
			168-1 Part	0-07-50	
			168-6 Part	0-05-00	
			168-5 Part	0-05-00	
			168-3 Part	0-03-00	
			168-4 Part	0-06-50	
			168-7 Part	0-03-00	
			170-Part	0-04-00	G.P.
			152-1 Part	0-14-00	

1	2	3	4	5	6
			11-2 Part	0-14-00	
			153-Part	0-27-00	
			151-2 Part	0-01-00	
			150-1 Part	0-05-50	
			150-2 Part	0-13-50	
			150-3 Part	0-07-50	
			150-4 Part	0-00-25	
			149-4 Part	0-03-00	
			148-4A Part	0-02-50	
			148-4B Part	0-10-00	
			148-3 Part	0-08-00	
			148-8 Part	0-03-00	
			148-9 Part	0-03-50	
			147-1A Part	0-17-00	
			147-2 Part	0-00-50	
			210-Part	0-07-00	G.P.
			211-Part	0-12-00	G.P.
			219-Part	0-46-25	
			218-Part	0-03-00	
			215-Part	0-05-00	
			217-2 Part	0-18-00	
			244-4 Part	0-14-00	
			244-5 Part	0-07-00	
			244-6 Part	0-07-00	
			244-7 Part	0-05-50	
			245-1 Part	0-07-50	
			245-2 Part	0-06-50	
			245-3A Part	0-01-00	
			242-Part	0-03-00	G.P.
			239-4C Part	0-05-50	
			239-4D Part	0-03-00	
			239-B Part	0-26-50	
			256-Part	0-04-00	
			257-5 Part	0-01-00	
			276-1 Part	0-09-50	
			276-5A Part	0-05-00	
			276-5B Part	0-04-00	
			276-5C Part	0-03-50	
			276-5D Part	0-04-00	
			276-3 Part	0-11-50	
			276-7 Part	0-09-00	
			276-8A Part	0-05-50	
			276-8B Part	0-03-50	
			G. Total	5-26-75	or 13-01 AC

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2845.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम-पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ,

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है ;

अर्थात् कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमि., के.जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमहली-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप अथवा विधि व्यवसाय के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ;

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
नरसपुरम से पेरवलि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरि(आ.प्र.)	पेनूगेंड	पेनूगेंड	341-	भाग 0-03-00	लिपि
			343-	भाग 0-07-00	
			347-3	भाग 0-10-50	
			" 4 "	0-11-50	
			" 5 "	0-05-00	
			351-5	भाग 0-01-50	
			" 6 "	0-05-50	
			" 7 "	0-04-50	
			" 8 "	0-13-00	
			" 9 "	0-02-00	
			352-	भाग 0-03-50	
			346-	भाग 0-10-00	
			350-	भाग 0-01-50	
			354-1	भाग 0-14-50	
			" 2 "	0-10-00	
			" 3 "	0-05-50	
			355-	भाग 0-03-00	जीपी
			372-1	भाग 0-14-50	
			371-1	भाग 0-26-50	
			370-	भाग 0-25-05	
			369-3ए	भाग 0-03-75	
			" 3बी "	0-03-75	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरि (आं.प्र.)	पेतगोंड	पनूगोंड	368- भाग 0-04-00		जि.पी
			242-2 भाग 0-09-50		
			241-1 भाग 0-12-50		
			241-2 भाग 0-04-50		
			240-1 भाग 0-13-00		
			240-2 भाग 0-12-50		
			240-3 भाग 0-01-00		
			249-6 भाग 0-03-00		
			249-5 भाग 0-03-00		
			249-4 भाग 0-03-00		
			249-7 भाग 0-19-00		
			250-3 भाग 0-04-50		
			250-2ए भाग 0-12-50		
			250-2बी भाग 0-07-50		
			238-1बी भाग 0-10-00		
			1		
			238-1बी2 भाग 0-06-00		
			बी		
			238 1-बी2ए भाग 0-06-00		
			221-1बी भाग 0-10-50		
			221-1सी भाग 0-09-50		
			221-3 भाग 0-01-00		जि.पी
			220-1वी भाग 0-22-50		
			220-2ए भाग 0-00-50		
			218- भाग 0-33-50		
			219-3 भाग 0-03-00		
			217-5 भाग 0-12-00		
			217-6 भाग 0-11-50		
			203-1 भाग 0-16-00		
			203-2ए भाग 0-14-00		
			203-2बी भाग 0-01-00		
			204-3 भाग 0-00-50		
			199-1 भाग 0-14-00		
			197-1 भाग 0-11-50		
			196- भाग 0-24-50		
			कुल जोड़ 5-02-50 या		
			ए. सी. 12-42 सेन्ट्स		

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2845.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users

in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

### SCHEDULE GAS PIPE LINE PROJECT

Narasapuram To Paravali

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari A.P.	Penugonda	Penugonda	341-Part	0-03-00	G.P.
			343-Part	0-07-00	
			347-3Part	0-10-50	
			347-4 Part	0-11-50	
			347-5 Part	0-05-00	
			351-5 Part	0-01-50	
			351-6 Part	0-05-50	
			351-7 Part	0-04-50	
			351-8 Part	0-13-00	
			351-9 Part	0-02-00	
			352-Part	0-03-50	
			346 Part	0-10-00	
			350-Part	0-01-50	
			354-1 Part	0-14-50	
			354-2 Part	0-10-00	
			354-3 Part	0-05-50	
			355-Part	0-03-00	G.P.
			372-1 Part	0-14-50	
			371-1 Part	0-26-50	
			370-Part	0-25-50	
			369-3A Part	0-03-75	
			369-3B Part	0-03-75	G.P.
			368-Part	0-04-00	
			242-2 Part	0-09-50	
			241-1 Part	0-12-50	
			241-2 Part	0-04-50	
			240-1 Part	0-13-00	
			240-2 Part	0-12-50	
			240-3 Part	0-01-00	
			Total	2-42-50	
			249-6 Part	0-03-00	
			249-5 Part	0-03-00	
			249-4 Part	0-03-00	

	4	5	6
249-7 Part	0-19-03		
250-3 Part	0-04-50		
250-2A Part	0-12-50		
250-2B Part	0-07-50		
238-1B1 Part	0-10-00		
238-1B2B Part	0-06-00		
238-1B2A Part	0-06-00		
221-1B Part	0-10-50		
221-1C Part	0-09-50		
221-3 Part	0-01-00		G.P.
220-1B Part	0-22-50		
220-2A Part	0-00-50		
218- Part	0-33-50		
219-3 Part	0-03-00		
217-5 Part	0-12-00		
217-6 Part	0-11-50		
203-1 Part	0-16-00		
203-2A Part	0-14-00		
203-2B Part	0-01-00		
204-3 Part	0-00-50		
199-1 Part	0-14-00		
197-1 Part	0-11-50		
196-Part	0-24-50		
Grand Total	5-02-50	Or AC 12.42 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

दई बिल्ली, 2 बिमनगर, 1993

का. आ. 2846.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसपुरम से पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमि. के . जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमंड़ी-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।



## अनुसूची

## गेस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

नरसपुरम से परवल

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट/ एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	पाल्लिकेल्लू	उल्लपल्लू	179-2 भाग	0-15-00	
			,, 4 ,,	0-05-00	
			180-1 ,,	0-24-00	
			183-1 ,,	0-14-00	
			,, 3 ,,	0-22-50	
			213-1 ,,	0-06-50	
			,, -3 ,,	0-18-00	
			,, 4 ,,	0-06-50	
			215-2 ,,	0-16-25	
			177- ,,	0-02-50	जी.पी.
			169- ,,	0-04-00	जी.पी.
			योग :	1-34-25	या ए.सी. 3-31½

[सं. एल. -14016/14/93-जी. पी.]  
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2846.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users

in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Narasapura To Peraulai

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Palacollu	Ullamparru	179-2 Part	0-15-00	
			177-4 Part	0-05-00	
			180-1 Part	0-24-00	

	4	5	6
183-1 Part		0-14-00	
183-3 Part		0-22-50	
213-1 Part		0-06-50	
213-3 Part		0-18-00	
213-4 Part		0-06-50	
215-2 Part		0-16-25	
177-Part		0-02-50	G.P.
169-Part		0-04-00	G.P.
G. Total		1-34-25	OR AC 3.31 1/2

[No. L-14016/14/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2847.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि से दोम्मेर पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमि. कं. जी. भसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1 राजमहरी-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति के यह विशेष रूप से निश्चित करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रथम विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलिसे दोम्मेर

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट/ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदवरी (आं.प्र.)	निडदोलु	मदूरु	85-4 भाग	0-09-00	
			„ 6 „	0-12-00	
			„ 7 „	0-18-00	
			„ 8 „	0-00-50	
			88-1 भाग	0-04-00	
			„ 2 „	0-03-00	
			„ 5 „	0-00-50	
			87- भाग	0-16-00	

	4	5	
पश्चिम गोदवरी (आं प्र )	निड थोलु	मदूरु	
	102-	भाग	0-38-00
	103-10	भाग	0-06-00
	„ 12	„	0-10-00
	104-6	भाग	0-00-25
	101-1ए	भाग	0-03-00
	100-1	भाग	0-02-00
	„ 5	„	0-16-00
	„ 3	„	0-01-00
	„ 4	„	0-14-00
	99-1	भाग	0-10-50
	„ 2	„	0-01-00
	„ 5	„	0-00-25
	„ 6	„	0-00-50
	124-2ई	भाग	0-08-00
	98-1	भाग	0-01-00
	2	„	0-19-50
	3	„	0-07-50
	97-1	भाग	0-12-50
	„ 5	„	0-15-50
	„ 8	„	0-19-50
	96-	भाग	0-00-50
	125-	भाग	0-03-50
	231-	1बी भाग	0-01-00
	„ 2ए	„	0-12-00
	„ 2बी	„	0-23-50
	„ 3ए	„	0-07-00
	230-1	भाग	0-07-50
	„ 2	„	0-20-50
	226-1	भाग	0-12-00
	„ 2ए	„	0-04-00
	227-3	भाग	0-03-50
	„ 4	„	0-13-50
	„ 5	„	0-22-00
	225-1	भाग	0-13-00
	213-2	भाग	0-14-00
	„ 3	„	0-16-50
	170-1बी	भाग	0-12-50
	1सी	„	0-05-50
	171-1ए	भाग	0-04-00
	„ 1बी	„	0-17-50
	172-1	भाग	0-11-50
	„ 2	„	0-14-50
	180-1	भाग	0-01-00
	„ 1बी	„	0-06-00

लि. पि.  
लि. पि.

लि. पि.

1	2	3	4	5	6
			180 1सी भाग	0-06-50	
			„ 1डी भाग	0-05-50	
			„ 2	0-22-50	
				3-11-00	

पश्चिम गोदावरि (आ.प्र.)	निडवयोलु	मदूरु	181-1सी भाग	0-09-50	
			„ 2 „	0-23-50	
			„ 3 „	0-05-50	
			183-भाग	0-03-00	
			182-भाग	0-05-00	जि.पि.
			95-भाग	0-02-50	जि.पि.
			232-9ए भाग	0-15-00	
			„ 9बी „	0-03-50	
			„ 9सी „	0-09-50	
			„ 9डी „	0-03-50	
			234-4 भाग	0-19-00	
			236-1 भाग	0-12-00	
			„ 2 „	0-08-00	
			„ 3एफ „	0-18-50	
			220-3 भाग	0-01-00	
			„ 6 „	0-11-00	
			जोड़.	7-10-50	और ए सी 17.56 सेंट्स

[सं एल.-14016/14/93-जी पी.]

अर्घेन्नु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2847.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Paravali to Dommeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Perawali & Dommeru

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Kovvuru	Madduru	85-4 Part	0-09-00	
			85-6 Part	0-12-00	
			85-7 Part	0-18-00	
			85-8 Part	0-00-50	
			88-1 Part	0-04-00	
			88-2 Part	0-03-00	
			88-5- Part	0-00-50	
			87-Part	0-16-00	
			102 Part	0-38-00	
			103-10 Part	0-06-00	
			103-12 Part	0-10-00	
			104-6 Part	0-00-25	
			101-1A Part	0-03-00	
			100-1 Part	0-02-00	
			100-5 Part	0-16-00	
			103 Part	0-01-00	
			10-4 Part	0-14-00	
			99-1 Part	0-10-50	
			99-2 Part	0-01-00	
			99-5 Part	0-00-25	
			99-6 Part	0-00-50	
			124-2E Part	0-08-00	
			98-1 Part	0-01-00	
			98-2 Part	0-19-50	
			98-3 Part	0-07-50	
			97-1 Part	0-12-50	
			97-5 Part	0-15-00	
			97-8 Part	0-19-50	
			96 Part	0-00-50	G.P.
			125 Part	0-03-50	G.P.
			231-1B Part	0-01-00	
			231-2A Part	0-12-00	
			231-2B Part	0-23-50	
			231-3A Part	0-07-00	
			230-1 Part	0-07-50	
			230-2 Part	0-20-50	
			226-1 Part	0-12-00	
			226-2A Part	0-04-00	
			227-3 Part	0-03-50	
			227-4 Part	0-13-50	
			227-5 Part	0-22-00	
			225-1 Part	0-13-00	
			213-2 Part	0-14-00	
			213-3 Part	0-16-50	

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

और ऐसी आपत्ति दर्ज करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रथम विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## अनुसूची

## गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलि से दोम्मरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
पश्चिम गोदावरि (प्रां. प्र.)	निडदवोलु	विज्जेस्वरम	11-2 भाग	0-34-50	
			10-3 भाग	0-04-00	
			10-2 भाग	0-09-50	
			10-1 भाग	0-14-50	
			7-3 भाग	0-03-00	
			7-2 भाग	0-06-00	
			7-1 भाग	0-18-50	
			4-5 भाग	0-29-00	
			4-6 भाग	0-05-50	
			1- भाग	0-09-00	जि. पि.
			योग	1-33-50 या ए.सी. 3.30 सेंट्स	

[सं. एल.-14016/14/93-जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2848.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dammeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
PERAVALI to DOMMERU

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
West Godavari (A.P.)	Nindadavolu	Vijjeswaram	11-2 Part	0-34-50	G.P.
			10-3 Part	0-04-00	
			10-2 Part	0-09-50	
			10-1-Part	0-14-50	
			7-3 Part	0-03-00	
			7-2 Part	0-06-00	
			7-1 Part	0-18-50	
			4-5 Part	0-29-00	
			4-6 Part	0-05-50	
			1 Part	0-09-00	
			Total	1-33-50	
	or	AC 3.30 Cents			

[No. L-14016/14/93-GP]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2849.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि से दोम्मेरू पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाता है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण (अधिनियम, 1962 1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ;

बशर्त कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिमूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7/1/3/1 राजमंजूरी-533104, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और एसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निश्चित करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलि से दोम्मेरू

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर / एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरि (आ.प्र.)	निडदवोलु	गोपवरम	164-1	भाग 0-20-00	जि. पि.
			165-2	भाग 0-15-00	
			166-1	भाग 0-12-00	
			166-2	,, 0-02-50	
			166-3	,, 0-16-00	
			4	,, 0-01-00	
			166-5	भाग 0-01-00	जि. पि.
			166-6	भाग 0-02-00	
			170-2	भाग 0-29-00	
			,, 1	भाग 0-05-50	
			169-2	भाग 0-06-00	
			167-1	भाग 0-17-50	
			,, 2	भाग 0-01-50	जि. पि.
			100-	भाग 0-23-00	
			95-	भाग 0-36-50	
			94-	भाग 0-03-00	
			49-1	भाग 0-20-50	
			,, 2	भाग 0-07-50	
			50-4	भाग 0-31-00	
			93-	भाग 0-24-00	



1	2	3	4	5	6
			92-3 भाग	0-11-00	
			92-4 भाग	0-11-00	
			91- भाग	0-03-00	जि.पि.
			90-1 भाग	0-08-50	
			90-4 भाग	0-09-50	
			90-3 भाग	0-09-00	
			85-2 भाग	0-13-00	
			86-3 भाग	0-21-50	
			88- भाग	0-01-50	जि.पि.

3-72-50 (या) एसी 9-20 पर सेन्ट

[सं. एन. 14016/14/93-जी. पी.]

प्रर्वेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2849.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dammeru Pipeline to be laid by the Gas Authority of India. Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
Peravali & Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
West Godawari (A.P.)	Nidadavolu	Gopavaram	164-1 Part	0-20-00	
			165-2 Part	0-15-00	
			166-1 Part	0-12-00	
			166-2 Part	0-02-50	G.P.
			166-3 Part	0-16-00	
			166-4 Part	0-01-00	
			166-5 Part	0-01-00	
			166-6 Part	0-02-00	
			170-2 Part	0-29-00	
			170-1 Part	0-05-50	
			169-2 Part	0-06-00	
			167-1 Part	0-17-50	
			167-2 Part	0-01-50	
			100 Part	0-23-00	G.P.
			95-Part	0-36-00	

1	2	3	4	5	6
			94 Part	0-03-00	G.P.
			49-1 Part	0-20-50	
			49-2 Part	0-07-50	
			50-4 Part	0-31-00	
			93 Part	0-24-00	
			92-3 Part	0-11-00	
			92-4 Part	0-11-00	
			91 Part	0-03-00	G.P.
			90-1 Part	0-18-50	
			90-4 Part	0-09-50	
			90-3 Part	0-09-00	
			85-2 Part	0-13-00	
			86-3 Part	0-21-50	
			88 Part	0-01-50	G.P.
			Total	3-72-50 OR AC 9.20 Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2850—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हिा में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि—दोमोरु पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि-टैड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने को मंशा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंड्री—533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है ।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलि—दोमोरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	निडवोलु	पुरुषोत्तपल्लि	1-भाग	0-04-00	जी. पी.
			2-1-भाग	0-01-00	
			2-2-भाग	0-13-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (भा.प्र.)	निडदवोलु	पुरुषोत्तपल्लि	2-11-भाग 2-12-भाग 2-13-भाग 2-14-भाग 4-5-भाग 4-7-भाग 4-8-भाग 4-6-भाग 3-2-भाग 3-3-भाग 3-4-भाग 3-5-भाग 3-6-भाग 3-7-भाग 3-8-भाग 3-9-भाग 3-12-भाग 6-1-भाग 47-4-भाग 47-5-भाग 47-6-भाग 47-7-भाग 47-8-भाग 46-9-भाग 46-10-भाग 46-13-भाग 49-1-भाग 49-2-भाग 49-3-भाग 49-4-भाग 49-6-भाग 50-1 ए -भाग 50-1-पी- भाग 48-8-भाग	0-13-50 005- 50 0-14-25 0-00-25 005-50 005-50 0-07-50 0-00-25 0-03-00 0-03-00 003-00 004-50 003-50 003-00 0-02-00 0-01-50 0-00-50 001-00 0-04-00 006-00 006-00 0-64-50 0-10-00 0-01-00 003-50 0-6-50 0-10-00 0-05-00 0-05-00 0-10-00 0-09-00 0-13-00 0-20-00 001-00	
			जोड़	2-19-75	

[मं. एन 14016/14/93 जी पी]

अर्थेन्नु सैन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2850.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dommeru Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

### SCHEDULE GAS PIPE LINE PROJECT

#### Peravali-Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godawari (A.P.)	Nidadavolu	Purushothapalli	1 Part	0-04-00	G.P.
			2-1 Part	0-01-00	
			2-2 Part	0-13-00	
			2-11 Part	0-13-50	
			2-12 Part	0-05-50	
			2-13 Part	0-14-25	
			2-14 Part	0-00-25	
			4-5 Part	0-05-50	
			4-7 Part	0-05-50	
			4-8 Part	0-07-50	
			4-6 Part	0-00-25	
			3-2 Part	0-03-00	
			3-3 Part	0-03-00	
			3-4 Part	0-03-00	
			3-5 Part	0-04-50	
			3-6 Part	0-03-50	
			3-7 Part	0-03-00	
			3-8 Part	0-02-00	
			3-9 Part	0-01-50	
			3-12 Part	0-00-50	
			6-1 Part	0-01-00	
			47-4 Part	0-04-00	
			47-5 Part	0-06-00	
			47-6 Part	0-06-00	
			47-7 Part	0-14-50	
			47-8 Part	0-10-00	
			46-9 Part	0-01-00	
			46-10 Part	0-02-50	
			46-13 Part	0-06-50	
			49-1 Part	0-10-00	
			49-2 Part	0-05-00	
			49-3 Part	0-05-00	

1	2	3	4	5	6
			49-4 Part	0-10-00	
			49-6 Part	0-09-00	
			50-1 A Part	0-13-00	
			50-1C Part	0-20-00	
			48-8 Part	0-01-00	
			G. Total	2-19-75	

[No. L-14016/14/93-GP]  
AROHENDU SEN, Director

नई दिल्ली 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2851.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरबलि—दोमरे पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाता है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के, जी वसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1-3/1, राजमंडी-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

#### अनुसूची

#### गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

#### पेरबलि—दोमरे

अनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हैक्टे एकड़ में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	निडिदवोलु	पन्डलपुरम	1—भाग	0-06-50	(जि.पि.)
			2-1-भाग	0-03-00	
			2-2-भाग	0-12-50	
			2-3-भाग	0-17-00	
			3-1-भाग	0-06-00	
			3-4-भाग	0-05-50	
			3-5-भाग	0-07-00	

1	2	3	4	5	6
पश्चिम गोदावरी (आ.प्र.)	निडिदवोलु	पम्बलपुरम	3-6-भाग	0-05-50	
			4-1-भाग	0-07-50	
			4-3-भाग	0-07-50	
			4-4-भाग	0-05-50	
			4-5-भाग	0-10-00	
			5-1-सी-भाग	0-00-50	
			5-1डी-भाग	0-07-50	
			5-1ई-भाग	0-01-50	
			5-3ए-भाग	0-19-50	
			5-3बी-भाग	0-00-50	
			5-5-भाग	0-02-50	
			5-6-भाग	0-00-50	
			5-7-भाग	0-00-50	
			15-1ए-भाग	0-00-50	
			15-8-भाग	0-05-00	
			15-9-भाग	0-13-50	
			15-15-भाग	0-03-00	
			15-16-भाग	0-02-50	
			15-17-भाग	0-03-00	
			15-18-भाग	0-03-00	
			15-1ए-भाग	0-04-00	
			17-1डी-भाग	0-03-50	
			17-1 डी-भाग	0-07-50	
			17-1ई-भाग	0-09-50	
			17-1एफ-भाग	0-06-50	
			17-2एम-भाग	0-03-00	
			17-2एन-भाग	0-00-50	
			17-2ओ-भाग	0-01-00	
			17-2 पी-भाग	0-02-50	
			17-2 एस-भाग	0-03-00	
			17-2 टी-भाग	0-03-00	
			17-2 डब्ल्यू-भाग	0-03-00	
			17-2 एक्स-भाग	0-03-00	
			17-2ए-5-भाग	0-06-50	
			कुल जोड़	2-13-50 या एसी 6.28 सेन्ट्स	

[सं एल--14018/14/93 जी.पी.]

अर्धेन्दु मेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2851.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dammeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE  
GAS PIPE LINE PROJECT  
Peravali—Dommeru

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
West Godawari (A.P.)	Nidadavolu	Paudalaparru	1-Part	0-06-60	G.P.
			2-1 Part	0-03-00	
			2-2 Part	0-12-50	
			2-3 Part	0-17-00	
			3-1 Part	0-06-00	
			3-4 Part	0-05-50	
			3-5 Part	0-07-00	
			3-6 Part	0-05-50	
			4-1 Part	0-07-50	
			4-3 Part	0-07-50	
			4-4 Part	0-05-50	
			4-5 Part	0-10-00	
			5-1C Part	0-00-50	
			5-1D Part	0-07-50	
			5-1E Part	0-01-50	
			5-3A Part	0-19-50	
			5-3B Part	0-00-50	
			5-5 Part	0-02-50	
			5-6 Part	0-00-50	
			5-7 Part	0-00-50	
			15-1A Part	0-00-50	
			15-8 Part	0-05-00	
			15-9 Part	0-13-50	
			15-15 Part	0-03-00	
			15-16 Part	0-02-50	
			15-17 Part	0-03-00	
			15-18 Part	0-03-00	
			17-1A Part	0-04-00	
			17-1B Part	0-03-50	

4	5
17-1D Part	0-07-50
17-1E Part	0-09-50
17-1F Part	0-06-50
17-2M Part	0-03-00
17-2N Part	0-00-50
17-2O Part	0-01-00
17-2P Part	0-02-50
17-2S Part	0-03-00
17-2T Part	0-03-00
17-2W Part	0-03-00
17-2X Part	0-03-00
17-2A5 Part	0-06-50
Grand Total	2-13-50 Or AC 5-28 Cents

[No. L-14016/14/93-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2852.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पेरवलि—कोम्मेर पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण, अधिनियम) 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार करने की मंशा को घोषणा करती है।

वशात कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के जी वसीन प्रोजेक्ट 29-7- 1/3/1 राजमंडी 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विणेष रूप से निर्विष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से विधि व्यवसायक के माध्य से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

पेरवलि—दुम्मेरु

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/ एकड़ में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पश्चिमी गोदावरी (आं. प्र.)	निडवालू	कलवचल	248-7-भाग	0-01-00	
			248-8-भाग	0-18-50	
			248-9-भाग	0-20-50	



1	2	3	4	5	
पश्चिम गोदावरी (आं प्र.) लिडदाबोलु	कलवचर्ल	233-2-भाग	0-16-00		
		232-1-भाग	0-05-00		
		232-3-भाग	0-13-00		
		231-1-भाग	0-10-00		
		231-2 भाग	0-06-00		
		231-4-भाग	0-05-50		
		230-1-भाग	0-09-00		
		230-2-भाग	0-10-50		
		230-4ए-भाग	0-00-50		
		230-9-भाग	0-17-50		
		229-2-भाग	0-16-00		
		229-4-भाग	0-03-00		
		229-3-भाग	0-14-00		
		228-भाग	0-07-50		
		237-1-भाग	0-02-50		
		237-2-भाग	0-09-00		
		237-3-भाग	0-11-50		
		212-1-भाग	0-05-50		
		212-5-भाग	0-09-00		
		212-6-भाग	0-10-00		
		212-7-भाग	0-05-50		
		211-1-भाग	0-05-50		
		211-2-भाग	0-05-50		
		211-9-भाग	0-00-50		
		211-10-भाग	0-07-50		
		120-भाग	0-03-00		
		119-1-भाग	0-18-00		
		2-भाग	0-00-50		
		3-भाग	0-10-00		
		10 सी-भाग	0-00-25		
		11-भाग	0-09-50		
		124-1-भाग	0-15-00		
		4-भाग	0-13-50		
		5-भाग	0-13-00		
		102-भाग	0-05-50		जीपी
		104-1 बी-भाग	0-07-00		
		104-2ए-भाग	0-12-00		
		127-1-भाग	0-05-50		
		127-2-भाग	0-11-50		
		127-3 बी-भाग	0-13-50		
		127-6-भाग	0-09-50		
		127-8ए-भाग	0-07-00		
		127-9बी-भाग	0-06-50		

1	2	3	4	5	6
			127-9-भाग	0-08-50	
			94-1-भाग	0-10-00	
			94-2-भाग	0-03-00	
			94-5-भाग	0-07-50	
			94-6-भाग	0-06-50	
			94-7-भाग	0-02-50	
			92-2-भाग	0-22-00	
			92-1-भाग	0-09-50	
			92-3-भाग	0-09-00	
			96-1-भाग	0-22-50	
			89-भाग	0-12-00	
			79-2ए-भाग	0-12-00	
			79-2 बी-भाग	0-09-50	
			79-3-भाग	0-01-50	
			79-4-भाग	0-03-00	
			80-5ए-भाग	0-01-00	
			80-5 बी-भाग	0-02-00	
			80-6-भाग	0-09-00	
			86-1-भाग	0-11-50	
			85-2ए-भाग	0-01-50	
			85-2 बी भाग	0-02-00	
			85-2 सी भाग	0-02-50	
			81-1-भाग	0-14-50	
			81-2-भाग	0-16-00	
			81-2-भाग	0-16-00	
			82-भाग	0-02-80	
			Total	2-63-00	
			1st page Total	3-24-25	

5-87-28 or Ac 14-50 Cents

[सं. एल-14016/14/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2852.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Peravali to Dammeru Gas pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-13/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Pervali-Dommeru**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
West Godavari (A.P.)	Nidadavolu	Kalavacharla	248-7 Part	0-01-00	G.P.
			248-8 Part	0-18-50	
			248-9 Part	0-20-50	
			233-2 Part	0-16-00	
			232-1 Part	0-05-00	
			232-3 Part	0-13-00	
			231-1 Part	0-16-00	
			231-2 Part	0-06-00	
			231-4 Part	0-05-50	
			230-1 Part	0-09-00	
			230-2 Part	0-10-50	G.P.
			230-4A Part	0-00-50	
			230-9 Part	0-17-50	
			229-2 Part	0-16-00	
			229-4 Part	0-03-00	
			229-3 Part	0-14-00	
			228-Part	0-07-50	
			237-1 Part	0-02-50	
			237-2 Part	0-09-00	
			237-3 Part	0-11-50	
			212-1 Part	0-05-50	G.P.
			212-5 Part	0-09-00	
			212-6 Part	0-10-00	
			212-7 Part	0-05-50	
			211-1 Part	0-05-50	
			211-2 Part	0-05-50	
			211-9 Part	0-00-50	
			211-10 Part	0-07-50	
			120-Part	0-03-00	
			119-1 Part	0-18-00	G.P.
			119-2 Part	0-00-50	
			119-3 Part	0-10-00	
			119-10C Part	0-00-25	
			119-11 Part	0-09-50	
			124-1 Part	0-15-00	
			124-4 Part	0-13-50	
			124-5 Part	0-03-00	
			102-Part	0-05-50	
			104-1B Part	0-07-00	G.P.
			104-2A Part	0-12-00	
			127-1 Part	0-05-50	
			127-2 Part	0-11-50	
			127-3B Part	0-13-50	
			127-6 Part	0-09-50	

1	2	3	4	5	6
West Godawari (A.P.)	Nidadavolu	Kalavacharla	127-8A Part	0 07 00	
			127-8B Part	0 06 50	
			127-9 Part	0 02 00	
			94-1 Part	0 10 00	
			94-2 Part	0 03 00	
			94-5 Part	0 07 50	
			94-6 Part	0 06 50	
			94-7 Part	0 02 50	
			92-2 Part	0 22 00	
			92-1 Part	0 09 50	
			92-3 Part	0 09 00	
			96-1 Part	0 22 50	
			89-Part	0 02 00	G.P.
			79-2A Part	0 12 00	
			79-2B Part	0 09 50	
			79-3 Part	0 01 50	
			79-4 Part	0 03 00	
			80-5A Part	0 01 00	
			80-5B Part	0 02 00	
			80-6 Part	0 09 00	
			86-1 Part	0 11 50	
			85-2A Part	0 01 50	
			85-2B Part	0 02 00	
			85-2C Part	0 02 50	
			81-1 Part	0 14 50	
			81-2 Part	0 16 00	
			82-Part	0 02 50	G.P.
			Ist Page Total	3 24 25	
Total				5-87-25 AC 14-Cents	

[No. L-14016/14/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2853.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए नरसापुरम पेरवलि पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरुद्ध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बेसिन प्रोजेक्ट 29-7-1/3/1 राजमंडी-533 104 आन्ध्र प्रदेश प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

अनुसूची  
गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
नरसापुरम — पेरवल्लि

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे/एकड़ में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)
पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	पेन्तुगोतड़	चेरु कुवाडा	160-भाग	0-02-50	
			161-1-भाग	0-11-50	
			162-2-भाग	0-05-50	
			162-3-भाग	0-04-00	
			162-6-भाग	0-10-50	
			168-2-भाग	0-02-00	
			168-3 बी-भाग	0-01-00	
			162-4ए-भाग	0-03-00	
			162-4बी-भाग	0-10-00	
			171-4 बी-भाग	0-04-00	
			171-6-भाग	0-08-00	
			171-7-भाग	0-03-50	
			172-5-भाग	0-15-50	
			173-6 बी भाग	0-00-50	
			173-7-भाग	0-09-00	
			173-8-भाग	0-09-50	
			260-3-भाग	0-05-00	
			260-4-भाग	0-01-50	
			260-5-भाग	0-01-00	
			260-2-भाग	0-07-50	
			259-3 बी भाग	0-27-00	
			259-3 ए भाग	0-01-00	
			259-4 बी-भाग	0-07-50	
			259-4 सी भाग	0-08-00	
			253-1-भाग	0-15-00	
			253-2 भाग	0-07-50	
			253-3 भाग	0-03-00	
			253-4 भाग	0-05-00	
			253-6-भाग	0-00-50	
			251-2-ए भाग	0-01-00	
			251-2 बी भाग	0-05-50	
			252-1 भाग	0-11-50	
			252-2-भाग	0-08-00	
			252-3-भाग	0-04-50	
			252-7-भाग	0-09-50	

4	5	6
200-1-भाग	0-01-50	जि. पि.
200-2-भाग	0-05-50	
200-3ए-भाग	0-03-00	
200-3बी-भाग	0-03-00	
200-3सी-भाग	0-05-50	
200-4ए-भाग	0-06-50	
200-4बी-भाग	0-04-00	
200-4डी-भाग	0-01-50	
199-1बी-भाग	0-13-00	
199-2ए-भाग	0-16-00	
199-2बी-भाग	0-01-50	
198-4-भाग	0-00-50	
209-2-भाग	0-00-50	जि. पि.
208-1-भाग	0-01-00	जि. पि.
208-2-भाग	0-03-00	जि. पि.
211-2बी-भाग	0-20-00	
212-3-भाग	0-15-50	
213-2-भाग	0-19-50	
216-भाग	0-19-00	
216ए-भाग	0-33-50	
जोड़	4-03-00 या ऐसी 9.96 सेक्टर	

[सं. एल 14016/14/93 जी पी]  
अर्धेन्दु से निदेशक

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2853.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas through Narasapuram to Peravali pipeline to be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum

& Minerals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

**SCHEDULE**  
**GAS PIPE LINE PROJECT**  
**Narasapuram to Peravali**

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
West Godawari (A.P.)	Penugonda	Cherukuvada	160-Part 161-1 Part	0-02-50 0-11-50	G.P.

1	2	3	4	5	6
West Godawari (A.P.)	Penugonda	Chervukavada	162-2 Part	0-05-50	
			162-3 Part	0-04-00	
			162-6 Part	0-10-50	
			168-2 Part	0-02-00	
			168-3B Part	0-01-00	
			168-4A Part	0-03-00	
			168-4B Part	0-10-00	
			171-4B Part	0-004-00	
			171-6 Part	0-208-00	
			171-7 Part	0-03-50	
			172-5 Part	0-15-50	
			173-6B Part	0-00-50	
			173-7 Part	0-09-00	
			173-8 Part	0-09-50	
			260-3 Part	0-05-00	
			260-4 Part	0-01-50	
			260-5 Part	0-01-00	
			260-2 Part	01-0-50	
			259-3B Part	0-27-00	
			259-3A Part	0-01-00	
			259-4B Part	0-07-50	
			259-4C Part	0-08-00	
			253-1 Part	0-15-00	
			253-2 Part	0-07-50	
			253-3 Part	0-03-00	
			253-4 Part	0-05-00	
			253-6 Part	0-00-50	
			251-2A Part	0-01-00	
			251-2B Part	0-05-50	
			252-1 Part	0-11-50	
			252-2 Part	0-08-00	
			252-3 Part	0-04-50	
			252-7 Part	0-09-50	
			200-1 Part	0-01-50	G.P.
			200-2-Part	0-05-50	
			200-3A Part	0-03-00	
			200-3B Part	0-03-00	
			200-3C Part	0-05-50	
			200-4A Part	0-06-50	
			200-4B Part	0-04-00	
			200-4D Part	0-01-50	
			199-1B Part	0-13-00	
			199-2A Part	0-16-00	
			199-2B Part	0-01-50	
			198-4C Part	0-00-50	
			209-2 Part	0-00-50	G.P.
			208-1 Part	0-1-00	G.P.
			208-2 Part	0-00-00	G.P.
			211-2B Part	0-20-00	
			212-3 Part	0-15-50	
			213-2 Part	0-19-50	
			216-Part	0-19-00	
			216A Part	0-33-50	
Total				4-03-00	or AC 9.96 Cnts

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. आ. 2854—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25/11/93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/15/एफ/93-आई आर.-सी II]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2854.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of FCI and their workmen, which was received by the Central Government on 25-11-93.

[No. L-22012/15/F/93-IR-CII]

RAJA LAL, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU MADRAS

Thursday, the 21st day of October, 1993

## PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A. B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 47/1993

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of Food Corporation of India, Madras).

## BETWEEN

The Zonal Secretary, Food Corporation of India Employees Union, 24/25, Ranganathan Street, T. Nagar, Madras-17

## AND

The Zonal Manager, Food Corporation of India, No. 2, Haddows Road, Nungambakkam, Madras-6.

## REFERENCE :

Order No. L-22012/15/F/93-IR(C.II), dated 13-5-93, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day or final disposal in the presence of Thiru S. Vaidyanathan, for Thiruvalluvar Row and Reddy, Advocates appearing for the workmen, upon perusing the reference and other connected papers on record and the workmen having not filed the claim statement, this Tribunal passed the following

## AWARD

This dispute between the Workmen and the Management of Food Corporation of India, Madras arises out a reference under Section 10(1)(d) and Sub-section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India, for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India, in imposing wage cut for 16-9-91 in respect of the members of Employees Union is justified? If not, to what relief they are entitled to?"

Claim statement not filed. Further time refused. Petitioner called absent. Industrial dispute dismissed for default. No costs.

Dated, this the day of October, 1993

THIRU R. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. आ. 2855—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इद्वयुं सी एल. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बम्बई नं. 1 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/403/91 आई आर सी-II]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2855.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 1 as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of WC Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25-11-93.

[No. L-22012/403/91-IRC-II]

RAJA LAL, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

## PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-45 of 1992

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Rajur Colliery of W.C. Ltd.

## AND

Their workmen

## Appearance :

For the Management—Shri G. S. Kapoor, Advocate.

For the Workman—No appearance.

INDUSTRY : Mining

STATE : Maharashtra

Chandrapur, dated the 5th day of November, 1993  
(Dictated in the open Court during the camp Court sitting at Chandrapur, from 3rd November, 1993 to 5th November, 1993)

## AWARD

The following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour by letter dated 24-2-1992.

"Whether the termination of services of Shri Firangi Bhagwan, Loader, from 7-7-1991 by the Sub Area Manager, W.C. Ltd., Dist. Yeotmal, Wani Area, is legal and justified? If not to what relief the workman entitled to?"

This reference came up before me on 4-11-1993. There was no appearance on behalf of the workman and therefore, the matter was adjourned to 5-11-1993. Today also, there is no appearance on behalf of the workman. The workman has been served with the notice of this hearing at Chandrapur, and the management has filed an affidavit in support of the service. In spite of this, the workman has not appeared nor, filed any statement of claim.

It is to be noted that after receipt of this reference, in June, 1992, notices were sent to both the parties. There was no appearance on behalf of the workman in spite of the fact that the notice was duly served on him. Thereafter, the matter came to be adjourned and came up before me for hearing at Nagpur on 17-8-1993, 18-8-1993 and



20-8-1993, and notice of the same was issued to the Union. Thereafter the matter was fixed at Chandrapur on 4-11-1993 and for which notice was sent through the management representative. However, he did not avail of these opportunities. It is therefore, evident that the workman is not interested in getting this dispute adjudicated. The reference is disposed off, award accordingly with no order as to costs

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. आ. 2856—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम ई सी एल. के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 25 नवम्बर, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्याएल-22012/171/92-आईआर (सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2856.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25th November, 1993.

[No. L-22012/171/92-IR C-II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR  
PRESENT:

Sri R. K. Dash, I.L.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.  
Industrial Dispute Case No. 46 of 1992 (Central)  
Dated, Bhubaneswar, the 16th November, 1993

BETWEEN

The management of Ib Valley Area of South Eastern Coalfields Ltd., P.O. Brajragnagar, District Sambalpur (Orissa) z ...First party—

management.

AND

Their workmen represented through Brajragnagar Coal Mines Workers Union, At Lamtibahal, P.O. Brajragnagar, District Sambalpur. ...Second party—  
workmen.

APPEARANCES:

None—For both the parties.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon it by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-22012/171/92-IR (C. II) dated 22nd October, 1992:—

“Whether the action of the management of South Eastern Coalfields Ltd., Ib Valley Area, Brajragnagar, District Sambalpur (Orissa) in deducting 8 days wages of the workmen of Bundia Mines for not performing any duty on 5th April, 1991 was justified?

If not, to what relief the workmen are entitled to?”

2. In this case both parties remained absent on the date of hearing despite of notice by registered post. As it appears

they have lost interest in the ‘lis’. In absence of any material, it is difficult to answer the reference in either way. In the circumstance, I have no other alternative but to pass a no dispute award in the case. Accordingly, a no dispute award is passed in so far as the present reference is concerned.

R. K. DASH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. आ. 2857—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू सी एल के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई नं. 1 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्याएल-22012/455/91आईआर (सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2857.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of W.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25th November, 1993.

[No. L-22012/455/91-IR C-II]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

PRESENT:

Shri Justice R. G. Sindbakar, Presiding Officer.  
Reference No. CGIT-11 of 1992

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ballarpur Colliery of W.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Management—Shri G. S. Kapoor, Advocate.

For the Workman—Workman present in person.

INDUSTRY: Mining.

STATE: Maharashtra.

Chandrapur, dated the 3rd day of November, 1993  
(Dictated in the open Court during the camp Court sitting at Chandrapur, from 3rd November, 1993 to 5th November, 1993).

AWARD

The following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, by letter dated 24th February, 1992:—

“Whether the dismissal of Shri Jagguwar, Trammer-cum-Loader from 13th April, 1991 by the Superintendent, Ballarpur Colliery, W.C. Ltd., Ballarpur 3 and 4 Pits is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. Statement of claim as well as written statement has been filed. The employer has also filed the papers of enquiry report and the order passed by the Disciplinary Authority.

3. It appears that the workman was charge sheeted on the allegation that he assaulted his co-worker on duty. The Enquiry Officer held him guilty of the charge under clause 13(i) and 27 of the Standing Order applicable to him, and the Competent Authority accepted the findings and imposed the penalty. It is against this penalty, that the workman entertains the present grievance and thus the present reference has been made to this Tribunal.

4. The matter was fixed at Chandrapur to suit the convenience of the parties and when it came up before me, today, the workman as well as the management filed a settlement to the dispute. A joint petition has also been filed for passing an award based on consent.

5. As per the terms of the settlement, the workman is being re-employed on the post which he held at the time of his termination and he is allowed to join duties within 30 days from the date of the consent award, which is 3rd November, 1993. He will be joining at a place to which he is posted by the General Manager Personnel. He will be not entitled to payment for the intervening period during which he had not worked. He shall be on probation for a period of one year and his conduct and performance will be watched during this period. If it is found satisfactory, his services will be confirmed and continuity of service will be given only for the limited purpose of gratuity.

6. The terms of the settlement shall be treated as a final settlement of the issues covered by the reference. No further claim shall be made by the workman or any Trade Union on his behalf in that behalf. The settlement appears to be fair, reasonable and in the interests of the parties. The terms and conditions have been explained to the workman in the open court, in the presence of Shri Babulal Sirpal, who is present in the Court to safeguard the interest of the workman, while passing the consent award.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. अ. 2858.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उल्लू सी एल. के प्रबन्धन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई नं. 1 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-18012/4/81-डी बी (पार्ट)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2858.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 1 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of W.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25th November, 1993.

[No. L-18012/4/81-D.V(B)(Pt.)]  
RAJA LAL, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.  
Reference No. CGIT-63 of 1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of Umrer Colliery of W.C. Ltd.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management—Shri Badar, Advocate.

For the Workmen—Shri S. D. Shukla, Advocate.

INDUSTRY : Mining. STATE : Maharashtra.  
Bombay, dated the 10th day of November, 1993

## AWARD

By order dated 26th August, 1992, the following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

"Whether the action of the management of Umrer Colliery of W.C. Ltd. in terminating the services of their workman Shri Harish Chandra S/o Laxmidhar Das, Ex-Dozer Operator of Umrer Colliery w.e.f. 1st November, 1980 is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Statement of claim has been filed by the workman, and the same has been replied to, by written statement by management. To understand the nature of the dispute between the parties, it would be better to set out the following undisputed facts. Shri Harishchandra Lakshmidhar Das was appointed as a Dozer Operator on 10th February, 1960 by the National Coal Development Corporation. The posting was at Hazaribag in Bihar State. In 1970, he came to be transferred to the Umrer Colliery under the Western Coalfields Limited. Initially, he was a daily wager, and after completion of 6 months his services were confirmed. At the time of the impugned order of dismissal, he was drawing Rs. 37.50 (Ps.) per day.

3. According to him, he had an unblemished record right from 1960. On 6th July, 1979, the charge sheet came to be served on him alleging that on 18th August, 1978, he was negligent in operating the Dozer, which resulted in the death of Mr. Sunil Pathak, an employee. It was further alleged that he deliberately suppressed this fact. By doing so, he contravened the provisions of the Regulation 190 of the Coal Mines Regulations 1967. He replied to the charge sheet denying the same, mentioning that he has not committed any misconduct.

4. He further states that the show of enquiry was made and he was punished by an order of dismissal from service. He contends that he was denied the assistance of a co-worker in the departmental enquiry. As against this, he states that the management was represented by Mr. O. P. Srivastava, a legally trained person, experienced in conducting Departmental Enquiry. He further contends that he was unable to defend himself in the enquiry and calls the enquiry a farce.

5. He further contends that though asked for a copy of the enquiry report, the same was not supplied to him till the order of dismissal was passed. Therefore, according to him, the management failed to comply with the principles of natural justice and contravened the provisions of Standing Order No. 17(2). He was not given any opportunity to show cause against the findings of the Enquiry Officer.

6. He further stated that the finding of the Enquiry Officer are perverse and not based on any legal evidence. His contention is that there was no material to show the cause for the death of Mr. Sunil Pathak, and he was not supplied with any copy of the postmortem report. He, therefore, states that there was no evidence whatsoever to show that he had operated the Dozer negligently and dangerously, causing the death of a co-worker, and that he concealed the fact of the death of Mr. Sunil Pathak.

7. He further states that the police were moved in this behalf, and they took no action clearly indicating that he was innocent. He, therefore, prayed that the order be set aside and he be reinstated in service.

8. The management challenged the contentions raised by and on behalf of the workman. According to them, there is material on record to show that he was guilty, and the Enquiry Officer held him guilty of the charges levelled against him after giving him opportunity and following the rules of natural justice. They further contended that the findings recorded by the Enquiry Officer were justified.

9. The points those would arise for consideration would be as follows :

- (1) Whether the Departmental Enquiry was legal proper and fair ?
- (2) Whether the findings of the Enquiry Officer are perverse?
- (3) Whether a fresh enquiry is found necessary ?
- (4) What relief if any, the workman is entitled to?

10. So far as the grievance of the workman is concerned, it is to be noted that the charge against the workman was that while operating the dozer, he did so, negligently and dangerously, and caused the death of Shri Sunil Pathak, a co-worker. A charge-sheet was served upon him and he was called upon to reply the same within 45 hours. This, according to the workman was impermissible and unjustified. It is to be noted that the incident took place on 18-8-1978 and the chargesheet was served on him on 16-7-1979, that is, after a lapse of about 11 months. If there was no hurry in framing the charges against him, and in starting the departmental enquiry, there was hardly any reason for reducing the time given to reply to 45 hours.

11. It is also to be noted that the Standing Order 17(2) says that "Where after an enquiry, it is proposed to dismiss a workman, a copy of the enquiry proceedings shall be given to him at his request."

12. It is to be noted that in this particular case, the workman has asked for the enquiry papers and the report by his letter dated 29-7-1980 (Annx-I). By reply dated 29-8-1980, the Personnel Manager informed that the matter will be dealt with under the provisions of Standing Order No. 17(ii), and a copy of the report was supplied to him only alongwith the dismissal order, and that is evident from the order itself.

It is mentioned therein that "The Enquiry Officer appointed to hold such enquiry has since completed the enquiry and submitted his report containing his finding. The copy of that report is enclosed herewith."

13. It is by this order dated 31-10-1980, Shri Das came to be dismissed. Therefore, there is contravention of section 17(2) inasmuch as copy of the report was not given to him though demanded by him. It is obvious that he was not called upon to say why the report of the Enquiry Officer should not be accepted. It can be seen that the management did not apply its mind, and therefore, the action is improper and illegal, and it amounted to an unjust order.

14. The grievance of the workman is that he was not given assistance of a co-worker. However, it is seen from the record that though he was told at the commencement of the enquiry that he would be at liberty to take assistance of a co-worker, he informed the Enquiry Officer that he did not want assistance of the co-worker. It is therefore, not possible to accept that part of the grievance made by the workman. At any rate, as stated above, contravention of Standing Order 17(2), in not supplying a copy of the enquiry report is proved.

15. It was urged on behalf of the workman, that the Enquiry Officer relied upon certain material which was not supplied to the delinquent workman. He states that the Enquiry Officer has during the course of the enquiry, referred to the report of Shri A. R. Reddy, Dy. Director of Mines Safety who conducted an enquiry on 24-8-1978. He submits that in this report Shri Reddy, the Dy. Director of Mines Safety stated that considering the seriousness of the misconduct, ..... severe punishment be awarded.

16. The learned counsel submits that the Enquiry Officer referred to the Director of Mines Safety's report while recording his finding. The submission made on behalf of the management in this connection is that, the Enquiry Officer did not make use of the report/findings of the Director Mines Safety. I am unable to agree with him. On going through the findings recorded by the Enquiry Officer it is evident that the Enquiry Officer heavily relied upon the findings of the Mines Safety Officer. This is what he observes : "The Directorate of Mines, Safety Nagpur Region, had after a detailed enquiry found Shri H. C. Das guilty of contravening Reg. 190 of Coal Mines, Regulation 1957 and also of deliberately concealing the body of Sunil Pathak under the heapsof coal over which he dozed to make the coal surface plain." He also mentions : "I have also closely observed him while he was brought at the enquiry, he appeared to be suffering from a guilty conscience all through the proceedings." This shows the approach of the Enquiry Officer.

17. The next defect in the enquiry is that the findings could never have been reached on the material which was available to the Enquiry Officer. In this connection, it is to be noted that the Enquiry Officer has recorded the evidence of Shri Dhudhe, Fitter Gr-III. According to the evidence of this witness, he was in the canteen at about 11.13 p.m. alongwith Shri Sunil Pathak. He sent Shri Sunil Pathak to the Coal Handling Plant to check the Dozer No. 39, which was being operated by Shri H. C. Das and Sunil Pathak went to Dozer No. 39, at about 0.15 hours. This is the evidence he gave. According to him around 1.00 a.m. Shri Das came to the canteen, he asked Mr. Dhudhe to check Dozer No. 39. Mr. Dhudhe told him that he has sent Mr Sunil

Pathak to check Dozer No. 39, in reply Das told him that no body had come to him at Dozer No. 39. Therefore, it can be seen that right from the beginning, Mr. Das was stating that he has not met Mr. Sunil Pathak at all. Now, the other witness examined on behalf of the management Shri Hardayal Singh says that Mr. Das came to Quarry No. 1 with Dozer No. 39, at about 1.30 a.m. and that the dozer did not work as the gear box seal was leaking.

18. Mr. Amarsingh, another witness, told that while he was at the canteen, alongwith Sunil Pathak, and Dhudhe, Das came to the canteen at about 1.00 a.m. and that after tea, Sunil Pathak went to quarry No. 2. Once again I find that this witness has not been cross-examined by the delinquent and therefore, whatever, the said witness Shri Dudhe stated came to be read in evidence.

19. The next witness examined is Dr. Sonsetty. He is a Doctor. He states that the body of Shri Sunil Pathak was in a highly decomposed state and exact cause of death could not be ascertained.

20. Witness No. 6 is Shri S. V. Pathak, who is an uncle of Shri Sunil Pathak, and he states that; finally the 3rd blade brought out the body of Sunil Pathak. He further stated that the matter was intimated to the S.A.M. and to the Police. . . . At the time I became certain that Shri Das knew about the burial of the body of Shri Sunil Pathak, I also informed the S.A.M. of my suspicion. The entire material that has been placed in my opinion cannot justify a finding that it was the delinquent who was responsible for the death of Shri Sunil Pathak. All that has been stated is that it was not a normal dozing area, from where the dead body was found and that it was found when the delinquent workman was taking it out. From all this material it is impossible to draw an inference that the workman was responsible. I do not see how in view of this material it can be concluded that the delinquent workman was responsible for driving the Dozer negligently towards Sunil Pathak thereby causing his death.

21. Advocate Shri Bader appearing on behalf of the management submitted that for criminal proceedings, circumstantial evidence is not sufficient, but it can be accepted in a departmental enquiry. Reference was made to a decision of the Supreme Court in the case between Jeewan Mal Kochar Vs. Union of India, reported in the year 1983—4SCC, p. 148. The head note reads therein that; "the Statutory rules and the Principle of Natural Justice not violated—Head Supreme Court's interference with the concurrent findings of the departmental authorities and High Court not called for—". Here, in this case, it can be seen that there is violation of the principles of natural justice in so far as no copy of the enquiry report has been given to the delinquent workman, and also that he was given only 45 hours to reply to the charges levelled against him. The Enquiry Officer was also biased in so far as he relied upon the report of the Dy. Director Mines Safety. Without giving delinquent copy thereof Enquiry Officer seems to have been considerably influenced thereby.

22. In another decision in the case between the management of Balpara Tea Estate, and its workmen reported in AIR-1960, page 191, it has been observed that—

"In making an award in an industrial dispute referred to it, the Tribunal has not to decide itself whether the charge framed against the workman (in this case falsification of funds) has been established to its satisfaction. It has only to be satisfied that the management of a business concern was justified in coming to the conclusion that the charge against the

workman was well founded. If there is finding by the Tribunal that the management has been actuated by any sinister motives, or has indulged in unfair labour practice or that the workman has been victimised for any activities in connection with the Trade Union activities, it may have reasons to be critical of the enquiry held by the management."

It further observed that:—

"The Tribunal misdirects itself in judging the case against the workman concerned afresh on its merits as if it were a trial for a criminal offence for the falsification of accounts and misappropriation of funds. In doing so, the Tribunal, is not only sitting as a Court of appeal on the order of dismissal passed by the management, even though it does not find any mala fides or want of good faith or any irregularity in the proceedings, taken by the management against the workman concerned but it also lays down a wrong approach to the case."

It is not that the Tribunal is sitting in appeal over the Enquiry Officers' findings. However total lack of evidence to lead to the conclusion reached by the Enquiry Officer has to be taken into account. In view of the above, and in consideration of the facts and circumstances of this present case, I find that there is violation of the principles of Natural Justice so far as not supplying a copy of the enquiry report, though asked for, under section 17(2) Standing Orders and also that the delinquent workman was given only 45 hours time to reply to the charge sheet. The Enquiry Officer did not refer to the evidence recorded while deciding about it, and he relied upon the earlier report by the Mine Safety Officer. In my opinion, under the circumstances, the order of dismissal passed against the workman is bad in law and unjustified, and it has to be set aside and the management should be directed to reinstate the workman with full back wages.

23. During the course of the argument the counsel informed that the workman would have retired ordinarily on attaining the age of superannuation in 1992, and therefore, it is not possible to reinstate the workman if so directed by this Tribunal. Under these circumstances, he will be entitled to the wages for the period between 31st October, 1980 and the actual date of his retirement, which the management shall pay. Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. ग्रा. 2859.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिनियर पोस्टर ग्राफ पोस्ट ऑफिस सिनियर सुपरिन्टेण्डेंट ग्राफ पोस्ट ऑफिस बंगलौर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम लेबर कोर्ट बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25 नवम्बर, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-40012/158/91 आई आर डी यू]  
के. वी. बी. उष्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2859.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of The Sr. Post of

Post Office, O/o Sr. Supdt. of Post Office, Bangalore and their workmen, which was received by the Central Government on 25-11-1993.

[No. L-40012/158/91-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

# ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, this 17th day of November, 1993

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding Officer.

Central Reference No. 13/92

## I PARTY :

G. V. Venkateshaiah,  
S/o Late Sri Venkatanarasappa,  
No. 99, I Main Road,  
Seshadripuram,  
Bangalore-560020.

(By Sri M. S. Anandaramu, Advocate)

V/s.

## II PARTY :

The Sr. Supdt. of Post Offices,  
O/o. Sr. Supdt. of Post Office,  
Bangalore South Dvn.,  
Bangalore-560041.

(By Sri M. C. Ravikumar, Advocate)

## AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its Order No. L-40012/158/91-IR (DU) dated 23-1-92 under Section 10(2-A)(1)(d) of I. D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

"Whether the Department of P&T (Sr. Supdt. of Post Office), Bangalore is justified in dismissing the services of Sr. G. V. Venkateshaiah, Postal Asstt. ? If not, what relief he is entitled to ?"

2. In the claim statement the I party workman has contended :—

The I party workman was appointed as postal assistant w.e.f. 20-10-83 in relaxation of recruitment rules because the I party was an outstanding sportsman (kabbadi player). After he completed practical training, he was posted as postal assistant w.e.f. 14-9-83. The I party workman has earned annual increments. Though the I party workman was working sincerely, he received a notice of termination (Ex. M-8) dated 8-12-86 and by that notice his services were to be terminated after expiry of a period of one month from the date of receipt of that notice. The I party workman preferred appeal before the Post Master General. The appeal was rejected. The termination of the services of the I party is illegal. The termination of the services of the I party is on the ground of alleged misconduct of unauthorised absence from duty. The order of termination could not have been passed without holding an enquiry against the I party. The I party workman has continuously worked for more than 240 days in a year. Provisions of Sec. 25-F of I.D. Act have not been followed.

3. As has been already stated the I party workman was appointed relaxing the rules of recruitment. The provisions of Central Civil Service (Temporary Service) Rules 1965 under which the services have been terminated have no application. The I party workman was not placed on probation initially. The notice of termination (Ex. M-8) is illegal. In any view of the matter the order of termination is illegal. The II party has committed unfair labour practice. The I party has shown sufficient reasons for his absence. The order of termination has to be set aside and the I party workman should be reinstated with back wages.

4. In the counter statement it is contended :—

This Tribunal has no jurisdiction to entertain the matter since it relates to service conditions. The I party should have gone to Central Administrative Tribunal. The performance of the I party was not satisfactory. He was negligent. He used to absent himself without permission. It is not true that the I party had a good record of service. Minor penalty of withholding of one increment for a period of 3 months was imposed on the I party. The I party was considered for quasi permanency, but it was not granted since he had undergone punishment and was irregular in attendance. The I party did not improve though opportunities were given to him to improve. So his services were terminated as per Ex. M-8 which was delivered to I party on 27-1-87. I party's services stood terminated w.e.f. 26-2-87. The services of I party were terminated as per C.C.S. Rules governing temporary appointments. It is true that the I party workman had put in service of more than 240 days continuously. But the provisions of I. D. Act are not applicable. Application of Section 25-F etc. does not arise. The order of termination is valid. Holding of a departmental enquiry in cases of termination of service under Rule 5(1) of CCS Rules is not mandatory. It is not true that the services of I party were confirmed. The post of I party was temporary. The action taken by the II party against I party terminating his services is legal. The reference has to be rejected.

5. On 4-8-92, as could be seen from the order sheet, it is stated that the point for adjudication is covered by the schedule to reference and no separate issues are required. It is also made clear that all other subsidiary points would be considered at the time of final arguments.

6. On behalf of the II party MW-1 Narasimhachar, Sr. Supdt. of Post Office, Bangalore (Since retired) has been examined. On behalf of the I party he has got himself examined and closed his case.

7. At the outset a small discrepancy in the reference made has to be mentioned. The reference says that the I party was dismissed. The order of termination Ex. M-8 passed under Rule 5(1) of C.C.S. (Temporary Service) Rules, 1965 says that the services of the I party shall stand 'terminated' w.e.f. the date of expiry of period of one month from the date on which notice was served on the I party.

8. MW-1 Narasimhachar who was the then Superintendent of Post Office has stated that the I party workman was appointed as per Ex. M-1. Ex. M-1 shows that the I party was appointed as time scale postal Assistant in relaxation of normal rules of recruitment. The normal rules of recruitment were relaxed, as is clear from Ex. M-1, because the I party workman was an outstanding sportsman (Kabbadi player). No doubt Ex. M-1 says that the appointment is purely temporary and the appointment was subject to the provisions of C.C.S. (Temporary Service) Rules, 1965.

9. Ex. M-8 is the order passed by MW-1 terminating the services of the I party workman under Rule 5(1) of the CCS (T.S.) Rules 1965. Ex. M-8 dated 8-12-86 says that the services of the I party shall stand terminated w.e.f. the date of expiry of a period of one month from the date on which the notice was served on the I party. MW-1 has stated that finding that I party was a trouble to the department, notice as per Ex. M-6 was issued. He has further stated that notice Ex. M-6 was issued because the I party workman remained absent as per Ex. M-7. What is clear is that the services of the I party workman were terminated as per M-8 because of the absence of I party as mentioned in Ex. M-7. As per Ex. M-7 the I party was absent for the following periods :—

11-2-86 to 15-2-86

3-3-86 to 5-3-86

12-3-86 to 14-5-86 (in several spells)

17-6-86 to 19-6-86

3-7-86 to 26-7-86

17-10-86 to 21-10-86

6-11-86 to 19-11-86

He has again applied for 12 days leave from 2-12-86 to 13-12-86.

10. MW-1 who terminated the services of I party workman as per Ex. M-8, has admitted in cross examination that for the periods stated in Ex. M-7 the I party had applied for leave. MW-1 has further admitted that he has passed orders on the leave applications, regarding the kinds of leave mentioned in Ex. M-7, regularising the leave applied for by the I party. It bears repetition. The services of I party were terminated as per Ex. M-8 because he remained absent for the periods mentioned in Ex. M-7. The periods for which the I party was absent have admittedly been regularised by granting him the leave. Thus I party has been removed for absence which has been regularised.

11. "In *G. Papaiah v/s. Asst. Director (Medical Services)* (ATR 1976 AP 75) it has been held that when once leave is granted to a public servant, in respect of a particular period, it must be considered that he is permitted to absent himself from duty for that period. In such a case, it is not permissible or open to the employer or any other authority to proceed against him for absence from duty for the same period and punish him. In *Bhur Singh, Hari Singh Rajput v/s. The State of Gujarat* (1982 (1) SLJ 697) it was held that once the leave is sanctioned of whatever character it might be the sting from that absence is taken away. It was held that in such a case, the disciplinary authority cannot impose punishment on the Government servant concerned".

12. MW-1 has stated in his evidence that the I party had earned three increments prior to his termination. In the same breath he has stated that he is not sure whether I party had earned three increments and in any event he had earned one increment. The I party workman has stated in his evidence that he had earned three increments. This has not been challenged in cross-examination. Whatever may be the discrepancy in the number of increments earned by I party workman, the fact remains that he had earned increment. It has been laid down by the Hon'ble Supreme Court in the decision reported in 1983 (2) SCC 217 (*Ajit Singh and others v/s. State of Punjab and another*) that grant of increment suggests that the work of incumbent was satisfactory (see para 10 of the decision). In my opinion, therefore, the termination of the services of confirmed I party workman invoking provisions applicable to temporary servants, passed as per Ex. M-8, cannot be sustained.

13. Ex. M-5 shows that the "next increment" of I party workman was withheld for a period of 3 months with cumulative effect for the absence of I party from 2-12-85 to 4-12-85. It is admitted that I party was not appointed on probation. MW-1 has stated in his evidence that when the increment of I party was postponed a regular departmental enquiry was held against I party. The conduct of the II party shows that it considered the I party workman as a permanent employee on an earlier occasion when his increment was postponed. So the subsequent removal as per Ex. M-8, without holding an enquiry in respect of absence of I party is illegal.

14. The Learned counsel for the II party relied on the decision reported in 1991 SCC (1) & S 368 (*Bikramjit Singh v/s. Union of India and others*) in which the Supreme Court was pleased to uphold the termination of the services of temporary employee remaining on leave for the major part of his service career. I have carefully and respectfully gone through this authority of the Supreme Court. The number of days the employee was on leave was a sad commentary on his dedication to work. It is clear that from 1973 to 1981, employer was on leave for 198 days, 144 days, 154 days, 137 days, 207 days, 126 days, 97 days, 177 days and 270 days respectively. In view of the fact that the employee was on leave for the major part of his service career, the Supreme Court was pleased to uphold the order of termination of the employee on the ground that his work performance in service was not found satisfactory. The conduct of the I party cannot be compared with the attitude of that kind of passage with whom that Hon'ble Supreme Court was dealing. This authority of the Supreme Court relied on by the Learned counsel for the II party is not applicable to the facts of the present case also for the reason that the I party was a permanent employee having

earned increment. In the authority of the Supreme Court the leave obtained by the employee each year was abnormal. This is not the case with regard to I party workman.

15. For the aforesaid reasons, in any view of the matter the order as per Ex. M-8 terminating (dismissal is used the schedule to reference) the services of the I party workman cannot be allowed to stand.

16. All other documents not referred to by me above are not relevant. In any case they do not alter my conclusions reached above. In the counter statement it is stated that the termination order Ex. M-8 was delivered on I party on 27-1-87 and his services stood termination w.e.f. 26-2-87.

#### ORDER

The order of termination as per Ex. M-8 is set aside. The II party is directed to reinstate the I party workman forthwith, with continuity of service. The I party workman is entitled to 25% of the back wages w.e.f. 26-2-87. Award passed as stated herein accepting the reference. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 17th day of November, 1993).

Dated : 17-11-1993.

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का. आ. 2860—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भक्करा बीयास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निरदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लैबर कोर्ट, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल - 42012 / 76 / 85-डी-II(बी)]

के. बी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2860.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board and their workmen, which was received by the Central Government on 25-11-93.

[No. L-42012/76/85-D.II(B)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 69/86

Rakesh Kumar

Vs.

Bhakra Beas Management Board,

For the workman—Shri R. K. Singh.

For the management—Shri C. Lal.

#### AWARD

Central Government vide Gazette notification no. L-42012/76/85-D.II(B) dated 15th December, 1986 issued U/S 10(1)(d) of I.D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication;

"Whether the action of the management of BBMB in terminating the services of Satri Rakesh Kumar, Ex-wireman w.e.f. 12-9-85 is just and legal? If not, to what relief is the worker entitled to and from what date?"

2. Brief facts as emerged in the statement of claim is that the petitioner was employed as wireman with the respondent w.e.f. 2-4-1984. He continued working till 27-7-1985 when he was asked verbally not to join the duty from the following day. He stated to have put in more than 240 days during the 12 calendar months preceding the date of termination. He has claimed his termination in violation of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. He has also claimed that he was not served with an charge sheet or enquiry was conducted which is against the principle of natural justice. He has also claimed violation of Section 25-G having retaining his junior Shiv Bhushan son of Shri Kishan Chand who was employed on 5-9-1984 but retained at the time of his termination. He has also claimed violation of Section 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947 having management recruited fresh hands in his place. He has thus sought re-instatement with full back wages and cost.

3. The management in the written statement has taken the preliminary objection that the petitioner himself had abandoned the service. His services were never terminated and hence the reference is invalid. On merits the plea of the management that the petitioner had worked in various capacity such as wireman, unskilled mazdoor, mali during his period from 2-4-1984 to 27-7-1985. During the said period he remained absent on 6-5-1984, 6-6-1984, to 12-6-1984, 1-7-1984 to 31-7-1984 and on 1-8-1984. Further plea of the management that the petitioner himself had abandoned his service on 28-7-1985. The petitioner was duly informed vide letter dated 6-8-1985 and 26-8-1985 to join back duty but he did not care for the reasons best known to him. The petitioner having voluntarily abandoned the job, question of having issued the charge sheet and holding of enquiry does not arise. The management further took the stand since the management had not retrenched the services of the petitioner and the petitioner himself left the job, violation of provisions of Section 25-F, 25 and 25-H are not attracted. The management had also offered to take him back on the job against some other pending work but the petitioner himself was not interested. Thus the management sought the dismissal of this reference.

4. The petitioner filed his affidavit Ex W1 in evidence. He admits in cross-examination that he is employed at Thermal Plant i.e. 15-9-1987 and drawing Rs. 2,000 per month. MW1 R. D. Adlekhia is the management's witness. He filed his affidavit Ex. M1. He also relied on documents Ex. M2 and M3 the memos sent to the petitioner. The respective parties closed their case.

5. I have heard both the parties gone, through the evidence and record.

6. Representative appearing on behalf of the petitioner has argued that the petitioner was not allowed to work w.e.f. 28-7-1985 which amounts to retrenchment although he had completed 240 days by the said date and the management was not complied with the provisions of Section 25-F and 25-G of the Industrial Disputes Act, 1947 and sought reinstatement with backwages. On the contrary the plea of the management that the petitioner having abandoned his services on 28-7-1985 is not entitled to any relief. Thus controversy between the parties is whether the petitioner voluntarily abandoned from work w.e.f. 28-7-1985 or he was refused to perform work from the said date. I have perused all the aspects of this case. Contract of service comes to an end where the workman abandoned his job. In order to constitute abandonment there must be total giving up of duties so as to indicate an intention not to resume the same. It must be total and in the circumstances which clearly indicate an absolute relinquishment. The question as to whether the job, in fact has been abandoned or not is a question of fact which is to be determined in the light of length of absence, act and conduct of the parties and surrounding circumstances whenever the workman is not allowed to perform the duty from a particular date the only remedy left to the workman is either to represent to the higher authority of the management or to raise demand notice. According to the work-

man he made representation on 1-8-1985, to the Chief Engineer for which the management has shown ignorance. Obviously not getting favourable response from the higher authorities the petitioner resorted to the remedy by raising demand notice before the Regional Labour Commissioner (Central). The said demand notice was raised by him immediately thereafter in 1985. Had there been any intention of the workman to abandon the job he would not have resorted to the remedy of raising the demand notice immediately after his termination. The management is trying to fill up the lacuna by saying in the pleadings that the management was keen to take him on the job but he was least interested. However there is no evidence whether any said offer was made by the management in the conciliation proceedings before the A.L.C. (C) after the petitioner had raised the demand notice. Thus that would be the appropriate stage for the management to offer employment to the petitioner justifying their plea that they had not terminated the services rather the petitioner himself had abandoned the job. However there is complete silence in that regard.

6. Much reliance has been placed by the management on the letters dated 26-8-1985 and 6-3-1985 Ex. M2 and M3 stated to have written to the petitioner asking him to resume the duties. The said letters admittedly were sent to the petitioner under the ordinary post with no guarantee and evidence to that effect the same has been received by the petitioner. The management can not wash their hands off while sending said two letters under the ordinary mail. However it was obligatory upon the management to send registered notice to the petitioner in relation to the joining of his duties and ultimately could resort to public notice if no reply received from the petitioner or could hold a brief enquiry before treating services of the petitioner abandoned. No contemporaneous material has been placed by the management to show that any attempt was made by them to inform the petitioner through a registered notice or through public notice or any enquiry was held before treating services of the petitioner having abandoned. All the factors which constitute abandonment i.e. length of service, act and conduct of the parties and surrounding circumstances do not exist in the present case. Therefore the plea of the management that the petitioner had abandoned the job voluntarily can not be accepted and thus rejected.

7. The petitioner admittedly had worked from 2-4-85 to 27-7-1985 without any break except for few days for which the petitioner stated to have remained absent. Further while calculating the number of days put in by the petitioner proceeding 12 calendar months he does complete more than 240 days from the date of termination i.e. 28-7-1985. Admittedly the petitioner was not paid any retrenchment compensation and pay in lieu of notice. Once he had rendered continuous uninterrupted service for the period of one year or more within the meaning of Section 25-F and his services is terminated for any reason whatsoever and his case does not fall in any of the excepted category the termination of services certainly be illegal and invalid. The ratio of case of L. Robert D'Souza, Executive Engineer, Southern Railway and another 1982 (44) F.L.R. 250 (Supreme Court) is followed.

8. The petitioner has also claimed the violation of Section 25G having retaining his juniors Shiv Bhushan son of Kishan Chand also violation of Section 25-H having the management recruited fresh hands after his termination. The said plea of the petitioner has not been contravened by the management in the pleadings or in the evidence.

9. In view of the discussion made in the earlier paras the petitioner stands reinstated with all consequential benefits.

10. The petitioner has not alleged in his pleadings that he remained unemployed throughout. He is also silent in his evidence in this regard. He only in his cross-examination had volunteered that he remained unemployed from July, 1985 to September, 1987. He admits having employed w.e.f. 15-9-1987 at Thermal Plant and drawing Rs. 2,000 per month. In view of the peculiar situation of the case, the petitioner is allowed only 70 per cent of the back wages from the date of termination till 15-9-1987.

11. In a way the present reference is answered accordingly.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer



नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का० आ० 2861 — औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 42012/73/88-डी II(बी)]  
के. वी. बी. उष्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1993

S.O. 2861.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Food Technology Research Institute, Mysore and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-93.

[No. L-42012/73/88-D II(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated this 17th day of November, 1993

## PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Ss., B.L., Presiding Officer  
CENTRAL REFERENCE NO. 3/90

I party	II party
Sri J. Venkatesh,	v/s. The Director.
No. 1020, 8th Cross,	
Sunnadakeri,	
Mysore	

(By Sri N. G. Phadke, Adv.,) (By Sri Sulaiman Sait, Adv.,)  
Central Food Technological  
Research Institute,  
Cheluvamba Mansion,  
Mysore-13.

## AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its order No. L. 42012/73/88-D II(B) Dt. 19-1-90 under Sec. 10(2A)(1)(d) of I.D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

"Whether the management of Central Food Technological Research Institute is justified in terminating the services of Sh. J. Venkatesh. Watchman, w.e.f. 6-6-85? If not, to what relief the workman is entitled?"

## 2. In the claim statement it is contended :—

The I party was appointed as at watchman in the II party industry in Mysore on 15-11-1972 and his services were dispensed with, w.e.f. 2-3-83 on the allegation of absence from duties. The II party after considering the request of the I party again appointed him as a watchman by Memo No. FT/21-13/Vig-75/82 Dt. 27-4-83 imposing several unjust and one sided conditions in the time scale of pay of Rs. 192—322 as per Ex. W.1. The I party has satisfactorily completed his period of probation of one year. In the meanwhile the II party management started extracting the work of a Mali from the I party which the I party used to protest. This was not relished by the II party and hence the II party without assigning any reasons what-so-ever terminated the services of the I party by Memo No. FT-V(343)/E.I/83 Dt. 6-6-85 by

invoking unjust clause 5 of the Memo of appointment Ex. W.1. The order of termination of the services of the I party is illegal. The action of the management is in violation of the mandatory condition stipulated in the clause 5 of the Memo of appointment Ex. W.1 in as much as the management has failed to give one month's notice or to pay one month's wage in lieu of notice. The management has also failed to offer one month's wages. Clause 5 of the appointment order being unjust and illegal and one sided and not enforcement, the management cannot have recourse to that stipulation to terminate the services of the I party. The reference should be accepted and the I party workman should be reinstated with back wages.

3. In the counter statement filed by the II party it is contended:—

The II party carries out research in Applied and Pure Sciences in the Country. It is not an Industry as defined Under Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act. This Tribunal has no jurisdiction to decide the point referred to for adjudication since II party is not an industry. It is true that the I party was appointed as a watchman on 15-11-72 and his services were terminated w.e.f. 2-3-83 because of his irregular attendance. Since the I party and his family appeared before the Director of the II party and pleaded their difficulties, the I party was appointed afresh on 27-4-83 on humanitarian grounds. It is not true that any illegal or unjust conditions were imposed. It is not true that clause 5 of the letter of appointment (Office Memorandum) is unjust. In view of I party's frequent absence his services were terminated under Clause 5 of the terms of appointment Ex. W.1. The action of the II party is perfectly legal. The Management ordered that he shall be entitled to claim a sum equivalent to a month's salary plus allowance for the period of notice of one month at the same rate at which he was drawing his salary, immediately before the termination of his services. The said amount has not been claimed by the I party though there has been an offer to pay the same from II party. The reference has to be rejected.

4. As could be seen from the order sheet Dt. 11-9-90 this Tribunal has stated that separate issues are not required since the point for termination was covered by the schedule to reference.

5. Subsequently the Learned Counsel for the II party stressed that the Tribunal should hear on maintainability on the ground that II party was not an Industry. Arguments were heard on this point.

6. This Tribunal by its separate considered order dt. 18-12-91 has held that the II party is an Industry.

7. On merits, on behalf of the II party M.W.1 Venkata Kamakshi, Dealing Assistant of II party has been examined. On behalf of the I party he has got himself examined and closed his case.

8. M.W.1 has stated in his evidence that the probation period of I party workman was extended with some conditions as per page 60 in the book Ex. M.2 (Personal file of I party). M.W.1 has stated that since I party was taking frequent leave without sanction the committee which extended the probation period, felt that the I party should be changed from watchman and so he was transferred as a mali. He has stated that the report of the Committee is at page 34 of Ex. M.2. M.W.1 has stated that the I party accepted the transfer as Mali as shown at page 37 of Ex. M.2. Page 37 of Ex. M.2 shows that the I party reported for duty on transfer from watch and ward unit to Agri Horticultural Section. I have carefully gone through this duty report at page 37 in Ex. M.2. Nowhere it is stated at page 37 that the I party reported himself as Mali. On the contrary it shows that he had reported himself as a watchman. The Office memorandum at page 48 in Ex. M.2 shows that the probation period of I party workman was extended for a period of 6 months w.e.f. 29-4-84. This document also shows that the II party treated the I party workman as a watchman. At page 88 of Ex. M.2 is found the Office Memorandum dt. 6-6-87 terminating the services of the I party Under Clause 5 of the appointment order (Ex.W.1). This termination order dt. 6-6-87 also mentions at two places the I party as at watchman.

9. From the aforesaid circumstances it is clear that I party was a watchman and not a mali. There is therefore



no substances in this argument that the reference is bad because I party was a mali and not a watchman.

10. M.W.I, Dealing Asstt. of II party has stated in his evidence that there was an enquiry against the I party and his services were terminated. For this purpose Inquiry Committee was constituted. Ex. M.1 is the service file of the I party and it contains several records including the findings of the Enquiry Committee which was formerly constituted in 1983. M.W.I has stated that enquiry report is at page 29 of Ex. M.1. M.W.I has stated in his evidence that after the committee gave its report, I party met the Director and begged pardon.

11. M.W.I has stated that the request of the I party workman was not granted by the Director. Then the wife and mother of I party met the Director and begged pardon. The pardon letter written by the I party is at page 44 of Ex. M.1. The pardon letter written by the wife and mother of I party is at page 45 of Ex. M.1. After the mother and wife prayed for pardon, the I party was appointed afresh as per order at page 46 in Ex. M.1 dt. 27-4-83 (Ex. W.1 is the xerox copy of the appointment order produced by the I party).

12. It bears repetition, Ex. M.1 is the service file of I party showing the constitution of a committee and its decision to terminate the services of I party, subsequent pardon prayed for by the I party and his family members and consequently appointing I party as a watchman afresh as per Ex. W.1. The Dealing Asstt. M.W.I has admitted that Ex. M.1 has nothing to do with the order of termination of I party workman on 6-6-85.

13. As I have already stated the Office Memorandum dt. 6-6-85 terminating the services of I party is found at page 88 in Ex. M.2. No reasons are mentioned in the termination order dt. 6-6-85. What the termination order says is in pursuance of clause 5 of the order of appointment dt. 27-4-83 I party's services were terminated forthwith and that I party shall be entitled to claim a sum equivalent of the amount of his pay allowances for the period of notice of one month.

14. Before coming to Clause 5 of Ex. W.1. as per which the services of the I party workman were terminated, it is necessary to see whether the I party was a temporary employee or a permanent employee. As per Ex. W.1 Clause 4 (Terms and Conditions) the I party was appointed on 27-4-83 on probation for a period of one year. The Office Memorandum at page 68 in Ex. M.2 shows that the probation period of I party was extended for a period of 6 months w.e.f. 29-10-84 since the I party was found to be irregular in attendance. If this 6 months extension of the period of probation w.e.f. 29-10-84 is taken into consideration, the probation period ended on 29-4-85. This means that the I party workman had become a permanent employee, since he had completed probation period. The order of termination of the service has been passed (page 88 in Ex. M.2) on 6-6-85. M.W.I has stated that before passing the order of termination on 6-6-85 no enquiry was held. The order of termination of a permanent employee without holding an enquiry, in my opinion, cannot be sustained. M.W.I has admitted in cross-examination that all the absence of I party workman has been regularised by granting proper leave. M.W.I has stated that I party was removed Under Clause 5 of appointment order Ex. W.1.

15. Clause 5 of the appointment order Ex. W.1 dt. 27-4-83 says :—

"5. On satisfactory completion of the probationary period, if his services are continued, the appointment may be terminated at any time by a month's notice given by either side i.e., the appointee or the appointing authority, however, reserve the right of terminating his services forthwith or before expiration of the stipulated period of notice by making payment to him of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice, or the unexpired portion thereof."

No doubt this clause 5 as per which the services of the I party have been terminated says that the appointment may be terminated at any time giving one month's notice or

before expiration of the stipulated period of notice by making payment to employee of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice. I have already come to the conclusion that the I party had become a permanent employee. The termination order does not mention the reason for termination of the services of I party.

16. What happened in the Supreme Court Authority in 1986 (53) F.L.R. 523 (Central inland Water Transport Corp. Ltd. v/s. Brojo Nath Ganguly and Tarun Kanti Sengupta) was that the services of permanent employees were terminated by merely giving them 3 months notice without disclosing any reason Under Rule 9(i) of Central Inland Water Transport Corp. Ltd. (Discipline and Appeal) Rules which conferred upon the Corporation the power to terminate the services of a permanent employee (see para 99 of the Hon'ble Supreme Court Authority) by giving him 3 months notice in writing or in lieu thereof to pay him the equivalent of 3 months basic pay and D.A. The Supreme Court was pleased to hold that such a clause was illegal and struck it down.

17. I have extracted above Clause 5 of the order of appointment of I party workman. This clause 5 of the terms and conditions of the order of appointment which gives absolute power to the II party to terminate the services of a permanent employee, is similar to rule 9(i) of Central Inland Water Transport Corp. Ltd. (D.&A.) Rules 1979 which was held illegal by the Hon'ble Supreme Court. For the reasons stated hereinbefore I hold that the portion of clause 5 of Ex. W.1 giving power to II party to terminate the services of a permanent employee at any time is illegal and it has to be ignored. The I party is entitled to reinstatement.

18. It is theoretically argued by the Learned counsel for the II party that reinstatement will amount to putting a premium on crime. This argument cannot be accepted because, in law, the I party is entitled to reinstatement. It is further argued by the Learned counsel for the II party that I party workman has made too large a draft on the generosity of the II party and does not deserve sympathy. Here I agree with the Learned counsel for the II party, to some extent. Once bitten, twice shy. The party's services were terminated on an earlier occasion (Ex. M.1), the II party was generous enough to appoint him. The afresh on compassionate grounds. The I party did not show improvement in his attendance and invited trouble. For these reasons I am of opinion that the backwages of the I party should be slashed to a minimum. 25 per cent of backwages will meet the ends of justice.

19. For the aforesaid reasons I pass the following order :—

#### ORDER

The termination of the services of I party watchman w.e.f. 6-6-85 as per termination order at page 88 in Ex. M.2 is set aside. The II party shall reinstate the I party as a watchman, with continuity of service, forthwith. I party is entitled to 25 per cent of the backwages. Reference accepted as stated herein and award passed accordingly. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 17th day of November 1993).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2862—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नान कन्वेंशनल एनरजी सोर्सिज, चंडीगढ़ के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार

औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन - 42012/3 / 87 डी - 2 (बी पार्ट)]

के. वी. वी. उष्णी, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2862.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Non-Conventional Energy Sources, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on 1st December, 1993.

[No. L-42012/3/87-D.II(B)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 54/88

Amarjit Singh

Vs.

Non-conventional Energy Sources

For the Workman—Shri J. C. Sharma,

For the management—Shri Arun Walia.

#### AWARD

Central Government vide gazette notification No. L-42012/3/87-D. II(A) dated 29th July, 1988 issued u/s 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of department of non-conventional Energy Sources, Chandigarh in not employing Shri Amarjit Singh son of Shri Bachan Singh is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled to and from what date?"

2. Brief facts as emerged in the statement of claim that the petitioner was appointed as driver on 24th October, 1985 on daily wage basis of Rs. 22.50 per day. He stated to have worked under the management from 24th October, 1985 to 16th June, 1986 for which he was issued the certificate that he is honest and hard worker and good moral character. His services were terminated on 16th June, 1986 without any rhyme and reasons. He alleges that the action of the management is arbitrary and against the principle of natural justice. He was not given any notice before termination of his services. He claims that the management has taken other persons on deputation as driver in his place. He was not afforded opportunity before his termination. Action of the management is illegal and he has thus sought reinstatement with full back wages.

3. The management in their written statement has taken the preliminary objection that the department is not an 'industry' and the application is bad for non-joinder of necessary parties. On merits the plea of the management that the petitioner was appointed on daily wage basis as driver on 24th October, 1985. He worked up to 16th May, 1986 and not up to 16th June, 1986 as alleged by the petitioner, due to non-availability of any deputationist/regular driver. However on joining of driver on deputation from other Central Government offices his services were terminated on 16th May, 1986. The respondent management is not bound to give any reason for termination and no notice was required being petitioner was on daily wage basis. It was denied that the petitioner was ever called to work on Sundays/holidays and thus has sought the dismissal of the reference.

4. The petitioner in evidence examined himself. He filed his affidavit Ex. W1. MW1 S. S. Bawa Principle Scientific Officer is the management's witness. He filed his affidavit

Ex. M1. The workman got proved the certificate Ex. W2. The management also relied attendance register which was allowed to exhibit as Ex. M2 to M9. The respective parties closed their case.

5. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

6. The management has not stressed to the points raised in the preliminary objections. The said objections are stands over ruled.

7. Counsel appearing on behalf of the petitioner has laid a stress that the termination of the services of the petitioner is in violation of Industrial Disputes Act having management not issued any notice to the petitioner before termination of his services. He has also relied on a certificate issued by the management stating the petitioner is honest and hardworker. It was also stressed that the management has appointed another person in place of the petitioner. I do not agree to the contentions raised by the counsel for the petitioner. The petitioner in his own showing in the statement of claim had worked from 24th October, 1985 and stated to have continued up to 16th June, 1986. The date 16th June, 1986 does not seems to be correct having management denied the same stating the same should be 16th May, 1986 which seems correct because the petitioner himself has relied a certificate Ex. W2 issued by the management dated 19th May, 1986 stating that the petitioner has worked w.e.r. 24th October, 1985 to 16th May, 1986 which is consonance with the stand taken by the management. Otherwise had the petitioner worked in the month of June 1986 also, there would not have been a certificate dated 19th May, 1986 Ex. W2 relied by the petitioner. Therefore, the only tenure the petitioner had worked with the respondent management is from 24th October, 1985 to 16th May, 1986. The same also got proved from the attendance roll which has been relied by the management Ex. W2 to Ex. M9 which too stands in consonance with the certificate Ex. W2 relied by the petitioner. In relation to violation of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, the workman has to prove that he continued serving for not less than one year under the management who retrenched him from the service and during that period of 12 months he had rendered for not less than 240 days. His tenure of service is from 24th October, 1985 to 16th May, 1986. Even if Sundays/holidays are included, it only comes to 204 days and thus can not allege violation of Section 25-F of the I.D. Act, 1947.

8. Constant stand of the management that the appointment of the petitioner was only on account of non-availability of deputationist/regular driver and however on the joining of the driver on deputation from other Central Government office the petitioner was removed from service. This itself has been admitted by the petitioner in the statement of claim. The petitioner could only possibly stay in that position till the regular incumbent of that post join the duties and after the joining of incumbent of that post, the petitioner had to vacate the same. In the face of his factual position the petitioner is certainly not entitled to any relief.

9. Hence nothing survive in the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to any relief what so ever.

10. However I must express my concern for the poor workman since he had already worked with the respondent management and has an experience to the post. I, therefore, recommend to the respondent management to give opportunity to the petitioner for the post subject to the availability as an act of benevolence or goodwill gesture on their part.

11. The reference is answered accordingly.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh.  
11-11-1993.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2863.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिब्रीजन्त इंजीनियर टेलीकाम, महबूबनगर के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[एन 40012/46/90/आई आर (डी यू) (पीटी)]

के. वी. बी. उण्णी, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2863.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Engineer, Telecom, Mahboobnagar and their workmen, which was received by the Central Government on 1-12-93

[No. L-40012/46/90-IR(DU)(PT)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

## BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

## PRESENT:

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 18th day of November, 1993

Industrial Dispute No. 68 of 1990

## BETWEEN:

The Workmen of Divisional Engineer,  
Telecom, Mahboobnagar, A.P. ... Respondent

## AND

The Management of Divisional Engineer,  
Telecom, Mahboobnagar, A.P. ... Respondent.

## APPEARANCES:

Sri C. Suryanarayana, Advocate—for the Petitioner

Suryasri M. Panduranga Rao, B. G. Ravinder Reddy,  
Advocates—for the Respondent.

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/46/90-IR(DU), dt. 30-11-1990 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of Divisional Engineer, Telecom, Mahboobnagar to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of Divisional Engineer, Telecom, Mahboobnagar in retrenching the workman Sri Venkataiah, Ex-Casual Mazdoor w.e.f. 1-4-86 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 68 of 1990 and notices were served on both parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows:—The Petitioner was employed to perform “Class IV duty in TRA Sec. “TDE-MBN”, i.e. the duty of a Grade ‘D’ employee in the Respondent’s office. he was paid daily wage of Rs. 6.00 per day which was paid to a Casual Mazdoor, treating the Petitioner as a Casual Mazdoor. The Petitioner engagement was, however, not ‘casual’ not only because he was employed in a Group ‘D’ post but also because he was employed for a total 231 days during the period from 30-1-1984 to 30-11-1984 excluding 37

Sundays, 10 second Saturdays and 14 National/Telegraph holidays on which he was entitled to wages. Thus he has worked for a total of 292 days (including the said holidays). According to the decision in workmen of American Express International Banking Corporation v. Management of American Express International Banking Corporation (1985 (2) LLJ 539—1985 SCC (L&S) 940) Sundays and other paid holidays should be taken into account for the purpose of reckoning the total number of days on which the workman could be said to have actually worked. The Petitioner is therefore entitled to payment for those paid holidays and also to count those days as days on which he worked. A group ‘D’ Official is entitled to the same. The Petitioner was retrenched from service w.e.f. 1-12-1984 without notice and without payment of the notice period wages and also without complying with the other mandatory provisions of Section 25F of the I.D. Act. The Petitioner’s retrenchment w.e.f. 1-12-1984 was also in violation of the orders contained in the former DG, P&T New Delhi No. 269/130/78-STN dt. 1-10-1984 according to which it was decided that “such of those Casual Mazdoors who serve the Department for at least a total period of 240 days in a year and whose services are proposed to be terminated by the Department shall be served a notice of one month before termination of their service or one month wages in lieu thereof be paid to them”. He was retrenched from service even while his juniors were continuing in service. The Petitioner’s termination on and from 1-12-1984 was therefore retrenchment which is illegal, null and void and hence he is entitled to full wages for the said period of retrenchment (from 1-12-1984 to 30-6-1985) and to reckon the period as service for all purposes. He was, however, recalled to duty with effect from 1-7-1985 and employed in the same post till 31-3-1986 and again retrenched from service w.e.f. 1-4-1986 without notice and without payment of notice period wages and also without complying with the other mandatory provisions of Sec. 25-F aforesaid. Needless to say, this retrenchment was also violative of the aforesaid order dt. 1-10-1984 of the DG P&T, New Delhi. Thus from any point of view the Petitioner’s termination from 1-4-1986 onwards is retrenchment which is illegal. Even if the Petitioner was deemed to have been employed not as a Group ‘D’ employee or to perform the duty of a Group ‘D’ employee but only as a Casual Mazdoor, he is entitled to absorption in a Group ‘D’ post as per the direction of the Supreme Court in Daily rated Casual Labourers in P&T v. Union of India & others (AIR 1987 SC 2342) of course according to his turn in the seniority list of Mazdoors of Mahaboobnagar Telecom District. Therefore the Petitioner is entitled to reinstatement as a Group ‘D’ employee with full back wages protection of his seniority and for all other benefits which are incidental and consequential to such reinstatement. That even if the Petitioner is treated as a Casual Mazdoor, his retrenchment on both the above mentioned occasions, viz. 1-12-1984 and 1-4-1986 being illegal and void, he is entitled to reinstatement in service with full back wages, protection of his seniority among the mazdoors of Mahaboobnagar Telecom District, an absorption in regular establishment according to his turn in the seniority list and pending the same for conferment of temporary status and make an Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows:—It is submitted that the Petitioner was engaged as casual labour for a specific work and for specified purpose w.e.f. 30-1-84. The petitioner was clearly informed that he would be provided with work as and when it is available and his services are liable to be disengaged when there is no work. He worked as casual mazdoor for 231 days during the year 1984, 109 days during 1985 and 74 days during 1986. The petitioner was engaged to render Class IV duties purely on casual basis as there was heavy absenteeism and shortage of Group ‘D’ staff in the office. It is submitted that the engagement of the petitioner was never continuous but is only casual depending upon the availability of work. The Petitioner was engaged on specific understanding that as and when the Group ‘D’ staff is available, his services would not be engaged. The petitioner was paid wages at Rs. 6.00 per day for the work done by him. It is submitted that with effect from 1-4-1986 was no work for the petitioner and therefore his services are to be disengaged for want of work. The petitioner for the first time made his claim for reinstatement after 4 years of his disengagement and raised the present industrial dispute. It is submitted that in the case of casual labour the question of termination does not

arise as the work itself is casual in nature. It is submitted that the petitioner has no merits in his claim and he is not entitled for employment under the Respondent nor for any back wages as claimed by him.

4. The point for adjudication is wages the action of the Respondent in retrenching the workman Sri Venkataiah, Ex-Casual Mazdoor w.e.f. 1-4-1986 is justified or not ?

5. W.W1 was examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W17. M.W1 was examined on behalf of the Respondent and no documents were marked on its side.

6. W.W1 is Venkatayya. In brief he deposed that he joined as Casual Mazdoor in the Respondent on 30-1-1984. He worked for 231 days during the above period. During the above period he was not given paid weekly off which includes 37 Sundays 10 Second Saturdays and 14 National/ Telegraph Holidays. After 30-11-1984 he was not assigned any work. On 1-7-1985 he was taken back to the work in the same post. He worked continuously upto 31-3-1986. Ex. W3 is the xerox copy of certificate dt. 23-7-1986 showing the working days. He worked for 183 days between 1-7-1985 to 31-3-86. He was not given paid weekly offs during the period also. The total of weekly offs comes to 43 days. At the time of his termination w.e.f. 1-4-1986 he was not given any notice nor he was paid wages in lieu of notice. He was taken into job by the Accounts Officer after verifying his employment card and S.S.C. certificate though he was not sponsored by the Employment Exchange. His junior Sri Niranjan Goud is still being continued in the service and he is conferred temporary status. Ex. W17 is xerox copy of order dt. 7-11-1989 according to which temporary status should be conferred on casual labour without regularisation.

7. M.W1 is P. Janardhana Rao. He deposed that he is the Respondent. The petitioner was engaged as there was heavy absenteeism in shortage of group 'D' employees on casual basis. Before his engagement, he was intimated that he was engaged only on temporary basis and in leave vacancies. The petitioner was engaged from 30-1-1984 to November, 1984 for 231 days from July, 1983 to March 1986 for 183 days. As there was no vacancy of Group 'D' employees after March 1986 the petitioner could not be engaged.

8. In this dispute the Petitioner-workman was retrenched from service w.e.f. 1-12-1984 without notice and without payment of the notice period wages and also without complying with the other mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act, and the Petitioner's retrenchment w.e.f. 1-12-1984 was also in violation of the orders contained in the former D.G., P&T., New Delhi No. 269/130/78-STN dt. 1-10-1984 according to which it was decided that "such of those Casual Mazdoors who serve the Department for at least a total period of 240 days in a year and whose services are proposed to be terminated by the Department shall be served a notice of one month before termination of their service or one month wages in lieu thereof be paid to them and that he was retrenched from service even while his juniors were continuing in service. Now this Tribunal has to see whether the Petitioner-workman has put in 240 days service in a year. A perusal of claim statement filed by the Petitioner-workman in para 4 thereof in which it was stated that the actual number of days for which the workman was employed during the period from 30-1-1984 to 30-11-1984 was 231 days. But 37 Sundays, 10 Second Saturdays and 14 National and Telegraph Holidays for which the workman is entitled to payment as wages have also to be added as part of his service within a year. The petitioner-workman relied upon the decision reported in Workman of American Express International Banking Corporation v. ITS Management (1985 (II) LLJ, page 539 S.C.) that Sundays and other paid holidays should be taken into account for reckoning the number of days on which the workman was employed. Taking the above decision into consideration, the petitioner-workman's total days of employment would come to 292 days. Thus the petitioner-workman is entitled to payment for those paid holidays and also to count those days as days on which he worked as Group 'D' official

is entitled to the same. The arguments of the Petitioner-workman is that during this period though the workman was employed as a Badli or Substitute in the leave vacancy of a Group 'D' employee he was not paid Group 'D' employees wage on the principle "equal work, equal wage" not with standing the fact that it is an incidence of such service. The contention was that the workman was recalled to duty and employed from 1-7-1985 till 31-3-1986 but retrenched again from 1-4-1986 without notice, without payment of notice period wages and compensation or without complying with the other mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. Though he was employed actually for 183 days during the period from 1-7-1985 to 31-3-1985 he was denied the benefit of paid holidays on 43 Sundays and other paid Holidays during that period. Thus the number of days of his employment worked to 226 days. But it may be recalled that he was illegally retrenched from 1-12-1984 to 30-6-1985, the period counts as service for all purposes. Therefore, I find the petitioner-workman should be deemed to be in continuous service during the one year preceding his retrenchment on 1-4-1986 and hence he is deemed to be in continuous employment from 30-1-1984 to 31-3-1986 as per Section 25-B of the I.D. Act, and thus entitled to the benefit or protection as Section 25-F of the I.D. Act notwithstanding his alleged employment as a Badli or substitute in the leave vacancy of a Group 'D' employee. The judgement of the Bombay High Court in Raymond Woollen Mills Ltd. v. C. S. Sonaware and ANR. (1993 Lab. I. C. Page 1494) wherein it was held that under the explanation to the proviso to Section 25-C as 'Badli workman' means a workman who is employed in an Industrial establishment in the place of another workmen whose name is borne in the Muster Rolls of the establishment but he shall cease to be a Badli workman if he was completed one year of continuous service in that establishment. Therefore, the High Court held that the workman is entitled to protection Sec. 25-F of the I.D. Act. The Bombay High Court also declared that he is entitled to full back wages for the period of his unemployment due to illegal retrenchment minus the wages earned by him in other organisations. The counsel for the Petitioner-workman cited a number of judgements with regard to back wages. (a) Gangenath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeet, Allahabad v. Sri Madanlal & Others (1993 Labour Law Reporter page 112), (b) Umesh Saxena v. P. O. Labour Court & Others (1993 LLR page 118), (c) The Central Co-Operative Consumers' Stores Ltd. v. Labour Court, Himachal Pradesh At Shimla and Another (1993 LLR page 577 S.C.), (d) Sri Ram Deen v. State Others (1993 LLR page 474 Rajasthan High Court) and (e) Municipal Corporation of Delhi v. Sri Khacherni through Municipal Employees Union & Another (1993 LLR page 5). The further contention of the Petitioner workman that even if the Petitioner was deemed to have been employed not as a Group 'D' employee or to perform the duty of a Group 'D' employee but only as a Casual Mazdoor, he is entitled to absorption in a Group 'D' post as per the direction of the Supreme Court in Daily Rated Casual Labourers. In P&T v. Union of India & Others (AIR 1987 page 2342 S.C.) of course according to his turn in the seniority list of mazdoors of Mahabubnagar Telecom District. If there are no posts of Group 'D' vacant to absorb the Petitioner, he is entitled to conferment of temporary status as laid down in the Department of Telecom Orders No. 269-10/89-STN dt. 7-11-89 which was said to have been issued pursuant to the above cited judgement of the Supreme Court to provide some relief and benefits to those who have put in one year service or more but could not be absorbed as directed by the Supreme Court. Considering all the facts and circumstances of the case, I am of the firm opinion that the Petitioner is entitled to reinstatement as Group 'D' employee with full back wages, protection of his seniority and for all other benefits which are incidental and consequential to such reinstatement.

9. In the result, the action of the Management of Divisional Engineer, Telecom Mahabubnagar in retrenching the workman Sri Venkataiah, Ex-Casual Mazdoor w.e.f. 1-4-1986 is unjustified. The Petitioner-workman is entitled to reinstatement in service with full back wages, protection of his seniority among the employees of Mahabubnagar Telecom District.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 18th day of November, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

#### Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Workmen/Petitioner :	Witnesses Examined for the Management/Respondent
W1 Venkataiah	M.W1 P Janardhan Rao

Documents marked for the Petitioner Workman :

- Ex. W1 17-12-83.—Xerox copy of the list of the Holidays for 1984.
- Ex. W2 —Xerox copy of the supplementary notification issued to W1.
- Ex. W3 —Xerox copy of the Certificate of working days of WW1.
- Ex. W4 1-10-84.—True copy of the order DGP&T New Delhi with regard to one month's notice or payment salary in lieu thereof.
- Ex. W5.—Xerox copy of the SSC Certificate of the Petitioner.
- Ex. W6 14/17-6-85.—Xerox copy of the order DGP&T New Delhi to regularise service of workman though not sponsored by the Employment Exchange.
- Ex. W7 7-8-89 —Xerox copy of the petitioner Vs. Complaint to the ALC(C) I, Hyderabad.
- Ex. W8.—Xerox copy of the parwise remarks filed by the Respondent on Ex. W7
- Ex. W9 26-12-89.—Petitioner's rejoinder to Ex. W8.
- Ex. W10.—Xerox copy of the failure report.
- Ex. W11. 9-4-84.—Xerox copies of the list of holidays.
- Ex. W12 31-4-84 —Xerox copies of the list of holidays.
- Ex. W13 1-1-85.—Xerox copy of the list of holidays 1985.
- Ex. W14 —Xerox copy of list of holidays for 1986.
- Ex. W15 1-10-90.—Xerox copy of the order of SDOI Mahboobnagar granting temporary stating to Sri G. Niraja Goud.
- Ex. W16 13-10-83.—Xerox copy of the Order of the Ministry of the Home Affairs with regard to regularisation of casual employees in Group 'D' Posts.
- Ex. W17 7-11-89.—Order of D. G. Telecom on grant of Temporary status

Documents marked for the Respondent  
NIL

नई दिल्ली 2, दिसम्बर, 1993

का. अ. 2864.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम, करीमनगर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/128/89 आई आर (डीयू) (पीटी)]

के. वी. बी. जण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2864.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Telecom. Karimnagar and their workmen, which was received by the Central Government on 1-12-93.

K. V. B. UNNY, Desk Officer

[No. L-40012/128/89-IR(DU)(Pt.)]

#### ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A.B.L.

Industrial Tribunal-I.

Dated : 18th day of November, 1993

Industrial Dispute No. 40 of 1990

BETWEEN :

P. Murali S/o Ramaiah, aged about 24 years.

Casual Mazdoor under the respondent's

herein H. No. 2-3, Bhagat Nagar,

Karimnagar.

.....Petitioner.

AND

1. The Sub-Divisional Officer,  
Phones, Karimnagar-505001.

2. The Telecom District Engineer,  
Karimnagar-505050.

3. The Chief General Manager, Telecom,  
A.P., Hyderabad-500001.

.... Respondents

APPEARANCES :

Sri C. Suryanarayana, Advocate for the Petitioner.

M/s. M. Panduranga Rao and B.G Ravinder Reddy,  
Advocates for the Respondents Nos. 1 and 2.

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/128/89-IR(DU), dt. 13-8-1990 referred the following dispute under Section 10(1)(d) & (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of M/s. Telecom, Karimnagar and their workman to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of M/s. Telecom, Karimnagar (A.P.) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the services of Sri P. Murali, Casual Mazdoor w.e.f. 22-11-1988 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 40 of 1990 and notices were served on both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows :—

The Petitioner's claim in the complaint to the RLC(C) at Hyderabad regarding the periods of his employment was not disputed by the respondents. They have not disputed the fact that the petitioner's service was terminated w.e.f. 2-11-1988 nor did they comply with the instructions of the Director General P&T New Delhi that either one month notice be given before terminating the service of a Mazdoor or one month's wages in lieu be paid. Though it was said that the 3rd Respondent rejected the Petitioner's request for condonation of the 'break' in his service, despite the 2nd Respondent's recommendation, the order rejecting the petitioner's request has not been communicated to him even till today. The Respondent's contention before the

Conciliation Officer that the benefit of the Supreme Court's judgment is available only to those that were recruited prior to 30-3-85 is not valid in view of the S.C.'s judgment dt. 17-4-90 in *Rumgopal and other v. Union of India and others* etc. vide WP (C) No. 1280/89 etc. The Petitioner was admittedly recruited and employed from 1-9-1984 and cannot be treated as a fresh entrant after 30-3-1985 merely because of his prolonged absence due to sickness which, under the provisions Sec. 25-B of the I.D. Act constitutes service for all purposes except wages. Even otherwise the admitted fact that the Petitioner was employed again from July 1988 "as there were works" shows that the break was condoned though no formal orders were issued. The Respondents wrongfully terminated the service of the Petitioner on the wrong plea that he was recruited after 30-3-1985 as submitted above and that it was contrary on the instructions of the former DG P&T, New Delhi. But these instructions have been declared to be invalid in the judgement dt. 4-5-1988 in O.A. No. 529/88 on the file of the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal, New Delhi in view of the judgement in AIR 1987 S.C. 2342 (between *Daily rated Casual Labour in P&T Services Vs. Union of India and others*). The decision of the said Principal Bench was upheld by the Supreme Court in its judgement dt. 17-4-1990 aforesaid, according to which even if a Casual Labourer is recruited and employed after 30-3-85, he is entitled to absorption and regularisation in the service of the Telecom Department if he has rendered 240 days of work in any one year period. The Supreme Court declared that no distinction can be drawn between those recruited and employed after 30-3-1985 and those that were continued and employed prior to that date and that the benefits of the decision in AIR 1987 SC 2342 apply to all Casual Mazdoors who are employed for 240 days in any year. Thus the Supreme Court conferred a new right on workmen recruited and employed for 240 days in a year to be considered for absorption and regularisation in service in preference to others, of course, according to their turn in the seniority list of mazdoors in a Telecom District. In this case, it is the Telecom District under the jurisdiction of the 2nd Respondent. The petitioner further submits that in view of the orders of Department of Telecom in their No. 269-10/89-STN, dated 7-11-1989 he is entitled to conformation of temporary status with all its attendant benefits pending his absorption and regularisation in the Telecom Department. In view of the foregoing facts and submissions, the Petitioner submits that his termination from service w.e.f. the A/N of 21-11-1988 is retrenchment and the same is illegal for non-compliance with the mandatory provisions of Section 25-F of the I.D. Act. He is therefore entitled to reinstatement in service with full back wages from the date of his illegal retrenchment (22-1-1988). The petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to hold accordingly and make the award directing the petitioner is reinstatement in service with full back wages and protection of seniority among Casual Mazdoors of Karimnagar Division and to grant all other incidental and consequential benefits aforesaid.

3. The brief facts of the counterfiled by the Respondent read as follows :—

It is submitted that the Petitioner was engaged as casual mazdoors under the Respondent with effect from 1-9-84 and when the work was available such as laying cables, erection of overhead lines etc. It is submitted that the work are not permanent or regular in nature. The petitioner was engaged on the following 21 days during September, 1984 and 29 days during October, 1984 and 26 days during February 1985. The Petitioner himself absented from March 1985 to June 1988 though the work was

available now and then. He produced a medical certificate in July 1988 for condoning his absence for 3 years, 3 months and requested for providing him the work. As the work were available, he was provided with work for 26 days in July 31 days in August, 1988, 30 days in Sept., 1988, 31 days in Oct., 1988 and 21 days in the month of Nov., 1988. Thereafter the petitioner was disengaged for want of work. The petitioner is not entitled to the benefits of service for the period of 3 years 3 months i.e. from March 1985 to June 1988 as he is only a casual labour and giving work is depending on the availability of work and also absenting himself for work when it was available. Disengagement of casual labour does not mean retrenchment and therefore the question of Section 25(F) of I.D. Act does not arise. That Section 25(F) of I.D. Act is not all applicable to the casual labour as they come under excluded category. It is therefore prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an award that the petitioner is not entitled to any relief.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent in terminating the services of Sri P. Murali Casual Mazdoor w.e.f. 22-11-1988 is justified or not ?

5. W.W1 is examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W12. On the other hand M.W1 was examined and marked Exs. M1 to M4.

6. W.W1 s P. Murali. He deposed that he is the concerned workman in the reference made in this case. He worked as casual mazdoor in Telecommunication Department at Karimnagar under the 1st Respondent from 1-9-1984 to 30-10-1984. Thereafter he suffered from Jaundice and therefore he informed the same to the Jr. Engineer by Htn Sri Raghuramiah and did not attend the duty from 1-11-1984 till the end of January 1985. Again he reported to the duty from 1st February, 1985 and worked during the entire month of February, 1985. Again he was attacked with Jaundice and stomach-ache. Therefore he did not attend the duty from 1-3-1985 onwards. He suffered with ill-health till 30-6-1988. Thereafter he reported for duty from 5-7-1988 after submitting Medical Certificate to the 2nd Respondent and he forwarded the same to the Chief General Manager, Telecom. A. P. Hyderabad recommending the condonation of his absence. Ex. W1 is the true copy of the covering letter dt. 8-12-1988 under which his medical certificate was sent to the Chief General Manager, Telecom, A.P. Hyderabad by the second respondent. He worked continuously from 5-7-1988 to 30-11-1988. Thereafter he was removed from the service by the 1st Respondent. No written order of removal from service is given to him by R1, nor he was paid one month's pay in lieu of not issuing the notice and he was also not paid any retrenchment compensation. He was paid the daily wages at Rs. 15.00 per day. Ex. W 6 is the copy of the order of the Director General, Post and Telegraph No. 28-11/77-SR/STN dt. 10-10-1980 in which the Telecom Dist. Engineer is authorised to condone the break in service. Ex. W 11 is the order No. 269-10/89/ETN dt. 7-11-1989 in respect of giving casual labour temporary status without regularisation Ex. W 12 is the copy of the judgement dt. 17-4-1990 of the Supreme Court in WP(C) No. 2180 of 1989 and Writ Petition Nos. 1246, 1248 of 1988, 176, 177 and 1248 of 1988.

7. M. W 1 is M. Raja Sekhar. He deposed that he has been working as Jr. Telecom Officer at Karimnagar since 6 years. He knows the facts of this case. W. W1 was engaged as casual mazdoor in the works of Overhead Lines Erection, underground cable trench works and attending the defects of Telecom Lines, on the days when the work was available during the period from 1-9-1984 to February 1985 with breaks in service. W. W 1 worked for 21 days in September, 1984, 29 days in October, 1984 and 26 days in February, 1985 and in total he worked 77 days during the period. W. W 1 absented himself from attending the work from March 1985 to June 1988. In July 1988 W.W1 approached the Department with a Medical Certificate for his absence and requested the Department to engage him as casual mazdoor. W.W1 was engaged for 26 days in July, 1988, 31 days in August, 1988, 30 days in September 1988, 30 days in October, 1988 and 21 days in November 1988. Thereafter he could not be engaged due to non-availability of works. The total No. of days W.W1 wor-

ked during July, 1988 to November, 1988 were 139 days. No person was engaged after July, 1988 in which month the Petitioner was engaged. The persons namely P. Mallaiiah, K. Kondaiah, G. Kishan, Mohd. Nazemuddin are seniors to the Petitioner.

8. There is no dispute with regard to the periods of the employment of the Petitioner-workman and there is no dispute with regard to the termination of the Petitioner-workman from service w.e.f. 2-11-1988. Now the contentions of the Petitioner-workman is that the benefit of the Supreme Court's judgement is available only to those that were recruited prior to 30-3-1985 is not valid in view of the S.C.'s Judgement dated 17-4-1990. The Respondents wrongfully terminated the service of the Petitioner on the wrong plea that he was recruited after 30-3-1985 as submitted above and that it was contrary to the instructions of the former D.G. P&T New Delhi. But these instructions have been declared to be invalid in the judgement dt. 4-5-1988 in O.A. 529/88 on the file of the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal, New Delhi in view of the judgement in AIR 1987 SC 2342, that the Supreme Court in its judgement dt. 17-4-90 aforesaid, according to which even if a Casual labourer is recruited and employed after 30-3-1985 he is entitled to absorption and regularisation in the service of the Telecom Department if he has rendered 240 days of work in any one year period. The further contention of the Petitioner workman is that the Supreme Court declared that no distinction can be drawn between those recruited and employed after 30-3-1985 and those that were recruited and employed prior to that date and that the benefits of the decision in AIR 1987 S.C. 2342 apply to all casual mazdoors who were employed for 240 days in any year. On the other hand the Respondents have not disputed the decisions of the Supreme Court mentioned above nor they uttered a single word in their counter filed before this Tribunal, that the decisions are not applicable to the present dispute. So it goes without saying that the decisions cited by the Petitioner-workman totally applies to the present dispute on hand. It is crystal clear that the Supreme Court conferred a new right on workmen recruited and employed for 240 days in a year to be considered for absorption and regularisation in service in preference to others, of course, according to their turn in the seniority list of mazdoors in a Telecom District. Now we have to see whether the Petitioner-workman has put in 240 days service in a year. The Petitioner-workman submitted that he was employed from 1-9-84 till the end of October. During November, 1984 to January, 1985 the workman was sick and therefore could not attend to work but he resumed work in February 1985 and was employed for 26 days. But he fell sick from March 1985 to June 1988 and on his approach together with the Medical Certificates of sickness for the above mentioned periods he was readmitted to duty and employed as submitted above. Thereafter he was retrenched from 1-11-1988 without notice or notice period wages and without any compensation whatever. The workman's representation and the medical certificates submitted by him were forwarded to the Chief General Manager, Telecom, A.P. Hyderabad through the letter Ex. W1 dt. 8-12-1988 for condonation of the breaks in his service though in view of Section 25-B(2) of the I.D. Act. But no orders were passed or communicated to the workman by any authority rejecting his request for condonation of the breaks. The contention of the Petitioner-workman is that the silence of the authorities should therefore be construed as condonation of the breaks in the workman's service. The Petitioner workman depends upon Section 25-B(2) of the I.D. Act which reads thus:

"(1) a workman shall be said to be in continuous service, for a period if he is, for that period, in uninterrupted service, including service, which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lockout or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman.

(2) where a workman is not in continuous service within the meaning of Clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer".

Further the Petitioner-workman relied upon the decision reported in Mohan Lal v. Bharat Electronics Ltd. (1981(2)-LLJ page 70 SC) with reference to Section 25-B of the I.D. Act, laid down in Para 11 of the above judgement:

"Sub-Section (1) and (2) introduce a deeming fiction as to in what circumstances a workman could be said to be in continuous service for the purposes of Chapter V-A Sub-section (1) provides and deeming fiction in that whereas workman is in service for a certain period he shall be deemed to be in continuous service for that period even if service is interrupted on account of sickness... or a cessation of work which is not due to any fault of the workman. ....Sub-Section (1) mandates that interruptions indicated therein are to be ignored meaning thereby that on account of such cessation in interrupted service shall be deemed to uninterrupted and such uninterrupted service shall for the purposes Chapter V-A be deemed to be continuous service."

In view of the above and in view of the Management's admission that the workman was kept idle when there is no work it is abundantly clear that termination of the workman's service was illegal retrenchment especially when the workman had shown that his juniors are continued in service. So taking into consideration of all the above facts into consideration I find the termination of the services of the Petitioner-workman as illegal and void, and that the Petitioner-workman was sick and submitted his medical certificates for the period of his absence, I am of the opinion that reinstatement of the petitioner-workman into service would meet the ends of justice.

9. In the result, the action of the Management of M/s. Telecom. Karimnagar (A.P.) represented by their Sub-Divisional Officer, in terminating the services of Sri P. Murali. Casual Mazdoor w.e.f. 22nd November, 1988 is unjustified. The petitioner-workman is entitled to reinstatement into service immediately after publication of this Award.

Award accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal. this the 18th day of November, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

#### Appendix of Evidence

Witness Examined on

behalf of the Petitioner/

Workman :

Witness Examined on behalf  
of the Respondent/Management:

W.W.1 P. Murali

W.W.1 M. Rajashekar

Documents marked for the Petitioner/Workman :

Ex. W1 8-12-88—True Copy of the Respondent No. 2's letter to Chief General Manager, Telecom, Hyderabad with regard to condonation of break in Petitioner's service.

Ex. W2 14-3-89—Xerox copy of letter addressed by the petitioner to Regional Commissioner of Labour(C), Hyderabad with regard to raising the Industrial Dispute.

Ex. W3 27-4-89—Copy of the letter dt. 27-4-89 addressed by the Sub-Divisional Officer, Phones, Karimnagar to the Telecom Dt. Engineer, Karimnagar with regard to parawise comments report from legal cell in C.G.M. Office.



Ex. W4 31-8-89—Copy of the Rejoinder dt 31-8-89 filed by Sri C. Suryanarayana, Representative of the Workman to the Conciliation Officer, Hyderabad.

Ex. W5 31-10-89—Copy of the letter dt. 31-10-89 addressed by the Asst. Labour Commissioner(C), Hyderabad to the Secretary, to the Government of India, New Delhi with regard to reporting failure of conciliation proceedings.

Ex. W6 10-10-80—Xerox copy of the Order dt. 10-10-80 issued by the Director General, P & T, New Delhi with regard to principles to be followed to condone break in service.

Ex. W7 12-8-81—Xerox copy of the Judgement of Nagpur Bench of the Bombay High Court in W.P. No. 1584/81 and the other cases declaring C/Mazdoors in P&T as workman under the I.D. Act, 1947.

Ex. W8 3-3-85—Xerox copy of the Order dt. 30-3-85 issued by D.G. P&T with regard to prohibition fresh recruitment of casual Mazdoors.

Ex. W9 4-5-88—Xerox copy of the Judgement of Principal bench of C.A.T., New Delhi in O.A. No 529/88 declaring the DG's Order dt. 30-3-85 (supra) as no more valid in view of AIR 1987 SC 2342.

Ex. W10 17-10-88—Xerox copy of the Order dt. 17-10-88 issued by the Asst. Director General (STN) to all Heads of Telecom. Circle etc. with regard to regular absorption of casual labourers in Group 'D' posts.

Ex. W11 7-11-89—Xerox copy Order dt. 7-11-89 issued by the DG., Telecom with regard to grant of temporary status to Mazdoors.

Ex. W12 17-4-90—Xerox copy of the Supreme Court's judgement in W.P.(C) No. 1280 of 1989 with W.P. Nos. 1246, 1248 of 1988, 176, 177 and 1248 of 1988 that even those recruited after 30-3-1985 are entitled to benefits of judgement AIR 1987 SC 2342. Documents marked for the Management:

Ex. M1—Working days particulars of Md. Nazimuddin.  
Ex. M2—Working days particulars of G. Mallesh.  
Ex. M3—Working days particulars of Sri Kishan.  
Ex. M4—Working days particulars of Sri Kondiah.

नई दिल्ली 30, नवम्बर, 1993

का. आ. 2865 ———कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1-12-1993 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-3 धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (i) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है, के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

“जिला कोयम्बतूर में कोयम्बतूर (दक्षिण) तालुक के मधुकाराई फिरका में राजस्व ग्राम ईत्तीमदाई, पिच्छानूर और मवुथामपथी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र”।

[संख्या एन 38013 28 93 एस एस -I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 1993

S.O. 2865.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st December, 1993 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely:—

Area comprising the revenue villages of Ettimadai, Pitchanur and Mavuthampathy in Madhukkarai Firkka, Coimbatore (South) Taluk Coimbatore District.”

[No. S-38013/28/93-SS.I]  
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली 30, नवम्बर, 1993

का. आ. 2866 ———कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप, धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1-12-1993 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

“जिला और तालुक त्रिचूर में राजस्व ग्राम कुरुम्बिलावू के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र”

[संख्या एस-38013/29/93 एस एस-I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 1993

S.O. 2866.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st December, 1993 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala namely:—

“The areas within the revenue village of Kurumbilavu in taluk and District of Thrissur.”

[No. S-38013/29/93-SS.I]  
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1993

शुद्धि पत्र

का. आ. 2867 ———भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) में दिनांक 23-1-93 पृष्ठ 218 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, की अधिसूचना का आ. 155 दिनांक 31 दिसम्बर 1992 में कुकुन्दापुरम के स्थान पर मूकुन्दापुरम पढ़ा जाए।

[संख्या एस-38013/22/92 एस. एस.-I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव



## CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd December, 1993

S.O. 2867.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 155 dated the 31st December, 1992 published on 23rd January, 1993 at page 218 of the Gazette of India, Part II, Section (3), Sub-section (ii) for 'Kukundapuram' read 'Makundapuram'.

[No. S-38013/22/92-SS II]  
I. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर 1993

का. आ. 2868:—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय राजदूतावास, अबू धाबी में द्वितीय सचिव (सी० एल० एण्ड डब्ल्यू.) श्री कंवल जीत सिंह सोही को 3 अगस्त, 1993 से सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन नियोजकों, जो उस देश में रोजगार के लिये किसी भारतीय नागरिक को भर्ती के प्रयोजनार्थ भारतीय नागरिक नहीं है, को परमिट जारी करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए-22020/1/91-उत्प्रवास]

जी. के. भट्टाचार्य, उत्प्रवास महासंरक्षी  
तथा संयुक्त सचिव,

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2868.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby authorises, w.e.f. 3rd August, 1993 Shri K.J.S. Sodhi, Second Secretary (C.L&W) in the Embassy of India, Abu Dhabi, to exercise the powers of competent authority and to sign the work permits to the employers, who are not citizens of India, for the purpose of recruiting any citizen of India for employment in that country.

[No. A-22020/1/91-Emig. II]  
G. K. BHATTACHARYA, Protector General  
of Emigrants and Jt. Secy.

नई दिल्ली 01 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2869:—उत्प्रवास अधिनियम 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय राजदूतावास, अबू धाबी में अतामे श्री के. एस. गुप्ता को सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन नियोजकों, जो उस देश में रोजगार के लिये किसी भारतीय नागरिक की भर्ती के प्रयोजनार्थ भारतीय नागरिक नहीं है, को परमिट जारी करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए-22020/1/91 उत्प्रवास]

जी. के. भट्टाचार्य, उत्प्रवास महासंरक्षी तथा संयुक्त सचिव

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2869.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby authorises Shri K. S. Gusain, Attache in the Embassy of India, Abu Dhabi to exercise the powers of competent authority and to

sign the work permits to the employers, who are not citizens of India, for the purpose of recruiting any citizen of India for employment in that country.

[No. A-22020/1/91-EMIG. II]

G. K. BHATTACHARYA, Protector General  
of Emigrants and Jt. Secy.

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2870:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय, ऐरनाकुलम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012(88)/88 डी-III (ए)]

एस. एस. के. राय, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2870.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Labour Court, Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th November, 1993.

[No. L-12012(88)/88-DIII(A)]  
S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT,  
ERNAKULAM

(Labour Court, Ernakulam)

Thursday, the 21st day of October, 1993

## PRESENT:

Shri M. V. Viswanathan, B.Sc., LL.B., Presiding Officer—  
Industrial Dispute No. 11 of 1988(C)

## BETWEEN

The Chief Regional Manager, State Bank of India, Shan-  
mugham Road, Cochin-682031 (Kerala).

## AND

The Organising Secretary, Bank of Cochin Employees  
Association, MAS Hotel, Ernakulam, Cochin-682018  
(Kerala).

## REPRESENTATIONS:

Sri B. S. Krishnan,  
Advocate, Ernakulam. ... For Management.

Sri M. Ramachandran,  
Advocate, Kochin-17. ... For Union.

## AWARD

This industrial dispute was referred to this Court by the Central Government as per the Order No. L-12012(88)/88-DIII(A) dated 27-10-1988. The dispute is between the management of State Bank of India (Bank of Cochin) and the workman Sri P. K. Varkey. The workman is represented by the Organising Secretary, Bank of Cochin Employees Association, Cochin-18 (Kerala). The issue referred for consideration is 'Whether the action of the management of State Bank of India (Bank of Cochin) in awarding the punishment of withholding of one increment and in making in eligible for promotion for a period of five years to Sri. P. K. Varkey for the charges levelled against him while he was working at Vilangan Branch of the Bank is justified'?

2. The workman concerned is an employee of the management bank. He was working as a Checking Clerk at the Vilangan Branch of the management bank during the year 1982-83. He was transferred from the said branch in July, 1983. In 1984, he was served with a memorandum of charges alleging suppression of material facts, dereliction of duty involving financial loss to the bank. He submitted his expla-

nation to the said memorandum of charges. But the management ordered a domestic enquiry into the said charges. The enquiry officer found the workman guilty of the charges of dereliction of duty. The Management then imposed the above said punishment of withholding of one increment and making him ineligible for promotion for a period of five years. The workman raised an industrial dispute regarding the above said punishment imposed on him and it resulted in the present reference.

3. The validity and legality of the domestic enquiry was challenged by the workman concerned and the union. So this court was pleased to consider the validity and legality of the domestic enquiry as a preliminary issue, and by the order of this court dated 23-12-1992, the domestic enquiry was set aside. The management was given an opportunity to adduce fresh evidence to substantiate the charges levelled against the workman.

4. The memorandum of charges dated 19-5-1984 issued to the workman is marked as Ext. M1 (nn). It reads as follows : It is reported that an S.B. Account No. 845 in the name of Rev. Fr. Antony Porathur, Porathur House, Pavaratty was opened at our Vilangan Branch on 27-12-1982 with an initial deposit of Rs. 50 by the Branch Manager Sri P. L. Dominic with your knowledge and connivance when you were working at Vilangan Branch.

(ii) On 3-1-1983, you while working the Checking Clerk at our Vilangan Branch, colluded with the then Manager Sri P. L. Dominic in the purchase of a bogus foreign cheque No. 1431 dated 4-12-1982 for US dollar 20000 amount to Indian Rupees 1,93,000 as FCBP 1/83 in the name of Fr. Antony Porathur. It is reported that the cheque was drawn in favour of the said Rev. Fr. Antony Porathur, drawn on Bank of America, California. The drawer of the cheque is said to be the 'Society for the propogations of faith'. The proceeds of the bogus cheque is seen credited by you dishonestly in the S.B. Account No. 845 maintained in the bogus name of Rev. Fr. Antony Porathur. The proceeds credited to the S.B. Account is seen withdrawn subsequently by the Manager, Sri P. L. Dominic himself with your help for forging the signature of the account holder.

(iii) Again on 16-5-1983 an Inland bogus cheque for Rs. 1,93,000 said to be drawn on Canara Bank, Madras by one Rev. Fr. Arulapa is seen purchased by the branch as CBP 204/83 and the proceeds is credited to S.B. Account No. 845 by you dishonestly and fraudulently with the intention to assist the Branch Manager, Sri P. L. Dominic to misappropriate the Bank's funds. On the same day liability outstanding against FCBP 1/83 is seen reversed by debiting S.B. Account No. 845 with ulterior motive by you.

(iv) In order to cover up the above transactions, the following Inland cheques of bogus nature were also purchased at the branch during your tenure as checking clerk with your knowledge.

CBP No.	Date of Purchase	Cheque No.	Amount	Date of reversal
285	15-7-83	0343537	Rs. 99,000/-	8-9-83
286	15-7-83	9343538	Rs. 94,000/-	8-9-83

In the above mentioned two cases, all the entries except the reversal entries are seen made by you dishonestly and knowingly of the bogus nature of the said transactions, you have also failed to report the above purchase to Head Office through the relevant monthly statements.

The above actions as alleged to have been committed by you, would amount to suppression of material facts from the notice of Head Office, dereliction of duty, involving financial loss of the bank.

You are therefore, hereby called upon to submit your explanation within seven days of receipt of this memorandum of charges.

Should you, however, fail to submit your explanation as herein called for, the nature will be proceeded upon without any further reference to you which please take notice.

This is issued without prejudice to our right to add or amend any of the alleged charges if and when found necessary.

5. The workman submitted his explanation to Ext. M1(nn) memorandum of charges. Ext. M1(oo) is the explanation dated 1-6-1984 submitted by the workman Sri. P. K. Varkey.

6. So the material points for consideration are :

(i) Whether the S.B. Account No. 845 in the name of Rev. Fr. Antony Porathur opened at the Vilangan branch by the Branch Manager Sri. P. L. Dominic was with the knowledge and the connivance of the workman Sri. P. K. Varkey.

(ii) Whether the workman Sri. P. K. Varkey had in any way dishonestly in the purchase and crediting of the Foreign Cheque FCBP 1/83. And whether the workman helped Manager Sri. P. L. Dominic in forging the signature of the account holder for withdrawing the amounts from S. B. Account No. 845.

(iii) Whether the workman Sri P. K. Varkey had done any act fraudulently and dishonestly with the intention of assisting the then Branch Manager Sri. P. L. Dominic in the purchase and crediting of the Inland Cheque CBP 204/83

(iv) whether the workman had done anything dishonestly in the matter of the purchase and crediting of the Inland Cheque CBP 285 and 286.

(v) Whether the workman had suppressed any material facts from the notice of the head office and thereby committed dereliction of duty involving financial loss to the Bank.

(vi) What order as to reliefs ?

7. Point No. 1.—The S. B. Account No. 845 was opened on 27-12-1982 in the name of Rev. Fr. Antony Porathur. The said account was opened with an initial deposit of Rs. 50. Ext. M1(b) M1(c) and M1(d) documents would reveal these facts. The evidence of MW1 who conducted an investigation in respect of the alleged forgery would reveal the fact that the said account was opened in the name of Rev. Fr. Antony Porathur and the account holder was introduced by the manager Sri P. L. Dominic. Ext. M1(a) report submitted by MW1 would also reveal this fact. It is also come out in evidence that the said S.B. Account No. 845 was opened by Manager Sri. P. L. Dominic and the necessary entries regarding the opening of that account were made by the then clerk Ligin C. George who made the first credit entry of Rs. 50. So the workman Sri. P. K. Varkey had nothing to do with the opening of the S.B. Account No. 845. It is further to be noted that it was none of the business of the Checking Clerk Sri. P. K. Varkey to doubt the identity of the account holder. Rev. Fr. Antony Porathur who was introduced by the Manager Sri. P. L. Dominic. So this point is found in favour of the workman concerned.

8. Point No. 2.—The facts and evidence of the case would show that the purchase of Foreign Cheques and Inland cheques is the duty and authority of the manager. The Checking Clerk or other Clerks of the bank have no right or authority to purchase cheques. The Foreign Cheque FCBP 1/83 was drawn in the name of Fr. Antony Porathur. The then manager Sri. P. L. Dominic exercised his right and authority to purchase the said cheque. So naturally the proceeds of the same cheque have to be credited in the account of Fr. Antony Porathur or the same have to be given in cash. But in this case, the proceeds of the Foreign Cheque FCBP 1/83 were credited in the S. B. Account No. 845. So there is nothing wrong in making credit entries regarding the purchase of the same Foreign Cheque FCBP 1/83. Likewise the account holder Fr. Antony Porathur has got the right to withdraw the said amount. It is come out in evidence that the amounts were withdrawn by self cheques. The evidence of MW2, the then Cashier of the Vilangan Branch would show that the said cheques were collected by the Manager. It is further to be noted that

the amounts were collected by the manager even without making the necessary entries in the cheques. MW2 has deposed about the practice of encashing cheques of VIPs he further deposed that VIP customers would not come to the cashier but they used to sit in the manager's cabin and so the amounts covered by the cheques were given to the Manager directly. It is come out from the evidence of MW2 that normal and usual procedures were not adopted in the matter of encashing the self cheques of Fr. Antony Porathur. Ext. M1(g) are the self cheques encashed at the instance of the Manager Sri. P. L. Dominic. It is further to be noted that the signatures in Ext. M1(g) and M1(k) cheques were not compared with the specimen signatures. It is admitted by MW1 that the comparison of the signatures has to be done by the Section Clerk. But in the instant case the concerned Section Clerk happened to be a close friend of one of the directors of the management bank. So no action was taken against the then section Clerk who failed to compare the signatures in the said cheques with the specimen signatures. But at any rate the workman concerned Sri. P. K. Varkey had nothing to do with the withdrawing of amounts from S. B. Accounts No. 845. So it can very safely held that the workman concerned is innocent of the charges regarding the purchase and credit of FCBP 1/83 and the withdrawing of the amounts from the S. B. Account No. 845. So this point is found in favour of the workman Sri. P. K. Varkey.

9. Point No. 3—I have already held that the purchase of cheques is the right and authority of the manager. In the case of inland cheque CBP 204/83 also the purchase of that cheque was done by the manager Sri. P. L. Dominic. It was credited in the S. B. Account No. 845, as per the directions of the manager. The workman as WW1 has categorically deposed that the advice of CBP 204/83 was received by telephonic message. He further deposed that the said telephonic message from the Canara Bank at Madras was received by the Manager, Sri. P. L. Dominic and the proceeds of that cheque was credited in the S. B. Account No. 845 as per the direction and instruction of the manager. It is to be noted that the workman was only a clerical staff under the direct control of the manager. So he being a subordinate staff was bound to obey the directions of the manager. It is further to be noted that then manager P. L. Dominic was influential and he was in the good looks of the directors of the management bank. There was nothing to doubt the integrity and honesty of the manager P. L. Dominic. MW2 has also admitted that fact regarding the credit worthiness of the then manager P. L. Dominic. The workman as WW1 has also deposed to that effect. So there is nothing wrong in obeying the directions of the manager. The workman Sri. P. K. Varkey fully believed the manager and obeyed the lawful orders of the manager. The management could not point out in his evidence to show that the workman has done any unlawful or unauthorised act in crediting the amount covered by CBP 204/83. On the other hand, MW1 has admitted the fact that there is a practice of obtaining advice regarding the collection of cheque over phone. So the workman is fully justified in making the entries regarding the credit of the sale proceeds of CBP 204/83 in the S. B. Account No. 845. It further to be noted that the said cheque CBP 204/83 was also purchased from Rev. Fr. Antony Porathur who was the account holder of S. B. Account No. 845. The case of the management that the account holder Rev. Fr. Antony Porathur is fictitious person cannot be accepted. The workman as WW1 has categorically deposed that there is a person by name Fr. Antony Porathur who was the then Burzar of St. Thomas College, Trichur. It is further to be noted that Vilangan Branch is situated in Trichur District.

10 It is true that the sale proceeds of CBP 204/83 was used for reversing the outstands liability in FCBP 1/83. But it is to be noted that the sales proceeds the CBP 204/83 was credited in S.B. Account No. 845 and only thereafter that amount was made use of for reversing the outstanding liability in FCBP 1/83. According to the management the practice of purchasing one cheque and making use of the sale proceeds of that cheque for reversing the outstanding liability in another cheque purchased is an unauthorised and unlawful act. But the definite case of the workman is that in the management bank namely Bank of Cochin there was such a practice. The workman as WW1 has categorically

deposed about the said practice. He further deposed that such transactions can be seen from the ledgers maintained in the various branches of the bank of Cochin. It is further to be noted that the workman concerned was transferred from Vilangan Branch in July, 1983. But even after his transfer from the said branch, the practice of purchasing another cheque for reversing the outstanding in earlier cheque purchased had been followed even after July, 1983. This fact is admitted by the management witnesses themselves. It is also come out in evidence that one Jose D. Tharayil was in the charge of checking clerk from July, 1983 onwards and the said Jose D. Tharayil had also made such entries regarding the purchase of cheques and making use of proceeds of the said cheque for reversing the outstanding in earlier cheque purchased. But it is an admitted fact that the said checking clerk Jose D. Tharayil was absolved from all liabilities and no punishment was imposed on Mr. Jose D. Tharayil. But the workman herein was found fault with and the above said punishment was imposed. Thus it can be seen that the management bank has adopted a step-motherly attitude towards the workman concerned Sri. P. K. Varkey. So the said action of the management can treated as arbitrary. The management was not impartial in the case of the workman concerned. Likewise, in the case of then Section Clerk and Cashier and Clerk Ligia C George the management bank has shown leniency.

11. MM1 has not denied the suggestion that there was a practice in the management bank regarding purchase of cheques and reversing the outstandings with the proceeds of the cheques purchased subsequently. According to MW1 there might have been such a practice prevaild in the management bank. Likewise MW3 has not denied the suggestion regarding the purchase of cheques and making use of the proceeds of cheques to clear the outstandings in the cheques purchased earlier. According to MW3 the branches are adopting their own practice and the Head Office could not find out those practices. So I have no hesitation to accept the testimony of MW1 that there was a practice of making use of proceeds of a cheque purchased for reversing the outstanding in another cheque purchased. Thus in all respects the workman concerned cannot be held guilty of the charge of dishonest and fraudulent actions in the purchasing and crediting of cheques. The point is also found in favour of the workman.

12. Point No. 4 : The discussions and findings on point No. 3 would show that the workman concerned had not done any unlawful and fraudulent acts while discharging his duties as a checking clerk at the Vilangan Branch of the management bank. The inland cheques CBP 285 & 286 were also purchased by the then manager and entries in the register were made by the workman concerned as per the instructions of the manager. The workman has only obeyed the reasonable and lawful orders of the then manager P. L. Dominic. It is further to be noted that the reversal of these two cheques were done by the manager himself. And the some of the subsequent entries regarding CBP 285 & 286 were done by Jose D. Tharayil. But the interesting aspect to be noted is that the checking clerk Jose D. Tharayil was exonerated from the charges of dishonest and fraudulent actions in connection with the transactions in respect of the CBP 285 & 286. It is true that the workman Sri. P.K. Varkey has committed a mistake in making the entries regarding the mode of payment of the proceeds of CBP 285 & 286. Ext. M1(m) would show that the sales proceeds in CBP 285 & 286 were given to the party in cash. But the said entries to that effect in Ext. M1(n) are not correct. But actually the proceeds of CBP 285 & 286 were used to reverse the liability in CBP 204. This can be seen from Ext. M1(n) and M1(u). But it is to be noted that the mistakes committed by the workman concerned in Ext. M1(m) will not in any way affect the management bank. No loss has been caused to the management bank. It is further to be noted that the workman concerned is not in any way benefited in making such an entry in Ext. M1(m). But at the same time the workman himself has made the entries in Ext. M1(p) and M1(u). It is further to be noted that the sale proceeds of these two cheques were used to reverse the liability in CBP 204 only as per direction of the then manager. If really the workman herein had any bad motive he would not have made such entry in Ext. M1(m). The fact that he himself made Ext. M1(p) and M1(u) entries would show that the mistake committed by the workman was not at all intentional

of wilful. But that can only be treated as an inadvertent mistake. So the workman is not guilty of the above said charges. The point is answered accordingly.

13. Point No. 5—The workman has categorically denied the allegation regarding suppression of material facts. And thereby causing financial loss to the management. The case of the workman is that he used to send the monthly statements and other statements in time with all the details. He further deposed that he never suppressed any material facts from the management with any mala fide intention or motive. According to the management the workman did not show the outstanding liability in respect of FCBP 1/83. C.B.P. 204/83. The case of the management is that the stipulated period for showing the outstandings in respect of Foreign Cheques purchased is only 30 days and in respect of Inland cheques purchased it is only 10 days. But it is to be noted that the management has not produced any documents to substantiated their case. MW-3 has categorically deposed that there is circular issued by the management bank stipulating the above said period of 30 days and 10 days regarding the outstandings. But the management has not produced any such circular to support their case. Ext. M-1 (aa) and M-1 (bb) are the reports submitted by the internal auditors. The internal auditors did not make any report regarding the outstandings in respect of FCBP 1/83 and CBP 204/83 in their inspection report. This would give an indication that the testimony of WW-1 regarding the period stipulated to treating the cheques purchased as outstanding has to be accepted. The management has not produced any circulars or supporting evidence to disprove the said case of WW-1.

14. A perusal of the entire evidence on record would show that the workman who was in charge of sending the monthly statements regarding the outstanding liability had sent the monthly statement with all the details. But he committed only one omission in Ext. M-1(cc) statement. WW-1 has admitted that at the time of Sending Ext. M-1(cc) statement the cheque FCBP 1/83 was outstanding. But he omitted to incorporate the same in the said statement. The explanation given by the workman is that he sent the statement of the bonafide belief that there was no outstanding in respect of FCBP 1/83. But it can be seen that the said omission was not wilful or deliberate, but only an accidentally omission. This conclusion is strengthened by the other statements submitted by the workman in respect of these cheques. Ext. M-1(y) is dated 25-8-1983 and this was prepared by the workman herein. In Ext. M-1(y) the workman concerned has reported about FCBP 1/83. Ext. M-1(ii) is the basic statistical return prepared by the workman in June, 1983. This is a half yearly statement. In Ext. M-1(ii) also he reported about FCBP 1/83. Ext. M-1(jj) is the half early statement in respect of Inland cheque purchased. This statement was also prepared by the workman. In this statement also he has reported about CBP 204/83. Ext. M-1(kk) is the analysis of all advance as on 25-2-1983 sent from the Branch to the Head Office. The amounts shown in this statement would take in the amount covered by FCBP 1/83. Ext. M-1(11) would also give an indication that the then manager himself had intimated the Head Office regarding the purchase of FCBP 1/83. So it can very safely be held that the workman Sri P. K. Varkey had no intention to suppress the material facts from the Head Office. A scrutiny of the evidence would also reveal the fact that the then manager P.L. Dominic failed to send statements to the Head Office. It is an admitted fact that the workman is duty bound to prepare the monthly statement and submit the same to the manager. It is the duty of the manager to send the same after affixing his signature. So if the manager failed to forward statements prepared by the workman, then it is not fair on the part of the management in finding fault with the workman concerned. There is sufficient evidence on record to show that the manager did not send the statement prepared by the workman. Hence I have no hesitation to hold that the workman concerned Shri P. K. Varkey had no intention to suppress any material facts from the Head Office. There is also nothing on record to show that the workman concerned wilfully neglected to discharge his duties as a checking clerk. It is true that there occurred some omissions and mistakes on the part of the workman. But the said omission and mistakes were not intentional or wilful. So the workman cannot be labelled with a charge of dereliction of duty. There is also no acceptable evidence on record to hold that the workman caused any financial loss to the management. So this point is also found in favour of the workman concerned.

14. Point No. 6—The forgoing discussions and the finding thereon would show that the workman concerned is not guilty of any of the charges levelled against him. But he was only guilty of negligence but the said negligence cannot be treated as wilful or deliberate. But the workman has committed some omissions and mistakes while discharging the duties as a checking clerk. But the said mistakes can only be treated as inadvertent mistakes committed by him. While discharging his duties as a checking clerk at the Vilangan branch of the management bank. So the punishment of barring one increment and making him ineligible for promotion for a period of five years can only be held an excessive and disproportionate. So the action of the management in awarding the punishment of barring one increment and making him ineligible for promotion for a period of five years is liable to be set aside. The management is directed to fix the salary of the workman concerned as if there was no such punishment of barring one increment. But it is made clear that the workman herein will not get arrears of his salary on the basis of the said fixation. The workman is directed to suffer the said financial loss for the omissions and mistakes committed by him, while discharging his duty as a checking clerk at the Vilangan Branch of the management Bank. The point is answered accordingly.

15. In the result, the order of punishment of withholding one increment and barring of promotion for a period of five years passed by the management is set aside the same is unjustifiable. The management is directed to fix the salary of the workman Sri P. K. Varkey as if there was no barring of one increment. But it is made clear that the workman is not entitled to get the arrears of salary on the basis of the said fixation of salary. The workman is directed to suffer the said financial loss for the omissions and mistakes committed by him while discharging his duties as a checking clerk at the Vilangan Branch of the management bank. The management is also directed to give the workman the eligible promotions if any available to him. An award is passed accordingly.

Ernakulam,

Dated : 21-10-1993

M. V. VISHWANATHAN, Presiding Officer

#### APPENDIX

Witnesses examined on the side of

Management :

MW-1—Sri Sunny Mathew.

MW-2—Sri A. C. Johny.

MW-3—Sri P. J. Sebastian.

Witnesses examined on the side of

Workman :

WW-1—Sri P. K. Varkey.

Exhibits marked on the side of Management :

Ext. M-1—File containing proceedings and report of domestic enquiry held against the workman.

Ext. M-1(a)—True copy of letter dated 11-2-84 from Inspector of Branches, Bank of Cochin, Vilangan Branch to the Manager, Inspection Department.

Ext. M-1(b)—Photo copy of Account opening from Regarding S.B. Account No. 845 dated 27-12-83.

Ext. M-1(c)—Photo copy of S.B. Account sheet regarding S.B. Account No. 845.

Ext. M-1(d)—Photo copy of pay in slip for Rs. 50 regarding S.B. Account 845.

Ext. M-1(e)—Photo copy of debit voucher regarding FCBP 1/83 dated 3-1-83.

Ext. M-1(f)—Photo copy of pay-in-slip of Rs. 1,93,000 regarding S.B. Account No. 845 dated 3-1-83.

Ext. M-1(g)—Photo copy of Self cheque for Rs. 15,000 Regarding S.B. account No. 845 dated 3-1-83.

Ext. M-1(h)—Photo copy of self cheque for Rs. 25,000 regarding S.B. account No. 845 dated 5-1-83.

Ext. M-1(i)—Photo copy of self cheque for Rs. 10,000 dated 17-1-83 regarding account No. 845.

Ext. M-1(j)—Photo copy of self cheque for Rs. 100,000 dated 28-1-83 regarding account No. 845.

Ext. M-1(k)—Photo copy of self cheque for Rs. 43,000 dated 17-12-83 regarding account No. 845.

Ext. M-1(l)—Photo copy of self cheque for Page No. 63 of C.B.P. Register.

Ext. M-1(m)—Photo copy of page No. 70 of C.B.P. Register.

Ext. M-1(n)—Photo copy of page No. 77 of C.B.P. Register.

Ext. M-1(o)—Photo copy of page No. 91 of C.B.P. Register.

Ext. M-1(p)—Photo copy of page No. 90 of C.B.P. Register.

Ext. M-1(q)—Photo copy of page No. 95 of C.B.P. Register.

Ext. M-1(r)—Photo copy of credit voucher reg. FCBP 1/83 dated 16-5-83.

Ext. M-1(s)—Photo copy of credit voucher reg. FCBP 1/83 dated 16-5-83.

Ext. M-1(i)—Photo copy of credit voucher reg. CBP 204 dated 15-7-83.

Ext. M-1(u)—Photo copy of credit voucher reg. CBPs 283 to 286.

Ext. M-1(v)—Scrits (4 Nos) Monthly statements.

Ext. M-1(w)—Letter dated 14-12-84 from workman to the Inspector of Branches.

Ext. M-1(x)—Letter dated 20-2-84 from P.L. Dominic to the Enquiry Officer.

Ext. M-1(y)—Photo copy of Annexure to the monthly statement.

Ext. M-1(z)—True copy of letter dated 13-2-83 from P.L. Dominic to Inspector of Branches.

Ext. M-1(aa)—Photo copy of Inspection Report of Sri A. L. Thomas dated 15-2-83.

Ext. M-1(bb)—Photo copy of inspection report of Sri M. J. Thomas dated 12-8-83.

Ext. M-1(cc)—Photo copy of Basic statistical return No. 2.

Ext. M-1(dd)—Photo copy of Annexure to monthly statement No. 6 as on 24-6-83.

Ext. M-1(ee)—Photo copy of annexure to monthly statement as on 29-4-83.

Ext. M-1(ff)—Photo copy of annexure to monthly statement as on 29-7-83.

Ext. M-1(gg)—Photo copy of monthly statement No. 6 regarding FCBP as on 25-1-83.

Ext. M-1(hh)—Photo copy of monthly statement No. 6 regarding FCBP as 25-2-83.

Ext. M-1(ii)—Photo copy of basic statistical Return No. 1 (Part B).

Ext. M-1(ii)(a)—Photo copy of basic statistical return No. 1 (Part A).

Ext. M-1(jj)—Photo copy of basic statistical return Part-I as on June 1983.

Ext. M-1(kk)—Photo copy of Analysis of advance dated 15-3-83.

Ext. M-1(ll)—Photo copy of BCF 167 dated 4-1-83.

Ext. M-1(mm)—Photo copy of monthly statement No. 6 for FCBP as on 25-7-83.

Ext. M-1(nn)—True copy of Memo of charges dated 19-5-84.

Ext. M-1(oo)—Explanation of the workman dated 1-6-84.

2816 GI/93—27.

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1993

का.श्रा. 2871.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (नं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/239/88-डी3(ए)]

एम. एस. के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2871.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 1-12-1993.

[No. L-12012/239/88-D.3(A)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 15 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Ranchi and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri T. K. Guha, Dy. General Secretary.

On behalf of the employers—Shri A. K. Gupta, authorised representative.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 23rd November, 1993

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/239/88-D.3(A) dated the 14th August, 1989.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India in paying Shri Jitan Ram, Sweeper 1/2 wages from October, 1983 (from his date of appointment) and 3/4 wages from recently and not regularising his service as permanent sweeper is justified? If not, to what relief the workman entitled?"

2. In this reference the action of the management has been challenged in paying Shri Jitan Ram, Sweeper 1/2 wages from October, 1983 and 3/4 wages from recently and not regularising his services as permanent sweeper.

3. The concerned workman filed his statement of claim stating that he was a member of S.C. community and was appointed as permanent sweeper on 10-8-83 and there was nothing to show in the aforesaid appointment letter to suggest that he was appointed as part time sweeper on 1/2 wages or he was to work for a specified hours of work.

4. It was contended that he was confirmed in the permanent services after 6 months of probation vide Bank's memorandum dated 29-5-84 and that also did not suggest that he was confirmed as part time sweeper.

5. It was further contended that though the concerned workmen was appointed as full time worker and he worked as such he was irregularly paid 1/2 salary from the date of his appointment and 3/4th wages from 1st July, 1987 despite his repeated request and protest. He was also not allowed to make attendance in the Attendance register according to the hours of work which he put in. He contended that one Shri Jag Mohan Ram who has been sweeping first floor gets full salary while the concerned workman sweeping second floor got 1/2 salary till 30th June, 1987 and so in this way he was discriminated. The workman pointed out this discrimination and demanded payment of full salary and then the Bank came out with a noble plea in their memorandum dated 19-10-87 that Shri Jag Mohan Ram work in different establishment (Ranchi Branch). The concerned workman also pointed out the case of Mukul Ram who was later on confirmed in the permanent services along with the concerned workman who subsequently was converted to the cadre of full fledged subordinate cadre with full pay. The concerned workman represented his case many times before the management but it was of no use and ultimately an industrial dispute was raised giving rise to the present reference.

6. The management also filed separate W.S. refuting each and every claim of the concerned workman. It was submitted that an interview was conducted on 28-9-83 for appointment of the permanent part time sweeper in which Shri Jitan Ram the concerned workman had also appeared and he was selected. In this way Shri Ram was appointed as permanent part time sweeper vide management's letter dated 5-10-83 on 1/2 salary depending upon hours of work per week. Since the date of appointment he was required to work only for 19 hours in a week and so he was paid 1/2 wages as per terms and condition of service.

7. Since 1st July, 1983 Shri Ram's working hour was increased and he was required to work for 29 hours and since then he is being paid 3/4th of the wages scale. Shri Ram raised industrial dispute in the year 1988 before the ALC(C), Ranchi for alleged non-payment of proper wages and also for not regularising him in permanent services. The ALC(C) sent F.O.C. to the Ministry of Labour Government of India and the Ministry of Labour in turn wrote a letter on 25-1-1989 to the ALC(C) Ranchi for conversion of the part time employees on full time basis in which the name of Shri Jitan Ram was specifically mentioned. In pursuance of the aforesaid policy the Regional Office (under the Zonal Office) issued a call letter dated 10-1-89 for conversion from part time to full time employees. This call letter was also sent to the concerned workman through the Bank's Peon but he refused to accept the letter. This refusal was conveyed to the Ministry of Labour in reply to their letter dated 25-1-89. However, the concerned workman was given another chance for appearing in the interview vide call letter dated 21-4-89. But this time also he did not avail the chance. Again for the 3rd time i.e. on 8-1-90 an interview letter was sent for the purpose but the concerned workman did not appear. By making such statement it was submitted that the concerned workman has got no case and he is not entitled to any relief.

8. The question for consideration is as to whether the concerned workman was entitled for full time wages and also for regularisation in the services.

9. Admittedly, the concerned workman was appointed vide management's letter No. CRM/PER/GENL/656/83 dated 5-10-83 (Ext. W-1). However, according to the management the concerned workman was appointed as permanent part time sweeper on 1/2 salary and allowance depending upon the hours of work per month. It is further stated that till 30th June, 1987 he was required to work only 19 hours in a week and so he was paid 1/2 of the scale wage. But according to the workmen he was appointed as permanent sweeper under the signature of the then Personnel Officer. In this connection I have perused the appointment letter Ext. W-1 which does not whisper even a word like part time employee as sweeper rather it states about the appointment for the post of Sweeper. From the letter it also transpires that an interview for the post of Sweeper had already been conducted on 28-9-83. By the letter he was called in the office on 7-10-83 to complete all formalities and medical check up. The management admitted that in the said interview the concerned workman appeared and he was selected.

It has been suggested to the concerned workmen WW-1 that the said call letter was only for part time sweeper. The witness has denied the suggestion. In the circumstances it was obligatory on the part of the management to produce the interview letter dated 28-9-83 to prove that the concerned workmen was interviewed for his appointment as part time sweeper. Non-production of that call letter will draw adverse information against the management. The learned representative for the management urged that appointment letter was issued in normal course and the technicalities was not examined. I think the argument so advanced cannot be appreciated in right direction. Actually by the appointment letter the concerned workman was made to understand that he was appointed as fullfledged sweeper and not a permanent part time sweeper. Be that as it may the omission of the word "Part time" sweeper in the appointment letter, in my opinion, was very serious. Anyway the stand taken by the concerned workman is further strengthened by Ext. W-2 which is a photo copy of the confirmation letter dated 29-5-84 addressed to the concerned workman. The contents of the letter is very clear to support the fact that the concerned workman was confirmed in his appointment to the post of Sweeper in Bank's services with effect from 10-4-84. This means he was confirmed on the post immediately after 6 months of his appointment as Sweeper. Even the confirmation letter did not speak that he was a permanent part time sweeper. Even supposing for the sake of argument he was appointed as permanent part time sweeper even then by this letter (Ext. W-2) the management confirmed him as full fledged permanent sweeper.

10. MW-1 Shri G. J. Sao was Personnel Officer in the SBI Zonal Office, Ranchi from October, 1983 to May, 1989. He stated that the concerned workman was appointed as permanent part time sweeper. It was urged during the course of argument that the witness has not been cross-examined on this point and so the evidence adduced will be taken as ex-parte. The submission could have been very well appreciated had the statement been supported by any documentary evidence. The documentary evidence (Ext. W-1 and W-2) are silent on this point. The evidence of the witness that the concerned workman was appointed as permanent part time sweeper stands nullified in the face of Ext. W-2, the confirmation letter.

11. The witness has proved photo copy of the format page 191 reference book of Staff matter which has been marked Ext. M-17. As stated it is with respect to temporary part time employees. It was published in the year 1988. By this document the management wanted to impress upon that the proforma was not in existence when the concerned workman was appointed. It was also meant for temporary part time employees and not for permanent part time employees. Admittedly, the word temporary does not appear in the proforma in Ext. M-17. I think the matter has already been discussed and sufficiently answered. It was for the management to take precaution that while issuing the appointment letter the word "permanent" part time sweeper should have been noted.

12. Shri Jitan Ram, WW-1 stated that he was appointed as permanent sweeper and was never told that he was appointed as part time sweeper. He had written letter to the authority including the Hon'ble Prime Minister for rectification of discrepancy in his salary. He had written letter dated 3-12-85 to the Chief Regional Manager for the enhancement of his salary under (Ext. W-17). In the letter there was a reference of previous letter dated 19-8-85. There was no reply of that letter. Ext. W-18 is the registration receipts but they do not disclose as to which receipt appertain to which authority. It appears that Shri Ram did not sit idle rather his efforts for redressal of his grievance continued and he wrote another appeal dated 4-7-87 to the Dy. General Manager, Ranchi again requesting for full pay on the ground that he was appointed as permanent sweeper. (Ext. W-5). In this letter also he noted that one Jag Mohan Ram junior to him was getting full salary but he was being discriminated. The concerned workman again wrote similar letter on 27-7-87 to the same authority. However, this time a reply to the letter dated 4-7-87 of the concerned workman was sent to him vide Memo No. 950 dated 19-10-87. The reply did not state that the concerned workman was a part time sweeper. However, with regards to the pay of Jag Mohan Ram a very evasive and conjectural reply was submitted stating that there must be requirement of full time workman where Shri Jag Mohan Ram was working. Ext. W-8 is the reply of the memo



No 950 dated 19-10-87. Again the concerned workman asserted that he was a permanent employee and he cannot be paid as part time sweeper. It is dated 31-10-87. Lastly the concerned workman having seen no sign of remedy wrote to the Hon'ble Prime Minister of India Ext. W-10 for which a show cause notice was issued by the management against him Ext. W-11. Ext. W-12 is the reply of the show cause. Ext. W-9 is the letter written to the Dy. P.M., S.B.I., Ranchi by the Dy. General Secretary of SBI employees union for payment of full salary to the concerned workman. In this way it is a very manifest that the concerned workman after his confirmation has always been representing his case for full salary on the ground that he was appointed as full time sweeper. It was canvassed at the bar that non-mentioning of the word 'part time' was simply an omission. In my view that may be an omission but the propriety demanded that the concerned workman should have been appraised of this position and specially when he himself was making correspondence for years together with the management for his full payment.

13. It is the cardinal principle of law that a workman is entitled to full salary only when he works for whole day i.e. the prescribed hours of work. Shri Jitan Ram has stated in his evidence that he has been discharging his full time duty but the bank management has been forcing him to write 5 hours duty per day. He had also stated that while getting 1/2 wages he used to work 20 hours in a week but his attendance was marked for 19 hours only. Admittedly he did not write to any authority that he was forced to write five hours of work and that his attendance was marked for 19 hours when he was doing for 20 hours. I find that this assertion in absence of any documentary evidence has got no force and it cannot be accepted. In this connection we may have a look to Ext. M-13 prescribing hours of work in a week for part time subordinate staff. He will be paid 1/2 wages for the working hours between 13 hours to 19 hours. Similarly he will be paid 3/4th of the scale wage if the working hours are more than 19 hours to 29 hours. He will be paid full wages beyond 29 hours. Ext. M-15 prescribed hours of work per day excluding Sunday and Saturday for permanent subordinate staff. A permanent subordinate staff other than drivers and watch and ward staff is required to work in 7 hours per day. The concerned workman was entitled for 1/2 wages for 19 hours of in a week and his demand as that he should be paid 3/4th wages only for 1 hour extra duty per week which reasonably should not be allowed. It was his contention that he had been working for 20 hours in a week although 20 hours of his work has not been substantiated through any documentary evidence.

14. The salary of the concerned workman was enhanced from 1/2 to 3/4th from July, 1987 with a direction that he was required to work more than 19 hours in a week. Ext. M-10 is the pay roll statement showing that in the month of June, 1987 the concerned workman was getting 1/2 salary i.e. Rs. 239. His name appears at Sl. No. 3/018. In the month of July, 1987 it was raised to Rs. 358.50 P. which was equivalent to 3/4th of the salary. On behalf of the concerned workman it has been contended that he has been doing full time duty but he was paid less wages. Ext. M-8 is the photo copy of the Attendance Register of the concerned workman and others. The register shows that the employees both permanent and part time were required to work six days in a week. It was the case of the concerned workman that he had been working five hours every day including Saturday and in that way he had been doing for 30 hours in a week, and so was entitled for full salary. However, according to the management the concerned workman worked for 4 hours only on each Saturday. Thus his total working hours in a week did not exceed 29 hours, and was entitled for 3/4th salary which he was getting from the management. It was pointed out that as per Ext. M-8 even the permanent employees were required to work till 2 P.M. on each Saturday then now a part time employee can be engaged from 7.30 A.M. to 12.30 P.M. on Saturday. It may be mentioned that the working hours of Shri Jitan Ram was from 7.30 A.M. to 12.30 P.M. and this can be certified from Ext. M-8 and W-16. The only controversy was that according to the management he used to work for four hours on Saturday but according to C/W he had been doing 5 hours each day including Saturday. It does not stand to my reason as to why the concerned workman will be asked to work till 12.30 P.M. on Saturday when the grace hour was allowed to the permanent workmen.

Again it looks something abnormal that the management remained silent spectator when the concerned workman was marking the departure time at 12.30 P.M. instead of 11.30 A.M. M.W-2 Shri A. K. Agarwal stated in his evidence that the concerned workman never worked for the whole day. According to him whole day working means duty from 10.00 A.M. to 5 P.M. That whole day working was done from Monday to Friday but on Saturday it was from 10 AM to 2 P.M. The concerned workman according to him was required to work for 29 hours from Monday to Saturday. This means 5 hours for 5 days and 4 hours on Saturday. But it was a folly on the part of the management that it did not prohibit the concerned workman from marking wrong of hours of departure on Saturday. The witness stated that he never instructed the concerned workman to write 11.30 A.M. since the matter was subjudice before the Tribunal. I think this statement cannot be appreciated for the reference was made in the year 1989 and the conciliation matter was pending in the year 1988. The concerned workman had written to the Hon'ble Prime Minister in the year 1988 and so it is wrong to suggest that the matter was subjudice in the year 1987. Anyway from these facts it is well established that the union failed to establish that the concerned workman was working full day and was entitled for full payment.

15. The concerned workman stated that there was no provision for any interview for raising salary from 1/2 to 3/4th and from 3/4th to full salary. Admittedly, the concerned workman did not attend the interview. In the W.S. it has been stated that the management asked the concerned workman to appear before the Interview Board on 13-1-89 and again on 29-4-89 for his conversion to full time worker with a view to frustrate the impending reference before the Tribunal. I think this contention merits no appreciation. According to own saying the concerned workman was doing 20 hours of duty and was getting 1/2 wages. This means he was discharging full duty nor getting full pay. There may not be any provision of rule or interview. Since the employees including the concerned workman were not getting full salary there should be something like formality to be gone into by the management before making full payment. The union says that the concerned was called for interview to frustrate the impending reference but for the reasons stated above the contention could not be appreciated. There could have been no question of any frustration. If the concerned workman was converted to full time worker even at the later stage he should have, if advised, claimed for difference of wages under the provision of the I. D. Act and so I am to hold that it was absolutely wrong on the part of the workmen when he did not attend the interview.

16. Ext. M-1 is the letter written by Shri N. K. Verma, Desk Officer to the ALC(C) Ranchi regarding conversion of part time employee to full time basis. Ext. M-2 is the interview letter issued under the memo No. 801 dated 10-1-89 directing the concerned workman to appear for interview on 13-1-89. The service was done through the Peon. The concerned workman refused to acknowledge receipt. Ext. M-11 is the refusal note of the Peon. The Ministry of Labour was apprised of this refusal by the concerned workman vide Ext. M-3. Ext. M-4 is another letter dated 21-4-89 sent to the concerned workman under registered cover directing him to appear for interview on 29-4-89 but this time also he did not appear. However, this time he replied vide Ext. W-14 that he was appointed on permanent basis and so there was no question of interview. I find that the management for the 3rd time issued call letter on 8-1-1990 vide Ext. M-5. But this time also he did not appear. In this way he was called three times to face interview but he always refused on the ground that he was a permanent employee and there was no provision for interview. The matter has already been discussed.

17. I have examined various aspect of the matter and I am to hold that the concerned workman was not entitled for full time salary. But the matter is directed to interview the concerned workman within 2 months from the date of the publication of this award and to confirm the concerned workman on his post. If the concerned workman fail intentionally to appear in the interview on the date to be fixed by the management he will be forfeiting his right for regularisation.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2872.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 वा 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/73/89-आई आर (बी I)]

एस. एस. के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2872.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, cum Labour Court, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-12-1993.

[No. L-12011/73/89-IR(B)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 169/89

Anil Kumar Sikka Vs. Bank of Rajasthan Ltd.  
For the workman : None.

For the management : Shri V. K. Gupta.

## AWARD

Central Govt. vide gazette notification no. L-12011/73/89-I.R. (Bank)-1 dated 17th October 1989 issued U/S 10(1)(d) of I.D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Bank of Rajasthan Ltd. in relation to their Rohtak Branch in terminating the services of Shri Anil Kumar Sikka & Shri Ved Parkash Sikka w.e.f. 19-1-1985 and thereafter not giving the opportunity for his re-employment is just, fair and legal? If not, to what relief the said workman is entitled to?"

2. Brief facts as emerged in the statement of claim that the petitioner was appointed as clerk against permanent vacancy. He performed his duties w.e.f. 31-10-1984 up till 18-1-1985. No appointment letter was given. He was not allowed to resume his duties on 19-1-1985 although his appointment was for indefinite period. He was not paid any retrenchment compensation in lieu of illegal termination. Action of the management was in violation of provisions of Sastri Award and also the Industrial Disputes Act 1947. It was further alleged that bank adopted unfair labour practice and appointed other persons in place of the petitioner. He has thus sought reinstatement with back wages with all consequential benefits.

3. The management in the written statement has denied that the appointment of the petitioner was against permanent vacancy. According to the management, under the rules and the policy of recruitments, recruitment for permanent vacancy is through competitive written examination conducted by the Institute of Banking Personnel Section. The candidate qualifying the said examination are finally empanelled for appointment in order of merits obtained in the examination/interview. No permanent vacancy can be filled except in accordance with the said procedure. However stop gap arrangements can be made by the local manager to carry on the work. The Rohtak branch was newly branch opened on 17-10-1984. The process of recruitment was time consuming and thus the petitioner was given temporary and fixed term employment as stop gap arrangement. He

was given appointment firstly for 31 days from 31-10-1984 to 30-11-1984 and then from 1-12-1984 to 18-1-1985 providing automatic termination of contract on the expiry of the said period. Therefore, there is no question of the petitioner to resume the duty on 19-1-1985. Contents of statement of claim that his appointment was against permanent vacancy and for indefinite period is deliberately false. The petitioner have stated to have not come to the Court with clean hands and thus sought the dismissal of the reference.

4. Various registered notices were sent to the petitioner. He did not put up appearance. Evidence of the management was called. The management produced MW1 Ranbir Singh Deputy Manager (P). He filed his affidavit Ex. M1. He also relied on the documents Ex. M2 and M3 and the management closed their evidence.

5. I have heard the counsel for the management and gone through the evidence and record.

6. Counsel appearing on behalf of the management has pointed out that the workman has lied while stating that his appointment was against permanent vacancy and for indefinite period and has pointed out his appointment letters Ex. M2 and M3 and has argued that his appointment was for specified period and ends at the expiry of the said period and thus his case falls under the exclusion clause (bb) of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act 1947. I agree with the contention raised by the learned counsel appearing on behalf of the management. Ex. M2 is the appointment letter of the petitioner dated 31-10-1984 wherein his appointment was only for 31 days from 31-10-1984 to 30-11-1984 and that too on account of leave arrangement of the staff. Similarly by virtue of Ex. M3 the subsequent appointment letter his employment was further continued from 1-12-1984 to 18-1-1985 for the period of 49 days in the same pattern on account of leave arrangement of the staff. Having the management opened a new branch at Rohtak and obviously the appointments were made as stopgap arrangement as regular recruitments could have a time consuming process, therefore, certainly the appointment of the petitioner was never against the permanent vacancy not for a indefinite period and the same was for a specified period. The clause (bb) of sub section (oo) of Section 2 of the I.D. Act is effective from 18-8-1984. It provides that termination of the services of the workman as a result of non renewal or contract between management and workman concerned on its expiry as the said contract being terminated under a stipulation in that behalf shall not constitute retrenchment. Therefore, it has to be held that the non-renewal of the services of the petitioner as a result of stipulation in that behalf contained in the said appointment letter it self and squarely covered by exclusion clause (bb) of Section 2(oo) of the Act and hence the said action could not amount to retrenchment on the part of the management.

7. The petitioner has failed to substantiate his claim for violation of Section 25-H of the I.D. Act 1947 obviously for the reason that he has not participated in the present proceedings. Even in the statement of claim he has nowhere alleged that who has been appointed after his termination and when the said appointment took place. The petitioner is heavily burdened to prove the same for which there is a complete lull. Even otherwise having the case of the petitioner fallen under the clause (bb) of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act 1947 does not constitute retrenchment as stated above. The petitioner can not as a matter of right claim benefits U/S 25-H of the I.D. Act 1947. The ratio laid down in K. Rajan and another Vs. The Kerala State Electricity Board and others 1992 Lab. I.C. 1208 is followed.

8. Hence nothing survive to the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to any relief whatsoever. In a way the reference is answered accordingly.

Chandigarh.  
16-11-1993.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer



नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 1993

का.आ. 2873.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, न. 1, मुंबई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17012/31/89 आई आर बी-1/II]

बी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2873.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 1-12-93.

[No. L-17012/31/98-IRBI/II]

V. K. VENUGOPAL, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY.

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer  
REFERENCE NO. CGIT-37 OF 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of  
L.I.C. of India.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Shri Ramachandran,  
Manager,

For the Workmen : Shri S. Mukherjee, re-  
presentative

INDUSTRY : Insurance

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 23rd of November, 1993.

#### AWARD

The following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by order dated 24-5-1990, for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

“Whether the action of the management of LIC in providing foot-wears only to the Watchmen and Drivers and not providing the same to the remaining 7-categories i.e., 1. Building Maintenance Staff, 2. Sweepers, 3. Cleaners, 4. Hamals, 5. Liftman, 6. Peons and 7. Head-Peons of Class

IV Employees of LIC is legal and justified ? If not, to what relief the workman are entitled for ?”

2. On behalf of the All India LIC Employees' Federation statement of claim has been filed. It has been stated there in that the federation is the apex body at the All India Level, to which various Divisional Unions of the workmen employed in the divisions of Life Insurance Corporation of India are affiliated. It is stated therein that the Subordinate Staff (Class-IV) consisted of the following categories, they are :

1. Building Maintenance Staff
2. Sweepers,
3. Cleaners
4. Hamals
5. Liftmen
6. Peons
7. Head Peons
8. Watchmen and
9. Drivers.

3. It further stated that the Management of LIC took a unilateral decision to provide footwear as a part of the uniform to only two categories of the staff, namely Watchmen and Drivers. This was conveyed to all the Zonal Managers by letter dated 4-5-1987. The employees were also informed about it by circular dated 29-1-1987. This decision of the management has been styled as unfair labour practice, discriminatory, bad in law, and was therefore, protested by representation dated 1-2-1988 of the Federation. It was followed by a demonstration and since there was no favourable response, a dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner and on failure of the same, the present reference has been made to this Tribunal. The grievance was that all the categories of substaff should be provided with uniform including footwear.

4. The management has infact issued a circular dated 26-5-1989 conveying the decision to supply a pair of shoes or chappals once in two years to all substaff (Class-IV) of the Life Insurance Corporation of India. As a result, the main dispute does not survive. However, the claim of the federation is that this decision should be made effective from the date when the earlier decision to provide Footwear to Watchmen and Drivers was taken i.e. 4-5-1987, and communicated by circular dated 29-12-1993.

5. The corporation filed its written statement and it has been not disputed that by the earlier decision only two categories of the sub-staff, namely, Watchmen and Drivers were to be provided with Footwear, and subsequently, the said facility has been made available to all other categories of the sub-staff. The prayer therefore, is, that in view of the subsequent decision, the present reference does not survive as there is no industrial dispute existing. In addition, the corporation have filed a detailed written statement and it has been stated therein that as a result of the settlement arrived at between the management and various employees' unions, in the year 1970, on the point of “outfit for Class-IV employees” the question of footwear to the eligible employees in Class-IV was settled and therefore, the workmen are not entitled to the supply of foot-

wear apart from what has been provided under the order subsequently passed by the corporation. They have therefore prayed for dismissal of the present reference.

6. Another body, namely, the Akhila Bharatiya Jeevan Bhima Nigam Chaturth Sreni Kamgar Sangh, represented by the Joint Secretary Shri S. S. Padwal filed its statement of claim after seeking permission from this Tribunal. The demand made by this statement of claim is that the footwear should be provided once in every year.

7. The circular dated 26-5-1989 has been produced on record, and in view of that I do not think there is any dispute now surviving. The circular dated 26-5-1989, a copy of which has been produced by the management deals with at item No. 5, the issue of Shoes/Chappals for Class-IV employees. It provides;

"It has been decided to supply one pair of shoes or chapelr once in two years to all confirmed Class IV employees. The employees may be allowed to purchase shoes or chappals of their choice at a cost not exceeding Rs. 150/-. They should be required to submit the cash receipt for the same. On submission of the cash receipt the actual amount subject to the limit specified above may be reimbursed to the employee. It may be noted that Drivers and Watchmen are already being supplied shoes and, therefore, in respect of employees belonging to these categories the cost may be reimbursed on the expiry of 2 years from the date of last supply of the shoes. A register of reimbursement cost of shoes/chappals to Class IV employees shall be maintained in the proforma given in Annexure I by all the Offices so that proper control is exercised."

8. Therefore, the demand raised by the Federation that all the Class-IV employees who were not provided with footwear alongwith the Watchmen and Drivers is met, and the grievance does not survive since the same facility extended to the other categories of the Class-IV employees.

9. The Kamgar Sangh's grievance that they should be provided footwear once in every year is in my opinion not covered by the present reference. It says :

"Whether the action of the management of LIC in providing foot-wears only to the Watchman and Drivers and not providing the same to the remaining 7-categories i.e. 1. building Maintenance Staff, 2. Sweepers, 3. Cleaners, 4. Hamals, 5. Liftman, 6. Peons and 7. Head Peons of Class IV Employees of LIC is legal and justified? If not, to what relief the workman are entitled for?"

10. In the statement of claim also the Federation has referred to the same demand which they have made before the Asst. Labour Commissioner. In para

5 of the statement of claim, they have specifically mentioned that the supply of foot wear may be effected to all categories of sub-staff (Class-IV) under the Establishment of Life Insurance Corporation of India.

11. Therefore, the demand made by the Kamgar Sangh, for supply of footwear once in every year cannot be adjudicated under the present reference. In the circumstances, I am unable to find any justification for this demand for supply of footwear once in a year.

12. The point that was urged was that they should be made applicable since the date the other workmen namely drivers and watchmen were granted benefit. The plea made was that they may be paid compensation for the period between 4-5-1987 and 26-5-1989. I am not inclined to grant this relief in the circumstances of this case.

13. In the circumstances, award is accordingly made with no order as to costs.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2874.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध में निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/45/86-डी-2(ए)]

वी. के. वणुगोपालन, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd December, 1993

S.O. 2874.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 1-12-1993.

[No. L-12011/45/86-DIA]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 106 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Bank of India ;

## AND

Their workmen.

## PRESENT :

Mr. Justice Manash Nath Roy, Presiding Officer.

## APPEARANCES :

On behalf of Management.—Sri R. N. Mazumdar, Advocate.

On behalf of Workmen.—Sri P. Roy Chowdhury, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

## AWARD

At the time of construction of the Multi-storied Head Office Building (hereinafter referred to as the said Building), of United Bank of India (hereinafter referred to as the said Bank), at 16B, Old Court House Street, Calcutta, some persons were appointed for maintenance and security of the building and so also the costly installations and materials, on the basis of certificate of registration under the Contract Labour Regulation and Abolition Act, 1970 (hereinafter referred to as the said 1970 Act), and the Union viz. United Bank of India Sramik Karmachari Samity (hereinafter referred to as the said Union), has claimed that 19 persons involved in this proceeding, were so employed by the said Bank on temporary basis, as Security Guards, Cleaners and Sweepers.

In fact, it has been stated that serial Nos. 1 to 9 of the Reference, the particulars whereof will be indicated hereinafter, were employed as Security Guards, serial Nos. 10 to 13 were appointed as Cleaners and those in serial Nos. 14 to 19, were engaged as Sweepers.

2. It was the case of the said Union that on the basis of the terms of appointment of those employees and the relevant circulars, they were required to be made permanent by the said Bank and they were also entitled to continue in uninterrupted temporary service as rendered, from March 1, 1977 to October 31, 1977 i.e. prior to their appointments on permanent basis, with effect from November 1, 1977 in their respective posts and since, such benefits were not given to them, because of the inaction of the said Bank, the dispute as quoted hereinunder :

“Whether the action of the management of United Bank of India, Calcutta, in not counting the uninterrupted temporary service rendered from 1-3-1977 to 31-10-1977 in the Bank's service prior to their appointment on permanent basis with effect from 1-11-77 in respect of 9 Security guards, four cleaners and 6 sweepers of the United Bank of India, Head Office, Calcutta, as per detail in Annexure to this Schedule is fair and justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?”

## Annexure

Sl. No.	Name and Designation	Date of appointment	Date of permanent absorption	Date of increment
1.	Jnanamoy Ghosh, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
2.	Debsekhar Nag, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
3.	Gopal Chandra Roy, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
4.	Jnan Bahadur Chhetri, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
5.	Niranjan Sarkar, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
6.	Supriya Saha, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
7.	Babunath Jha, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
8.	Himangsu Kar, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
9.	Samir Chatterjee, Security Guard	1-3-77	1-11-77	1-11-78
10.	Amal Ghoshal, Cleaner	1-3-77	1-11-77	1-11-78
11.	Dulal Dalal, Cleaner	1-3-77	1-11-77	1-11-78
12.	Panchu Prasad,— Cleaner	1-3-77	1-11-77	1-11-78
13.	Dulal Mondal, Cleaner	1-3-77	1-11-77	1-11-78
14.	Bipad Das, Safaiwala	1-3-77	1-11-77	1-11-78
15.	Ram Deo Das, Safaiwala	1-3-77	1-11-77	1-11-78
16.	Nanhilal Balmiki, Safaiwala	1-3-77	1-11-77	1-11-78
17.	Suresh Balmiki, Safaiwala	1-3-77	1-11-77	1-11-78
18.	Balbir Balmiki, Safaiwala	1-3-77	1-11-77	1-11-78
19.	Viki Das, Safaiwala	1-3-77	1-11-77	1-11-78

has been referred for adjudication to this Tribunal, by Government Order No. L-12011/45/86-D. II(A) dated August 11, 1987, under section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act).

3. By the written statement, filed on May 9, 1988, the said Union has stated that the employees as mentioned hereinbefore, were appointed with effect from March 1, 1977 and they were provided with letter of appointments and the terms therefore, were further extended from time to time and they have further stated that at a subsequent stage, with effect from November 1, 1977, all the employees as mentioned above, have been permanently absorbed in the employment of the said Bank, by issuing letters of confirmations to them. It has been stated, while granting such permanency, the said Bank, in an unequivocal language stated that the workmen concerned, were absorbed against permanent vacancies.

4. It has been alleged that although the employees concerned, were appointed on permanent basis, on and from November 1, 1977, consequent to their appointment as mentioned earlier, none of them were considered by the said Bank to have been employed with effect from March 1, 1977, which the said Bank, should have done and such refusal, caused resentment amongst the employees and ultimately, on failure of conciliation in the Bipartite level, the cause was espoused before the appropriate authorities and on failure of the cause the present Reference, was made. It has also been stated that even at any time during such conciliation, the said Bank never pleaded any justification of their action and in fact, they took the following stand :—

“5. That your Union/Applicants states that at a subsequent stage with effect from 1-11-1977 all the aforesaid workmen (Sl. Nos. 1 to 19 as in Paragraph 4 hereinabove) concerned have been permanently absorbed in the employment of the United Bank of India by way of grant of respective letters of confirmation to their respective appointments with effect from 1-11-1977.

Be it further stated that while granting permanency in the employment of the United Bank of India in respect of the aforesaid workmen, the employer-Bank in an unequivocal language stated that such workmen are being absorbed against permanent vacancies.

Your Union/Applicants craves leave to after to the relevant documents in respect of the claim that the concerned workmen were virtually granted absorption against permanent vacancies with effect from 1-11-1977 as stated hereinabove at the time of hearing.

6. That your Union/Applicants stated state although the aforesaid workmen were appointed on permanent basis on 1-11-1977

consequent to their respective appointments with the Union Bank of India with effect from 1-3-1977, no workman as aforesaid was considered by the Employers/Opposite Party to have been employed with effect from 1-3-1977 and this refusal caused resentment and grief amongst the concerned workmen as also amongst the workmen-class as a whole and, thereupon, the said workmen both individually as also collectively raised disputes in a bipartite level for times without number, but the Employers/Opposite Party refused to pay any heed to the said disputes and, as such, at last your Union/Applicants had to join issue.

Your Union/Applicants craves leave to refer to the correspondences of the Union/Applicants in a bipartite level with the workmen on the one hand and the Employers/Opposite Party on the other hand, at the time of hearing.

7. \* \* \* \* \*

The representation signed by you and others have been carefully examined by the appropriate authorities of the Bank. The terms and conditions of your appointment do not stipulate any provision for shifting back the date of your appointment and consequently the date of annual increment. Your date of appointment in the Bank is reckoned from the date you have been offered permanent appointment in the subordinate establishment of the Bank.

Regarding issue No. 2 of your representation please be informed that there is no scope of paying the full time sweeper any additional remuneration, other than his usual wages. Your idea on the contents of circular letter No. PD/44/83 dated 4-3-83 is mis-conceived and requires correction”.

5. It was the contention of the said Union, because of the illegal action and the erroneous stand taken by the said Bank, the employees concerned have suffered and are still suffering grave loss, in addition to losing benefits attached to the respective posts and the said Union has further claimed that the acts and activities of the said Bank, in not counting the temporary services of the employees concerned, was not only, in violation of the Rules and Procedure, but was also contrary to the Laws of the land, applicable to the employees and was further in violation of principles of natural justice and fundamentals of fair play and was illegal and inoperative and the respective provisions of the Sastri Award, as also paragraphs 20.7 and 20.8 of the Bipartite Settlement dated October 19, 1966, apart from being, in violation of the other provisions, as will be indicated hereinafter.

6. In view of the above, it has been claimed that an Award be made, holding inter alia amongst others that the action of the said Bank, in not counting the uninterrupted temporary services rendered by the employees from March 1, 1977 to October 31, 1977, in their services, prior to their appointments on tempo-

rary basis with effect from November 1, 1977, did neither act fairly nor justifiedly and in fact, such action was illegal and irregular too.

7. The said Bank, in their written statement filed on September 9, 1988, has claimed, the Reference to be misconceived, ultravias the said Act and does not confer any jurisdiction on this Tribunal, to consider the same, as the enumeration of the security guards, cleaners and sweeper, as their numbers have been shown as 10, 4 and 5 respectively; whereas the annexure to the schedule, contained details of 9 Security Guards, 4 Cleaners and 6 Sweepers. This preliminary point, to my mind, has lost all its efficacy, in view of the corrections made to the schedule, vide Corrigendum dated August 28, 1991. It has also been contended that the Reference in question, has been purportedly made in respect of 19 employees of the said Bank, without application of mind and in a mechanical manner, as would be evident from the concerned annexure. But, such stand, in my view because of the Corrigendum as indicated, has also lost all its force. The claim has further been stated to be a stale one. I do not find much substance in such stand, as taken by the said Bank, not only in view of the pleadings and so also the evidence, as adduced and the law on the point.

8. Without prejudice to the stand as indicated hereinafore, but fully relying on them, the said Bank has dealt with and sought to meet the case of the said Union on merits and has claimed, after stating the background of the initial appointments given to employees concerned that after giving such appointments, they received a communication from the Department of Revenue and Banking, requiring to discontinue work on contract basis and to departmentalise the employees on discontinuation of such basis. It has been stated that thereafter, the said Bank, instead of asking the contractors to remove the workers, engage them on ad-hoc basis temporarily for a period of two months at a time, as a good gesture, with effect from March 1, 1977 and such ad-hoc appointments were extended from time to time. It has been stated that as there was no sanction of permanent vacancies, the employees concerned, were appointed on and from November 1, 1977, as permanent confirmed sub-staff, without requiring them to undergo probationary period, specifically mentioning the date of increment after 1 year, i.e., on November 1, 1978 and such position, was accepted by the employees.

9. It has also been stated that at the relevant time, as per Recruitment Rules of the said Bank, a panel of temporary sub-staff was maintained in each Branch/Office and those empanelled sub-staffs, used to work as and when necessary. It has also been indicated that such panel of temporary staff, was prepared through a certain process of selection by the said Bank and such empanelled sub-staffs, were subsequently absorbed in permanent vacancies, on the basis of their seniority, which was to be counted from the date of their initial appointments as temporary sub-staff. In this case, it has been stated that the dates of appointment, were however, considered from the appointment of the employees as probationer sub-staff, as to dates of joining the said Bank, irrespective

of the dates of initial appointment as temporary sub-employee, it was pointed out by the said Bank that paragraph 508 of the Sastri Award (hereinafter referred to as the said Award), has classified the employees of a Bank as (i) Permanent employees (ii) Probationers (iii) temporary employees and (iv) Part-time employees. It has also been stated that paragraph 20.7 of the Bipartite Settlement dated October 19, 1986 (hereinafter referred to as the said Settlement), postulates that in supersession of paragraph 1.28 and Sub-clause (c) of paragraph 23.15 of the said Award, "Temporary employee" will mean a workman, who has been appointed for a limited period for work, which is essentially temporary in nature or will be employed temporarily, as additional workman, in connection with temporary increase in work of a permanent nature and includes, a workman other than permanent workman, who is appointed in a temporary vacancy caused by any absence of any particular workman and paragraph 20.8 of the said Settlement indicates, that a temporary workman, may also be appointed to fill up permanent vacancy, provided that such temporary appointment, shall not exceed a period of 3 months, during which, the Bank shall make arrangement for filling up the vacancy, permanently. If such temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary appointment, will be taken into account, as part of his probationary period.

10. The said Bank has said that paragraph 20.8 of the said Agreement (Ext. M-1), will not be applicable, in case of the concerned workman, as they were not appointed to fill up any permanent vacancy and in fact, there was no permanent vacancy existing at that time and in any event, such or any temporary appointment must not exceed a period of three months, during which the said Bank has to make arrangements for filling up the vacancy permanently and if such temporary workmen are ultimately selected for filling up the vacancy, such period of temporary employment will be taken into account as part of the probationary period. It has further been stated that since there was no vacancy, the question of filling up any vacancy permanently, did not arise and as such, the ad-hoc temporary employment of the employee's concerned could not be taken into account, as a part of Probationary period. It was also the case of the said Bank that the term "work load" has not been defined and as there was no sanctioned post, there also existed no permanent vacancy and the works were being done by Contractors workmen. It was also the case of the said Bank that after abolition of Contract Labour, the said Bank took Contractor's men, initially for 2 months on ad-hoc basis and thereafter, such period was extended from time to time. The said Bank has further stated that for assessing vacancies for necessary sanction, they had to assess the workload involved and cost factor, apart from suitability and the actual requirement, which was not immediately possible and so, as stop gap arrangement, the said Bank, instead of asking the Contractors, to remove their men, engaged them on ad-hoc basis and that too temporarily. It has also been stated that during the period of such ad-hoc appointment or at the time of appointment of the permanent employees, there was no sanctioned vacancy and as such also, the provisions of paragraph 20.8 as above was not attracted and further, those provisions, if at all, could be attracted, in cases where workmen were employed

as Probationers and not otherwise. According to the said Bank, the workmen concerned, were taken into the service of the said Bank, on November 1, 1977, as permanent confirmed employees, without requiring them to undergo any period of Probation, specifically mentioning of the next increment in their respective appointment letters and the said paragraph 20.8 as stated above, was not also attracted in the case of the workmen concerned. It was the further case of the said Bank that the workmen concerned, have entered into the contracts with them, in terms of the letter of appointments Ext. M-2 series, which they accepted unequivocally and thus, were bound by those terms and could not claim the appointments, to relate back to some other date and such claim, was not legal and should be deemed to be unjustified. In any event, it has been stated that the workmen concerned, were and are bound by the terms as accepted and as such, they could not claim or contend otherwise.

11. While dealing with the case as sought to be made out by the said Union in their Written Statement, apart from repeating and reiterating the facts, as indicated above, the said Bank has also disputed that the appointments of the employees concerned here, were merely on temporarily basis and has reiterated that they were employed on ad-hoc measure and on temporary basis. It was the specific case of the said Bank that the letter of appointment Ext. M-2 series, contained the terms of service and conditions of employment, beyond which, the employees concerned, could not authorisably travel. In any event, it has been denied and disputed that they were appointed with the said Bank from March 1, 1977. It was also claimed that the disputes, as raised and as referred to, were unjustified and not maintainable, both in law and in fact and on the basis of the clear provisions of the said settlement and when there was no permanent vacancy, the employees concerned, could not be deemed to be appointed on temporary basis against permanent vacancies and as such, the cases were not covered by paragraphs 20.7 and 20.8 of the said Settlement. It was claimed further that the employees concerned, were not appointed on probationary basis and in fact, as stated earlier, they were confirmed sub-staffs, without any probationary period. It has further been contended that the concerned workmen, wanted to have extra contractual and extra legal benefits, to which the said Bank could not agree and the dispute here, was not a valid one, in view of the clear and unambiguous terms of the letters of appointments and any claim contrary to those terms, should be deemed to be an afterthought.

12. The said Bank has contended that the acts or actions in this case, as taken by them, were not illegal or unjustified as claimed by the said Union or such actions were violative of the Rules and Procedure or law, as applicable and the said Bank has not violated any of the provisions of Sastri Award or Paragraphs 20.7 or 20.8 of the said Settlement. In view of the above, the claims or demands as made by the said Union, have been categorically denied and disputed by the said Bank.

13. WW-1, Himangshu Kar was employed as Watch and Ward Staff of the said Bank and claimed to be knowing the facts of this case. He could not say, if exbt. W-6 was addressed to the Labour

Commissioner and he agreed that he signs in Bengali. He has of course said that Exbt. W-7, was addressed to the Chairman-cum-Managing Director by the employees and his signature was not there in that Exhibit. He has further agreed that he was appointed as Watch and Ward Staff of the said Bank on March 1, 1977 and he indicated that he was deposing for and on behalf of all the staff and that too, on being authorised by them, orally. He has also claim himself to be a Committee member of the said Union i.e. Sramik Karmachari Samity and was looking after all the cases, on their behalf. It was his evidence that he made an application to the said Bank, for his job. But, it was not possible for him to show the said application and he claimed that the other employees will also not be able to show this applications, since all of them including himself, were appointed first, under the Contractors and according to his recollection, such appointments were not made on the basis of any advertisement and the names of the employees concerned, were also not sponsored by the Employment Exchange. He did not and said, would not be able to produce his appointment letter, if asked. On being shown the appointment letter Exbt. M-2(18), he stated that the employees have accepted the workings or the terms in the appointment letters and was not sure, if the said Bank had acted duly, in terms of the appointment letters. MW-1 Tapan Kumar Roy, Deputy Manager of the said Bank, deposed on behalf of the Management and stated that in April 1977, he joined the N. S. Road Branch of the said Bank, as an Officer of the Personnel Department and his initial appointment was at the Head Office and he had no idea, when the said Building was constructed. He said that he was aware of the terms of the said Settlement and Exbt. M-1, will show the relevant provisions thereof and according to him, Exbt. M-2 series, were the appointment letters, issued by the said Bank and according to his recollections, the employees concerned were Contractors' employees and were employed for maintainance of security and also for sweepings of the said Building. He also stated that there was a directive from the Central Government, under the said 1970 Act, that workmen employed in perennial nature of job, be departmentalised, and on the basis of such directives, the employees were departmentalised. According to him, no permanent posts were available the time of such directives and Exbt. M-2 series, will show that the appointments were, for Head Office only and Exbt. M-3 series will also show, the appointments were also made on permanent cadre on the said Bank and the employees accepted the terms and conditions as contained in those two Exhibits. It was also his evidence that while offering employments to the employees concerned, the policies available at the relevant time, were not followed and the employees concerned, were not sub-staffs and were not empanelled before they were appointed. He agreed that Exbt. W-1 was the directive, about which he has spoken. He also testified and said that perhaps all the 19 employees as mentioned in the Order of Reference, have been absorbed in permanent vacancies and they were so made permanent, on and from November 1, 1977. According to him, the employees concerned were initially Contractors' labour and on the basis of the Central Government Notification and since they were engaged in perennial nature of work, they were

absorbed ultimately. According to him, it will appear from Exbt. M-2 series that the employees concerned, were offered appointments from March 1, 1977, by the said Bank and that Exbt. M-2 series, will not of course show that they were employed through Contractors.

14. According to Sri Majumdar, all the employees here, were initially employed as Contractors' labours, for the purposes of the said Building, as indicated earlier and they were departmentalised on December 27, 1976, in terms of Exbt. W-1 and such fresh employment was effective from November 1, 1977, when only, they were employed on permanent basis. He indicated that it will also appear from Exbt. M-2 series that the employees concerned, were appointed engaged temporarily, which position, they also accepted or on which, they have acted.

15. It was the further contention of Sri Majumdar that the employees concerned, have claimed continuity of service and permanency. But, while considering such claim, the admitted delay as occurred in this case, the Tribunal should consider, as that claim, if allowed, will disturb the seniority position of others, which should not be done or at least, sought to be avoided. It was Sri Majumdar's submission that right, if any, of the employees concerned, emanated from Exbt. M-2 series and specifically, not under paragraph 20.7 of the said Settlement, as admittedly, the three conditions as indicated therein, have not been fulfilled in these cases and which according to him, have only application, here. He further pointed out that the case of the employees concerned, were not sponsored by the Employment Exchange. In reply, to the submission of Sri Roy Chowdhury to which reference would be made hereafter, Sri Majumdar contended that paragraph 20.8 of the said Agreement, should be read along-with 20.7 and not in isolation as indicated earlier. In any event, he submitted that paragraph 20.8, was inapplicable in this case. In reply to the further submissions on behalf of the said Union, he indicated that Exbt. M-2 series, will unequivocally establish that the appointments/engagements of the employees concerned, were not against permanent posts and the employees concerned, in the facts of the case, would be governed by the terms of the said Exbt. M-2 series.

16. Sri Roy Chowdhury contended that if the terms of Reference, are duly construed and considered alongwith paragraphs 20.7 and 20.8, the terms whereof are quoted hereunder —

"20.7. In supersession of paragraph 21.20 and sub-clause (c) of paragraph 23.15 of the Desai Award. "Temporary Employee" will mean a workman who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman.

20.8. A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary employment will be taken into account as part

there would be no other alternative, but to hold that the employees concerned, because of the terms of Exbt. M-3 series, were entitled to be absorbed in permanent services from their initial dates of appointments i.e. March 1, 1977 and services rendered by them, from that date upto the date prior to their permanency, were entitled to get the continuity in permanent services and any construction or holding other than the above, would be unreasonable, the more so when, they were appointed against permanent posts or such works, which were and are of perennial nature or they were appointed against vacancies in permanent cadre. It was suggested that on the basis of the evidence as available or the Exhibits, as on record, there was no power of the said Bank, to consider the employees concerned as appointed, to be on probationary basis. Shri Roy Chowdhury, in alternative to his submissions of paragraphs 20.7 and 20.8 as quoted, also contended that Exbt. M-3 should prevail.

17. On the basis of paragraphs 5.117 and 5.118 of Desai Award, which deal with increments, Sri Roy Chowdhury contended that the employees concerned, were not only entitled to two increments, but from the fact that they were paid such increments, it would be evident that they were employed permanently and continuously from the dates of their initial appointments, as Exbt. M-3 shows that they were initially appointed against sanctioned vacancies and that Exhibit would further establish without any doubt that the employees concerned, were appointed as Watch and Ward Staff in a permanent cadre, on the sub-staff cadre of the said Bank, with effect from November 1, 1977 and that document will further establish that the increments in the scale of pay, will fall due on November every year, commencing from November 1, 1978. There cannot be any two opinion regarding the employment of the employees concerned from November 1, 1977 in the permanent cadre on the subordinate grade of the said Bank.

18. It must further be noted that under Clause 14.1 of the Desai Award, the said Bank is required to maintain a seniority list, category-wise and in the manner as indicated therein, subject to the amendment as indicated in paragraph 14.2 of that Award, which again, has noted that the demand of All Indian Bank of India Staff Federation in that respect, required to be considered, as the revised demand. There is also no doubt that the said Bank will have to maintain a category-wise seniority list in terms of the provisions as above.

19. Paragraph 20.7 of the said Settlement as in Exbt. M-1, which is under the heading "Temporary Employment", has got the various limits as indicated by Sri Majumdar viz (i) Workman who has been



appointed for a limited period for work; (2) which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and (3) that includes a workman, other than a permanent workman, who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman. The specified jobs, for which the employees concerned were appointed here by Ext. M-2 series, can be said to be of perennial in nature, as such jobs were there and will be there, so long the said Bank will function and operate. Therefore, they cannot be considered to be "Temporary Employees" in terms of paragraph 20.7 of the said Agreement. If that is so, then the employees concerned, can only and if at all, claim to have the benefits of paragraph 20.8 of the said Agreement. Thus, they will really be governed by the terms of Exbt. M-3 series read with the said paragraph 20.8 and when the said Bank has ultimately selected them for filling up the vacancies permanently, the period of their temporary employment will have to be taken into account, even though they were not specially employed as Probationers. They were really and for all practical purposes appointed as "Temporary Employees" as indicated in paragraph 20.8 and not as Probationers.

20. On the basis of the pleadings and records, as produced and more particularly paragraphs 20.7 and 20.8 of Exbt. M-1 and even if, those two provisions are read not in isolation, but in conjunction, it cannot thus be denied that the employees concerned had gained a right to the postings, on permanent basis, from the date of their initial appointments, and so the seniority list, in terms of the provisions as above, be maintained by the said Bank.

21. As such, I think this Reference should be answered in the affirmative and in favour of the employees concerned and that too when, the works of these employees were and are perennial in nature and that too, when considering such fact, by Exbt. M-3, the employees concerned have also been granted employment against permanent vacancies.

22. The Reference is thus answered in the affirmative and in the manner as indicated.

23. This is my Award.

Dated, Calcutta.

The 13th September, 1993.

MANASH NATH ROY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 1993

का.प्रा. 2875.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एयर इंडिया के प्रबंधन के सदस्य नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लेबर कोर्ट नं. 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11011/6/91-आई. आर. (विविध)]

बी.एम. डैविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2875.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-

Labour Court No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air-India and their workmen, which was received by the Central Government on 25-11-93.

[No. L-11011/6/91-IR(Misc.)]

B. M. DAID, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY.

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-13 OF 1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of Air-India

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management :—Shri M.P. Bharucha  
:—Advocate.

For the Workmen :—Mrs. Nilima Dutta,  
:—Advocate.

INDUSTRY : Airlines

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 17th day of November, 1993

#### AWARD

The following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by letter dated 26-2-1992.

"Whether the action of the management of Air India over the alleged denial of promotion to Mr. L. P. Gangurde, Staff No. 2580, Air Craft Technician to the post of Senior Air Craft Technician with effect from 1-8-1987 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. Statement of claim was filed on behalf of the workman by the Secretary, Air Corporation Employees' Union, and it was stated therein that Shri Gangurde joined the services of the Corporation on 21-7-1982 as an Air Craft Technician, and that as per prevailing practice in the Corporation and in view of the settlements between the union and the management, he was due for promotion to the higher post of Senior Aircraft Technician on completion of five years as Aircraft Technician. The promotion was due with effect from 1-8-1987. However, he was in fact promoted with effect from 1-8-1988, that is, exactly a year later.

3. No reply has been filed on behalf of the management to the statement of claim. However a copy of the order dated 8-10-1993 giving promotion to the workman Shri Gangurde with effect from 1-8-1987 as Senior Aircraft Technician has been produced on record. It has been stated therein that order that Shri Gangurde has been promoted to the post of Senior Aircraft Technician with effect from 1-8-1987 instead of 1-8-1988, and deemed to have been confirmed with effect from 1-2-1988. It is clear therefrom that the grievance made by the workman has



been redressed and, therefore, the dispute does not survive. Under the circumstances the reference is disposed off and award is accordingly made.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 1993

क्र.आ. 2876.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार धम्बई पोर्ट ट्रस्ट, धम्बई के प्रबंधकों के संघ के नियोजकों और उनके कामगारों के बीच, अन्वय में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण केवर कोर्ट नं. 1, धम्बई के पंचवट को प्रेषित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 30-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-31011/15/90 आई. आर. (विवाद)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st December, 1993

S.O. 2876.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on 30-11-93.

[No. L-31011/15/90-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY.

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.  
REFERENCE NO. CGIT-39 OF 1991.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust, Bombay

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management : Shri B. B. Anchan, Advocate

For the Workmen : Shri Talreja, Advocate

INDUSTRY : Port & Docks

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 8th day of November, 1993

AWARD

By order dated 4th April, 1991 the Government of India, Ministry of Labour has made the following reference to this Tribunal :

"Whether the management of Bombay Port Trust—Bombay, were justified in (a) dismissal of Shri S. M. Muday-Watchman No. 33 and (b) retiring compulsorily Shri C. G. Waghmare Watchman No. 56 from services with effect from 19-3-1988 ? If not, to what relief are those workmen entitled to ?"

2. The statements of claim have been filed by both the watchmen.

3. The facts in brief leading to the present Industrial Dispute would be briefly stated as follows :—

4. Shri Mudday and Shri Waghmare were appointed Watchmen in the security organisation of the Bombay Port Trust, on different dates, Mr. Muddey was appointed on 1-9-1978 while Mr. Waghmare was appointed on 11-11-1980. A Shed Superintendent in Chembur Yard, lodged a complaint with the Trombay Police on 19-4-1984 alleging theft of cassettes from the contained cell of Bombay Port Trust, Chembur Yard. A criminal case was registered at CR No. 172/83 under 379/114 of the Indian Penal Code. Both the Watchmen, namely Shri Mudday and Waghmare came to be arrested in connection with the theft on 18-7-1984 by the Crime Branch C.I.D. They were released on bail on 18-7-1984 by the Crime Branch C.I.D. They were released on bail on 6-8-1989.

5. They did not comply with the provisions of Regulation 3(8) of the Bombay Port Trust Employees' (Conduct) Regulations 1976, inasmuch as, they did not inform their superiors promptly in writing about the fact of their arrest. They were suspended for the charge of theft but they came to be acquitted by the Additional Chief Metropolitan Magistrate, 37th Court, Esplanade, Bombay on 6th December 1985.

6. The Administrative Officer, after coming to know about the acquittal directed the workmen by memo dated 12-1-1986 to report to the office for resuming duty. The suspension order was revoked and they were allowed to resume duties with immediate effect. The workmen thereafter reported for duty, and were allowed to resume with effect from 15-1-1986...

7. However, on 12-3-1987, the deputy Chairman forwarded a copy of the articles of charges and the statement of imputation of mis-conduct, witnesses and documents and called upon the workman to submit written statements in his defence. The Deputy Chairman informed the workman that it was proposed to hold a departmental enquiry against the workmen.

8. After the departmental enquiry, the management ordered dismissal of Shri Mudday and compulsory retirement of Shri Waghmare.

9. Both of them contended that the action of the management of Bombay Port Trust is not proper legal and valid. They also contended that the penalty is disproportionate to the gravity of the lapse on their part.

10. The contention on behalf of the management is that, the watchmen were bound to inform in writing the fact of their arrest and detention under police custody in accordance with the provisions of the BPT Employees' (Conduct) Regulations 1976, and inasmuch as they did not do so admittedly, they were rightly held guilty by the disciplinary authority. It was further contended that the enquiry conducted was in accordance with the rules and principles of natural justice.

11. The parties produced relevant documents and both the watchmen filed affidavits in support of their

contentions and they were cross-examined on behalf of the management.

12. There is no dispute on the point that these two Watchmen were arrested in connection with a criminal case registered under C.R. 17 of the 1984, under section 379 & 114 of the Indian Penal Code, on 18-7-1984. It is also not disputed that they were released on bail on 6-8-1984. It is also not in dispute that they did not report in writing this fact of their arrest. The case of the watchman is that they did not know about the regulation that made it obligatory upon them to report in writing about their arrest and detention under police custody to the management. The management has produced the papers of enquiry at Exhibit M-1. Regulation 3(8) of the BPT Employees' (Conduct) Regulations 1976 has been quoted in the statement of imputation and it reads thus :

"An employee who is convicted by a Court of Law or arrested, shall promptly report in writing the fact of such conviction or arrest to his departmental superiors."

Therefore, it is evident that the workman have contravened the provision of regulation 3(8) of the BPT Employees' (Conduct) Regulations 1976. According to the workmen, the fact of their arrest and detention by the Police was known to the management. Their contention is that, after they were released on bail, they went to the office to report to duty on 8-8-1984 and met Mr. Raje the then Administrative Officer and Mr. Pawaskar the then Zonal Manager, and during the course of the discussion, the fact about their arrest and detention under police custody was informed to them, and already known to them. They also contended that the Senior Police Inspector Detection, Crime Branch, CID, Bombay vide his letter dated 31-7-1984 had also informed the management about the arrest of these two watchman on 18-7-1984 and later by letter dated 20-8-1984. In fact they were released on bail on 6-8-1984. Copies of these two letters are at Exhibit W-2 and W-3. The workmen's contention therefore, is that, the management was aware of the fact that these two watchmen were arrested and detained by the police before they went to report immediately after their release on bail. Mr. Raje and Mr. Pawaskar also did not advise them to inform the management in writing about their arrest. The contention in short, in this behalf is that the lapse on their part is not of a serious nature, and it is purely of a technical nature. They also contended that neither Mr. Raje nor Mr. Pawaskar were examined during the course of the enquiry. In fact in this proceeding, before me, Shri Mudday has stated in his affidavit that he had gone to the office and met Mr. Raje and Mr. Pawaskar, during the discussion he informed them about the arrest. He further states that the officer told him that it is for this reason that he could not be taken on work.

13. The case against Shri Waghmare was as can be seen from the document at Exhibit M-2, that he has committed misconduct of wilful violation of the provisions of the BPT Employees' (Conduct) Regulations, 1976. In view of the facts and circumstances of the case stated above, it is difficult to hold that the violation or breach of the regulation of the BPT Employees' conduct Regulation was wilful. He has as

can be seen from the records stated that they went to resume duties and met Shri Raje the then Administrative Officer and Mr. Pawaskar, the then Zonal Manager and informed them about the arrest and subsequent release on bail. Neither Mr. Raje, nor Mr. Pawaskar was examined either before the Enquiry Officer, or in this proceeding before me. In the circumstances, it is difficult to say that it was a wilful violation or breach of Regulation 3(8) of the BPT Employees' (Conduct) Regulations, 1976 of which Shri Waghmare was charged.

14. The workman has been charged also for dishonesty in connection with Port Trust work under section 22(2)(b) of the Bombay Port Trust Rules and Regulations for the Non-Scheduled Staff, and thereafter for violation of regulation 3(1) of the Bombay Port Trust Employees' Conduct Regulation (BPTECR) 1976. This amounts to misconduct under BPT Employees' Conduct Regulations 1976. Now, so far as dishonesty in connection with BPT work is concerned, I do not find any material to show on which basis charge under Rule 3(1) of the BPT Employees' Regulation 1970 was framed. It has been already noted that the charge of theft which failed in the Criminal Court was not levelled against the workman under this regulation. I fail to see how failure to inform in writing his superiors about his arrest can lead to dishonesty in connection with Port Trust work. Besides about clause (b) of Section 22, subsection (2) it has been stated and the statement of imputation reads thus :

"Shri G. G. Waghmare did not report the fact of his aforesaid arrest by the police to the Chief Security Officer or to any of his departmental superiors as required under regulation 3(8) of the BPT Employees' (Conduct) Regulations, 1976."

Dishonesty in connection with Port Trust work and property has to be read 'Ejusdem Generis' I fail to see how this clause is attracted. It is also alleged that he violated the regulation 3.1 of the BPT Employees' Conduct Regulations and it reads thus :

"Every employee shall, at all times, maintain absolute integrity and devotion to duty."

Once again I fail to see how this can be a different charge. Violation of Regulation 3(8) is the only charge that could have been framed against the delinquent workman for failure to inform his superiors about his arrest and detention in police custody in writing. It can at the most amount to violation of rules and regulations covered by 31 A xii and the other two charges levelled against him to which I have made a reference above are not correct. If one reads the report of the Enquiry Officer, it can be seen that after holding that reporting in writing was not promptly made, observed :

"This clearly shows that they have committed the misconduct of wilful violation of Regulation 3(8) of the BPTE (Conduct) Regulations, 1976, and dishonesty in connection with Port Trust work under Rule 22(2)(b) of the BPT Rules and Regulations for Non-Scheduled Staff thereby violating Regulation 3(1) of the BPTE (Conduct) Regulations, 1976."

Therefore, it is clear that the only charge that could have been levelled against the delinquent Shri Waghmare is violation of Regulation 3(8) of the BJTE (Conduct) Regulations 1976, for failure to report the fact of his arrest promptly in writing to his superiors. However, it does not call for the penalty of compulsory retirement in the case of Shri Waghmare. BPT Employees' (Classification, Control, and Appeal) Regulations, 1976 deals with the misconducts and the penalties. However, it does not say what penalty has to be imposed for what kind of misconduct. Considering these factors I find that the penalty imposed on the delinquent Shri Waghmare is rather harsh and disproportionate. Section 11-A of the Industrial Disputes Act, 1947 enables this tribunal to set aside the order of dismissal if not satisfied with the justifications given and direct reinstatement of the delinquent. Considering all these, I find that the order of compulsory retirement deserves to be set aside which I do and direct reinstatement of the workman Shri Waghmare, by withholding two increments with cumulative effect.

15. The case of the other workman Shri Muddey is the same except for the charge that he had submitted a false Medical Certificate issued by Dr. P. R. Agarwal dated 8-8-1984 stating that Shri Muddey was under the treatment of Dr. Agarwal from 18-7-1984 to 7-8-1984, and that he was required to take complete rest. He further stated that he is now fit to resume duties with effect from 8-8-1984. This was produced by Shri Muddey and to that effect Smt. Chonkar gave evidence before the Enquiry Officer. He was in fact under the Police Custody during this period, and that fact was established by the letter of the Sub-Inspector of Police, dated 31-7-1984. It stated that the two workmen Shri Waghmare and Muddey were arrested on 18-7-1984 in connection with Trombay Police Station C.R. No. 172-84 under section 379-114 of the Indian Penal Code. And the further letter the Sr. Inspector of Police dated 20-8-1984 showed that they were released on 6-8-1984. Therefore, it is clear that he was under the Police Custody during the period. In the statement before the Enquiry Officer, Shri Muddey stated that his health had got deteriorated since he was in the jail and therefore, he went to Dr. Agarwal who did not ask him where he was during this period and he did not tell him that he was in jail. He also stated before the Enquiry Officer that he had orally informed Shri Raju, the then Administrative Officer about his arrest and detention under Police Custody. Therefore, it is clear that he was in jail when he produced the medical certificate. Therefore, it is also clear that the certificate issued by Dr. Agarwal is also a false one. This is a misconduct which is to be taken into account while finding out whether non reporting about the arrest amounted to breach of Regulation 3(8) of the BPTE C.R. 1976. In my opinion, that the charge has been rightly held proved against him by the Enquiry Officer and he reported accordingly.

16. It is to be noted that in the statement dated 31-3-1987 he stated that he was under the treatment of Dr. Agarwal from 14-7-1984. In fact this is not what Dr. Agarwal says. He says that Mr. Muddey was under his treatment from 18-7-1984.

17. The other charges against him are in respect of dishonesty in connection with Port Trust work under Rule 22(2)(b) and BPTE (Conduct Rules for the Non-scheduled Staff, and violation of clause 3(8) of the BPTECR. I find that the charge of violation of Regulation 3(1) is also substantiated by this act of Shri Muddey. In the circumstances, the action of the management in imposing the punishment of dismissal from service is justified, and he is not entitled to any relief.

Award is accordingly made with no order as to costs.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1993

का. आ. 2877.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पोर्ट लेबर सर्वीस के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित और उनके कार्यवाहों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लेबर कोर्ट नं. 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-11-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-31011/19/91-आईआर. (विविध)  
वी. एम. डेवीड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th December, 1993

S.O. 2877.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Port Labour Services and their workmen, which was received by the Central Government on 25-11-93.

[No. L-31011/19/91-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer  
ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY.

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar,  
Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-38 OF 1992

PRATIES :

Employers in relation to the management of  
Port Labour Services.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management : Shri Dalvi, Representative.  
For the Workmen : No appearance.

INDUSTRY : Port & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 17th day of November, 1993

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi to this

Tribunal for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide letter dated 20/26-5-1992. The schedule of the reference is to the following effect.

"Whether the action of the management of M/s. Geo-Chem. Lab. Pvt. Ltd. and M/s. Port Labour Services Bombay in arbitrary termination of S/Shri Anant R. Patade and 7 other Survey Clerks from various dates (as per annexure 1-B) without complying the provision of section 25F of the I.D. Act 1947 is just, legal and proper? If not, to what relief are these workmen entitled to?"

AND

"Whether the action of the management of M/s. Geo-Chem. Lab. Pvt. Ltd. and M/s. Port Labour Services Bombay in terminating the services of S/Shri Anant R. Patade & other 7 workmen without compliance of the "provisions of I.D. Act 1947 amounted to "un-fair labour practice" as per the provisions of Industrial Disputes Act, 1947? If so, to what relief are these workmen entitled to?"

2. The union was served with the notice of this reference and there was no appearance on behalf of the union on 6-7-1992. On 30-7-1992, the management filed its written statement, though no statement or claim has been filed on behalf of the union. The matter came up for hearing on 28-8-1992, 2-11-1992, 24-12-92, 15-2-1993, 19-4-1993. Even then, no statement of claim was filed, nor was there any reply to the written statement filed on behalf of the management. On 13-7-1993, notice was directed to be issued to the parties because, till that date, the post of the Presiding Officer was vacant. This notice also has been served on the union and yet there is no appearance on behalf of the union on the following two occasions, that is, 2-9-1993 and 28-10-1993. It is therefore, not possible to proceed with the reference and adjudicate the dispute in the absence of any statement of claim. It is evident therefore, that the union is not interested in pursuing the reference and getting the same adjudicated. The reason appears to be that there has been a settlement between the workmen and the management, and it has been stated in the written statement filed on behalf of the management on 13-7-1992 that 5 out of the 8 workmen have settled their dispute with the management, and the names of the workmen are at serial numbers 1, 3, 5, 6 and 8 of the annexure to the schedule. Therefore, in the absence of any statement of claim, I hold that the workmen have no dispute which requires to be adjudicated.

3. The reference is disposed off with award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 1993

का.आ. 2878.—केन्द्रीय सरकार ने यह समझान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2

के खंड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1314 दिनांक 25 मई, 1993 द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 8 जून, 1993 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अद्य, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 8 दिसंबर, 1993 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/12/85 डी-1(ए)]

एस.एस. पाराशर, अवसरसचिव

New Delhi, the 6th December, 1993

S.O. 2878.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1314 dated 25th May, 1993 the iron ore mining industry to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 8th June, 1993;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 8th December, 1993.

[No. S-11017/12/85-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2879.—लौह-अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण विधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 2 के खंड (छ) के उप खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26-10-91 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्या 2734 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ श्रम कर्म संबंधी कारखानों के रूप में घोषित करती है।

## अनुसूची

1. मैसर्स मद्रास सीमेंट लि., रामामाध्रज नगर-626204  
जि. कामराजार (तमिलनाडु)
2. मैसर्स टी ए एन इंडिया लि., पो. बा. सख्या-191, संख्या-21, गांधीपुरम मेन रोड, कुमारापालयम-638183  
(तमिलनाडु)।
3. मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लि., स्मेल्टर, विशाखापट्टनम  
(आंध्र प्रदेश)।
4. मैसर्स आन्ध्र स्टील कार्पोरेशन लि., मत्कापुरम, विशाखा-  
पट्टनम (आंध्र प्रदेश)।
5. मैसर्स ए. के. कार्पोरेशन लि., मत्कापुरम, विशाखापट्टनम  
(आंध्र प्रदेश)।
6. मैसर्स नागाजुन सीमेंट लि., माटमपल्ली, हजूरनगर,  
जिला-नासर्गोडा।
7. मैसर्स ए. पी. रिफ्रेक्टरीज लि., अनामपुडी, सब्बावरम,  
विशाखापट्टनम।
8. मैसर्स भारतीय सीमेंट निगम लि., आदिलाबाद (आंध्र  
प्रदेश)।
9. मैसर्स डक्कन सीमेंट लि., भवानीपुरम, जिला नालगोंडा  
(आंध्र प्रदेश)।
10. मैसर्स काकतिया सीमेंट लि., मीनारामपुरम, जगम्यापेट,  
जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश)।
11. मैसर्स बी बी सी फेरोस आलायज लि., रुद्रमगांव, सांगरेड्डी,  
जिला मेडक।
12. एसोसिएटेड साईट कार्पोरेशन लि., मृडक्करे सीमेंट  
वर्क्स, मृडक्करे, जिला कोयम्बटूर।
13. भारतीय सीमेंट निगम लि., येररागुंटल सीमेंट फैक्ट्री,  
येररागुंटल-बाकवर-516309, जिला कुड्डाया (आंध्र प्रदेश)।
14. मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स लि.,  
औद्योगिक क्षेत्र, पाटनचेरु-502320,  
जिला-मेडक।
15. इंडियन सीमेंट लि.,  
मांकरी, मलेम-637303 (तमिलनाडु)।
16. मैसर्स तमिलनाडु सीमेंट्स एंड केमिकल्स लि.,  
25, सिपकोट, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स,  
रानीपेट।
17. मैसर्स आंध्र सीमेंट कंपनी लि.,  
दुर्गा सीमेंट वर्क्स, आकवर-दुर्गापुरम,  
ठाचेपल्ली, जिला-गुंटूर (आंध्र प्रदेश)।
18. मैसर्स श्री विष्णु सीमेंट लि.,  
सीतारामपुरम, कोडाड (टीकू), बाकवर-होडापाड,  
508245, जिला-नालगोंडा।
19. मैसर्स कोणार्क क्रोम केमिकल्स,  
कालुंगा औद्योगिक क्षेत्र,  
जिला-सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)।
20. मैसर्स इस्पात अलॉयज लि.,  
बालासोर, उड़ीसा।
21. मैसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लि.,  
चौहदार, कटक।
22. मैसर्स कोणार्क क्रोम केमिकल्स।  
राऊरकेला, सुन्दरगढ़।
23. मै. इंडियन सीमेंट लि., पंडारीपलाई, गोधन रोड,  
जिला जगदालपुर-बस्तर (म.प्र.)।
24. मै. हीरा इंडस्ट्रीज लि., पांडेबोपोनी, गोधन रोड,  
जिला जगदालपुर, बस्तर (म.प्र.)।
25. मै. डायमंड सीमेंट्स, पो. आ. नरसिंहगढ़,  
जिला बिलासपुर (म.प्र.)।
26. मै. सतना सीमेंट वर्क्स, स्टील फाउंडरी,  
पो. आ. बिरला विकास कालोनी, सतना (म.प्र.)।
27. मै. भिलाई रिफ्रेक्टर्स प्लांट, नरादुआ,  
पो. आ. मोवल, जिला-दुर्ग (म.प्र.)।
28. मै. रेमण्ड सीमेंट वर्क्स गोपालनगर,  
जिला-बिलासपुर (म.प्र.)।
29. मै. मोदी सीमेंट लि., बालोदा बाजार, रायपुर (म.प्र.)।
30. मै. सैचुरी सीमेंट, पो. आ. बैकुंठ, जिला-रायपुर (म.प्र.)।
31. मै. मेहर सीमेंट, पो. आ. सरला नगर, मेहर,  
जिला-सतना (म.प्र.)।
32. मै. जे. पी. रेखा सीमेंट, पो. ओ. जयप्रकाश नगर, जिला  
रीवा।
33. मै. श्रीनिवास फेरो एलॉयज प्रा. लि., प्लॉट नं. 278-  
279, सैक्टर, सी, उरला इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर।
34. मै. अन्नपूर्णा इंजीनियरिंग लि., प्लॉट नं. 216, सैक्टर-सी,  
उरला इंडस्ट्रीज एरिया, रायपुर (म.प्र.)।
35. मै. श्री गिरजा स्मॉलर्ट्स, प्रा. लि.,  
2, प्रताप सदन, राठौर चौक, रायपुर (म.प्र.)।
36. मै. दीपक पैटो एलायज लि.,  
2 प्रताप सदन, राठौर चौक, रायपुर (म.प्र.)।
37. मै. रंघुबीर फेरो एलॉयज प्रा. लि.,  
प्लॉट नं. 130-135, 'सी' ब्लॉक, उरला इंडस्ट्रियल  
कॉम्प्लेक्स, रायपुर (म.प्र.)।
38. मै. नवोक्रोम (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 114-122, सैक्टर-सी,  
उरला इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर (म.प्र.)।
39. मै. बालाघाट सीमेंट (प्रा.) लि., रोड, बालाघाट (म.प्र.)

40. मै. धर सीमेंट, जिला  
जिला-धर (म.प्र.) ।
41. मै. सी.सी.आई. नयागांव सीमेंट फैक्टरी,  
जिला मंडसौर (म.प्र.) ।
42. मै. विक्रम सीमेंट, पो. आ. खोरे, नयागांव,  
जिला मंडसौर (म.प्र.) ।
43. श्री सरोदा फेरी एलायज, रवि बलासा, टकाली मंडल  
श्रीकाकुलम-532212 (आ.प्र.) ।
44. मै. सागर सीमेंट्स लि.,  
मत्थमपल्ली,  
मत्थमपल्ली मंडल, नलगोंडा, जिला-508225 (आ.प्र.) ।
45. मै. टैक्स मैको लि., सीमेंट डिबिजन, मेरागुंटल  
516309, कुडुप्पा जिला (आ.प्र.) ।

[फा. सं. एस. 23025/1/89-कII]

आर. के. नरुला, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 1993

S.O. 2879.—In exercise of powers conferred by Sub-Clause (ii) of Clause (g) of section 2 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) and in continuation of this Ministry's notification No. S.O. 2734 published in part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 26-10-1991, the Central Government hereby declares the factories specified in the schedule below to be metallurgical factories for the purpose of the said Act.

#### SCHEDULE

- (1) M/s. Madras Cement Ltd.,  
Ramassamraja Nagar-626204,  
Mamarajar Dt. (TN).
- (2) M/s. TAN INDIA LTD.,  
Post Box No. 191,  
No. 21, Gandhipuram Main Road,  
Komarapalayam-638183 (TN).
- (3) M/s. HINDUSTAN ZINC LTD.,  
Zinc Smelter,  
Visakhapatnam (AP).
- (4) M/s. ANDHRA STEEL CORPORATION  
LTD.,  
Malkapuram, Vishakhapatnam (AP).
- (5) M/s. A. K. CORPORATION LTD.,  
Malkapuram, Vishakhapatnam (AP).
- (6) M/s. NAGARJUNA CEMENTS LTD.,  
Mattampally, Huzurnagar (TQ),  
Nalgonda Dt.
- (7) M/s. A. P. REFRACTORIES LTD.,  
Anampudi, Sabhavaram,  
Vishakhapatnam (AP).
- (8) M/s. CEMENT CORPORATION OF  
INDIA LTD.,  
Adilabad (AP).
- (9) M/s. DECCAN CEMENTS LTD.,  
Bhavanipuram, Nalgonda Dt. (AP).
- (10) M/s. KAKATHIYA CEMENTS LTD.,  
Sitarampuram, Jaggayyapet,  
Krishna Dt. (AP).
- (11) M/s. V. B. C. FERRO ALLOYS LTD.,  
Rudram Village, Sangareddy,  
Medak Dt.
- (12) THE ASSOCIATED CEMENT COs. Ltd.,  
Mudukkaraj Cement Works,  
Madukkari, Coimbatore Distt.
- (13) M/s. CEMENT CORPORATION OF  
INDIA LTD.,  
Yerranguntle Cement Factory,  
Yerranguntla-P.O.-516309,  
Cuddapah Disitt. (AP).
- (14) M/s. PRATAP STEEL ROLLING MILLS  
LTD.,  
Industrial Area, Patencheru-502320,  
Medak Distt.
- (15) THE INDIA CEMENTS LTD.,  
Sankari, Salem-637303 (TN).
- (16) M/s. TAMILNADU CHROMATES AND  
CHEMICALS LTD.,  
25, Sipcot, Industrial Complex, Ranipet.
- (17) M/s. ANDHRA CEMENT CO. LTD.,  
Durga Cement Works, Durgapuram P.O.  
Dachepally, Guntur Dt. (AP).
- (18) M/s. SRI VISHNU CEMENTS LTD.,  
Sitapuram, Kodad (TQ),  
DONDAPADU P.O.-508245,  
Nalgonda Dt.
- (19) M/s. KONARK CHROME CHEMICALS,  
At Kalunga Industrial Estate,  
Distt. Sundergarh (Orissa).
- (20) M/s. ISPAT ALLOYS LTD.,  
Balasore, ORISSA.
- (21) M/s. INDIAN CHARGE CHROME LTD.,  
Choudwar, CUTTAK.
- (22) M/s. KONARK CHROME CHEMICALS,  
Rourkela, SUNDERGARH.
- (23) M/s. RUDRA CEMENT LTD.,  
Pandariplai, Goodhan Rd.  
Jagdalpur Distt. BASTAR (MP)
- (24) M/s. HIRA INDUSTRIES LTD.,  
Pandevoponi, Goodhan Rd.,  
Jagdalpur Distt. BASTAR (MP).
- (25) M/s. DIAMOND CEMENTS,  
P.O. Narsingarh, Distt. Bilaspur (MP).
- (26) M/s. SATNA CEMENT WORKS,  
Steel Foundry, P.O. Birlavikas Colony,  
Satna (MP).
- (27) M/s. BHILAI REFRACTORES PLANT,  
Naradua, P.O. Nowal,  
Distt. Durg (MP).
- (28) M/s. MODI CEMENT LTD.,  
Baloda Bazar, Raipur (MP).

- (29) M/s. RAYMOND CEMENT WORKS,  
Gopalnagar,  
Distt. Bilaspur (MP).
- (30) M/s. CENTURY CEMENT,  
P.O. Baikundh, Distt. Raipur (MP).
- (31) M/s. MAIHAR CEMENT,  
P.O. Sarla Nagar, Maihar,  
Distt. Satna (MP).
- (32) M/s. JAYPEE REWA CEMENT,  
P.O. Jaiprakashnagar,  
Distt. Rawa.
- (33) M/s. SREENIVASA FERRO ALLOYS  
PVT. LTD.,  
Plot No. 278-279, Sector-C,  
Urla Industrial Area,  
RAIPUR.
- (34) M/s. ANNAPURNA ENGG. LTD.,  
Plot No. 216, Sector-C,  
Urla Industrial Area, Raipur (MP).
- (35) M/s. SHRI GIRJA SMOLTARS PVT.  
LTD.,  
2, Pratap Sadan, Rathore Chowk,  
Raipur (MP).
- (36) M/s. DEEPAK FERRO ALLOYS PVT.  
LTD.,  
2, Pratap Sadan, Rathore Chowk,  
Raipur (MP).
- (37) M/s. RAGHUDEER FERRO ALLOYS  
PVT. LTD.,  
Plot No. 130-135, 'C' Block,  
Urla Industrial Complex,  
Raipur (MP).
- (38) M/s. NAVOCHROME (P) LTD.,  
Plot No. 114-122, Sector-C,  
Urla Industrial Area,  
Raipur (MP).
- (39) M/s. BALAGHAT CEMENT (P) LTD.,  
Plot Road,  
Balaghat (MP).
- (40) M/s. DHAR CEMENT,  
Distt. Dhar (MP).
- (41) M/s. C.C.I. NAYAGAON CEMENT  
FACTORY,  
Distt. Mandasapur (MP).
- (42) M/s. VIKRAM CEMENT,  
P.O. Khore, Nayagaon,  
Distt. Mandasaur (MP).
- (43) SHRI SARODA FERRO ALLOYS,  
Ravi Valasatekkali Mandal,
- (44) M/s. SAGAR CEMENT LTD.,  
Mathampally,  
Mathampally Mandal,  
Nalgonda Distt.—508225 (AP).
- (45) M/s. TEXMACO LIMITED,  
Cement Division, Yerragauntla-516309,  
Cuddapah Distt. (AP).

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2880.—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना 2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जो असाधारण राजपत्र (सं. 437, दिनांक 1-8-90) में प्रकाशित किए गए थे। इन्हें एतद्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्तियों/सुझावों को लिखित रूप में इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण "बी" ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी देना चाहिए।

संशोधन

पृष्ठ सं. 122 पर, "बंगला क्षेत्र" शीर्षक के अंतर्गत बायीं तरफ के कालम के नीचे प्रथम पैरे में निम्नलिखित पैरा जोड़े जाने का प्रस्ताव है :—

"नई दिल्ली के बंगला जोन का चित्रण"

नई दिल्ली का बंगला जोन लगभग 2800 हेक्टेयर है, जिसमें उपजोन डी-3 (कस्तूरबा गांधी मार्ग), डी-4 (संसद मार्ग-भाग), डी-6 (रिज क्षेत्र), डी-8 (इंडिया गेट), डी-9 (केन्द्रीय सचिवालय), डी-10 (रिज क्षेत्र), डी-11 (खान मार्फेट इत्यादि भाग); डी-12 (अकबर रोड इत्यादि); डी-13 (चाणक्यपुरी-भाग) डी-14 (सफदरजंग क्षेत्र) के क्षेत्र सम्मिलित होंगे। रिज के साथ सीमा धौला कुंआ, पूसा रोड, लिफ रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट, ताल कटोरा रोड, बिसम्बर दास मार्ग के समानांतर सचिस लेन, पंडित पंत मार्ग, अशोक रोड, उपक्षेत्र डी-1 (कनॉट प्लेस और उसके विस्तार) टालस्टाय मार्ग, स्कूल लेन ब्रिज, रेलवे लाइन, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, लोदी रोड, अरविधों मार्ग, रेलवे लाइन, विनय मार्ग, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, नाले के साथ पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग से आगे धौला कुंआ तक होंगी। तथापि, इसमें संपत्ति सख्या (डी-4, डी-5, डी-13, डी-15 और डी-16) सीमा रेखा के बाहरी तरफ का क्षेत्र भी शामिल होगा।

2. आवासीय प्लॉट—समूह आवास (002) शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ सं. 160 के बायीं ओर के कालम के नीचे निम्नलिखित जोड़ना प्रस्तावित किया जाता है :—

आवासीय बंगला प्लॉट (डिवीजन-डी भाग, नई दिल्ली के बंगला जोन के अंतर्गत आने वाले) वे प्लॉट, जो बंगला हाइप निर्माण के हैं, निम्नलिखित विकास मानदंड प्रस्तावित किए जाते हैं :—

(क) विद्यमान भवन आकार के अन्दर तक सीमित आवर्द्धन/परिवर्तन जो विद्यमान तल कवरेज,

[File No. S-23025/1/89-W.II]  
R. K. NARULA, Under Secy.

एफ.ए.आर. और ऊंचाई आदि की अधिकतम सीमा तक।

- (ख) जहाँ प्लॉट खाली होता है, वहाँ उपर्युक्त पैरामीटरों के अंदर पहले निर्माण की अधिकतम सीमा तक नया निर्माण सीमित होगा यदि प्लॉट खाली है तो साथ वाले बंगला प्लॉटों का विद्यमान भूतल कवरेज, एफ.ए.आर. ऊंचाई इत्यादि, जो भी कम हो, को लागू किया जाए :—

- (ग) आवासीय-समूह आवास :

पहले से स्वीकृत/निर्मित समूह आवास योजनाओं में किसी आवर्धन/परिवर्तन के मामले में विकास नियंत्रण मानदण्ड स्वीकृत योजना अथवा दिल्ली मुख्य योजना-2001 के निर्धारित कोड, जो भी कम हो, के अनुसार होंगे।

- (घ) क्षेत्र के विद्यमान स्वरूप को बनाए रखने के लिए कम सघनता विकास को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक आवास के बंगला प्लॉटों को छोड़कर आवासीय पाकेटों/क्षेत्रों के विकास/पुनर्विकास के लिए डी.यू.ए.सी. के शहरी फार्म अध्ययन और अनुमोदन पर आधारित दिल्ली मुख्य योजना-2001 के निर्धारित विकास कोड के अनुसार होंगे।

- (ङ) गैर-आवासीय-बंगला प्लॉट

दिल्ली मुख्य योजना 2001 में दर्शाए गए गैर-आवासीय उपयोग में आवर्धन/परिवर्तन आवासीय बंगला प्लॉटों के उपर्युक्त निर्धारित पैरामीटर के अनुसार होंगे।

- (च) सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग)  
रेस कोर्स क्षेत्र (भाग)

7 मी. अधिकतम ऊंचाई सहित कम सघनता निर्माण, भूतल कवरेज डी.यू.ए.सी. के शहरी स्वरूप के विद्यमान अनुमोदन से अधिक न हो।

पृष्ठ संख्या 162 पर बायीं तरफ का कालम, कॉपरनिकस मार्ग में व्यावसायिक केन्द्र को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

अधिकतम भूतल कवरेज 25%  
अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात 50  
अधिकतम ऊंचाई 14 मी.  
अन्य नियंत्रण :

भूतल के नीचे तहखाना और तल कवरेज की अधिकतम सीमा तक की अनुमति प्रदान की जायेगी और यदि पार्किंग एवं सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो एफ. ए. आर. में उसे शामिल नहीं किया जाए/उसे हटाये जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली मुख्य योजना-2001 में दिया गया भूमि उपयोग, "लगभग 1.6 हेक्टेयर क्षेत्र, जो उत्तर

में कनिंग रोड, दक्षिण में एक बंगले पूर्व में कॉपरनिकस मार्ग और पश्चिम में केरल स्कूल से घिरा हुआ है और जो "व्यावसायिक उपयोग" के लिए निर्धारित है। उसे "आवासीय उपयोग" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

ऊँचे भवनों पर नीति दिल्ली मुख्य योजना 2001 के पृष्ठ सं. 143 (राजपथ) की सातवीं पंक्ति को इस प्रकार पढ़ा जाए "और इसके विस्तार एवं राजपथ के दक्षिण में बंगला क्षेत्र"। यह प्रस्तावित किया जाता है कि "राजपथ के दक्षिण" शब्द को हटा दिया जाए।

संगठित अनौपचारिक क्षेत्र नाट्य स्थल के शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ सं. 129 (राजपथ) पर प्वाइंट 2 "मंडी हाऊस के निकट प्रस्तावित समुदाय भवन" पढ़ा जाता है। इसे हटाया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रस्तावों को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए, उपनिदेशक (मुख्य योजना) मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार छठी मंजिल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली के पास सभी कार्य दिवसों में उपर्युक्त अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. 20(5)/92-मु. यो.]

विश्व मोहन बंसल, सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th December, 1993

S.O. 2880.—The following modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001, published vide Extraordinary Gazette (No. 437 dated 1-8-1990) are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Secretary, DDA 'B' Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023 within a period of 30 days from the date of issue of this Notice. The person making objection/suggestion should also give his name and address.

### MODIFICATIONS

1. On page 122, right side column below first para under heading "Bungalow Area" the following paragraph is proposed to be added :

Delineation of "Bungalow Zone of New Delhi".

The bungalow zone of New Delhi of about 2800 hec's., shall comprise the areas of sub-zones D-3 (Kasturba Gandhi Marg) ; D-4 (Sansad Marg part) ; D-6 (Ridge Area) ; D-8 (India Gate) ; D-9 (Central Secretariat) ; D-10 (Ridge Area) ; D-11 (Khan Market etc. part) ; D-12 (Akbar Road etc.) ; D-13 (Chanakya-nuri-part) ; D-14 (Safdarjung Area). The boundary shall run from Dhola Kuan along the ridge, Pusa Road, Link Road, Mandir Marg, Park Street, Talkatora Road, Service lane parallel to Bishamber Das Marg, Pandit Pant Marg, Ashoka Road, Boundary of sub-zone D-1 (Connaught Place and its extension), Tolstoy Marg, School Lane Bridge,



Railway line, Mathura Road, Lala Laipat Rai Marg, Lodi Road, Aurbindo Marg, Railway Line, Vinay Marg, Satya Marg, N'ti Marg, Panchsheel Marg along the Nallah, Sardar Patel Marg then Dhaula Kuan. However, this will also cover one plot depth of properties on (D-4, D-5, D-13, D-15 and D-16) outer side of the boundary line.

2. On page No. 160, Left side column below para (i) under Heading—Residential Plot—Group Housing (002), the following is proposed to be added :

**Residential-Bungalow plot (part division-D, falling in bungalow zone of New Delhi)—plots having bungalow type construction the following development control norms are proposed :**

- (a) Addition/alteration or reconstruction to be limited within the existing building envelop, to the maximum extent of existing ground coverage, FAR and height etc.
- (b) Where the plot is fallen vacant, new construction is to be limited to the maximum extent of the earlier construction within the parameters as above. In case plot is vacant then existing ground coverage, FAR, height etc. on adjoining, bungalow plots, whichever is lower, to be followed.
- (c) Residential—Group Housing.—Any addition/alteration/re-construction in Group Housing schemes already sanctioned/constructed, dev. control norms to be as per sanctioned scheme or as per prescribed development code of MPD-2001, whichever is lower.
- (d) Residential—Public Housing.—For development/re-development of residential pockets/ areas other than bungalow plots for public housing, development control norms to be as per prescribed development code of MPD-2001, based on urban form study and approval of DUAC with a view to have a low intensity development to maintain the existing character of the area.
- (e) Non-Residential—Bungalow plots.—Bungalow plots shown for non-residential use in MPD-2001, additions/alterations shall be as per the parameters prescribed above for residential-bungalow plots.
- (f) Government land (use undetermined).—Race Course Area (Part)—Low intensity construction with maximum 7 mts. height, ground coverage not to exceed the existing with urban form approval from DUAC.

3. On page 162, left side column, provision of commercial Centre at Copernicus Marg, which reads as below :

Maximum ground coverage	25%
Maximum floor area ratio	50
Maximum height	14m

Other controls :

Basement below the ground floor and to the maximum extent of ground coverage shall be allowed and

if used for parking and services should not be counted in FAR, is proposed to be deleted.

4. Land use plan contained in MPD-2001, an area measuring about 12.6 ha. bounded by Canning Road in the North, a bungalow in South, Copernicus Marg in East and Kerala School in West and earmarked for 'Commercial' use is proposed to be changed to 'residential' use.

5. Policy on tall buildings.—In Seventh line of page 143 (Gazette) of MPD-2001, reads as "and its extension and the bungalow area South of Rajpath", it is proposed to delete the words "South of Rajpath".

6. Under heading organised informal Sector eating places :

Point 2 on page 129 (Gazette) read as "proposed community centre near Mandi House" is proposed to be deleted.

7. The plan indicating the above proposals is available for inspection at the office of DD(MP) Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I. P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(5)/92-MP]

V. M. BANSAL, Secy

सार्वजनिक-पूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1993

का.आ. 2881.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, "बी" ब्लॉक आई.एन.ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :

"योजना डिब्बीज "बी" में पड़ने वाले और उत्तर में मार्ग संख्या 40 (60 मीटर मार्गाधिकार) से, पश्चिम में पुराने रोहतक रोड को जाने वाली 30 मीटर चौड़ी रोड से दक्षिण और पूर्व में शाहजादा बाग औद्योगिक क्षेत्र से घिरे 2.00 हेक्टेयर (5 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "व्यावसायिक" (समाज सदन) में बदलने का प्रस्ताव है"।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उप-निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, वरप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ 20(13)/93-मु. यो.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 16th December, 1993

S.O. 2881.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B', I.N.A. New Delhi, within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and address.

**MODIFICATION**

"The land use of an area, measuring 2.00 ha. (5 acres) falling in planning division 'B'

and bounded by road No. 40 (60 metres right of way) in the North, 30 metres wide road leading to Old Rohtak Road in the West, Shahajada Bagh Industrial Area to the South and East, is proposed to be changed from 'recreational' to 'commercial' (community centre)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(13)/93-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.